खण्ड–513, अंक–08
मंगलवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1942
(02 मार्च, 2021 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, वर्ष 2021)

(खण्ड 513 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2021

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-149
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	149-151
जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद अन्तर्गत झींझक स्थित सिकन्दरा, बिल्हौर राज्य मार्ग के बीच में पड़ने वाले जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	152
जनपद बुलन्दशहर अन्तर्गत एन0आर0ई0सी0 महाविद्यालय खुर्जा को विश्वविद्यालय बनाने तथा विश्वविद्यालय का नाम प्रो0 राजेन्द्र सिंह उर्फ रज्जू भैया कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	152
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत ग्राम अहलादपुर से धरावाँ मार्ग का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	152-153
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र कैन्ट में हुसैनगंज से डी0ए0वी0 कालेज तक बने उपरिगामी सेतु के दोनों तरफ सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	153
जनपद बरेली के विकास खण्ड फरीदपुर के अन्तर्गत टिसुआ से शिवपुरी होते हुए नगरिया कलाँ मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	153
जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्राम उमरी कलाँ में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	153-154
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद अन्तर्गत अल्ट्राटेक सीमेन्ट तथा ए0पी0एल0 अपोलो के सामने तिराहे पर अन्डरब्रिज बनाये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	154
जनपद शाहजहाँपुर के तहसील तिलहर के अन्तर्गत ग्राम चित्तीवोझी घनश्यामपुर में कतिपय भू-खण्डों पर अवैध कब्जा रोके जाने एवं भू-स्वामी को कानूनी संरक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	154

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत कतिपय बस्तियों एवं गांवों में सामुदायिक केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	155
जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर अन्तर्गत ग्राम ऊँचाडीह मजरा चमरौहा में बरदहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	155
जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चतरा में स्वीकृत इण्टर कालेज का बाधित निर्माणाधीन कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	155-156
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत चिलकहर विद्युत स्टेशन एवं सब-स्टेशन से विभिन्न ग्रामों में जाने वाली जर्जर विद्युत लाइनों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	156
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीराबाद के अन्तर्गत ग्राम ताहरपुर इशाक में मकानों के ऊपर से 11 हजार एस0टी0 विद्युत लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	156-157
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत ब्लाक मुजफ्फराबाद में स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	157
जनपद सहारनपुर सदर के अन्तर्गत ग्राम उमाही से ग्राम कोटा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	157-158
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत मौरावां मोहनलालगंज-उन्नाव मुख्य मार्ग से बाबा बिलेश्वर धाम तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	158
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत मुगलसराय, भुपौली, चहनियां मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	158
जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम राजेपुर में होम्योपैथिक चिकित्सालय की नई बिल्डिंग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	158-159

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद वाराणसी के ग्राम सभा धौरहरा के अन्तर्गत डा0 भीमराव अम्बेडकर रैन बसेरा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	159
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में अधिग्रहीत जनपद सुल्तानपुर एवं जनपद अमेठी के किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	159
उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा यू0पी0पी0सी0एस0 2021 में एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	159-160
जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाई-वे पर गतिरोधक लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	160-161
जनपद प्रयागराज के न्याय नगर में सड़क पर इण्टरलाकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	161
जनपद मिर्जापुर एवं जनपद भदोही के बीच पड़ने वाले जोपा रामपुर घाट-गोपीगंज के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	161
जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत महमूदपुर चट्टी से मानपुर कहोतरी तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	161-162
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर विद्युत व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	162
जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम मंशापुर में बाबा डम्मर दास की तपोस्थली एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	163
जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड दानपुर के अन्तर्गत ग्राम डिरौरा में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	163
ई-कॉमर्स के विस्तार के कारण छोटे-बड़े स्टोर और पारम्परिक दुकानों को चलाने वालों का व्यापार बन्दी के कगार पर पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	163-164

विषय	पृष्ठ-संख्या
उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (वि0प0 से वापसी की सूचना)...	164
उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 (वि0प0 से वापसी की सूचना)...	164
उ0प्र0 शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021 (वि0प0 से वापसी की सूचना)...	164
उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 (वि0प0 से वापसी की सूचना)...	164-165
श्री ब्रजेश कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से संबंधित छः याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)...	165-166
कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से संबंधित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	166-167
श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से संबंधित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	167
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से संबंधित याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	167
श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से संबंधित उन्नीस याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	167-169
श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से संबंधित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	169
श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से संबंधित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	170
अपराह्न भोजन की सूचना...	170
श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से संबंधित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	170-171
श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से संबंधित दो याचिकाएं (व्यपगत)...	171
श्री प्रेमसागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से संबंधित तीन याचिकाएं (व्यपगत)...	171
श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से संबंधित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	172

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी व जनपद लखनऊ से संबंधित एक-एक याचिकाएं (व्यपगत)... ...	172
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से संबंधित नौ एवं जनपद हरदोई से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)...	173-174
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से संबंधित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	174
श्री सुभाष पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर व जनपद अम्बेडकरनगर से संबंधित पांच-पांच याचिकाएं (व्यपगत) ...	174-175
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से संबंधित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	176
श्री उमाशंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से संबंधित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	176
श्री उपेन्द्र नाथ पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से संबंधित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	176-177
श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से संबंधित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	177
प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से संबंधित दो याचिकाएं (व्यपगत)	177-178
श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से संबंधित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	178
श्री अरूण कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से संबंधित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	178
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	179
श्री आजाद अरिमर्दन, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	179-180
श्री गंगा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	180

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	180
श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं) ...	181
श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	181
श्री मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	181
श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	182
श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित चार याचिकाएं (व्यपगत)...	182-183
श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	183
श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	183
डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	183-184
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	184
डॉ0 संगीता बलवन्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	184-185
डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ की एक व जनपद बरेली की दो याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयी) ...	185
डॉ0 अरूण कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	185-186
श्री आनन्द शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	186
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	186

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	187-202
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं	203
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	203-204
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	204-205
आय-व्ययक की साधारण चर्चा में भाग लेने वाले दलीय नेताओं एवं मंत्रीगण हेतु समय-सीमा का निर्धारण	205
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	205-306
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	307-309
जनपद श्रावस्ती के गिलौला बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम फेरन पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	309-310
जनपद उन्नाव के अन्तर्गत भौरेश्वर धाम मन्दिर को जोड़ने वाले रास्ते का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य... ...	310-312
जनपद उन्नाव के अन्तर्गत चौकी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य...	312-313
बांदा राजकीय जिला अस्पताल में नवीन भवन संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य... ...	314
जनपद चित्रकूट के मानिकपुर के अन्तर्गत मऊ पेयजल योजना के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य...	314-315

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 02 मार्च, 2021

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-354

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
8. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
10. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
11. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
12. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
13. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
14. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
15. अनीता लोधी राजपूत, डा0 — बुलन्दशहर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
21. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
22. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
23. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
24. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
27. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
28. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
29. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
30. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
31. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
32. असलम अली, श्री — हापुड़
33. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
34. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
35. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
36. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
37. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
38. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
39. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
40. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
41. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
42. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
43. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
44. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
45. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
46. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
47. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री — कानपुर नगर
48. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
49. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
50. उषा सिरोही, श्रीमती — बुलन्दशहर
51. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
52. ओमकुमार, श्री — बिजनौर

53. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
54. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
55. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
56. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
57. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
58. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
59. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
60. काली प्रसाद, श्री देवरिया
61. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
62. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
63. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
64. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
65. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
66. केसर सिंह, श्री बरेली
67. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
68. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
69. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
70. गंगा, श्री कुशीनगर
71. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
72. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
73. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
74. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
75. गौरी शंकर, श्री जालौन
76. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
77. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
78. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
79. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
80. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
81. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
82. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
83. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
84. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
85. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
86. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
87. जयमंगल, श्री महाराजगंज
88. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
89. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
90. जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
91. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
92. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
93. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
94. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
95. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
96. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
97. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
98. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
99. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
100. दल बहादुर, श्री रायबरेली
101. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
102. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
103. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
104. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
105. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
106. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
107. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
108. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
109. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
110. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
111. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
112. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
113. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
114. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
115. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
116. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
117. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़

118. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
119. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
120. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
121. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
122. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
123. नाहिद हसन, श्री शामली
124. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
125. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
126. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
127. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
128. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
129. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
130. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
131. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
132. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
133. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
134. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
135. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
136. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
137. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
138. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
139. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
140. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
141. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
142. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
143. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
144. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
145. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
146. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
147. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
148. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
149. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
150. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
151. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
152. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
153. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
154. बावन सिंह, श्री गोण्डा
155. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
156. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
157. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
158. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
159. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
160. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
161. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
162. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
163. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
164. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
165. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
166. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
167. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
168. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
169. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
170. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
171. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
172. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
173. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
174. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
175. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
176. महबूब अली, श्री अमरोहा
177. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
178. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
179. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
180. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
181. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
182. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
183. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
184. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच

185. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहाँपुर
186. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
187. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
188. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
189. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
190. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
191. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
192. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
193. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
194. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
195. योगेश धामा, श्री बागपत
196. योगेश वर्मा, श्री खीरी
197. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
198. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
199. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
200. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
201. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
202. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
203. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
204. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
205. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
206. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
207. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
208. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
209. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
210. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
211. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
212. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
213. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
214. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
215. राज करन कबीर, श्री बांदा
216. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
217. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
218. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
219. राजबाला, श्रीमती रामपुर
220. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
221. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
222. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
223. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
224. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
225. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
226. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
227. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
228. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
229. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
230. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
231. राम गोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
232. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
233. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
234. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
235. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
236. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
237. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
238. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
239. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
240. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
241. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
242. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
243. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
244. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
245. लकी यादव, श्री जौनपुर
246. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
247. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
248. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी

249. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
250. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
251. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
252. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
253. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
254. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
255. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
256. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
257. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
258. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
259. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
260. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
261. विनय शाक्य, श्री औरैया
262. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
263. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
264. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
265. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
266. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
267. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
268. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
269. वीरेन्द्र, श्री एटा
270. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
271. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
272. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
273. शशांक वर्मा, श्री खीरी
274. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
275. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
276. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
277. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
278. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
279. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
280. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
281. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
282. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
283. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
284. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
285. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
286. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
287. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
288. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
289. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
290. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
291. संगीता चौहान, श्रीमती अमरोहा
292. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
293. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
294. संजय, श्री बुलन्दशहर
295. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
296. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
297. संजय यादव, श्री बलिया
298. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
299. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
300. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
301. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
302. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
303. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
304. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
305. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
306. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
307. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
308. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, डा0 देवरिया
309. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
310. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
311. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
312. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
313. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
314. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी

315. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
316. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
317. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
318. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
319. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
320. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
321. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
322. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
323. सुभाष राय, श्री अम्बेडकर नगर
324. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
325. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
326. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
327. सुरेश कुमार, श्री शामली
328. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
329. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
330. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
331. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
332. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
333. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
334. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
335. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
336. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
337. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
338. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
339. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
340. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
341. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
342. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
343. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
344. सौरभ सिंह, श्री खीरी
345. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
346. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
347. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
348. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
349. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
350. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
351. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
352. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
353. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
354. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :- जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में आवारा जानवरों से किसानों की फसल को हो रहे नुकसान की जांच व इसका मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में

***1-श्री मनोज कुमार पाण्डेय तथा श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत तीन वर्षों में छुट्टा जानवरों के कारण किसानों की फसल का कितना नुकसान हुआ है ? क्या सरकार उक्त का मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अभी तक निर्गत अधिसूचनाओं/ शासनादेशों द्वारा घोषित आपदाओं के अन्तर्गत छुट्टा जानवरों से किसानों की फसलों का नुकसान किसी आपदा के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

***श्री उमाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से मा0 मंत्री जी से दो छोटे-छोटे अनुपूरक करूंगा, क्योंकि इस प्रश्न को लाने का उद्देश्य मा0 मंत्री जी भी समझ रहे होंगे और पूरा सदन समझ रहा होगा। हम इससे इन्कार भी नहीं कर सकते हैं, यह समस्या सबकी समस्या है। यह नहीं है कि हम इधर बैठे हैं तो आरोप लगायें, आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं है। इसका हमें हल निकालना चाहिए, हल निकालने में आपने प्रयास भी किया है। जगह-जगह आपने गौ आश्रय या गौशालाओं को संचालित किया है।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल क्या है ?

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कल एक प्रश्न आया था कि हम प्रति जानवर 900 रुपये की धनराशि दे रहे हैं। मा0 मंत्री जी सोच सकते हैं। एक जानवर एक दिन में कम से कम 17 से 18 किग्रा0 भूसा खाता है। अगर एक महीने का देखें तो 5 क्विंटल से अधिक उसके भूसे की खपत हो जाती है। आप अन्दाजा लगाइये कि यह 5 क्विंटल भूसा कितने में मिलेगा। मुझे तो लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है। जो धनराशि 900 रुपये निर्धारित है, क्या मा0

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी इस बजट को बढ़ायेंगे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस जानवर को अपने यहां रखने को तैयार हो जाये ताकि गौशालाओं में या जहां पर इस तरह के आश्रय बने हों, वहां पर जानवरों की मृत्यु न हो। चारा मिल नहीं रहा है तो जानवरों की मृत्यु हो रही है। क्या मा0 मंत्री जी 900 रुपये से बढ़ाकर धनराशि देने के लिए प्रस्ताव सदन में लायेंगे, जिससे कि जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके ?

***जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह)-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इनकी सरकार के समय तीन साल में 3 करोड़ रुपये दिये गये थे, सपा सरकार में 10 करोड़ रुपये दिये गये थे और मेरी सरकार के तीन साल में 81 करोड़ रुपये दिये गये हैं। हर तरीके की व्यवस्था गौ संरक्षण, गौ संवर्धन के लिए की जा रही है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गौ सेवा आयोग बनाया। पहली बार मा0 योगी सरकार ने गौ आश्रय स्थल बनाने का काम किया है। मा0 योगी सरकार ने पहली बार गौ वध पर कानून बनाया है। मा0 योगी सरकार ने पहली बार 30-30 रुपये देकर जो गौ पालन करना चाहते हैं, निराश्रित पशुओं को लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि इससे अच्छी व्यवस्था पूरे भारत के अन्दर कहीं नहीं है और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जो सरकारी खजाने से धन खर्च करके गौ संरक्षण के लिए काम कर रहा है।

(सदस्य, श्री उमाशंकर सिंह के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य उमाशंकर सिंह जी इस पर कल भी काफी डिस्कशन हुआ था।

इस पर कल भी डिस्कशन हो चुका है। कल भी आप बोले थे।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दूसरे पैरे का जो सवाल है कि क्या सरकार उक्त का मुआवजा देगी। मंत्री जी ने बताया कि इतनी व्यवस्था सरकार दे रही है, उनको पर्याप्त पैसा दिया जा रहा है, इस स्थिति के बावजूद अगर किसान की फसलों का नुकसान होता है और आपके ही अधिकारी उसका वेरीफिकेशन करते हैं, तो क्या उन फसलों का मुआवजा किसानों को सरकार देगी।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल कई बार हुआ है।

डा0 महेन्द्र सिंह-

अध्यक्ष जी, मुझको कहते हुए गर्व हो रहा है कि जबसे गौ-माता की पूजा और गायों का संरक्षण शुरू हुआ है, प्रतिवर्ष किसानों की उपज बढ़ रही है और मैं आंकड़ा प्रस्तुत करना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूँ, यह आंकड़ा आनलाइन है, सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई भी देख सकता है, पिछली बार 601 लाख मी0 टन पैदावार थी इस बार बढ़कर 620 लाख मी0 टन पैदावार हुई है। अगर पाँच सालों का आंकड़ा पढ़ें तो प्रतिवर्ष पैदावार बढ़ती चली जा रही है। अगर सब नुकसान हो जा रहा है, तो पैदावार कहाँ से बढ़ रही है। किसान तो हमारा भगवान है, किसान अन्नदाता है, किसान तो गौओं की पूजा करता है। गौओं का पालन करता है, इसलिए गौ-माता की बड़ी कृपा है कि उपज बढ़ती चली जा रही है और उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल होता चला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी आप क्यों खड़े हो रहे हो आप तो पूछ चुके थे कल।

***श्री लालजी वर्मा-**

माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया पूरे प्रदेश का, माननीय उमाशंकर सिंह जी ने स्पेसिफिक प्रश्न किया था कि जहाँ पर छुट्टा जानवरों से किसान की फसल की क्षति होती है और अधिकारी स्तर पर रिपोर्ट भी आती है, तो क्या उस स्पेशल किसान का सबका तो होगा नहीं। जहाँ तक आपने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने की बात कही है, यह तो अनवरत् हो रहा है हमारे वैज्ञानिकों की रिसर्च के कारण, किसानों की मेहनत के कारण खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ा देकर आप बचना चाह रहे कि किसानों का नुकसान नहीं हो रहा है, यह उचित नहीं है। माननीय उमाशंकर सिंह जी ने स्पेसिफिक पूछा कि जिन किसानों की फसल छुट्टा जानवरों से नष्ट होती है, उसकी जाँचोपरान्त अधिकारी रिपोर्ट भी करते हैं कि इनका नुकसान हुआ, उस विशेष नुकसान को क्या सरकार उनको मुआवजा देकर पूरा करने का काम करेगी। भाषण नहीं केवल इतने का जवाब दीजिए।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मैं इतने का ही जवाब दे रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से कोई रिपोर्ट इस प्रकार की नहीं आई है कि इन पशुओं के कारण हमारी फसल नष्ट हो गई, हमको मुआवजा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

प्रदेश में बाढ़ से बचाव हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

***2-श्री संजय गर्ग-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ से बचाव हेतु क्या कार्य वर्तमान में किये जा रहे हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह)-

बाढ़ से बचाव हेतु नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनायें, पुनरोद्धार की योजनायें, तटबन्धों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण एवं जल निकास/ड्रेनेज की योजनाएं संचालित हैं। उक्त के अतिरिक्त अनुरक्षण के कार्य कराये जा रहे हैं।

जी हाँ।

विवरण निम्नवत् है:-

1- वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रारम्भ में 254 बाढ़ परियोजनाएं संचालित थीं, जिनमें से 146 बाढ़ परियोजनाएं माह दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण की जा चुकी हैं, जिनका लोकार्पण मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा किया जा चुका है।

2- आगामी बाढ़ से बचाव हेतु उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति की दिनांक 14-12-2020 को सम्पन्न बैठक तथा विशेष बैठकों के द्वारा कुल 221 परियोजनाएं (कुल लागत रु0 1461.12 करोड़) की स्वीकृति की गयी, जिनमें से 183 परियोजनाओं को संचालित कर दिया गया है।

3- बाढ़ नियंत्रण के मूल बजट प्राविधान रु0 966.00 करोड़ के अतिरिक्त गत वर्ष की संचालित परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने तथा नयी परियोजनाओं को माह जनवरी, 2021 से प्रारम्भ करने हेतु रु0 747.95 करोड की अतिरिक्त बजट व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से करायी गयी, जिसके फलस्वरूप बजट रु0 1713.95 करोड़ हो गया।

4- इसी प्रकार बाढ़ अनुरक्षण मद में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष रु0 141.54 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

***श्री संजय गर्ग-**

अध्यक्ष जी मेरे केवल दो प्रश्न हैं। एक तो सहारनपुर में शिवालिक के बाद बहुत तेजी के साथ पानी आता है वह पूरा का पूरा सोयल इरोजन करके आस-पास के गांवों की भूमि का कटाव करता है। यह बात पहले भी उठी थी कि वहाँ पर चेकडैम बनाने चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में क्या वहाँ पर चेक डैम बनाने की कोई योजना बाढ़ नियंत्रण परिषद् में पास हुयी है अथवा नहीं ? दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो नगर का विधान सभा क्षेत्र है, उसमें वर्ष 2013 में धमोला नदी में इतनी बाढ़ आ गयी थी कि लोगों के घरों की छतों के ऊपर पानी था। उसको पिचिंग के लिये और कुछ जगहों पर भूमि के कटाव को रोकने के लिये योजना बनी और उत्तर प्रदेश बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति ने 2019 में उसे मंजूर भी किया, परन्तु उसके साथ यह लगा दिया कि चूंकि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह शहर के अन्दर है, इसलिये नगर विकास विभाग इसे पोषित करने का काम करेगा। मेरे द्वारा बार-बार लिखने के बावजूद न तो नगर विकास विभाग द्वारा और न ही बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा उसे वित्त पोषित किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहते हुये मा0 मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि उस योजना को वित्त पोषित करने हेतु सरकार कोई व्यवस्था करने का काम करेगी अथवा नहीं ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझको बहुत गर्व है कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और शामली से ही आने वाले हमारे आदरणीय मंत्री विजय कश्यप जी हमारे साथ राज्य मंत्री हैं। पिछली बार उन्होंने जितनी परियोजनाएं वहाँ की बतायी थीं हमने उन सभी परियोजनाओं को लिया है और सारी परियोजनाएं अब तक पूर्ण भी करा दी गयी हैं और उनका लोकार्पण भी आदरणीय मुख्य मंत्री जी द्वारा हो चुका है। हमारे मा0 संजय गर्ग जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। 44 करोड़ 82 लाख की परियोजना पिछली बार थी और इस बार भी जितनी परियोजनाएं जिलाधिकारी ने लिखकर दीं, जनप्रतिनिधियों ने लिखकर दीं, सांसद, विधायकों ने रिकमेंड किया, सारी की सारी परियोजनाएं हमने ले ली हैं, एक भी परियोजना छोड़ी नहीं है। आपने चेकडैम की बात कही है। चेकडैम सिंचाई विभाग नहीं बनाता है। आपका यह प्रश्न लघु सिंचाई से संबंधित है, इसमें यह नहीं आता है। आपने बाढ़ से संबंधित बात कही थी, तो आदरणीय अध्यक्ष जी, बाढ़ के सम्बन्ध में मै मा0 संजय भाई साहब को भी और पूरे सदन को भी आपके संरक्षण में कहना चाहता हूँ कि आजादी से लेकर अभी तक 24 जनवरी, 1950 से लेकर अब तक अगले वित्तीय वर्ष में पैसा सेंक्शन किया जाता था, लेकिन आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार जनवरी माह से ही कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कोई संकट न आने पाए और हम लोगों ने उन परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर दिया है और काम भी शुरू कर दिया है। मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि 15 लाख हेक्टेयर जमीन जो उस समय बाढ़ से बुरी तरह से आच्छादित हुयी थी, इतना अच्छा काम करने के कारण अब वह घटकर 12 हजार पर आ गयी है। आपके यहाँ पर भी अगर बाढ़ से संबंधित कोई चीज होगी तो आप दे दीजियेगा, आप चिन्ता मत करियेगा, यह योगी सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर काम करती है, इसलिये निश्चित रूप से हम लोग उस काम को करेंगे।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बहुत लम्बा प्रलाप किया है, इतना लम्बा प्रलाप करने की जरूरत नहीं थी। इनकी महिमा क्या है, वह सारा प्रदेश जानता है। मेरा कैटेगरिकल केवल एक प्रश्न है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिलाधिकारी द्वारा शासन को कई बार रिमाइंडर लिखे जा चुके हैं। सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र में धमोला नदी की पिचिंग का काम बहुत बड़े प्रोजेक्ट का नहीं है कि वह हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट हो, बल्कि वह तो मात्र 8-9-10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन वह केवल इस उलझन में उलझा हुआ है कि बाढ़ नियंत्रण में पैसा होने के बावजूद

भी उसे नगर विकास विभाग पोषित करेगा। नगर विकास को लिखने के बाद न तो उनके द्वारा पोषण की कोई जिम्मेदारी ली जा रही है। मैंने मा0 मंत्री जी को भी लिखकर दिया, परन्तु आपके द्वारा भी उसके पोषण की जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। वह नेचुरल नदी है जिसकी पिचिंग होनी है, जिसके अभाव में भूमि कटाव के कारण 2013 की बाढ़ में वहाँ बहुत ज्यादा बुरी स्थिति बनी थी और बरसात के दिनों में आम आदमी का वहाँ पर शांति से सोना भी मुश्किल है, वह इस बात से डरता है कि रात को अगर बाढ़ आ गयी और फिर दोबारा उस तरह की प्रलय जैसी स्थिति हुयी तो हालात क्या होंगे। पूरे प्रदेश में इन्होंने कितने हेक्टेयर जमीन इन्होंने बचा ली, कितनी नहीं बचाई, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। इन्होंने चेकडैम की बात टाल दी कि यह लघु सिंचाई का काम है। स्वायल इरोजन होगा, बाढ़ के साथ अभी जिस तरह का काम उत्तरांचल में हुआ और तेज धार के साथ, तेज रफ्तार के साथ पानी आ करके भूमि कटाव करेगा तो उस कटाव को रोकने के लिये चेकडैम की जरूरत है, सिंचाई के लिये वहाँ पर चेकडैम की जरूरत नहीं थी। उस तरह के छोटे-छोटे वाटर रिजर्वायर बनाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

आप मा0 मंत्री जी के विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न ही पूछिये।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मेरा जो अपनी विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है उस पर मैं आपका संरक्षण चाहते हुए मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि उसे या तो अपने ही विभाग के द्वारा या नगर विकास विभाग के द्वारा पोषित कराने का काम किया जाये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहाँ हैं और मा0 नगर विकास मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, मुद्दा बाढ़ का है, इसलिये नगर विकास विभाग या बाढ़ नियंत्रण में से कोई भी उसे कर दे। सहारनपुर के जिलाधिकारी महोदय द्वारा कई बार लिखा जा चुका है और जिलाधिकारी महोदय ने जो लिखा है मैं उसका रिमाइंडर भी दे दूंगा।

***श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-**

मा0 अध्यक्ष जी, गाजीपुर जनपद में सुकनी, बैरिकपुर और पुरैना ये तीन गांव गंगा के कटान से दो बार विस्थापित होकर दूसरी जगह स्थापित हुए हैं। वर्तमान समय में मा0 मंत्री जी ने कुछ पैसा दिया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि बैरिकपुर, सुकनी और पुरैना इस तरह के लगभग 8 से 10 गांव हैं, जिनको गंगा काट देती है। क्या इन गांवों को मा0 मंत्री जी कुछ धन देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आज के सवाल में ये गांव पहले से नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, ये विषय बाढ़ से ही सम्बन्धित हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ऐसे ही सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों के गांवों के बारे में पूछेंगे जो मा0 मंत्री जी की फाइल में गांव होंगे ही नहीं तो उनका जवाब वह कैसे देंगे ?

श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

मा0 अध्यक्ष जी मा0 मंत्री जी सक्षम हैं इन गांवों के लिए कुछ व्यवस्था करा दें ताकि किसानों के ऊपर कोई कृपा दृष्टि हो जाय। मा0 मंत्री जी बस आश्वासन दे दें, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी मैं इनका भी जवाब दिए दे रहा हूँ और उनका भी दिए दे रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मान्यवर, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया था कि जितनी भी प्राथमिकतायें आधारित आपकी परियोजनायें हैं उनको आप लोग लिखकर दे दीजिए हम उनको सम्मिलित करना चाहते हैं। आदरणीय संजय जी भाई साहब को भी पत्र मिला होगा। हमने सभी विधायकों और सांसदों को पत्र लिखा था और जितने लोगों ने लिखकर भेजा है उनकी एक भी परियोजना हमने छोड़ी नहीं है, सबको हमने सम्मिलित किया है। जहां तक गाजीपुर की बात थी तो गाजीपुर में पिछली बार भी हमने बहुत काम कराये थे और इस बार भी जितनी परियोजनायें गाजीपुर की आई हैं सबको हमने सम्मिलित कर लिया है और सब पर काम शुरू होने जा रहा है। इसलिए संजय जी ने जो बात नगर विकास और जल शक्ति विभाग के सम्बन्ध में कहीं है ऐसा कोई पत्र आज तक इनको अभी नहीं मिला है, अगर ये हमारे संज्ञान में लायेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने नगर विकास मंत्री जी से बातचीत करके देखेंगे कि उसका समाधान कहाँ से हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी आश्वासन आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने आश्वासन ही तो दिया है कि आप जो पत्र देंगे हम समाधान करायेंगे।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी हमने सहारनपुर के जिलाधिकारी को पत्र दिया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने कहा तो है कि पत्र उपलब्ध करा दें।

श्री संजय गर्ग-

ठीक है मान्यवर।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या के सापेक्ष शिक्षकों की मानकानुसार नियुक्ति किये जाने विषयक

***1-श्री विनय शंकर तिवारी-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या के सापेक्ष शिक्षकों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार मानकानुसार शिक्षकों की कमी को देखते हुये प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी)-

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1,20,82,855 छात्र-छात्राओं के सापेक्ष 3,32,734 अध्यापक कार्यरत हैं।

जी हाँ।

आवश्यकतानुसार रिक्त पदों पर विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

***श्री विनय शंकर तिवारी-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमारे प्रश्न पर अनुपूरक पूछने के लिए समय दिया इसके लिए आपका आभारी हूँ। मा0 मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1,20,82,855 छात्र-छात्रायें हैं उनके सापेक्ष 3,32,734 अध्यापक कार्यरत हैं। आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार एक अध्यापक के ऊपर या कितने छात्रों के ऊपर एक अध्यापक होना चाहिए ? और क्या यह मानक पूरा है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो अध्यापक हैं, जो यह संख्या दी गयी है 3,32,734 इसमें क्या अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी शामिल हैं या उससे अलग हैं ? क्या यह संख्या पर्याप्त है अगर पर्याप्त है तो ठीक है अगर नहीं पर्याप्त है तो कितने दिनों में उस संख्या को पूरा कर लिया जायेगा ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात है प्राथमिक विद्यालयों के लिए 30 पर 1 है। 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। आज की तिथि में उत्तर प्रदेश में 35.9 और एक का अनुपात है अर्थात हम लगभग आदर्श अनुपात के नजदीक है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह अनुपात प्लस 35 का होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में आज की तिथि में 53

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और 1 का है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह अनुपात अभी इसलिए हम आदर्श स्थिति के नजदीक नहीं पहुँचा पा रहे हैं क्योंकि वहां पर सीधी भर्ती की व्यवस्था नहीं है एक बार विशेष अभियान में केवल गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती हुई थी, प्राथमिक विद्यालयों की पदोन्नति के माध्यम से ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हम भर्ती करते हैं। मामला न्यायालय में लम्बित होने के कारण एक विवाद उसमें है कि जो प्रोन्नति होनी है उनको भी टी0ई0टी0 पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके कारण यह मामला न्यायालय में है अतः इस मामले में भी यथाशीघ्र समाधान नहीं हो सकता है कि प्रोन्नति करके उसको भी कर सकें। इसका प्रयास कर रहे हैं। अभी माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि यह जो शिक्षकों की संख्या है क्या उसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी शामिल हैं, जी हां अध्यक्ष जी शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी अध्यापन के कार्य के लिए ही रखे गये हैं इसलिए वह संख्या भी इसमें शामिल है और एक और जानकारी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को पूरे सदन को और पूरे प्रदेश को देना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अप्रैल 2017 के बाद से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए और छात्र-शिक्षक अनुपात को आदर्श स्थिति में पहुंचाने के लिए 119287 शिक्षकों की भर्ती की है और इसके अलावा भी समय-समय पर एडेड जूनियर हाई स्कूल जो थे जिनकी भर्ती की व्यवस्था सरकार ने अपने हाथ में ली है लगभग 1900 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन भी मांगे गये हैं और समय-समय पर जितनी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है उस मानक को पूरा करने के लिए सरकार लगातार उनकी भर्ती करने का काम कर रही है।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय, मंत्री जी का कहना है कि संख्या पूरी है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक उदाहरण के लिए हम गोरखपुर जिले का उदाहरण देना चाहेंगे। गोरखपुर में जो संख्या है 319864 बच्चे नामांकित हैं और उनके सापेक्ष 6300 शिक्षक हैं तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एकल व्यवस्था है, एक ही शिक्षक है, कहीं पर दो हैं, जहां पर 7 शिक्षक चाहिए, 8 शिक्षक चाहिए लेकिन कहीं एक है, कहीं दो है और शिक्षकों की शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के बाद भी भारी कमी है उस हालात में उन बच्चों का कैसे कल्याण होगा ? एक जिले का केवल उदाहरण है हम अपने जिले की केवल बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

द्विवेदी जी ने पूरे जिले का और पूरे प्रदेश का बता दिया है।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने एक जिले का बता दिया कि कितना कम है। जो मानक है एक पर तीस का या एक पर पैंतीस का उसके हिसाब से कितना कम है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्राइमरी शिक्षा है उसमें पूरे हैं और जूनियर है उसमें कम है तो जो कम है वह कब तक पूरा कर लिये जायेंगे ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे उत्तर प्रदेश का अनुपात और हमारे प्रयास के बाद अगर इसी तरह का ध्यान अगर पिछले 10-15 वर्षों में दिया गया होता तो यह स्थिति नहीं होती लेकिन एक लाख उन्नीस हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति भरने के कारण हम उस एक और 35.9 के अनुपात पर पहुंच चुके हैं। लगातार उसमें सुधार की कोशिश कर रहे हैं। पूरे प्रदेश का मुझसे अनुपात पूछा गया था यह मैंने औसत बताया है मा0 सदस्य किसी एक जनपद की बात कर रहे हैं अभी तय करेंगे चूंकि स्कूल खुल चुके हैं हम बीच में कोई समायोजन नहीं कर सकते। अभी हमने जो नियुक्तियां की हैं, जनपदवार कैडर होता है शिक्षक वहाँ पर प्लेसमेन्ट हुआ है और समर वैकेशन में हम शिक्षक से आवेदन मांगेंगे हमारे कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ शिक्षक अतिरिक्त हैं जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हैं कई विद्यालय ऐसे हैं जहां जितना होना चाहिए उससे कम है यह आन्तरिक समायोजन अन्तर्जनपदीय समायोजन के माध्यम से समर वैकेशन में हम पूरा कर लेंगे और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी प्राथमिक विद्यालय में जहां यह परिदृश्य था कि अक्सर शिक्षक न होने के कारण स्कूल बन्द होते थे हमने जो नियुक्तियां की हैं लगभग एक लाख उन्नीस हजार से ज्यादा उसके कारण आज हमारा कोई भी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है।

प्रदेश में प्राइमरी के समस्त छात्रों को शासकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में समायोजित कर सकने की क्षमता तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

***2-श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट (अनुपस्थित)-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि प्राइमरी विद्यालयों से शिक्षा पूर्ण करने वाले समस्त विद्यार्थियों को उक्त माध्यमिक स्कूलों में समायोजित करने की क्षमता है ? यदि नहीं, तो उक्त के निराकरण हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (डॉ0 दिनेश शर्मा)-

प्रदेश में 2272 शासकीय एवं 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

उक्त के अतिरिक्त 21023 वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय एवं 1070 विद्यालय उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकर्ता मा0 श्री प्रभात कुमार वर्मा जी उपस्थित नहीं है।

***3-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

(4थे बुधवार के ताराकिंत प्रश्न सं0-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

***4-श्री अजय कुमार लल्लू-**

(4थे मंगलवार हेतु स्थगित)

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत बेसिक शिक्षकों का सामान्य बीमा राज्य कर्मचारियों की भांति 2 लाख रु0 करने विषयक

***5-अवस्थी बाला प्रसाद (अनुपस्थित)-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत बेसिक शिक्षकों के लिए वर्तमान में सामान्य बीमा योजना के तहत एक लाख रुपये के बीमा हेतु कटौती होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य कर्मचारियों के भांति बेसिक शिक्षकों का भी सामान्य बीमा 2 लाख रुपये करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

शासनादेश सं0-254/68-5-2020, दिनांक 22-04-2020 द्वारा शिक्षकों/शिक्षा मित्रों/अनुदेशकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु रुपये पांच लाख बीमित राशि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के ग्रुप टर्म इन्श्योरेन्स पॉलिसी की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य श्री अवस्थी बाला प्रसाद जी उपस्थित नहीं हैं।

प्रदेश व टाण्डा के नगर शिक्षा क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/अध्यापक की नियुक्ति न होने से शिक्षण कार्य बाधित होने के कारण शिक्षकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में

***6-श्री लालजी वर्मा-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर शिक्षा क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में विगत कई वर्षों से प्रधानाध्यापक/अध्यापक की नियुक्ति न होने से शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकरनगर में नगर शिक्षा क्षेत्र टाण्डा में लगभग 20 प्राथमिक विद्यालयों में भी विगत कई वर्षों से अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हाँ, तो उक्त नगर शिक्षा क्षेत्र टाण्डा में कब तक अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापक/ प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं, किन्तु प्रदेश के नगर क्षेत्र में संचालित 4,490 प्राथमिक विद्यालयों में 5,46,157 नामांकित छात्र-छात्राओं के सापेक्ष 9,467 शिक्षक एवं 3,843 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। कार्यरत शिक्षकों/ शिक्षा मित्रों से शिक्षण कार्य सुचारु रूप से कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जनपद अम्बेडकरनगर के नगर शिक्षा क्षेत्र टण्डा में 11 प्राथमिक विद्यालय तथा 03 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 1265 (प्राथमिक विद्यालय में 1167 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 98) छात्र/छात्राएं अध्ययनरत् हैं। प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 08 सहायक अध्यापक व 15 शिक्षा मित्र कार्यरत है, जिनसे शिक्षण कार्य सुचारु रूप से कराया जा रहा है।

नियुक्ति/तैनाती यथाशीघ्र की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि टाण्डा में 14 विद्यालय हैं और उसके सापेक्ष केवल 08 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं और बाकी 15 शिक्षा मित्र हैं। इन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक कहीं भी नहीं हैं। मान्यवर, जब विद्यालय में शिक्षक नहीं रहते हैं तो बच्चे धीरे-धीरे कम हो जाते हैं और वह दूसरी जगह पर एडमीशन ले लेते हैं। हमारे प्रदेश में जो बच्चों की तादाद है वह कम नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जो पहले प्रश्न का उत्तर दिया है वहां भी शिक्षक कम होने के कारण निजी संस्थाओं में बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि टाण्डा के 14 विद्यालयों में जो रेगुलर शिक्षकों के रिक्त पद हैं उनकी पूर्ति कब तक कर लेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि प्रधानाचार्य के जो पद रिक्त हैं उनकी पूर्ति कब तक करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि आदर्श शिक्षा व्यवस्था सभी बच्चों को निःशुल्क मिल सके और पब्लिक स्कूलों से लोगों का भार कम हो इस दृष्टि से जो छात्रों की तादाद है उसको भी साथ लेकर इस तरह का आदर्श विद्यालय कब तक स्थापित कर लेंगे। संविधान के अन्तर्गत राज्य का कर्तव्य निर्धारित है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाये तो इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए कब तक कार्यवाही की जायेगी।

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की स्थिति में मिशन कायाकल्प के अन्तर्गत जो आमूल-चूल परिवर्तन का काम हुआ है उसका परिणाम यह है कि वर्ष 2017 के बाद से लगातार प्रतिवर्ष प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में लाखों की संख्या में छात्रों का नामांकन बढ़ रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद् के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के आस-पास जो निजी

विद्यालय हैं उनकी संख्या कम हो रही है और लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। इसका कारण यह है कि मिशन कायाकल्प के माध्यम से हमने उनकी बिल्डिंग ठीक की है,

मान्यवर, बात शिक्षाप्रद रंगाई-पुताई की है। बाउण्ड्री बनाई है। विद्युतीकरण कराया है। पेयजल की व्यवस्था की है। पहली बार उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की फर्श पर संगमरमर और टाईल्स दिखी है। हमने अभी जो धनराशि जारी की है लगभग चार सौ करोड़ की, उसके बाद उत्तर प्रदेश का कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं बचेगा जहां फर्नीचर न हो और समाज के सहयोग से सी0एस0आर0 फण्ड से विभाग के धन से माननीय मुख्य मंत्री जी की विशेष रुचि के कारण लगातार हमको जो धन मिल रहा है, उससे ग्राम पंचायत निधि से पंचायत राज विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में तेजी से फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा की बात जो माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कही है उसमें कक्षा एक से कक्षा आठ तक के छात्र-छात्राओं की पूरी निःशुल्क शिक्षा हमारे बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में है। हम उनको दो जोड़ी अच्छी रंगीन ड्रेस भी दे रहे हैं। जूते-मोजे भी दे रहे हैं। पहले सिर्फ खाकी रंग का यूनिफार्म मिलता था। हम उनको बैग के साथ-साथ किताबें भी दे रहे हैं। माननीय नेता बसपा अभी जो बात अम्बेडकरनगर के सापेक्ष में कही है।

माननीय अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा में 2008 से जो नियुक्ति हो रही है उसमें शिक्षकों का जो पदस्थापन होता है वह अध्यापक तैनाती नियमावली के अन्तर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही पदस्थापन हो सकता था। यह व्यवस्था वर्ष 2008 से बनी हुई थी, जिस कारण नगर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी हुई। वर्ष 1996 के पहले स्थानान्तरण के माध्यम से उसको पूरा कर लिया जाता था, लेकिन वर्ष 1996 के बाद से स्थानान्तरण भी नहीं हुआ है। वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में कुछ स्थानान्तरण भी हुए, लेकिन यह विवाद हो गया कि किसको ग्रामीण क्षेत्र से नगर में भेजा जाय और किसको न भेजा जाय इस नाते यह प्रक्रिया रुक गयी, जिसकी वजह से उल्टी स्थिति हो गई। हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापक ज्यादा हो गये, लेकिन नगर में कम हो गये। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार किसी सरकार ने समग्रता में पूरी बेसिक शिक्षा की समस्याओं को संज्ञान में लिया है। हमारे गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और शिक्षक मिल सकें इसलिए हम अध्यापक तैनाती नियमावली में भी संशोधन करने जा रहे हैं। ग्रामीण और नगर का यह विभाजन खत्म करेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्र में जहां अतिरिक्त शिक्षक हैं उनका पदस्थापन नगर क्षेत्र में करेंगे। अम्बेडकर नगर ही नहीं पूरे प्रदेश में नगर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी है, उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। ऐसे तमाम जरूरी संशोधन हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे इस तरह की समस्याओं का समाधान हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कह सकता हूं कि यथाशीघ्र हम बहुत जल्दी ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे चूंकि वह कैडर समाप्त करना है, नगर और ग्रामीण का विभाजन समापन करना है इसलिए मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जब आप अगली बार सदन में आयेंगे तब तक आपके समक्ष नई नियमावली आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी अब तो स्पष्ट आश्वासन हो गया है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, आश्वासन तो हो गया है, लेकिन इनके उत्तर से ही मेरा एक सवाल निकलता है, अगर आपकी अनुमति हो तो।

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब तो पूरा आश्वासन आ गया है। इसमें आप लोगों को शोर मचाने की क्या जरूरत है ?

(श्री कैलाश नाथ सोनकर जी और श्री उमाशंकर जी द्वारा लगातार एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बोलते चले जा रहे हैं पहले हमारी बात तो सुनिये। मंत्री जी के उत्तर में कम से कम तीन बार आश्वासन आया है कि वह अतिशीघ्र यह कमियां पूरी करेंगे। जब तीन बार स्पष्ट आश्वासन आ गया है तो इसमें बाद में लगातार बहस करने का क्या मतलब है ?

***श्री कैलाश नाथ सोनकर-**

मान्यवर, मेरी जो विधान सभा क्षेत्र है वहां पर मैंने शुरू-शुरू में अपनी निधि से कुछ विद्यालयों में डेस्क, बैंच दिया था। अभी इंग्लिश मीडियम के जो विद्यालय बनाये गये हैं वहां डेस्क बैंच तक नहीं लगे है।

श्री अध्यक्ष-

आपके विधान सभा क्षेत्र का जो भी मामला है उसे आप माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए।

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सारे प्राइमरी विद्यालयों में उन्होंने डेस्क-बैंच उपलब्ध करा दिये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका जो विषय है उसे दिखवा लिया जायेगा।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। इसलिए कभी इधर-उधर की बात नहीं करता हूँ। मैंने कहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ज्यादातर विद्यालयों में फर्नीचर हो गये थे जो शेष बचे थे उन सबके लिए लगभग 400 करोड़ की धनराशि हमने जारी की है। अब उत्तर प्रदेश का कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय फर्नीचर विहीन नहीं रहेगा। जैसे सोनभद्र में, मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री भी हूँ। जनपद खनिज निधि से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहाँ के सभी प्राथमिक विद्यालयो में भी फर्नीचर की व्यवस्था हो रही है। आगे प्राथमिक विद्यालयों में भी फर्नीचर हो हम उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं भी गाँव में प्राइमरी स्कूल में पढ़कर आया था और जहाँ पढ़ने जाता था वहाँ कोई भवन नहीं था। चार खम्भे खड़े थे और बचपन से हमको यही बताया गया था कि यही स्कूल है। मैं कह रहा हूँ कि उस स्थिति से निकालकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टाइल्स की व्यवस्था की है, पंखे लग रहे हैं। मैं जल शक्ति मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर जल शक्ति मिशन के तहत हर स्कूल को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करा रहे हैं। किचन शेड दिया है। यह सारी व्यवस्थायें कर रहे हैं। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, 50 साल में जो नहीं हुआ 3-4 साल में सब कुछ संतृप्त हो जायेगा यह संभव नहीं है। मा0 विधायक जी ने अपने क्षेत्र के संदर्भ में जो बात कही है, मा0 अध्यक्ष जी वह हमको लिखकर दे देंगे तो मैं उसको दिखवा लूंगा।

***डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

मान्यवर, एक अनुपूरक प्रश्न है। (इस बीच सदस्य बोलते रहे लेकिन उनका माइक ऑफ था)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, आपका विषय आ गया। वह कह रहे हैं कि जो लिखकर आप देंगे वह करा देंगे। आपका भी हो जायेगा।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

मान्यवर, जो बच्चे 2010 से पहले हाई स्कूल, इण्टर, बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम किये हैं उनका एकेडेमिक गुणांक कम रहता है। इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। वह 40 साल से ऊपर हो रहे हैं। ओवर एज हो रहे हैं। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति एकेडेमिक गुणांक हटाकर सुपर टेट के आधार पर करेंगे जिससे ओवर एज हो रहे बच्चे समायोजित हो सकें ?

श्री अध्यक्ष-

यह नीतिगत प्रश्न है।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

मान्यवर, इस सदन में भी और बाहर भी जब कभी कोई भर्ती, केवल भर्ती परीक्षा के अंकों के आधार पर होती है तब एक सवाल खड़ा होता है कि जिस लड़के ने परीश्रम करके हाई स्कूल से लेकर पी0जी0 तक अच्छे अंक अर्जित किये हैं उनको आप महत्व नहीं दे रहे हैं और जब हम केवल एकेडेमिक गुणांक के आधार पर भर्ती करते हैं तब यह कहा जाता है कि इस पीरियड में नकल होती थी, इसलिए नम्बर ज्यादा आ गया या ग्रामीण में नम्बर ज्यादा आ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है। तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार की मंशा यह रहती है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो और कोई पक्षपात का आरोप न लगे। इसलिए हमने दोनों व्यवस्थाओं को लिया है। मा0 अध्यक्ष जी 60 प्रतिशत हम लेते हैं जो भर्ती परीक्षा हुयी है उसके जो मेरिट अंक हैं उसको और 40 प्रतिशत भारांश हम लेते हैं एकेडेमिक गुणांक को। ताकि यह बैलेंस रहे। छात्र ने हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक जो पढ़ाई की है जो परीश्रम किया है उसको भी भारांश देते हैं और भर्ती परीक्षा को भी शामिल करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत उचित व्यवस्था है और इसका कोई बेहतर विकल्प कभी मा0 सदस्यगण सुझायेंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी।

प्रदेश में लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार की मौजूदा व्यवस्था की जानकारी एवं उक्त हेतु धनराशि बढ़ाने पर विचार सम्बन्धी

***7-हाजी इरफान सोलंकी (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लावारिस शवों का पोस्टमार्टम उपरान्त धार्मिक आधार पर अंतिम संस्कार कराने के वर्तमान में प्रचलित नियम क्या हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार उक्त हेतु धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में लावारिस शव का पोस्टमार्टम उपरान्त धार्मिक आधार पर अन्तिम संस्कार कराने के लिए शासनादेश सं0-1178/6-पु-2-2012-1500(11)/98टीसी-II, दिनांक 01-11-2012 द्वारा प्रति लावारिस शव को कफन के लिए 06 मीटर कपड़े की धनराशि हेतु रु0 300/-, शव जलाने हेतु लकड़ी अथवा कब्र में दफनाये जाने, खुदाई व पटाई पर निर्धारित धनराशि रु0 2000/- तथा शव को शव स्थल से चीरघर तक ले जाने व मर्घट/कब्रिस्तान ले जाने हेतु किराये की धनराशि रु0 400/- इस प्रकार रु0 2700/- अनुमन्य थी। शासनादेश सं0-1178/6-पु-2-2012-1500(11)/98टीसी- II, दिनांक 01-11-2012 की छायाप्रति संलग्न है।

जी हां। शासनादेश सं0-01/2021/94/6-पु-2-2021-1500(11)/98टीसी-II, दिनांक 22-02-2021 द्वारा पूर्व अनुमन्य कुल धनराशि रु0 2700/- में वृद्धि रु0 3400/- कर दी गयी है। शासनादेश की प्रति संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकर्ता हाजी इरफान सोलंकी का नाम पुकारे जाने पर, उनके अनुपस्थित होने पर)

प्रदेश में अप्रैल 2017 से 20 जुलाई 2020 तक सरकार द्वारा लिये गये मुकदमों के सम्बन्ध में

***8-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल 2017 से 20 जुलाई 2020 तक सरकार द्वारा किन-किन व्यक्तियों के मुकदमे वापस लिये हैं एवं इनमें से कितने मुकदमे

राजनीतिक श्रेणी के हैं ? क्या सरकार उक्त गंभीर श्रेणी एवं गम्भीर आपराधिक श्रेणी के आपराधिक मुकदमों को वापस लेने का कारण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विधि एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

राज्य सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2017 से 20 जुलाई, 2020 तक 670 मुकदमें वापस लिये जाने की संस्तुति जनहित में की गयी है। यह मुकदमें सामान्यतः राजनेताओं एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं से संबंधित हैं। भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत राजनीतिक श्रेणी के मुकदमों को परिभाषित नहीं किया गया है।

कम गंभीर अपराध के मामलों में अभियुक्त की भूमिका को ध्यान में रखते हुये उन्हें अनावश्यक प्रताड़ना से विमुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा मुकदमा वापसी की संस्तुति जनहित में की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

***श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मा0 मंत्री जी ने अपनी वाणी से स्वीकारोक्ति भी की है कि राजनेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से संबंधित मुकदमें वापस लिए गए हैं और उनकी संख्या करीब 670 है। "सबका साथ और सबका विश्वास" चूंकि आपको 24 करोड़ जनता को विश्वास में लेना है, डिसीजन यूनिवर्सिली होना है। इन 670 मुकदमों के सम्बन्ध में मेरी जिज्ञासा यह है कि दलों के आधार पर विभक्तिकरण जरूर हुआ होगा तो उन दलों का आंकड़ा क्या है ? दूसरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार के केस किसी अन्य पर भी शेष हैं, चाहे वह पक्ष का हो, विपक्ष का हो एवं निष्पक्ष हो या 24 करोड़ की जनता का हो। उनमें अगर इसी प्रकार के समानता के आधार पर केस लम्बित है तो क्या सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी जो सरकार निर्णय ले चुकी है ? सरकार में गंभीर, अति-गंभीर और कम गंभीर की कैटेगरी कौन तय करता है ?

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, गंभीर और अति-गंभीर की आई0पी0सी0 और सी0आर0पी0सी0 में कोई विवेचना नहीं की गई है। वहां पर घोर अपराध लिखा गया है। घोर अपराध से मतलब यह है कि इतनी पिटाई करना कि हड्डी टूट जाए, आंख को क्षति पहुँचे या ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचे जो ठीक नहीं की जा सकती हो, उसको घोर अपराध की श्रेणी में माना गया है। मा0 सदस्य ने जो सवाल पूछा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में गत सरकारों में जो हुआ और जो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की सरकार में हो रहा है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ और यह सदन एवं इस प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। इसी सदन में प्रथम सत्र के दौरान मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि राजनीतिक दृष्टि से दर्ज मुकदमों को वापस लेंगे और हमारी सरकार ने इस घोषणा पर काम शुरू किया। हम कोई भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुकदमा वापस लेने से पहले एक दरख्वास्त चाहते हैं, मा0 विधायक या मा0 सांसद जी लिख दे और जनप्रतिनिधि के साथ-साथ सामान्य जनमानस के लोग भी लिख दें। हम उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से 13 बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगते हैं, रिपोर्ट आने के बाद प्रमुख सचिव, गृह और प्रमुख सचिव, न्याय की एक समिति है और समिति परीक्षण करने के बाद हमारे सामने प्रस्तुत करती है, उसके बाद हम वापस लेने पर निर्णय लेते हैं। जहां तक मा0 सदस्य ने सवाल पूछा है कि किन-किन दलों के लोग हैं। मान्यवर, हमें कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम दलगत आधार पर उसका परीक्षण करें और उसकी हम घोषणा करें। यह कानून हमें इजाजत नहीं देता है, लेकिन मा0 सदस्य ने कहा है और हमारे पास पूरी फेहरिस्त है, सभी मा0 सदस्य बैठें हैं और कुछ मा0 सदस्य नहीं है। हम नाम पढ़ेंगे तो यह मेरे मन को गंवारा नहीं करता है। मैं जनपद पढ़ सकता हूँ और यदि मा0 अध्यक्ष जी अनुमति दें तो मैं नाम भी पढ़ सकता हूँ। कई मा0 विधायक हैं जो विभिन्न दलों के हैं। मैं एक बात और कह दूं कि मा0 सदस्य को इस बात से सहमत होना चाहिए कि हम लोग भले ही अलग-अलग दलों में रहकर सामाजिक काम करते हैं और यहां तक पहुँचे हैं। हम लोगों के व्यक्तिगत प्रताड़ना के जो भी सवाल है जिनको राजनीतिक दृष्टि से प्रताड़ित किया गया है, उसके हित की चिन्ता सदन को करनी चाहिए, इस बात के लिए मा0 अध्यक्ष जी, भी संरक्षण प्रदान करेंगे। हमने बराबर चिंता की है और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सूची को दलगत आधार पर सार्वजनिक कर दूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सूची को सार्वजनिक कर दूँ, दलगत आधार पर और कहिए तो नाम भी पढ़ दूँ। जो सामने भी सदस्य बैठे हैं, और आपके भी दल के हैं, अगल-बगल के दल के भी हैं, दाहिने भी हैं, बाएं भी हैं, कहिये तो मै सार्वजनिक कर दूँ। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा भेजे थपथपाई गयी) अध्यक्ष जी, अनुमति देंगे वो मैं सार्वजनिक कर दूंगा।

उससे जानते हैं क्या होता है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में किसी की मदद करते हैं और उसको कह देते हो तो वह मदद नहीं मानी जाती है, वह किसी के प्रति अपराध होगा और सामाजिक जीवन में शुचिता बनाये रखना जितना हमारा धर्म है, उतना सदन का धर्म है, उतना आपका भी है, आप मेरे वरिष्ठ सम्मानित सदस्य हैं। आपने यह सवाल पूछा है तो एक सवाल का जवाब मैं और आपको बता दूँ, (मा0 लालजी वर्मा के कुछ कहने का प्रयास करने पर) आप कह रहे हैं तो मैं नाम बता दूँ कि आपके सबसे पीछे जो चौथी सीट पर बैठे है और आपके एकदम पीछे जो मा0 सदस्य बैठें हैं। जो बाईं तरफ बैठे हैं उनका भी नाम मैं किसी का नहीं लूंगा और दाहिने तरफ जो बैठे हैं, किसी को भी मैंने छोड़ा नहीं है। मैं लिस्ट लेकर आया हूँ, आप कहेंगे तो नाम भी मैं पढ़ सकता हूँ और यह भी बता दूँ कि यह छोटा सवाल नहीं है। अध्यक्ष जी, आप मुझे अनुमति दे दीजिए, मैं स्पष्ट कर दूँ कि गंभीर अपराधों को वापस करने से पहले मेरी कलम कांपती है। हमने ऐसे मुकदमों को अलग श्रेणी में रखा है जो हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, अपहरण, छिनैती के मुकदमों पर कलम चलाने से पहले कलम कांपती है क्योंकि मुझे ईश्वर के पास जाना है, सबको जाना है। हमने न्याय व्यवस्था में मुकदमों का बोझ कम हो और शुचिता की राजनीति बनी रहे, इसके तहत मुकदमें वापस लिये हैं। मान्यवर, लेकिन इन्होंने छेड़ा है तो एक बात सुन लीजिए, अगर आप 2013 की लिस्ट पढ़ेंगे,

वह सूची मैं सदन में लेकर आया हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, अगर इसको हम पढ़ दें, हम नाम नहीं केवल धारा और अपराध पढ़ेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविंद चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, सवाल तो इस सत्र का पूछा गया है, मा0 सदस्य शर्मा जी का जो सवाल है वह इस सत्र का है, उसमें टाइम है 2017 से पढ़ रहे हैं 2013 का।

श्री ब्रजेश पाठक-

2017 का जवाब पूरा हो गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 शर्मा जी ने एक स्पेस्फिक पूंछा कि किस-किस दल के कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर से मुकदमे वापस लिये गये हैं तो इसमें बताने में कोई हर्ज है नहीं 2017 से लेकर अब तक का बता दीजिये।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये।

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको हमने सिद्ध कर दिया है। दूसरी बात, ये जो सूची हमारे पास है, यह थोड़ी पुरानी है लेकिन सुनेंगे तो देश के प्रदेश के लोग देखेंगे। जो आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमें थे उनको इन्होंने वापस लिया है। 2013 में जनपद वाराणसी में धारा 3-4-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना दशाश्वमेध घाट, इसको इन्होंने वापस लिया है। जनपद गोरखपुर में इन्होंने वापस लिया, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-7 क्रिमिनल अनॉ0 18/23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप अधिनियम थाना कैंट गोरखपुर। इसके बाद जनपद बिजनौर में शासकीय गोपनीयता अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता थाना नजीबाबाद और उसमें जो अभियुक्तों के नाम पढ़ देंगे एक में शमीम अहमद, दूसरे में तारिक ताजमीन, तीसरे में अहमद हसन चौथे में मुख्तार हुसेन, पाँचवें में मोहम्मद अली। फिर सुनिए-याकूब, नासिर हुसेन, मोहम्मद खलील.....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

***श्री नाहिद हसन-**

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी जो सूची पढ़ रहे है, वह 2013 की है। 2017 के बाद किन-किन लोगों के मुकदमे वापस लिए गए, उनके नाम मंत्री जी बता दें। 2017 के बाद कितने लोगों के मुकदमे वापस लिए गए ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए। आप उन्हें बोलने तो दीजिए, यह बताने को तैयार हैं।

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, हम पढ़ रहे हैं। सर, लखनऊ में जहाँ का मैं जनप्रतिनिधि हूँ, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 16, 18, 20, 23 थाना हुसेनगंज, जनपद लखनऊ- याकूब, दूसरा जनपद लखनऊ में 121, 121ए, 122, 115, 120बी, 124 भा0द0वि0, थाना नाका नासिर हुसेन। इसके अलावा जनपद लखनऊ धारा-4/5, 16, 18, 20, 23 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप।...

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपकी बात सुन लिए हैं। ये मुकदमें आपकी सरकार ने वापस लिए हैं ? (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) ये मुकदमें जिनको आप पढ़ रहे हैं, उस समय आपकी सरकार नहीं थी। आप अपने समय के मुकदमों के बारे में बताइये।

श्री ब्रजेश पाठक-

सरकार सतत् प्रक्रिया है, कस्टोडियन आते-जाते रहते हैं, सरकार किसी की भी हो।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप छात्र नेता है, मैं भी छात्र नेता हूँ, आपका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है, उसका तो उत्तर दीजिए। जो प्रश्न पूछा ही नहीं गया है, उसका उत्तर आप क्यों दे रहे हैं ? प्रश्न पूछा गया है, 2017 के बाद से और जवाब पढ़ेंगे सन् 52 का।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री ब्रजेश पाठक-

अध्यक्ष जी, इन्होंने आतंकवाद का पोटा अधिनियम वापस लिया है, इन्होंने 2013 में इस सदन में पोटा वापस लिया है, सरकार ने पोटा वापस लिया है। सामने बैठे लोग क्या पूछेंगे, इनकी सरकार में आतंकवाद के दर्ज मुकदमों को वापस लिया गया है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने शेम-शेम के नारे लगाये)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिए। संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं। आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, आप लोग संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनिए।

श्री ब्रजेश पाठक-

अध्यक्ष जी, 2013 में जनपद रामपुर में पोटा वापस लिया गया। कानून का मजाक बना दिया था।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रश्न देख लें।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में आने लगे)

श्री ब्रजेश पाठक-

ये पोटा वाले आ गए, ये पोटा वाले आ गए। अध्यक्ष जी, आप चदरा दे दीजिए, ये मुँह लपेट लें, शर्म आ रही होगी।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान जारी)

(वेल में आए हुए समाजवादी पार्टी के सदस्य लगातार नारे लगा रहे थे)

[x x x]

***संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मा0 शर्मा जी वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा उसका जवाब उन्हें मा0 ब्रजेश पाठक जी ने दे दिया कि जनहित में जितने भी मुकदमें वापस हुए हैं, सभी पार्टियों को इशारा करके बता दिया। इधर यह होता है कि अगर मा0 मंत्री जी के पास सूचना है और कोई अनुपूरक सवाल पूछता है तो उस पर बताई जाती है तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है।

श्री नाहिद हसन-

वर्ष 2017 के बाद जितने मुकदमें वापस लिए गए उनका क्या-क्या नाम है।

(व्यवधान के मध्य)

इस मुल्क में दहशत पैदा करने की कोशिश की, बनारस, गोरखपुर और लखनऊ में इन्होंने बम ब्लास्ट किया।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थान पर जाएं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल से वापस चले गए।)

श्री राम गोविंद चौधरी-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए एक सीधा-साधा सवाल है, मा0 शर्मा जी ने यह पूछा है कि क्या न्याय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 2017 से 20 जुलाई, 2020 तक सरकार द्वारा किन-किन व्यक्तियों के मुकदमे वापस लिए गए हैं, इसमें से कितने मुकदमें राजनीतिक श्रेणी के हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल मा0 मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूँ और उम्र में आप छोटे भी हैं इसके बावजूद भी जो प्रश्न दिए गए और जो पूछे गए हैं।

(कतिपय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर सदन में शोर तथा व्यवधान की स्थिति)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(शोर एवं व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सदन की परम्परा रही है कि अगर किसी प्रश्न के सम्बन्ध में कोई भी अनुपूरक प्रश्न किसी भी सदस्य को अगर कोई आवश्यकता है या जानने की उत्सुकता है तो पूछा जाता रहा है। मान्यवर, पहले क्या हुआ, इसमें गलत क्या है ? यह सदन की परम्परा रही है। इसमें नई बात कोई नहीं है, इससे इनको तकलीफ क्यों हो रही है ? इसमें तकलीफ इसलिए हो रही है कि पूरे प्रदेश के लोग कल जब अखबार देखेंगे, तब वे इनका चेहरा जानेंगे कि जो ये कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो लोग इनका चेहरा देखेंगे। मान्यवर, आतंकवादी जो एण्टी नेशनल है जिन्होंने दहशत पैदा करने के उद्देश्य से बनारस, गोरखपुर और लखनऊ में बॉम बार्ड किया, कचहरियों पर बॉम बार्ड किया, तब उन लोगों के मुकदमें वापस हो रहे थे। आप देखिए तो यह छोटी बात नहीं है इसलिए इनको तकलीफ हो रही है।

(कतिपय सदस्यों द्वारा लगातार एक साथ बोलते रहने पर शोर तथा व्यवधान की स्थिति)

(शोर एवं व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं तो अनुपूरक का कैसे आ गया ? आप जैसा बड़ा अपराधी इस प्रदेश में कोई नहीं है आप लोगों ने अपने मुकदमे वापस लिए। यह पहला अवसर है जब कोई मुख्य मंत्री अपने ही आपराधिक मुकदमे वापस ले। ऐसा कोई नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के इतिहास में। मा0 अध्यक्ष जी, अभी मूल प्रश्न का उत्तर आया ही नहीं तो अनुपूरक पर उत्तर कैसे होगा। पहले मूल प्रश्न का उत्तर आवे, तब न अनुपूरक का उत्तर होगा।

श्री बृजेश पाठक-

मान्यवर, मैं उत्तर देने जा रहा हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप विद्वान हैं मैं जानता हूँ और हम विद्वान नहीं हैं लेकिन मूल प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं। अभी तक नहीं आया, नहीं आया। आप विद्वान हैं मैं जानता हूँ। कहाँ आया मूल प्रश्न का उत्तर ?

श्री बृजेश पाठक-

मैं उत्तर देने जा रहा हूँ, आप सुनिए तो।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं भी आपके हाथ जोड़ रहा हूँ कि गड़बड़ाइए मत। आप मूल प्रश्न पर आइए। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य ने जो मूल प्रश्न पूछा है आप उस मूल प्रश्न पर आइए।

श्री ब्रजेश पाठक-

अध्यक्ष जी, गलती तो हुई है। अध्यक्ष जी गलती तो हमसे हुई है, हमने गलती स्वीकार की, गलती तो हमसे हुई है, गलत तो हमसे हो गई है कि-

रात को रात कह दिया मैंने, इस बात पर बुरा मान गई दुनिया,

सच को आईना दिखा दिया इस बात पर बुरा मान गई दुनिया।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूँ एक लाइन में। यह सवाल का जवाब है, स्पेसिफिक जवाब है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, निश्चित रूप से प्रश्नों के सम्बन्ध में अगर अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है और अगर मा0 मंत्री के पास सूचना है तो उन्हें उसे देने का अधिकार है, लेकिन केवल प्रश्नों के सम्बन्ध में तो मा0 सदन ने जो पहले जवाब या उत्तर मांगा है, पहले उसको दे दें और अगर उसके बाद कोई दृष्टान्त पूछे कि क्या इसके पहले भी ऐसा हुआ है, तब वे उसका भी जवाब दे सकते हैं। यह प्रश्न काल है, इसमें विधायक प्रश्न करता है, सदस्य प्रश्न करता है और मा0 मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई भी मंत्री उसका उत्तर दे सकता है। लेकिन सारे मा0 सदस्य उत्तर दे रहे है, ऐसा प्रश्न काल में नहीं होता। जब इन लोगों का समय अलग से आए तो ये उसमें बोल लेंगे लेकिन इस समय तो मा0 मंत्री जी इतने काबिल हैं कि उत्तर दे सकते हैं तो निश्चित रूप से मा0 मंत्री जी को ही इजाजत दीजिए और जो दूसरे सदस्य बोलने लगते है, उनको इसमें इजाजत देने का काम मत करिए।

श्री अध्यक्ष-

हम उनको इजाजत नहीं दे रहे हैं, हमने मा0 मंत्री जी को ही एलाउ किया है और किसी को एलाउ नहीं किया है।

श्री बृजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी, हमसे वर्ष 2017 के स्पेसिफिक सवाल के सम्बन्ध में कहा जा रहा है। हमने जवाब तो पूरा दे दिया है लेकिन वर्ष 2017 के ही सम्बन्ध में एक स्पेसिफिक सूचना भी सदन सुन ले।

श्री लाल जी वर्मा-

इसमें कितने-कितने लोग हैं, उसको तो अभी ही बता दें ?

श्री ब्रजेश पाठक-

वर्ष 2017 में अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हमारी जो पहली कैबिनेट भी उसमें जो प्रस्ताव आया था वह किसान ऋण माफी का आया था और जब भाई साहब लोगों की सरकार बनी वर्ष 2012 में जो हमारे सामने मित्र बैठे हैं इनकी सरकार बनी तो इनकी सरकार का कैबिनेट का पहला प्रस्ताव आतंकवादियों

के मुकदमों को वापस करने का था (सत्तापक्ष की तरफ से शेम-शेम की आवाजें सुनाई दीं)। मा0 अध्यक्ष जी, जहाँ तक नेता विरोधी दल महोदय ने कहा....

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह सब असत्य है। मेरे पास लिस्ट है यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूँगा आपने किनका-किनका मुकदमा वापस लिया उसमें क्या-क्या धारा थी, यदि मा0 अध्यक्ष जो आप अनुमति दें तो मैं इसको पढ़ दूँ। मेरे पास लिस्ट है।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल के साथ अन्य खड़े मा0 सदस्य आप लोग अपनी जगहों पर बैठ जायें।

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी, आज सदन में नेता विरोधी दल ने एक और महत्वपूर्ण बात कही....

श्री राम गोविन्द चौधरी-

कैबिनेट का वह फैसला दिखला दें जो हमारी सरकार में जो हुआ था। वह फाइल आप दिखलवा दीजिए। वह फैसला सुनवा दीजिए जिसमें आतंकवादी शब्द लिखा हो। जिसमें लिखा हो कि आतंकवादियों के मुकदमें वापस लिये जायें। यह कैबिनेट में कब हुआ इतना ही बता दीजिये। माननीय अध्यक्ष जो, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे और इनके बीच में कहा-सुनी हो रही है। कैबिनेट को किस डेट की मीटिंग में आतंकवादियों का मुकदमें वापस लिये जायें यह किस कैबिनेट में तय हुआ था। यह आतंकवादी शब्द किस कैबिनेट में था।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने से शोर की स्थिति)

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जो यदि अनुमति हो तो हम अपनी बात पूरी कर लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अब आप हमारे सामने गलत बोलेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, आप चाहे तो 10 मिनट सदन की कार्यवाही रोक दें ताकि उस कैबिनेट का फैसला मा0 मंत्री जी ले आये, जिस कैबिनेट में यह प्रस्ताव हो कि इतने आतंकवादियों के मुकदमें वापस लिये जायें। आप सदन की कार्यवाही रोक दीजिए। आप चाहे तो आधे घंटा के लिए सदन को स्थगित कर दें। मा0 मंत्री जी पूरी फुर्सत से जायें वह फाइल लेकर आये और सदन में उसको बता दें कि कैबिनेट की यह मद है, जिसमें लिखा गया है कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिये जायें।

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी, आप मुझे अनुमति दीजिये मैं इसको पूरा कर लूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी एण्टी टेररिस्ट ऐक्ट हर एक के खिलाफ नहीं लगता है केवल उन्हीं घटनाओं में लगता है जिनको आतंकवादी घटना कहा जाता है। (मेजों की थपथपाहट)। दूसरी

बात 15 मार्च सन् 2012 को समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और 28 मार्च को मुख्य सचिव की तरफ से एक सरकुलर जारी हुआ। पूरे प्रदेश में कि जहाँ-जहाँ इस तरह की घटनाओं मे लोग फँसे हैं उनकी डीटेल भेज दीजिए ताकि उनके खिलाफ लगे मुकदमें वापस लिये जा सकें। मान्यवर, यह 28 मार्च का है, मैं तारीख बता सकता हूँ। 28 मार्च को एक सरकुलर जारी हुआ पूरे प्रदेश में कि ऐसे मुकदमें जो आतंकवादी घटनाओं में जो लोग शामिल हैं उनके भेज दीजिए। ये उनको इस तरीके से दिया गया कि दो लोग निर्दोष हैं उनके मुकदमें वापस दे दें। ....

(घोर व्यवधान के मध्य)

लेकिन आंतकवादी घटनाओं के मुकदमें पूरे प्रदेश में थे और मान्यवर, जो आपने पढ़ कर सुनाया है, क्या यह सही नहीं है। हाई कोर्ट ने उस वक्त यह टिप्पणी की थी कि जाओ, आज इनके खिलाफ मुकदमें वापस ले लो, कल इनको पद्म सम्मान से सम्मानित कर देना। हमने इसी विधान सभा में यहां पर बैठकर यह विषय उठाया था कि आप इनके मुकदमें वापस ले लो, कल इनको पद्म सम्मान से सम्मानित कर दें। यह हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी।

श्री अध्यक्ष-

यदि इस प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा हो गयी है तो क्या हम आगे बढ़ें ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, पहली कैबिनेट का, जिसका मा0 मंत्री जी ने जिक्र किया और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, जो मुख्य सचिव की सूचना पढ़ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आपके घर कुँआ कैसा है तो यह बोल रहे हैं कि नाना के घर कुँआ बढ़िया था। मा0 मंत्री जी ने कहा कि पहली कैबिनेट में यह पास हुआ कि आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया जाये। मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ कि आप चाहे 10 मिनट या 20 मिनट सदन को स्थगित कर दीजिए लेकिन मा0 मंत्री जी वह फाइल लाकर इस सदन में दिखवा दें, जिसमें एक शब्द लिखा हो कि आतंकवादियों का मुकदमा वापस किया जा रहा है। आतंकवादी शब्द, आतंकवादी शब्द। यदि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे है तो मैं तो यह कह रहा हूँ कि सबसे बड़े प्रदेश में आतंकवादी, उधर जो बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह की टिप्पणी न करिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

कई आतंकवादी एम0पी0 हो गये, कई आतंकवादी मुख्य मंत्री हो गये, कई आतंकवादी उप मुख्य मंत्री हो गये, अगर मैं यह कह दूँ लेकिन हमको यह मुँह से कहना शोभा नहीं देता है। मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ कि मैं यह बात कह रहा हूँ।

(सदन में कई सदस्यों के अपने-अपने स्थान से एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह घोर आपत्तिजनक है और इस प्रकार की भाषा इनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप स्वयं आतंकवादियों की गतिविधियों का परिचालन करते हैं, स्वयं दंगा करवाते हैं, स्वयं हिन्दू-मुस्लिम करते है, इसी बात की राजनीति की हुई है। जनता से आपका कोई सरोकार नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी यह सबूत के साथ बात कर रहे है। यह किसी से छिपा नहीं है। जो मुकदमें वापस हुए, वह किसी से छिपा नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपका भी नहीं छिपा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उन लोगों के खिलाफ कौन सी धाराएँ लगी, यह किसी से छिपा नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम यह पढ़ दें ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

किसे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वह नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ दूँ ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वह कोई चोरी नहीं है, मान्यवर, यह जनहित में किये गये हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप इजाजत दे दीजिए यदि वह नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं पढ़ दूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसको मा0 मंत्री जी ही पढ़ देंगे। किसी आतंकवादी का मुकदमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वापस नहीं लिया गया। किसी का नहीं लिया गया।

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

अब इस प्रश्न के आगे चला जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आप कल्पना करिए कि अगर एंटी टेररिस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत जिन लोगों को नामजद किया गया है, बरसों जिन्होंने ट्रायल फेस किया, जो लोग कारागार में निरुद्ध रहे, सरकार इनकी थी, उसके बाद इनकी भी आयी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

दंगाइयों का मुकदमा आपने वापस किया है। दंगा करने वालों का मुकदमा आपने वापस किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नहीं किया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, किया है। वह नहीं किये है, आपने किया है। दंगे में जो लोग नामजद थे, उनका मुकदमा आपने वापस किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह जो टेररिस्ट में फँसे है, उनका किसी का मुकदमा वापस नहीं किया है। आप देख लीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी, कुछ तो सही बोलिए। जो दंगा कराने में नामजद थे, उनके मुकदमें आपने वापस किये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं किये हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वही आतंकवादी है। जो दंगा करते हैं और कराते हैं, वही आतंकवादी हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इनको इस बात के लिए माफी माँगनी चाहिए। यह तरीका नहीं है कि किसी को कुछ भी कह दो।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

संसदीय कार्यमंत्री जी, यह लिस्ट मेरे पास है लेकिन मेरा जमीर नहीं कहेगा कि मैं इसको पढ़ूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न लें ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो शब्द कहा है उसे कार्यवाही से निकाला जाय और इनसे कहा जाय कि यह अपने वक्तव्य पर खेद व्यक्त करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो लोग दंगा कराने में नामजद थे उनका मुकदमा आपने वापस लिया है।

(सदन में घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

ब्रजेश जी, आपके उत्तर में कुछ कहना शेष है।

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात यह रह गयी थी कि माननीय नेता विरोधी दल ने सवाल उठाया कि हमारी सरकार के आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया। वर्ष 2013 का एक आर्डर मेरे पास है, जो 16-10-2016 को निर्गत हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमा वापस लिया था, उसकी सूची मेरे पास है। अध्यक्ष जी, पूरी सूची नहीं थी परन्तु मैंने इण्टरनेट से डाउनलोड किया है। 08 साल पहले तत्कालीन हाई कोर्ट ने कहा था कि आतंकवादियों को पद्म विभूषण देना चाहिए। ये सच है, हाई कोर्ट का जो वक्तव्य है, उसका पूरा वीडियो है।

(सदन में घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, क्या यह बात सही नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी पर से मुकदमें वापस लिये गये ? क्या यह सही नहीं है कि माननीय उप मुख्य-मंत्री पर से मुकदमें वापस लिये गये ? क्या यह बात सही नहीं है कि दंगा कराने में जो लोग नामजद थे उनके मुकदमें वापस लिये गये, इसी सरकार में।

(सदन में घोर व्यवधान के मध्य)

श्री ब्रजेश पाठक-

मैं फिर घोषणा करता हूँ कि राजनीतिक दल पर दर्ज मुकदमें हम वापस लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

क्या अब यह माना जाय कि पर्याप्त डिसकसन हो गया ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पाठक जी ने पूरे सदन को इंगित करते हुए कहा कि इनके भी हुए, इनके भी हुए और सबके मुकदमें वापस हुए। कुल 670 मुकदमें।

श्री लाल जी वर्मा-

किस दल के कितने मुकदमें वापस हुए ?

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, संख्या हमें आवेदन-पत्रों की संख्या के आधार पर बतानी पड़ेगी। यह एक बड़ा सवाल है। मैं दल के आधार पर बता सकता हूँ, इसके लिए अध्यक्ष जी आपको अनुमति देनी पड़ेगी क्योंकि कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता कि कौन किस दल में हैं, कौन

किस दल का सक्रिय कार्यकर्ता है, कानून विभेद नहीं करता है। अध्यक्ष जी, यदि आप अनुमति दें तो मैं जरूर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जो, मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ। माननीय शर्मा जी ने यह प्रश्न किया था कि वर्ष, 2017 से वर्ष, 2020 तक सदन के कितने सदस्यों व राजनीतिक लोगों के मुकदमें वापस लिये गये। मैं अपने मित्र और काबिल मंत्री जी को शुरू से देख रहा हूँ कि वह वर्ष, 2017 पर आ ही नहीं रहे हैं, वर्ष, 2013, वर्ष, 2014 में, इसमें-उसमें की बात कर रहे हैं। वर्ष, 2017 का तो इन्होंने बताया ही नहीं। संसदीय कार्य मंत्री जी को बातों को घुमाने का तरीका आता है, क्योंकि वह कुर्सी ही ऐसी है। जो प्रश्न था उस पर मंत्री जी आये ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

शर्मा जी ने सप्लीमेंटरी की थी, तब मंत्री जी ने बताया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

प्रश्न था 2017 से 2020 तक का और माननीय मंत्री जी पढ़ रहे हैं 2013 का। मान्यवर, मैं सदन की गरिमा रखना चाहता हूँ। मेरे पास भी लिस्ट है लेकिन मैं आपकी बिना इजाजत के उसको नही पढ़ रहा हूँ। जो पूछा जा रहा है कि 2017 से 2020 तक कितने राजनीतिक मुकदमें वापस लिये गये हैं उसकी लिस्ट हो तो पढ़ दें।

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बृजेश पाठक-

मुकदमा अपराध संख्या-24/2014 धारा-143 भारतीय दंड विधान, जनपद प्रयागराज..

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अब तो मुझे भी इजाजत दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अब तो यह सवाल खत्म हो गया। प्रश्नों का समय समाप्त हुआ[†] जो सूची आपके पास है बहुत बढ़िया। अब यह लिस्ट न संसदीय कार्य मंत्री को दिखाना, न वर्मा जी को दिखाना।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम देंगे तो आपको देंगे। इनको तो कुछ भी कह देना है मेरी बिल्कुल प्रमाणिक सूची है मैं भी चाहता तो पढ़ देता। जैसे मंत्री जी ने पढ़ा लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सदन की

[†] नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

गरिमा को जानता हूँ, मैं संसदीय परम्परा को जानता हूँ, मैं माननीय सदस्यों, माननीय मंत्रियों और माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रतिष्ठा को जानता हूँ, इसलिये मैं इसे नहीं पढ़ूँगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्रदेश के निजी प्रबंधन के स्कूलों द्वारा बिना अनुमति फीस वृद्धि पर कार्रवाई विषयक

***9-श्री नाहिद हसन-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी प्रबंधन के विद्यालयों द्वारा वर्तमान शैक्षणिक-सत्र में फीस वृद्धि के कुल कितने प्रकरण प्रकाश में आए हैं ? क्या उक्त प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए तंत्र से विद्यालयों ने अनुमति प्राप्त की थी ? यदि नहीं, तो ऐसे विद्यालयों जिन्होंने बगैर अनुमति फीस वृद्धि की है, के विरुद्ध कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

वर्तमान शैक्षणिक सत्र में फीस वृद्धि का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सचिवालय में ई-आफिस सम्बन्धी स्थानान्तरण नीति को बांटने का आधार व मानक तथा 70-89 समीक्षा अधिकारियों को संदर्भदाता के नाम पर तैनाती की जांच व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

***10-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में ई-आफिस व्यवस्था लागू कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त विषयक जारी स्थानान्तरण नीति को 1, 2 एवं 3 श्रेणियों में बांटने का आधार एवं मानक क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त स्थानान्तरण नीति के विपरीत लगभग 70-89 समीक्षा अधिकारियों को सन्दर्भदाता के नाम पर तैनात रखा गया है जबकि वे सन्दर्भदाता की जगह समीक्षा अधिकारी का कार्य कर रहे है ? क्या सरकार इनकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ

जी हाँ।

चक्रीय स्थानांन्तरण नीति सभी कार्मिकों पर समान रूप से लागू करने हेतु सचिवालय के कुल 93 विभागों को संख्यात्मक आधार पर 31-31 के तीन समूह में अनुसूची-1, 2 व 3

के रूप में विभाजित किया गया है, न कि विभागों के कार्य एवं दायित्वों के दृष्टिगत। अतः मानक का आधार संख्यात्मक है।

जी नहीं।

सचिवालय प्रशासन अनु0-5(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06 जनवरी 2016 द्वारा संदर्भदाता प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया है। सचिवालय प्रशासन (अधि0) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-04-2018 के प्रस्तर- 4(ण) के अनुसार संदर्भदाता के कार्यों का निर्वहन कर रहे समीक्षा अधिकारी को अपरिहार्य स्थिति में विभागीय संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मार्च, 2017 से दिसम्बर, 2019 तक पुलिस की मुठभेड़ व मारे गये व्यक्तियों का वर्गवार विवरण दिये जाने विषयक

***11-श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2017 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक पुलिस की अपराधियों के साथ कुल कितनी मुठभेड़ हुई तथा उक्त मुठभेड़ों में कुल कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने घायल हुए है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मुठभेड़ों में मारे गये लोगों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों की अलग-अलग संख्या कितनी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ

दिनांक 20-03-2017 से 31-12-2019 तक प्रदेश में पुलिस एवं अपराधियों के मध्य 5253 मुठभेड़ों में कुल 103 अपराधियों की मृत्यु हुई है एवं कुल 1886 अपराधी घायल हुये हैं। उक्त के अतिरिक्त इन मुठभेड़ों में 05 पुलिस कर्मी शहीद हुए एवं 801 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। पंजीकृत अभियोगों का विवरण रजिस्टर नं0 04 में अंकित किया जाता है जिसमें जाति का उल्लेख किये जाने का कोई कालम नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हर घर नल से जल योजना के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति की प्रगति सम्बन्धी

***12-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में "हर घर नल से जल" योजना के अन्तर्गत दिनांक 28-10-2020 तक कितने घरों में जल पहुंचाया जा चुका है ? क्या

यह सरकार बतायेगी कि योजना से शत-प्रतिशत घरों तक जल पहुंचाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ? यदि नहीं,तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 28-10-2020 तक 20,52,347 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति करायी गयी है।

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश को अपराध मुक्त/भय मुक्त बनाने विषयक

***13-श्री संजय गर्ग-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश को अपराधमुक्त एवं भयमुक्त बनाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गयी हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ

जी हाँ।

प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य है। आम जनमानस में सुरक्षा की भावना में अत्याधिक वृद्धि हुई है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति/एण्टी रोमियों/फुट पेट्रोलिंग/बैंक चेकिंग/कैदियों की वैन/अवैध शराब/संदिग्ध वाहनों हेतु प्रभावी रूप से अभियान चलाये जा रहे हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि के अधिकांश अपराधी जेलों में बन्द हैं, असमाजिक तत्वों के विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्यवाही करायी जा रही है। प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द उच्च कोटि का है, वर्तमान सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ है। अपराधियों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी कराते हुये जेल भेजा जा रहा है। दुर्दान्त अपराधियों के विरुद्ध विशेष रूप से अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दुर्दान्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान दिनांक 20-03-2017 से 31-12-2020 तक कुल 129 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 2823 घायल हुये, इन कार्यवाहियों में पुलिस बल के 13 जवान अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुये वीरगति को प्राप्त हुये तथा 1039 पुलिस कर्मी घायल हुये। आतंकवादी/नक्सल घटनाओं पर पूर्णतः नियंत्रण रखा गया है। प्रदेश में अपराधों एवं भयमुक्त वातावरण बनाये रखने हेतु प्रदेश के समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/कमिश्नरेट/ परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारियों को पूर्ण शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु समय-समय पर विस्तृत निर्देश दिये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है।

सक्रिय अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कार्य योजना तैयार कर प्रभावी कार्यवाही करायी जा रही है।

बीट व्यवस्था प्रणाली को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या-01/2020 दिनांक 03-01-2020 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश में महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न रोकने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे है, फलस्वरूप महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों में शासन/प्रशासन के प्रति विश्वास की भावना में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

एण्टीरोमियों स्क्वाड द्वारा 22-03-2017 से 31-10-2020 तक प्रदेश में विद्यालयों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों (चौराहों, मार्केट, माल, पार्क एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थान) प्रतिष्ठानों आदि की चेकिंग की गयी जिसमें कुल 88,01,721 व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा 8,601 अभियोग पंजीकृत किये गये। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या- डीजी-आठ-81 (अप0अभि0)/2017 दिनांक 18-06-2019 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

"महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन" की स्थापना-

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों का उत्पीड़न रोकने, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने, उनकी सहायता करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु "महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन" की स्थापना की गयी है। जिसका क्रियान्वयन/ पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0 द्वारा किया जा रहा है।

यूपी डायल-112 द्वारा सुरक्षा कवच योजना-

प्रत्येक पीड़ित महिला द्वारा अपनी शिकायत वूमेन पॉवर लाइन 1090 सहित यूपी-112 पर दर्ज करायी जा सकती है। यूपी-112 इण्डिया मोबाइल एप द्वारा भी महिला सुरक्षा सम्बन्धी कार्यवाही संचालित है।

प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों में एक साथ विभिन्न प्रकार के विशेष अभियान चलाकर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए "मिशन शक्ति" के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत 1090, 112 व 181 (महिला हेल्प लाइन) पर तथा एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत किये जाने की दिशा में यू0पी0-112 परियोजना द्वारा प्रभावी कार्यवाही निरन्तर की जा रही है। वर्तमान में यू0पी0 -112 का रेस्पॉन्स टाइम भी पहले से बेहतर हुआ है, जो मार्च, 2017 में लगभग 38 मिनट था वर्तमान में लगभग 10:30 मिनट है, जिससे स्पष्ट है कि किसी प्रकार की घटना घटित होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुँच रही है। कोविड-19 के सम्बंध में सूचना मिलने पर यूपी-112 द्वारा तत्काल कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में होने वाली कार्य परिषद की बैठकों को रिकार्ड किये जाने व निर्देशों का पालन किये जाने विषयक

***14-डा0 श्याम बिहारी लाल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में होने वाली कार्य परिषद की बैठकों को वीडियो कैमरे रिकार्डिंग की पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देशों को वापस ले लिया गया है ? यदि नहीं,तो विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी द्वारा उक्त नियमों की अवज्ञा करने में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में होने वाली कार्य परिषद की बैठकों को वीडियो कैमरे रिकार्डिंग के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बुंदेलखण्ड में कम बारिश के कारण समाप्त हुई फसलों के कारण इसे सूखाग्रस्त घोषित करने व राहत धनराशि दिलाये जाने विषयक

***15-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विगत 2 माह में बरसात बहुत कम होने से उर्द, मूँगफली, तिल, धान, मक्का, ज्वार, आदि की फसलें लगभग समाप्त हो गयीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे करवाकर किसानों के नुकसान की भरपाई/राहत धनराशि दिलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद जालौन, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा एवं ललितपुर में प्रश्नगत अवधि में सामान्य वर्षा होने के कारण खरीफ की फसल क्षति नहीं हुई है।

जनपद झांसी में वर्षा कम होने के कारण उर्द, मूँग, तिल एवं मूँगफली की औसत 5 प्रतिशत की फसल क्षति हुई है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 32/7/2014, एनडीएम 1 दिनांक 08-04-2015 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से राहत सहायता दिये जाने हेतु निर्धारित मानकों एवं दरों में फसलों की 33 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति होने पर कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

उक्त प्राविधानित व्यवस्था के दृष्टिगत कृषकों को राज्य आपदा मोचक निधि से राहत सहायता दिये जाने का अवसर उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कोरोना के कारण स्थगित तहसील एवं थाना समाधान दिवस को सोशल डिस्टेसिंग के पालन के साथ पुनः शुरु कराये जाने के सम्बन्ध में

***16-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के कारण लॉकडाउन को देखते हुए तहसील तथा थानों के स्तर पर जन समस्या समाधान दिवस आयोजन को वर्तमान में स्थगित कर दिया गया हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जन समस्याओं के निराकरण हेतु सोशल डिसटेन्सिंग का पालन कराते हुए तहसील तथा थाना दिवस पुनः प्रारम्भ किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-581/पाँच-5-2020, दिनांक 17-03-2020 द्वारा तहसील दिवस (सम्पूर्ण समाधान दिवस) सहित विभिन्न प्रकार के आयोजनों को स्थगित किया गया था।

शासनादेश संख्या-1408/एक-4-2020-111बी-4/2012, दिनांक 11-09-2020 द्वारा पुनः "सम्पूर्ण समाधान दिवस" (तहसील दिवस) एव पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या-डी0जी0-6-35 (थाना दिवस)/2020 दिनांक 18-09-2020 द्वारा थाना दिवस का आयोजन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू करने विषयक

***17-श्री देवमणि द्विवेदी-**

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पी0एम0जी0एस0वाई0 की तर्ज पर प्रदेश में मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम विकास मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह")-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

***18-श्री मनोज कुमार पारस-**

राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त

अतारांकित प्रश्न

जनपद हाथरस के ब्लाक सहपऊ के ग्राम नगला बंजारा खौड़ा में पानी की टंकी के निर्माण हेतु

1-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सहपऊ के ग्राम नगला बंजारा खौड़ा ग्राम बंगला बादाम तथा ग्राम नगला बैंरू में ग्रामवासियों को शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हाथरस के ब्लाक सहपऊ के ग्राम नगला बंजारा, ग्राम खौड़ा, ग्राम नगला बादाम तथा ग्राम नगला बैंरू सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज के अधीन प्राथमिक पाठशाला तिखवा, विकास खण्ड कन्नौज में अध्यापिकाओं का बकाया वेतन भुगतान कराये जाने विषयक

2-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज के अधीन प्राथमिक पाठशाला तिखवा, विकास खण्ड कन्नौज में कार्यरत अध्यापिकाओं का जुलाई, अगस्त, सितम्बर वर्ष 2016 तथा मई, जून, जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 2020 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है ? क्या सरकार इनके बकाये वेतन का भुगतान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

जनपद कन्नौज के अधीन प्रा0पा0 तिखवा, विकास खण्ड कन्नौज में कार्यरत अध्यापिकाओं का कोई भी भुगतान अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के ग्राम पंचायत असकरनपुर मंगरोहनी में ग्राम समाज की भूमि, तालाब, चकरोड, नाली आदि को अवैध कब्जा मुक्त कराने विषयक

3-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के ग्राम पंचायत असकरनपुर मंगरोहनी में ग्राम समाज की भूमि, तालाब, चकरोड, नाली आदि पर कतिपय भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे कर लिये गये है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि, तालाब, चकरोड, नाली आदि चिन्हित कर उक्त को अवैध कब्जे से मुक्त करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

1- ग्राम-असकरनपुर मंगरोहनी, तहसील-सिराथू, विकास खण्ड सिराथू जनपद-कौशाम्बी में नाली के 43 गाटा है, जो मौके पर खाली है। चकरोड पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा नहीं किया है।

2- ग्राम-असकरनपुर मंगरोहनी में ग्राम सभा की भूमि तालाब खाते में 13 गाटे दर्ज है, जिसमें गाटा संख्या-488 के जुज (अंश) भाग में प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है एवं 352 व 382 के कुछ हिस्से में अनुसूचित जाति के लोगों के 20 से 25 वर्ष पुराने रिहायशी घर बने हुए है। उक्त कब्जादारों के पास अन्य रिहायशी मकान नहीं है। गाटा संख्या-464/4 पर 09 लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसमें अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ धारा-67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। शेष तालाब मौके पर खाली है।

3- ग्राम-असकरनपुर मंगरोहनी में ग्राम सभा की भूमि ऊसर खाते में 10 गाटे दर्ज है, जिसमे गाटा संख्या-310 व 422 में आंशिक रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के 15 से 20 वर्ष पुराने रिहायशी मकान बने हुए हैं, शेष ऊसर मौके पर खाली है।

4- ग्राम-असकरनपुर मंगरोहनी में ग्राम सभा की भूमि बंजर खाते में 19 गाटे दर्ज है, जिसमें गाटा संख्या-351 व 468 व 474 पर अंशिक रूप से अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के 15 से 20 वर्ष पुराने रिहायशी मकान बने हुए हैं, शेष बंजर मौके पर खाली है।

5- वर्तमान में असकरनपुर मंगरोहनी नगर पालिका परिषद मंझनपुर में शामिल हो गया है। अवैध कब्जाधारकों के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद मंझनपुर से रिपोर्ट प्राप्त करके अतिक्रमणियों के विरुद्ध नियमानुसार पी0पी0ऐक्ट के तहत वाद योजित करके अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2020 की अवकाश तालिका में अंकित निर्बन्धित अवकाश जनपद फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को न दिये जाने विषयक

4-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा जारी वर्ष 2020 की अवकाश तालिका में अंकित निर्बन्धित अवकाश जनपद फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं को नहीं दिये जा रहे है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

जनपद फतेहपुर में शिक्षक/शिक्षिकाओं को बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जारी किए गए पत्र दिनांक 24-12-2019 के माध्यम से विद्यालयों में वर्ष 2020 में दिये जाने वाले अवकाश की सूची में सम्मिलित शासकीय और निर्बन्धित अवकाश नियमानुसार दिए गए हैं।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी विकास खण्ड सिराथू ग्राम पंचायत असकरनपुर मंगरोहनी में पेयजल आपूर्ति करवाने विषयक

5-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के ग्राम पंचायत असकरनपुर मंगरोहनी में पेयजल आपूर्ति पाइप लाइन द्वारा नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में पानी टंकी बनवाकर पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के ग्राम पंचायत असकरनपुर मंगरोहनी सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर, विकास खण्ड सुकरौली के सखौली व कुसुम्हा गांवों में सड़क न बनाये जाने, पेयजल आपूर्ति बाधित होने व दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही विषयक

6-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर स्थित विकास खण्ड सुकरौली के सखौली व कुसुम्हा आदि गावों में पानी की टंकी बनने के बाद पाइप लाइन में तकनीकी कारण से पानी की आपूर्ति प्रायः बाधित रहती है ? यदि हां, तो उक्त का निराकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सुकरौली के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में सुकरौली पेयजल योजना का निर्माण किया गया था। सुकरौली पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी पूर्णरूप से निर्मित है, जिससे पूर्व में जलापूर्ति की जा रही थी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के चौड़ीकरण की प्रक्रिया में समानान्तर बिछायी गयी पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण विगत 02 वर्ष से जलापूर्ति बाधित है। "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सुकरौली के ग्रामों सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के सुकरौली में जनहित में पेयजल आपूर्ति हेतु अर्द्धनिर्मित पानी की टंकी को पूर्ण कराने विषयक

7-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के सुकरौली में जनता को पेयजल आपूर्ति के लिए पानी की टंकी अर्द्धनिर्मित होने के कराण उपयोग में नहीं लाई जा रही ? यदि हां, तो उक्त पानी की टंकी को जनहित में सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सुकरौली के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में सुकरौली पेयजल योजना का निर्माण किया गया था। सुकरौली पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी पूर्णरूप से निर्मित है, जिससे पूर्व में जलापूर्ति की जा रही थी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के चौड़ीकरण की प्रक्रिया में समानान्तर बिछायी गयी पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण विगत 02 वर्ष से जलापूर्ति बाधित है।

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सुकरौली के ग्रामों सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के सुकरौली थाना को आदर्श थाना रूप में विकसित करने विषयक

8-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के सुकरौली थाना को आदर्श थाना (माडल थाना) के रूप में विकसित सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद कुशीनगर में थाना सुकरौली स्थित नहीं है बल्कि थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र अन्तर्गत अस्थायी पुलिस चौकी सुकरौली स्थित है। जनपद कुशीनगर की अस्थायी पुलिस चौकी सुकरौली को आदर्श थाना (माडल थाना) बनाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रुधौली के सल्टौआ गोपालपुर अन्तर्गत पकरी व आमा रजवाहा माइनर की सफाई हेतु धन के व्यय के विवरण विषयक

9-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के सल्टौआ गोपालपुर के अन्तर्गत पकरी व आमा रजवाहा माइनर को बने लगभग 3 दशक हो चुके है परन्तु वर्तमान तक नहर में पानी नहीं छोड़ा गया है जबकि विभाग द्वारा प्रति वर्ष साफ-सफाई के नाम पर उक्त नहर पर धन व्यय करवाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त नहर में साफ-सफाई पर व्यय धन का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तदैव।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा गिरगिट्टी में 150 मी0 नाली निर्माण हेतु

10-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पचांयती राज विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा गिरगिट्टी में राम अवध के घर से मथुरा के घर तक दूरी

लगभग 150 मीटर नाली का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

ग्राम पंचायत गिरगिट्टी में स्थलीय सत्यापन में उक्त कार्य का नाम स्पष्ट नहीं है। ग्राम पंचायत में मथुरा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अतः कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा मटेहीकलां में 300 मी0 सड़क निर्माण हेतु

11-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा मटेहीकलां में दिनेश के घर से लाल बहादुर के घर तक दूरी लगभग 300 मीटर सड़क निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

ग्राम सभा मटेहीकलां में श्री दिनेश के घर से श्री लाल बहादुर के घर तक लगभग 300 मीटर सड़क निर्माण का कार्य अनुमन्य न होने के कारण कराया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, बभनजोत व मनकापुर के प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प योजनान्तर्गत विद्यालयों को संतृप्त किये जाने विषयक

12-श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, बभनजोत व मनकापुर के प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत कितने विद्यालयों को संतृप्त कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त में कितनी धनराशि व्यय हुई ? क्या सरकार शेष विद्यालयों को उक्त योजना द्वारा संतृप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, बभनजोत व मनकापुर के 484 परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के सापेक्ष 02 विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प योजनान्तर्गत 14 पैरामीटर्स के संतृप्तीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। शेष विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्तीकरण का कार्य पंचायती राज विभाग के स्तर से गतिमान है।

"ऑपरेशन कायाकल्प" योजनान्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा से संतृप्तीकरण का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम निधि में उपलब्ध धनराशि से कराया जा रहा है।

जी हां।

31 मार्च, 2022 तक संतृप्त कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के बभनजोत व छपिया में ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाये जाने विषयक

13-श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के बभनजोत व छपिया के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाकर कब तक कार्य पूरा कर लिया जायेगा ? क्या सरकार उक्त सभी गाँवों को संतृप्त कर के विकास का माडल बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजनान्तर्गत वित्त आयोग एवं मनरेगा की धनराशि के अभिसरण से पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है, शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन से संतृप्त किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में ग्राम पंचायतों में जलजीवन मिशन योजनान्तर्गत विकास खण्ड छपिया/बभनजोत/मनकापुर में टंकी लगवाने विषयक

14-श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, बभनजोत, मनकापुर सहित सभी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी लगाने का कार्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, बभनजोत, मनकापुर सहित सभी ग्राम पंचायतों एवं प्रदेश के समस्त ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के शिवरामपुर प्राथमिक विद्यालय भाग 2 के पीछे स्थित सरकारी तालाब की भूमि को अवैध कब्जे व अतिक्रमण से मुक्ति दिलाये जाने विषयक

15-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के शिवरामपुर प्राथमिक विद्यालय भाग-2, शिवरामपुर के पीछे स्थित सरकारी तालाब की जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर तालाब को पाट कर आवास बनाकर उसमें रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाब को अतिक्रमण से मुक्ति कराकर उसे पुनः प्राकृतिक स्वरूप दिलवायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मौजा शिवरामपुर परगना व तहसील कर्वी जनपद चित्रकूट में खाता सं0-696 की आ0न0 114 व रकबा 1.641 हे0 तालाब खाते में दर्ज है। उक्त तालाब भूमि के रकबा 0.017 हे0 पर प्राथमिक विद्यालय शिवरामपुर भाग-2 संचालित है तथा रकबा 0.422 हे0 पर अनुसूचित जाति के मजदूर श्रेणी के लगभग 34 परिवार विगत 60-70 वर्ष पूर्व में कच्चे-पक्के व झोपड़ीनुमा मकान बनाकर अवैध रूप से रह रहे हैं।

अवैध कब्जे के विरुद्ध उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-122 बी के तहत वाद योजित कर बेदखली के आदेश न्यायालय द्वारा पारित किये जा चुके हैं। अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति भूमिहीन है एवं अन्यत्र कोई भूमि आवास हेतु उपलब्ध न होने के कारण मौके पर बेदखली की कार्यवाही अभी सम्भव नहीं हो सकी है। उक्त लोगों को अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने के उपरान्त ही बेदखली की कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध एसआईटी व विजिलेंस जांच विषयक

16-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा कतिपय आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच एसआईटी व विजिलेंस से कराई है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त जांच में कितने आईपीएस अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कतिपय 05 आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की सतर्कता विभाग में जांच प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद शामली सहित प्रदेश में तालाबों व पोखरी व अन्य वाटर बॉडीज को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने से सम्बन्धित

17-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2018 से दिनांक 30-11-2018 तक जनपद शामली सहित प्रदेश में स्थित कितने तालाबों, पोखरों व अन्य वाटर बॉडीज को अवैध कब्जे से मुक्त सरकार ने कराया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्यानुसार माह जनवरी, 2018 से दिनांक 30-11-2018 तक जनपद-शामली सहित प्रदेश में स्थित कुल 57008 तालाबों, पोखरों व अन्य वाटर बॉडीज से अवैध कब्जा हटवाया गया है।

विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के तहसील मधुबन ग्राम सभा मुडाहार मनियार में ग्राम प्रधान व उच्चाधिकारियों द्वारा कराये गये विकास कार्यों में अनियमितताओं की जांच विषयक

18-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की तहसील मधुबन अन्तर्गत ग्राम सभा मुड़ाहार मनियार में वर्तमान ग्राम प्रधान व उच्च अधिकारियों की मिली-भगत से ग्राम में बनी नाली सी0सी0 रोड खड़जा पोखरा की खुदाई हैण्डपम्प की मरम्मत व नये हैण्डपम्प जो लगे हैं के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितातायें की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान प्रधान के पूरे कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच कराकर सरकारी धनराशि के दुरुपयोग करने के विरुद्ध कार्यवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

जनपद मऊ के तहसील मधुबन के अन्तर्गत ग्राम सभा मूड़ाडार मनियार के वर्तमान ग्राम प्रधान के कार्यों की जांच हेतु कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज व महराजगंज में कोरोना काल में सितम्बर, 2020 तक ग्रामीण इलाकों में बांटी गई सामग्री के विवरण विषयक

19-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज व महराजगंज में कोविड-19 की रोकथाम के लिये लगाये गये लॉकडाउन में माह

सितम्बर, 2020 तक ग्रामीण इलाकों में क्या सामग्री बाटी गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में लॉकडाउन में माह सितम्बर, 2020 तक 3140 खाद्यान किट, 23298.68 कुन्टल गेहूँ, 42066.32 कुन्टल चावल व 2396.66 कुन्टल चना का वितरण किया गया है।

विकास खण्ड महराजगंज में माह सितम्बर, 2020 तक 1193 खाद्यान्न किट एवं 19524.05 कुन्टल गेहूँ, 35927.90 कुन्टल चावल व 2021.05 कुन्टल चना का वितरण कराया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बुन्देलखण्ड पैकेज के तृतीय चरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 की धनराशि से गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बड़े तालाब/जलाशयों के गहरीकरण के सम्बन्ध में

20-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बुन्देलखण्ड पैकेज के तृतीय चरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 की धनराशि से गरौठा विधान सभा क्षेत्र के बड़े तालाब/जलाशयों को गहरीकरण करने की कोई कार्य योजना सरकार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रदेश में बुन्देलखण्ड पैकेज के तृतीय चरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की धनराशि से गरौठा विधान सभा क्षेत्र के बड़े तालाब/जलाशयों को गहरीकरण करने की कोई कार्य योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रुधौली तहसील परिसर में अधिकारियों के लिए आवास के निर्माण के सम्बन्ध में

21-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के रुधौली तहसील परिसर में अधिकारियों, एस0डी0एम0, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के आवासीय भवन न होने के कारण अधिकारी तहसील परिसर में रात्रि निवास नहीं कर पा रहे

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तहसील परिसर में आवासों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

तहसील परिसर में आवास निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृतियां जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है एवं निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नगला कली के प्रधान द्वारा की गई अनियमितता पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में

22-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नगला कली के प्रधान के खिलाफ जांच हेतु जिला अधिकारी आगरा के आदेश पत्र सं0-1086 अ0/जा0/प0/शि0/2020-21 दिनांक-09-07-2020 द्वारा दोषी ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबन्धित करते हुए अन्तिम जाँच भूमि संरक्षण अधिकारी टूण्डला आगरा को जाँच आख्या एक पक्ष (15 दिवस) के अन्दर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दोषी ग्राम प्रधान के साथ ही सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

विकास खण्ड बरौली अहीर की ग्राम पंचायत नगला कली में कराये गये विकास कार्यों की प्राप्त शिकायतों की जांच में दोषी पाये गये ग्राम प्रधान नगला कली के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को पंचायत राज अधिनियमों में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया गया है एवं पंचायत राज अधिनियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अंतिम जांच अधिकारी भूमि संरक्षण अधिकारी, टुण्डला आगरा को नामित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट पिटीशन संख्या-10747/2020 श्रीमती बविता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2-9-2020 के द्वारा चार सप्ताह में शपथ-पत्र लगाने के निर्देश जारी करते हुए प्रधान पद के रोके गये वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को बहाल कर दिया गया है, जिसके परिपालन में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर दिया गया है।

जिला विकास अधिकारी आगरा के कार्यालय आदेश दिनांक 14-10-2020 द्वारा दोषी पाये गये ग्राम विकास अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद के ग्राम नगला कली में कुआं वाली गली में खड़ंजा निर्माण कराने विषयक

23-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लॉक सादाबाद अन्तर्गत ग्राम नगला कली में कूंआ वाली गली में जलभराव की समस्या के निराकरण हेतु सी0सी0 टाईल्स/खडंजा निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

ग्राम पंचायत-नगला कली विकास खण्ड-सादाबाद जनपद-हाथरस में कुआं वाली गली में इण्टरलॉकिंग कार्य कराया गया है। वर्तमान में जलभराव की समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस ब्लाक सहपऊ के ग्राम नगला बिहारी में ग्रामवासियों को शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी के निर्माण सम्बन्धित

24-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सहपऊ के ग्राम नगला बिहारी में ग्रामवासियों को शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हाथरस के ब्लाक सहपऊ के ग्राम नगला बिहारी एवं प्रदेश के समस्त ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रुधौली, बस्ती के सल्टौआ गोपालपुर में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

25-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या जल शक्ति मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली, बस्ती के विकास क्षेत्र सल्टौआ गोपालपुर में स्वच्छ जल योजना के तहत वर्ष 2006-07

में 93.72 लाख रु0 की लागत से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना क्रियान्वित एवं संचालित पाईप लाइन से विगत 3 माह से पेयजल योजना बाधित है ? यदि हां तो क्या सरकार ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु पाईप लाइन अथवा अन्य उपकरणों का दुरुस्तीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली, बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सल्टौआ गोपालपुर में वर्ष 2006-07 में रु0 39.72 लाख के लागत की पेयजल योजना निर्मित की गयी थी। उक्त पेयजल योजना से सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराते हुए अगस्त, 2019 में सम्बन्धित ग्राम पंचायत को योजना हस्तान्तरित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच व कार्यवाही के सम्बन्ध में

26-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के सिंचाई विभाग द्वारा मनरेगा से कराये जा रहे कार्यों में मजदूरी से बिना कार्य कराये ही फर्जी मस्टर रोल बनाकर मजदूरी निकालने तथा धन का बन्दर बांट किये जाने की शिकायते सरकार को प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

27-श्री असलम अली-

(03रे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद गोण्डा के बभनजोत/छपिया/मनकापुर विकास खण्ड के अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या पूर्ण करने विषयक

28- श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के बभनजोत/छपिया/ मनकापुर विकास खण्ड के सभी प्राथमिक विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम के शिक्षकों की कमी

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इंग्लिश मीडियम के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की मानकानुसार संख्या पूरा करने पर विचार करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा तहसील मनकापुर केशवनगर ग्रान्ट में अनिवासियों को पट्टा दिये जाने की जांच व कार्यवाही विषयक

29-श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर व ग्राम केशवनगर ग्रान्ट में कतिपय लोग जो उक्त गाँव के निवासी नहीं है के नाम पट्टा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जॉच करवा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

ग्राम केशवनगर ग्रान्ट में कुल 5 व्यक्तियों को कृपा आवंटन का पट्टा किया गया था जिनके निरस्तीकरण की कार्यवाही जिलाधिकारी गोण्डा के न्यायालय में विचाराधीन है। दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी मनकापुर को आदेशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा मधवापुर में 800 मी0 इंटरलॉकिंग कार्य कराने विषयक

30-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा मधवापुर में सुनील के खेत से पारसीपुरवा मार्ग पर मीरा के घर तक दूरी लगभग 800 मीटर इंटरलाकिंग कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

अवर अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य का स्थलीय सत्यापन किया गया, जिसके अनुसार अनुमानित लागत रु0 37.50 लाख है। उक्त कार्य ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में शासन की उच्च प्राथमिकता वाले कार्य सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन का निर्माण, ऑपरेशन कायाकल्प, हैण्डपम्प मरम्मत एवं रि-बोर का कार्य कराया जाना है। अतः उक्त कार्य की अनुमानित लागत अत्यधिक होने के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा मधवापुर में 800 मी0 इंटरलॉकिंग कार्य कराने विषयक

31-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा मधवापुर में मिथलेश के घर से मेन रोड तक दूरी लगभग 800 मीटर इंटरलॉकिंग कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उक्त कार्य का स्थलीय सत्यापन अवर अभियन्ता द्वारा कराया गया है। अवर अभियन्ता की आख्यानुसार उक्त कार्य की अनुमानित लागत रु0 37.5 लाख रुपये होगी। वर्तमान समय में शासन की उच्च प्राथमिकता वाले कार्य यथा-सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन का निर्माण, आपरेशन कायाकल्प, हैण्डपम्प मरम्मत एवं रि-बोर का कार्य कराये जाने के पश्चात् अवशेष धनराशि से उक्त कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठला।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा कटघर में नाली निर्माण हेतु

32-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा कटघर में श्री राम गुप्ता के घर से मोहम्मद अली के घर तक नाली का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

श्री राम गुप्ता के घर से मोहम्मद अली के घर तक लम्बाई लगभग 250 मीटर नाली निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत की आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में सम्मिलित कर करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा विधान सभा क्षेत्र मांट के चौराहों, घाट, मंदिर, सार्वजनिक स्थल व बाजार में अराजक तत्वों द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाने विषयक

33-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के समस्त चौराहों, घाट, मन्दिर सार्वजनिक स्थल तथा बाजार में अराजक तत्वों द्वारा लगातार की जा रही आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत उक्त स्थानों पर सरकार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विधान सभा क्षेत्र मांट में थाना क्षेत्र मांट, सुरीर, नौहझील, राया, जमुनापार, शेरगढ़ में वर्तमान में मौजूद कैमरों की संख्या 12 है एवं भिन्न-भिन्न स्थानों पर अन्य 50 कैमरे लगवाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में सरकार द्वारा वर्तमान में लगवाये गये कैमरों की संख्या, स्थिति व अक्रियाशील कैमरों को चालू करवाने विषयक

34-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने कि कृपा करेंगे की जनपद मथुरा में सरकार द्वारा वर्तमान में कुल कितने सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये गये हैं तथा उक्त में से कितने कैमरे वर्तमान में चालू हालत में हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद के अधिकांश कैमरों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण कार्यशील नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को एडीजी स्तर से जांच कराकर समस्त सी0सी0टी0वी0 कैमरों को चालू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मथुरा के 16 थानों पर तकनीकी मुख्यालय द्वारा 42 कैमरे लगवाये गये हैं जिनमें से 36 क्रियाशील हैं एवं 06 अक्रियाशील हैं एवं जनपद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा व वृन्दावन में हृदय योजना के अन्तर्गत 148 कैमरे लगवाये गये हैं, जिनमें 148 क्रियाशील हैं।

मात्र 06 कैमरे तकनीकी खराबी के कारण क्रियाशील नहीं हैं जिन्हें ठीक कराकर चालू कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में वर्ष 2018 से अक्टूबर, 2020 तक बलात्कार, अपहरण व लूट की पंजीकृत घटनाएं व पकड़े गये अपराधियों का विवरण देने विषयक

35-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में वर्ष 2018 से अक्टूबर, 2020 तक बलात्कार, अपहरण तथा लूट पाट एवं डकैती की कुल कितनी घटनायें पंजीकृत हुई हैं तथा कितनी घटनाओं से संबंधित अपराधियों को पकड़ा जा चुका है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि पुलिस की निष्क्रियता से विगत वर्षों में जनपद में अपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है ? क्या सरकार प्रश्नगत वर्षों की घटनाओं से संबंधित अद्यतन स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मथुरा में वर्ष 2018 से 2020 तक घटित बलात्कार, अपहरण, लूट एवं डकैती से सम्बन्धित पंजीकृत अपराधों के अपराधियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर संलग्नक-1 के रूप में रख दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पंचायती राज विभाग के अधीन अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पदों पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार वरिष्ठता के आधार पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पद पर तैनाती विषयक

36-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज विभाग के अधीन अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के पदों पर सर्विस बेंच नं0 698 ऑफ 2011 दिनांक 02-05-2011 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के पद पर तैनाती सरकार देगी ? यदि हो, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

प्रश्न में उल्लिखित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02-05-2011 के क्रम में तत्समय याची के प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है। उ0प्र0 जिला पंचायत (अपर मुख्य अधिकारी का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, 1993 में अपर मुख्य अधिकारी के पद पर 60 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त कार्य अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा तथा 20 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा भर्ती का प्रावधान है। उक्तानुसार ज्येष्ठता के आधार पर अपर मुख्य अधिकारी के पद पर प्रोन्नति कर तैनाती की जाती है।

शासन द्वारा अपरिहार्य कारणों से रिक्त पदों के सापेक्ष जनहित एवं कार्यहित में तत्कालिक आवश्यकतानुसार नियमित अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक अपर मुख्य अधिकारी पद का प्रभार भी प्रदान किया जाता है।

प्रान्तीय सिविल सेवा के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निदेशालय व जनपद में नियुक्ति हेतु रिक्ति की प्रत्याशा में नियुक्ति देने विषयक

37-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय सिविल सेवा (यूपीपीसीएस) के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निदेशालय तथा जनपद में नियुक्ति हेतु रिक्ति की प्रत्याशा में पदानुक्रम में उच्च पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु क्या कोई नियमावली है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अधिकारियों की उच्च पदों पर बिना पदोन्नति पद रिक्त होने पर नियुक्ति हेतु आयोग की वरिष्ठता अनुसार नियुक्ति देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार अधिकारियों की उपलब्धता एवं कार्यों की आवश्यकता के अनुसार शासकीय कार्यहित एवं जनहित में पदों पर तैनाती करती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ, तहसील सदर, मो0 सहादतपुरा में आराजी सं0-390 ख पर सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जा हटवाने विषयक

38-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की तहसील सदर के अन्तर्गत मोहल्ला सहादतपुरा में आराजी सं0-390 ख बाहा सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

ग्राम सहादतपुरा, तहसील सदर, जनपद मऊ में स्थित गाटा सं0-390ख रकबा 0.0530 हे0 में से रकबा 0.014 हे0 पर राम अशीष राय पुत्र सूर्यदेव राय, निवासी सहादतपुरा द्वारा बाउन्ड्री बनाकर कब्जा किया गया है। अतिक्रमणकर्ता राम अशीष राय पुत्र

सूर्यदेव राय के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार सदर, जनपद मऊ वाद सं0-टी-201915510105099 रिपोर्ट बनाम राम अशीष में दिनांक 14-02-2020 को न्यायालय द्वारा अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध बेदखली तथा क्षतिपूर्ति रु0 11775 व निष्पादन व्यय रु0 1000 आरोपित करते हुए आदेश पारित किया गया। किन्तु इससे पूर्व ही अतिक्रमणकर्ता द्वारा न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) मऊ में वाद संख्या-673/2009 राम अशीष बनाम राम सरीख आदि दाखिल किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा (स्टे आर्डर) का आदेश पारित किया गया है।

स्थगन आदेश निरस्तीकरण हेतु वाद संख्या-673/2009 जिसमे सरकार पक्षकार है, न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात् अतिक्रमण हटवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ विधान सभा क्षेत्र घोसी स्थित नरजा व पिऊआ ताल जलाशय का नापी कराकर सीमांकन व डैम निर्माण कराने विषयक

39-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की विधान सभा क्षेत्र घोसी स्थित नरजा एवं पिऊआ ताल जलाशय जिसका क्षेत्रफल 100 एकड़ से भी अधिक है, की नापी कराकर सीमांकन एवं डैम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड महराजगंज में चिकनहवा ढाला के पास ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा पुल के निर्माण को पूर्ण कराने विषयक

40-श्री नफीस अहमद-

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में चिकनहवा ढाला के समीप ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराया गया पुल का नव निर्माण कार्य अधूरा होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुल के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ, पुल का नव निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण आवागमन सुलभ नहीं है।

कार्य की अवशेष धनराशि का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। विभाग डिपाजिट मद से कार्य करवाता है। विभाग के पास कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड बिलरियागंज में शारदा सहायक खण्ड-32 नहर के उत्तरी पटरी पर इस्माइलपुर गोरिया पुल से मसीरपुर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य कराने विषयक

41-श्री नफीस अहमद-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में शारदा सहायक खण्ड-32 नहर के उत्तरी पटरी पर इस्माइलपुर गोरिया पुल से मसीर पुर तक की दूरी लगभग 03 किलोमीटर का नव निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलरियागंज के ग्राम इस्माइलपुर गोरिया पुल से मसीरपुर तक शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ के नहर के उत्तरी पटरी पर सड़क/मार्ग निर्माण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रदेश व नगर फिरोजाबाद में अवरुद्ध पड़ी ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना को पूर्ण कराने विषयक

42-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहरों सहित फिरोजाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना न होने के कारण ओ0डी0ओ0पी0 में सम्मिलित काँच उद्योग की औद्योगिक आपूर्ति एवं परिवहन हेतु चलने वाले ट्रकों/ट्रेलर आदि सड़कों के किनारे एवं अन्यत्र स्थानों में खड़े होते हैं, जिसके कारण यातायात अवरुद्ध होने तथा दुर्घटना घटित होने की सम्भावनायें बनी रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद में अवरुद्ध ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना को पूर्ण कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद फिरोजाबाद में कांच उद्योग की औद्योगिक आपूर्ति एवं परिवहन हेतु चलने वाले ट्रकों/ट्रेलरों आदि सड़कों के किनारे व अन्यत्र स्थानों पर खड़े होने वाले वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर संयुक्त कार्यवाही की जाती है। परिवहन विभाग फिरोजाबाद के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अनाधिकृत रूप से सड़क के किनारे खड़े वाहनों के विरुद्ध मोटर अधिनियम के

अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। वर्ष 2020-21 में अवैध पार्किंग के विरुद्ध 889 चालान किये गये हैं, जिनसे रु0 68,700/- प्रशमन शुल्क की धनराशि प्राप्त हुई है।

नागरिक पुलिस, यातायात पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियमित ड्यूटी लगायी जाती है तथा वाहनों को व्यवस्थित ढंग से खड़ा कराया जाता है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन जनपद फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद क्षेत्रान्तर्गत राजस्व ग्राम नागऊ, तहसील-टूण्डला, जिला फिरोजाबाद के अन्तर्गत 13.766 हे0 भूमि का अर्जन ट्रान्सपोर्ट नगर योजना हेतु किया गया है। प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध न होने के कारण किसानों को प्रतिकर की राशि वितरित न कर पाने के कारण भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। किसानों को प्रतिकर का भुगतान करने हेतु रु0 2000 लाख का वित्तीय ऋण लेने की अनुमति हेतु प्रस्ताव आगामी प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रामनगर अन्तर्गत ग्राम नरखोरिया में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

43-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र रामनगर अन्तर्गत ग्राम नरखोरिया में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवन जर्जर होने से अध्यापिकायें बालिकाओं को मैदान में बैठ कर शिक्षण कार्य सम्पन्न करा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

विगत सत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रामनगर का विद्यालय भवन निर्माण कराने वाली कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, गोण्डा द्वारा भवन में लघु मरम्मत का कार्य कराया गया है तथा अवशेष भवन के मरम्मत का कार्य वर्तमान सत्र में हास्टल रख-रखाव व विविध मद से कराया गया है। छात्रों का पठन-पाठन विद्यालय भवन में संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद बलिया तहसील बैरिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत श्रीनगर में पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण के सम्बन्ध में

44-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की तहसील बैरिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत श्रीनगर में पानी के निकासी के लिए मुख्य मंत्री पोर्टल पर सन्दर्भ

संख्या-1800180192670, 40019318005279, 40093118005278 नाली निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत पर खण्ड विकास अधिकरी बैरिया द्वारा अपने पंत्राक संख्या-55/मुख्य मंत्री/सन्दर्भ/निस्तारण/2018-19, दिनांक 26/09/2018 की रिपोर्ट पर कार्यवाही विषयक है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

आवेदनकर्ता द्वारा जिस भूमि/गड्ढे में नाली निर्माण कर पानी निकासी चाहा जा रहा है वह भूमि विवादित है, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी से भी स्थलीय निरीक्षण कराकर आख्या प्राप्त की गयी है, जिसमें उक्त भूमि के विवादित होने का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मिलकर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सोख्ता गड्ढा बनाने का प्रस्ताव रखा गया, परन्तु उपरोक्त शिकायतकर्ता द्वारा इन्कार कर दिया गया। अछैवर वर्मा के घर से पूरब सुग्रीव वर्मा व अर्जुन वर्मा का मकान है जहां पर पंचायत द्वारा नाली बनाई गयी है। जो रेलवे लाइन के गड्ढे में है। अछैवर वर्मा का मकान उस नाली से काफी नीचे है, जिसके कारण इनके घर से नाली बनाकर उस नाली में मिलाने पर इनके घर से पानी की निकासी नहीं हो पायेगी। यदि शिकायतकर्ता द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जाती है तो ग्राम पंचायत द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सोख्ता गड्ढे का निर्माण कराया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रुधौली में लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत आवास सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में

45-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में कितने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवास की सुविधा मुहैया करायी गयी है तथा कितने लाभार्थी अभी तक योजना से वंचित हैं ? क्या सरकार वंचित लाभार्थियों को आवास की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्डों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 8538 लाभार्थियों को आवास की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्डों में आवास प्लस के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत तैयार की गयी स्थायी पात्रता सूची में से आवास स्वीकृति के बाद 4812 पात्र लाभार्थी शेष हैं।

योजनान्तर्गत शेष लाभार्थियों को आवास दिये जाने की कार्यवाही भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर निर्भर है।

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	वर्ष	उपलब्ध कराये गये आवासों की संख्या
1	रामनगर	2016-17 से 2020-21 में दिनांक-21-01-2021 तक	2109
2	रुधौली	2016-17 से 2020-21 में दिनांक-21-01-2021 तक	1992
3	सल्टौवा	2016-17 से 2020-21 में दिनांक-21-01-2021 तक	3564
4	साऊघाट	2016-17 से 2020-21 में दिनांक-21-01-2021 तक	873
योग :			8538

उपरोक्तानुसार।

अपट्रान कर्मियों में कार्यालय समापक देयकों के भुगतान हेतु बजट सुनिश्चित कराने विषयक

46-श्री संजय गर्ग-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2019 के प्रथम मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या-18 के उत्तर के क्रम में क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपट्रान कर्मियों के सेवा सम्बन्धी देयकों का विवरण जो अपट्रान प्रबन्धन के पास उपलब्ध है, प्राप्त कर कार्यालय समापक देयकों का भुगतान करने हेतु बजटीय प्राविधान कराकर उनका भुगतान सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। अपट्रान परिसमापन में है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कार्यालय समापक द्वारा अपट्रान की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करते हुए, गोमतीनगर स्थित अपट्रान के मुख्यालय को सितम्बर, 2016 में सील कर दिया गया था। वर्तमान में अपट्रान में कोई कर्मी कार्यरत नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नियुक्त कार्यालय समापक द्वारा कम्पनी के समापन की कार्यवाही प्रचलित है। सम्बन्धित अपट्रान कर्मियों द्वारा देयकों के भुगतान के लिए कार्यालय समापक के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जाना होगा। कर्मचारियों के देयकों के भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही कार्यालय समापक स्तर से ही की जानी है।

जनपद जौनपुर, विधान सभा क्षेत्र केराकत, ब्लाक मुफ्तीगंज, ग्राम अमरा में इण्टरलाकिंग कार्य कराने विषयक

47-श्री दिनेश चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लॉक मुफ्तीगंज के ग्राम अमरा में जनार्दन राय के घर से राम प्रसाद गुप्ता के घर तक एवं जनार्दन राय के घर से रामकिर्ती चौबे के घर तक सरकार इण्टरलांकिंग का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

उक्त कार्यों को आगामी वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर धनराशि की उपलब्धता होने पर प्राथमिकता के आधार पर करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा सर्रोकला 2 नं0 पुरवा मजरा में 800 मी0 इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु

48-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्रामसभा सर्राकला 2 नं0 पुरवा मजरा में डी0आर0डी0 से गाँव में प्राइमरी स्कूल तक दूरी लगभग 800 मीटर इण्टरलाकिंग कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

स्थलीय निरीक्षणोपरान्त जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा सर्राकला 2 नं0 पुरवा मजरा में डी0आर0डी0 से गाँव में प्राइमरी स्कूल तक की दूरी लगभग 740 मीटर है, जिस पर जिला पंचायत बहराइच द्वारा वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत खड़न्जा निर्माण कराया गया है, जो संतोषजनक स्थिति में है तथा आवागमन हेतु सुलभ है। उक्त मार्ग पर लगभग 2 वर्ष पूर्व लगे खड़न्जा पर पुनः इण्टरलाकिंग कार्य कराया जाना नियमानुसार व्यावहारिक एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक आपरेशन कायाकल्प योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि व निर्माण कार्य की जानकारी

49-मनीष असीजा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक आपरेशन कायाकल्प योजनान्तर्गत कितनी धनराशि प्राप्त हुई है एवं कितने विद्यालयों में कार्य पूर्ण हो गया है तथा कितने विद्यालय में कार्य कराया जाना है ? क्या

सरकार बतायेगी कि उक्त कार्यों में गुणवत्ता मानक अनुपालन सम्बन्धी सहित अन्य अनियमितताओं की कितनी शिकायत प्राप्त हुई है तथा उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या-2706/33-3-2019, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 के अनुसार 14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/ ग्राम निधि मद से ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विद्यालयों मे मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के कार्य किये जाने का प्राविधान है।

जनपद फिरोजाबाद से 105 विद्यालय 14 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त शेष हैं 1755 विद्यालयों में 14 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के कार्य कराया जाना अवशेष हैं।

ऑपरेशन कायाकल्प योजनान्तर्गत कार्यों को अन्तर्विभागीय समन्वय से कराया जा रहा है। गुणवत्ता मानक अनुपालन सम्बन्धी 04 शिकायत प्राप्त हुई थी-

1	श्री अशोक कुमार	ग्राम प्रधान एवं ठेकदार, द्वारा जमुना बालू एवं पीली ईंट तूरी द्वारा विद्यालय/शौचालय का निर्माण करने के सम्बन्ध में।
2	श्री नीलेश कुमार	ग्राम बरियार माऊ के प्राथमिक विद्यालय कुतुबुर बरियार माऊ की बाउण्ड्री में काली बालू व पीली ईंट का इस्तेमाल किये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री कृपाला	ग्राम सिकहरा हरदासपुर के प्राथमिक विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल में काली बालू तथा पीली ईंट के प्रयोग से क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में।
4	श्री महेन्द्र सिंह निषाद	प्राथमिक विद्यालय नगला काले में मानक के अनुरूप निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त शिकायतों को निस्तारण हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद को प्रेषित किया गया है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस ब्लाक सहपऊ में नगला ब्राहम्ण भाग मढ़ापिथू में बाल्मीकि बस्ती से नगला रमजू मार्ग में सी0सी0 टाइल्स/खड़न्जा निर्माण से सम्बन्धित

50-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सहपऊ के अन्तर्गत नगला ब्राहम्ण भाग मढ़ापिथू में बाल्मीकि बस्ती होते हुए नगला रमजू तक मार्ग में सी0सी0 टाइल्स/खड़न्जा का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

जी हाँ।

जनपद हाथरस के ब्लॉक सहपऊ के अन्तर्गत नगला ब्राहम्ण भाग मढ़ापिथू में बाल्मीकि बस्ती होते हुए नगला रमजू तक चकमार्ग पर मनरेगा योजनान्तर्गत मिट्टी का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है। ईंट खड़न्जा का कार्य धनराशि की उपलब्धता के उपरान्त अतिशीघ्र करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद, ग्राम करकौली व करैया में शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी के निर्माण विषयक

51-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लॉक सादाबाद के ग्राम करकौली एवं करैया में खारे व गन्दे पानी से निजात दिलाने हेतु ग्रामवासियों को शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

भारत सरकार द्वारा "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र सदर, ग्राम पंचायत पूरे ईश्वरनाथ सदर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय की सटी ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा हटवाये जाने विषयक

52-श्री राजकुमार पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम पंचायत पूरे ईश्वरनाथ सदर में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की सटी हुई ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह बतायेगी कि ग्राम सभा की उक्त जमीन को विद्यालय को दर्ज करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्यानुसार जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम पंचायत पूरे ईश्वरनाथ सदर में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की सटी हुई ग्राम सभा की जमीन के आंशिक हिस्से पर शोभनाथ यादव द्वारा गोबर रख कर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे हटवा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

चूँकि ग्राम-पूरे ईश्वरनाथ नगर पालिका, सीमान्तर्गत अधिसूचित हो चुका है, अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र सदर में बरा का सराय मंगरौरा की ओझला ड्रेन में गिरने वाले परैया नाले की गहराई व अन्य कार्य मानकानुरूप कराने विषयक

53-श्री राजकुमार पाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में बरा का सराय मंगरौरा की ओझला ड्रेन में गिरकर परैया नाले में मिलती है, उक्त नाला की गहराई मानक के अनुरूप न होने के कारण जल भराव होता है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की गहराई कार्य कर पुनरोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ। ओझला ड्रेन की कुल लम्बाई 7.341 किमी0 तथा शीर्ष डिस्चार्ज 1.43 क्यूसेक है। यह परैया नाले में गिरती है। उक्त ड्रेन के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 7.341 तक सिल्ट सफाई का कार्य जनवरी, 2021 में मानक के अनुरूप करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र सदर के सण्डवा चन्द्रिका ब्लाक में अग्निशमन केंद्र स्थापित कराने विषयक

54-श्री राजकुमार पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के सण्डवा चन्द्रिका ब्लॉक में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत अग्निशमन केन्द्र की स्थापना निःशुल्क भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में गाटा संख्या-791 व 789 पर हुये अवैध कब्जे को हटाने विषयक

55-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में गाटा सं0-791 व 789 क्रमशः खलिहान एवं नवीन परती भूमि पर दबंगों /भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से तालाब बनवा कर जल निकासी के प्राकृतिक नाले को पक्की दीवार बनाकर पानी रोके जाने से क्षेत्र की हजारों बीघे फसल डूब गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अवरोध को हटवाने विषयक स्थानीय नागरिकों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 08 जुलाई, 2020 उप जिलाधिकारी, बीघापुर, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्यानुसार जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत-त्रिपुरारपुर के राजस्व ग्राम त्रिपुरारपुर की गाटा संख्या-791, रकबा 0.379 हे0 खलिहान के रूप में एवं गाटा संख्या-789 मि0 रकबा 0.961 हे0 अभिलेखों में नवीन परती अंकित है। गाटा संख्या-789 मि0 रकबा 0.165 हे0 श्री छोटेलाल पुत्र श्री ठन्नादास व श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री छोटेलाल, निवासी-रम्माखेडा म0 त्रिपुरारपुर के नाम असंक्रमणीय भूमिधर अंकित है तथा गाटा संख्या-791 रकबा 0.379 है0 मौके पर खाली है। उस पर किसी का कोई कब्जा नहीं है। गाटा संख्या-789 मि0 रकबा 0.165 हे0 पर पटट्ेदार द्वारा कुछ अंश पर टीनशेड, बोरिंग एवं शेष रकबे पर फसल बोई गयी है। गाटा संख्या-789 मि0 क्षेत्रफल 0.961 अभिलेख में नवीन परती अंकित है एवं मौके पर तालाब के रूप में है। इसी से बरसात का पानी निकलने हेतु नाला निकला है, जिसमे दो तरफ पक्की ईंटों की दीवाल एवं लोहे की जाली लगाकर अवरुद्ध किया गया था, जिसे मौके पर जाकर खुलवा दिया गया है तथा अवैध अतिक्रमण हटवा दिया गया है। पानी से कोई फसल न तो नष्ट हुई है और न ही कोई फसल डूबी है।

जी हाँ।

उप जिलाधिकारी, बीघापुर द्वारा प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली पुरवा/रा0नि0 को पृष्ठांकित करते हुए जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकार नई संविदा नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित समूह ख व ग पदों पर नियुक्ति व विनियमितीकरण नियमावली, 2020 विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

56-श्री अजय कुमार "लल्लू"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नई संविदा नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग समूह ख व ग के पदों पर नियुक्ति (संविदा पर) एवं

विनियमितीकरण नियमावली, 2020 विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-अ-4/852 दिनांक 15-09-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों पर नियुक्ति (संविदा पर) एवं विनियमितीकरण नियमावली, 2020 के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अभियोजन अधिकारी संवर्ग के सहायक अभियोजन अधिकारी से उच्च पदों पर लम्बित प्रोन्नति शीघ्र कराने विषयक

57-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गृह विभाग के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी संवर्ग के सहायक अभियोजन अधिकारी से लेकर संयुक्त निदेशक पद के पात्र अधिकारियों की उच्च पदों पर प्रोन्नति डी0पी0सी0 विगत कई वर्षों से लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार पात्र अधिकारियों की प्रोन्नति/डी0पी0सी0 करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

चयन वर्ष 2019-20 में सहायक अभियोजन अधिकारी से अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु किसी भी सहायक अभियोजन अधिकारी की 07 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने के कारण डी0पी0सी0 नहीं हुई है, जबकि अन्य पदों यथा-ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, संयुक्त निदेशक अभियोजन एवं अपर निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नति हेतु डी0पी0सी0 हुई है। भविष्य में चयन वर्ष 2020-2021 के पात्र अधिकारियों की डी0पी0सी0 नियमानुसार की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी कार्यालय, लखनऊ के नियंत्रणाधीन आवासीय भवनों के आवंटन की जांच कराने व गलत आवंटन निरस्त कराने विषयक

58-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ के नियंत्रणाधीन आवासीय भवनों का आवंटन ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी किया गया है

जिनकी नियुक्ति जनपद लखनऊ से अन्यत्र है, जिससे जनपद लखनऊ में नियुक्ति पाये अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास सम्बन्धी असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर जनपद लखनऊ से अन्यत्र नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के जिलाधिकारी कार्यालय, लखनऊ द्वारा आवंटित आवासों को निरस्त करायेगी ? यदि हो, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जिलाधिकारी कार्यालय, लखनऊ के नियंत्रणाधीन आवासीय भवनों का आवंटन किसी भी ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को नहीं किया गया है, जिनकी नियुक्ति जनपद लखनऊ से अन्यत्र है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में चयनित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत कुल 3 पैकेज में शेष 3 मार्गों को स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक

59-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दो बैच के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत कुल तीन पैकेज में पांच मार्गों के प्रस्ताव में से मात्र दो मार्गों की ही स्वीकृति प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष तीन मार्गों की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ, जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बैच-1 के अन्तर्गत कुल तीन पैकेज संख्या-यू0पी0-1582, यू0पी0-1583, यू0पी0-1584 के अन्तर्गत कार्यों के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में पैकेज सं0-यू0पी0-1582 के अधीन मात्र दो मार्गों (01) एस0एच0-26 (नरखोरिया) से पकरी एवं (02) एस0एच0-26 (नरखोरिया) से कांटेखैरा (सगरा) मार्ग की स्वीकृति दिनांक 31-08-2019 को प्राप्त हुई है। उक्त मार्गों पर अनुबन्ध गठन कर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। अवशेष मार्गों पर भारत सरकार द्वारा कोई स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

शेष मार्ग पर भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मां सण्डवा चण्डिका धाम में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने विषयक

60-श्री राजकुमार पाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मां सण्डवा चण्डिका धाम में सामुदायिक शौचालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धार्मिक स्थल क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत उक्त स्थान के विकास हेतु रु0 46.98 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में शौचालय का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्माणाधीन खजुरनी मार्ग में अनियमितता कर घटिया किस्म की निर्माण सामग्री क्रय कर मार्ग निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच कर कार्रवाई करने विषयक

61-श्री राजकुमार पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निमार्णाधीन सड़क खजुरनी मार्ग में अनियमितता कर क्रय की गई सामग्री घटिया किस्म की है ? क्या सरकार उक्त मार्ग के निर्माण में की जा रही अनियमितता की जांच कराकर दोषियों कि विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी नहीं।

उक्त निर्माण कार्य की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (टी0ए0सी0) द्वारा की जा रही है। यदि जांचोपरान्त कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (टी0ए0सी0) जांच प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

62-श्री नफीस अहमद-

[दिनांक 19-02-2021 को तारांकित प्रश्न सं0-99 के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के गोड़हरा बाजार में पुलिस चौकी का निर्माण कराने हेतु

63-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत क्षेत्रवासियों के सुरक्षा के हित में गोड़हरा बाजार में पुलिस चौकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

गोड़हरा बाजार में पुलिस चौकी की स्थापना/निर्माण कराये जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के हित में गोड़हरा बाजार में पिकेट ड्यूटी, रात्रि गश्त एवं यू0पी0-112 स्थानीय रूप से लगायी गयी है।

प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी पद पर योगदान न कराये जाने विषयक

64-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवानिवृत्त 52 भूतपूर्व सैनिकों की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित ग्राम विकास अधिकारी के पद पर योगदान न कराये जाने के विषयक मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-अ-4/873 दिनांक 17-09-2020 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित उक्त पत्र प्राप्त हुआ है।

शासन के पत्र दिनांक 28-09-2020 द्वारा प्रेषित उक्त पत्र के सम्बन्ध में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी (सा0 च0) प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 2016 के अन्तर्गत अन्तिम चयन परिणाम में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के 70 अभ्यर्थियों द्वारा धारित सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र मानक के अनुसार न होने के कारण उनका परिणाम विदहेल्ड रखा गया था। इन विदहेल्ड अभ्यर्थियों में से आयोग में सुनवाई के उपरान्त 15 अभ्यर्थियों की संस्तुतियां प्रेषित की गयीं और शेष 55 में से 52 अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में आयुक्त, ग्राम विकास द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम विकास विभाग द्वारा किसी प्रकार की शिथिलता प्रदान न करने का निर्णय लिया गया है। वर्णित परिस्थितियों में आयोग द्वारा सशर्त/अभ्युक्ति के साथ प्रेषित संस्तुतियाँ स्वतः प्रभावशून्य एवं निष्प्रभावी हो जाती हैं।

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा योजित रिट याचिका में मा0 न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अपील संख्या-1206/2020 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम प्रमोद कुमार व अन्य मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर, ब्लाक सरसावां स्थित किसान इण्टर कालेज, चौरी मण्डी के अवैध सदस्यों को हटाकर नयी प्रशासनिक व्यवस्था का चुनाव कराये जाने विषयक

65-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ब्लाक-सरसावां में आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित किसान इण्टर कालेज, चौरी मण्डी को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की डबल बेंच के आदेशानुसार सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटी चिटफण्ड, सहारनपुर द्वारा सोसाइटी अधिनियम-1860 के अन्तर्गत अवैध सदस्यों को हटाकर नयी प्रशासनिक व्यवस्था को मान्यता दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कालेज समिति द्वारा अवैध सदस्यों को हटाये बिना ही नयी प्रशासनिक व्यवस्था का चुनाव कराया जा रहा है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या सरकार पुराने अवैध समिति सदस्यों को हटाते हुये जिला विद्यालय निरिक्षक, सहारनपुर के अधीन नयी प्रशासनिक व्यवस्था का चुनाव करायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-14162/2020 एवं वाद संख्या-720/2019 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सहारनपुर में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कटरा, जैतीपुर की जांच सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा तृतीय, बरेली मण्डल द्वारा कराने व दोषियों पर कार्रवाई विषयक

66-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या-18150190098470 जो जनपद शाहजहांपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कटरा, जैतीपुर, कलान, मिर्जापुर तथा खुदागंज की सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा तृतीय, बरेली

मण्डल द्वारा दिनांक 17-10-19 को की गयी जाँच में दोषियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18150190098470 के सम्बन्ध में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कटरा खुदागंज, जैतीपुर, कलान, मिर्जापुर की जांच सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तृतीय मण्डल, बरेली द्वारा पत्र संख्या-एस0एस0ए0/1785/2019-20, दिनांक 10-07-2019, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तिलहर (नगर), तिलहर (ग्रामीण) एवं जैतीपुर तथा पत्र संख्या-एस0एस0ए0/1787/2019-20 दिनांक 17-07-2019 द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कलान एवं कटरा खुदागंज तथा दिनांक 21-02-2020 द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मिर्जापुर का निरीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी। तत्क्रम में उक्त विद्यालयों के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत् है :-

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कटरा खुदागंज श्री गौरव कुमार, लेखाकार एवं श्रीमती अनीता तिवारी, वार्डेन, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कटरा खुदागंज को पदीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता के प्रति लापरवाही बरतने तथा विभागीय कार्यों में अरुचि के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु संविदा नवीनीकरण न किये जाने का निर्णय लिया गया।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जैतीपुर श्री राजू कश्यप, लेखाकार, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जैतीपुर के उपस्थिति कॉलम में हस्ताक्षर मिलने तथा मौके पर न पाये जाने के कारण सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक की संस्तुति के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 14-1-2020 द्वारा संविदा समाप्त कर दी गयी।

सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक की संस्तुति के आधार पर विद्यालय का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्था दीपजन कल्याण समिति, बरेली को अनियमितता के प्रति जिला शिक्षा परियोजना समिति, शाहजहांपुर के प्रस्ताव के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 13-11-2019 द्वारा विद्यालय संचालन के दायित्व से पृथक कर दिया गया है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कलान विद्यालय का संचालन करने वाली संस्था काशी विकास शिक्षण संस्थान, बदायूं को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 3-2-2020 द्वारा नोटिस जारी कर कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया तथा पुनः कार्यालय के पत्र दिनांक 13-2-2020 द्वारा स्वयंसेवी संस्था को भविष्य के लिये कठोर चेतावनी दी गयी कि भविष्य में उपरोक्त कमियां पाये जाने पर संस्था को विद्यालय के संचालन से पृथक करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मिर्जापुर निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा विद्यालय में स्वच्छता एवं छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से छात्रावास के बाहर गैलरी में एक

सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाने हेतु निर्देशित किया गया तथा शौचालय एवं स्नानघरों में मरम्मत का कार्य नियमानुसार कराये जाने के निर्देश दिये गये। के0जी0बी0वी0 मिर्जापुर की वार्डेन के पत्र दिनांक 14-08-2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कमियों का निराकरण करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की तहसील के ग्राम भानपुर में बालिका महाविद्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में

67-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के तहसील स्तरीय ग्राम भानपुर में बालिकाओं के उच्च शिक्षा हेतु व्यवस्था न होने के कारण उन्हें दूरस्थ जिला मुख्यालय के कन्या महाविद्यालय में ही जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बालिका महाविद्यालय की स्थापना करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जनपद बस्ती में पर्याप्त महाविद्यालय हैं, जहां छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं।

जी नहीं।

जनपद बस्ती में 05 राजकीय महाविद्यालय, 04 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं 54 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। तहसील भानपुर के विकास खण्ड-सल्टौवा में 01 राजकीय महाविद्यालय एवं 01 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित है। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र की छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। उक्त के अतिरिक्त मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में 01 राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संशाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद बस्ती के तहसील स्तरीय ग्राम भानपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का अवसर नहीं है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा गंगापुर, मजरा सरैय्या में 300 मी0 सड़क के इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु

68-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा में ग्राम सभा गंगापुर के मजरा सरैय्या अमीर चन्द के घर से नहर तक लम्बाई लगभग 300 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

स्थलीय सत्यापन में कार्य की अनुमानित लागत रु0 12 लाख होगी। उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में सम्मिलित कराते हुए करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा लौकाही में 300 मी0 नाली निर्माण हेतु

69-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा लौकाही में मोलहे के घर से भगेलू राणा के घर तक दूरी लगभग 300 मीटर नाली का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

अवर अभियन्ता की आख्यानुसार वर्तमान समय में नाली बनी हुई है। लगभग 25 मी0 शेष नाली नहीं बनी है, जिसको आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में सम्मिलित कर कार्य करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा विश्वनाथगांव गोसाईगांव में 300 मी0 सड़क निर्माण हेतु

70-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा विश्वनाथगांव गोसाईगांव में मुरारी के घर से छोटे के घर तक दूरी लगभग 300 मीटर सड़क निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

उक्त कार्य की अनुमानित लागत लगभग रुपये 7.00 लाख है। अतः धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उक्त कार्य को ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में सम्मिलित कराते हुए करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा झुम्मन गांव में 200 मी0 नाला निर्माण हेतु

71-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा झुम्मन गांव में पप्पू के बाग से ब्रहमानन्द के खेत तक दूरी लगभग 200 मीटर नाला का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

ग्राम में स्थलीय सत्यापन में उक्त कार्य का नाम स्पष्ट नहीं है। उक्त कार्य का विवरण ग्राम पंचायत कैलाशपुर झूमनगांव में नहीं है। अतः कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत में श्री अजीतनाथ जैन इण्टर कॉलेज ग्राम शेरपुर लुहारा में प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के कूटरचित हस्ताक्षर से प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में सहा0 अध्यापिका पद पर की गयी नियुक्ति की जांच विषयक

72-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2018 जोकि श्री अजीतनाथ जैन इण्टर कॉलेज ग्राम शेरपुर लुहारा जनपद बागपत में प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के कूटरचित हस्ताक्षर से प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति की जांच विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हाँ।

मा0 सदस्य, विधान सभा के उपरोक्त शिकायती-पत्र पर जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत के पत्र दिनांक 13-12-2019 द्वारा 03 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति के पत्र दिनांक 14-12-2019 द्वारा प्राप्त जांच आख्या के आधार पर श्री अजीतनाथ जैन इण्टर कॉलेज, शेरपुर लुहारा, बागपत में श्रीमती शुचि शर्मा की सहायक अध्यापिका (सामाजिक विज्ञान) के पद पर की गयी नियुक्ति के अनुमोदन को जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत के आदेश दिनांक 01-01-2020 द्वारा निरस्त करते हुए अनियमित वेतन भुगतान की वसूली के आदेश निर्गत किये गये थे।

सम्बन्धित अध्यापिका द्वारा उक्त आदेश दिनांक 01-01-2020 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-889/2020 में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 21-01-2020 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत के आदेश दिनांक 01-01-2020 को निरस्त करते हुए याची के प्रत्यावेदन को निस्तारित करने के आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत को दिये गये। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-01-2020 के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत के पत्रांक-मा02/9965-70/2020-21, दिनांक 20-02-2021 द्वारा याची श्रीमती शुचि शर्मा के प्रत्यावेदन को अमान्य करते हुए निस्तारित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट अन्तर्गत शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बाढ़ प्रवाह को रोकने हेतु तटबन्धों का निर्माण कराने विषयक

73-श्री नरेश सैनी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत प्रवाहित शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में बाढ़ प्रवाह को रोकने हेतु सरकार तटबन्धों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। जनपद सहारनपुर में कुल 24 नदियां हैं, जिसमें 02 बड़ी नदी एवं 22 छोटी-छोटी बरसाती नदियां हैं, जो शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर जनपद में आती हैं। जनपद सहारनपुर की बेहट तहसील का क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों से लगा हुआ है। नदियों में अत्यधिक ढलान होने के कारण बरसात का पानी अधिक मात्रा में तीव्र गति से आता है, जिसमें घुमाव एवं कटाव की प्रवृत्ति रहती है। इन बरसाती नदी के क्षेत्र में जल भराव नहीं होता है। अतः तटबन्धों का निर्माण साध्य नहीं है। कटाव की प्रवृत्ति को रोकने हेतु "जनपद सहारनपुर में तहसील सदर व बेहट के अन्तर्गत 16 बरसाती नदियों के 53 ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्यों की परियोजना" लागत रु0 796.09 लाख की तैयार की गयी थी, जिस पर रु0 350.00 का धनावंटन कर दिया गया है।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट अन्तर्गत शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में वन गुर्जरों के पुनर्वास हेतु भूमि आवंटित कराने विषयक

74-श्री नरेश सैनी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट अन्तर्गत शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र से फायरिंग रेंज में निवास कर रहे वन गुर्जरों के पुनर्वास हेतु भूमि उपलब्ध कराकर सरकार आवंटित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सेना फायरिंग रेंज के इम्पेक्ट एवं सेफ्टी डिस्टेन्स एरिया में आने वाले प्रभावित वन गुर्जरों की जान-माल की सुरक्षा की जांच हेतु आर्मी, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे किया गया। सर्वे के उपरान्त सेना द्वारा फायरिंग रेंज के इम्पेक्ट एवं सेफ्टी डिस्टेन्स एरिया में प्रभावित परिवारों की संख्या व उनको दी जाने वाली भूमि की उपलब्धता तथा वन गुर्जरों के द्वारा की गयी मांग का विवरण निम्न प्रकार है :-

वन गुर्जर परिवारों की कुल संख्या-220 है। वन गुर्जर परिवारों द्वारा आवास एवं कृषि हेतु प्रति परिवार 3756 वर्गमीटर अर्थात् कुल 82.632 हे0 भूमि की मांग की जा रही है,

जबकि वन गुर्जर परिवारों के लिए आवास एवं कृषि हेतु प्रति परिवार 369.56 वर्गमीटर अर्थात् कुल 8.1305 हे0 भूमि ही उपलब्ध है।

इस प्रकार कुल उपलब्ध भूमि एवं वन गुर्जर परिवारों की मांग के अनुसार आवश्यक भूमि में अन्तर है, वन गुर्जर परिवार उपलब्ध भूमि के अनुसार विस्थापन हेतु सहमत नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि वन गुर्जर प्रतिनिधियों द्वारा फायरिंग रेंज के इम्पेक्ट एवं सेफ्टी डिस्टेन्स एरिया से बाहर आरक्षित वन क्षेत्र में ही पुनर्वासन की इच्छा व्यक्त की गई है।

प्रस्तावित भूमि पर वन गुर्जर परिवारों द्वारा सहमति न दिए जाने तथा फायरिंग रेंज के इम्पेक्ट एवं सेफ्टी डिस्टेन्स एरिया से बाहर आरक्षित वन क्षेत्र में ही पुनर्वासन की इच्छा व्यक्त किए जाने के दृष्टिगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली, बस्ती ब्लाक रामनगर के कतिपय ग्रामों से गुजरने वाली नहर पर पैदल पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में

75-संजय प्रताप जायसवाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक रामनगर, रुधौली व सल्टौआ से होकर सरयू नहर खण्ड-4 के मुख्य नहर के दोनों पार किसानों को कृषि कार्य करने हेतु लगभग 3-4 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ब्लाक रामनगर के कुतुबपुर, नरखोरिया, सिसवां, चिरई बुजुर्ग, उकड़ा, धवाय, धुनियाडीह, ब्लाक सल्टौआ के मुडबरा, मदरहना, बसडीला देउरा एवं ब्लाक रुधौली के देउरा, हनुमानगंज प्राथमिक विद्यालय के सामने, अठदेउरा कड़जहना, बेलभरिया आदि गांव से गुजरने वाली नहर पर किसानों की सुविधा हेतु नहर पर पैदल पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त ग्रामों में से ग्राम-कुतुबपुर छपिया, नरखोरिया, धुनियाडीह में 500 मी0, ग्राम चिरई बुजुर्ग में 480 मी0, ग्राम उकड़ा 200 मी0, ग्राम-धवाय में 200 मी0, ग्राम-देउरा में 200 मी0, हनुमानगंज स्कूल के पास 500 मी0, ग्राम-अठदेउरा में 400 मी0, ग्राम-कड़जहना पर 650 मी0 एवं ग्राम बेलभरिया में 600 मी0 की दूरी एवं पुल निर्मित है।

76-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[03-बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

क्षेत्रीय कार्यालय अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में लम्बित मान्यता की पत्रावलियों को मान्यता प्रदान करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

77-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 17-01-2020 का पत्र जो क्षेत्रीय कार्यालय अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर में लम्बित मान्यता की पत्रावलियों का मान्यता प्रदान करने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हाँ।

श्री राम सहाय हायर सेकेण्ड्री स्कूल थरौली, बस्ती के हाई स्कूल (6-10) की मान्यता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, किन्तु विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-11-2012 के सन्दर्भ में नवीन विद्यालयों को मान्यता सम्प्रति प्रदान नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली, तहसील महराजगंज ग्राम सभा दोस्तपुर के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज की बहुमूल्य जमीनों पर कब्जा व शासन द्वारा प्राप्त ग्राम विकास निधि के दुरुपयोग की जांच कराने विषयक

78-श्री श्रीराम सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0-751/भा0ज0पा0/वि0म0द0 2020, दिनांक 04-08-2020 व तत्सम्बन्धी अनुस्मारक-पत्र सं0-873/भा0ज0पा0/वि0म0द0 2020, दिनांक 29-09-2020 जो ग्राम सभा दोस्तपुर, तहसील महराजगंज, जनपद रायबरेली के वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज की बहुमुल्य जमीनों पर कब्जा तथा शासन द्वारा प्राप्त ग्राम विकास निधि में दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच कराने सम्बन्धी है, उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

जांच अधिकारी की आख्यानुसार शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायतों की पुष्टि नहीं हुयी है और न ही कराये गये कार्यों में अनियमितता पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा में ग्राम सभा ककरहा में भगौती लोधी के खेत से मेन रोड के बीच स्थित पुलिया का निर्माण विषयक

79-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा ककरहा में भगौती लोधी के खेत से मेन रोड तक रोड के बीच में पुलिया का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

स्थलीय निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार संबंधित मार्ग चकरोड एवं कच्चा है, जिस पर किसी भी स्थान पर जलभराव नहीं है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार चकमार्ग के दोनों ओर खेत होने के कारण प्रश्नगत मार्ग चकरोड है। अतः पुलिया का निर्माण कराया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा लौकाही में 300 मी0 इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु

80-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा लौकाही में मोलहे के घर से भगेलू राणा के घर तक दूरी लगभग 300 मीटर इण्टरलॉकिंग का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। उक्त कार्य की अनुमानित लागत रुपये 10.80 लाख है। वर्तमान में ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य तथा विद्यालय कायाकल्प आदि का कार्य पूर्ण कराने के पश्चात् अवशेष धनराशि से उक्त कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा मधवापुर में 2 कि0मी0 सड़क निर्माण हेतु

81-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा मधवापुर में तेज प्रताप की दुकान से चरन सिंह के घर तक

दूरी लगभग 2 किलोमीटर इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य क्या सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

स्थलीय सत्यापन उपरान्त उक्त कार्य की अनुमानित लागत रु0 71.05 लाख है। अतः अनुमानित लागत ग्राम पंचायत के बजट से अत्यधिक होने के कारण उक्त कार्य को कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-678/2018 धारा-420, 467, 468, 471, 120बी भादवि व 13(1डी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने विषयक

82-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-678/2018 धारा-420, 467, 468, 471, 120बी भादवि व 13 (1डी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने विषयक क्षेत्राधिकारी, रिफाइनरी जनपद मथुरा का अपर निदेशक (बेसिक शिक्षा), प्रयागराज, उ0प्र0 को प्रेषित पंत्राक सी0ओ0आर0-विवे0-08/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 के पर्याप्त समय व्यतीत होने पर भी उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित करने की अनुमति नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

कार्यालय शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, प्रयागराज के आदेश संख्या-निरीक्षण/149/2020-21, दिनांक 23-02-2021 एवं आदेश संख्या-निरीक्षण/150/2020-21, दिनांक 23-02-2021 द्वारा क्रमशः (1) श्री विनोद कुमार पुत्र श्री सुखबीर सिंह, निवासी-07 हरबंश विहार, रोहटा रोड, पोस्ट फाजलपुर, मेरठ, तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी, नन्दगाँव मथुरा एवं (2) श्री उमेश कुमार गौतम पुत्र श्री मुंशीलाल, निवासी-135 प्रगतिनगर महोलिया श्योपर, हरदोई, तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी, मांट, मथुरा के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 678/2018 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि व 13 (1डी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने विषयक

83-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-678/2018 धारा-420, 467, 468, 471, 120बी भादंवि व 13 (1डी) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने विषयक क्षेत्राधिकारी, रिफाइनरी, मथुरा का पत्रांक सी0ओ0आर0-विवे0-08/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने के बाद भी पर्याप्त समय व्यतीत होने पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित करने की अनुमति नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

सुश्री नम्रता बरौनिया, प्रभारी प्रधानाचार्या, जी0जी0आई0सी0, फरह, मथुरा जिनका मूल पद प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान) है, के नियुक्ति पदाधिकारी अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0प्र0 होने के दृष्टिगत उनके विरुद्ध थाना कोतवाली जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-678/2018 धारा-420, 467, 468, 471, 120 बी भा0द0वि0 व 13(1डी) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मा0 न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अभियोजन की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक के स्तर पर निर्णय लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जांच में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के सेक्टर-8, इंदिरानगर चौराहे से रानी लक्ष्मीबाई स्कूल जाने वाली सड़क के दोनों तरफ वाहनों से होने वाले जाम को हटाकर आवागमन को सुचारु करने सम्बन्धी

84-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सेक्टर-8, इंदिरानगर चौराहे से रानी लक्ष्मीबाई स्कूल की तरफ (सेक्टर-8 चौराहे से गोरखपुर हाउस तक) चार पहिया

एवं दो पहिया वाहन खड़े होने से वहां के जनमानस को आवागमन में अत्याधिक असुविधा तथा जाम की स्थिति बने रहने की जानकारी सरकार को है ? क्या सरकार उक्त सड़क का आवागमन सुचारु करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सेक्टर-08, इन्दिरानगर चौराहे से रानी लक्ष्मी बाई स्कूल की तरफ (सेक्टर-08 चौराहे से गोरखपुर हाउस तक) चार पहिया एवं दो पहिया वाहन खड़े होने से कभी-कभी होने वाले अत्यधिक यातायात के सम्बन्ध में जानकारी है, उक्त मार्ग पर नगर निगम द्वारा नाले का निर्माण कराया जा रहा है तथा उसी मार्ग पर सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल, आर0पी0 यादव आर्थो क्लीनिक व थोड़ी दूर पर रानी लक्ष्मीबाई स्कूल होने के कारण अभिभावकों द्वारा दो पहिया व चार पहिया वाहन खड़े कर दिये जाने के कारण भी कभी-कभी अल्प समय के लिए यातायात की कठिनाई रहती है।

उक्त मार्ग पर विगत छः माह में नो-पार्किंग के उल्लंघन में कुल 855 वाहनों के चालान किये गये हैं। उकत मार्ग पर वाहन न खड़ा किये जाने के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक भी किया गया है। उक्त स्थल पर यातायात पुलिस की ड्यूटी लगाकर वाहनों का आवागमन सुचारु रूप से कराया जा रहा है तथा भविष्य में वहां पर आवागमन बाधित न हो, इसके लिये यातायात निरीक्षक महानगर को चक्रानुक्रम करके सुचारु रूप से यातायात संचालन के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में कृषि फार्म ड्रेन, सदर ब्लाक में अधूरे नाला निर्माण की शेष किस्त को जारी करने विषयक

85-श्री राजकुमार पाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में कृषि फार्म ड्रेन जो सदर ब्लॉक में पड़ती है, की लम्बाई 5 किलोमीटर के कार्य हेतु सन् 2003 में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से आधी किस्त जारी की गयी थी, का कार्य अधूरा है ? क्या सरकार अधूरे नाला निर्माण की शेष किस्त को जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

कृषि फार्म ड्रेन की लम्बाई 4.60 किमी0 है। वर्ष 2003 में पूर्वांचल विकास निधि से किमी0 1.570 से किमी0 3.800 तक पक्का कार्य एवं किमी0 0.000 से किमी0 1.570 तथा किमी0 3.800 से किमी0 4.600 तक कच्चा कार्य कराने का प्राविधान था। उक्त कार्य हेतु पूर्वांचल विकास निधि से रु0 26.745 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी थी। प्राप्त धनराशि से किमी0 1.570 से किमी0 2.740 तक (1.170 किमी0) पक्का कार्य करा दिया गया है तथा

कच्चे कार्य कराये जाने के दृष्टिगत जनहित को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर आवश्यकतानुसार ड्रेन की सफाई विभागीय अनुरक्षण मद से करायी गयी है। जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ग्राम पंजीठ, तहसील कैराना, जनपद शामली में कृत्रिम झील में जलमग्न पटट्ों से प्रभावित सीमान्त कृषकों के भरण-पोषण की समस्या दूर करने विषयक

86-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंजीठ, तहसील कैराना, जनपद शामली के सीमान्त कृषक जिनके पट्टे कृत्रिम झील में जलमग्न हो गए हैं, को अन्यत्र पट्टे उपलब्ध करवाने अथवा उनके मौजूदा पटट्ों से कृत्रिम झील का पानी निकलवाने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्यानुसार जनपद-शामली के ग्राम पंजीठ, तहसील-कैराना में किसी भी सीमान्त कृषक के पट्टें कृत्रिम झील में जलमग्न नहीं हुए हैं

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा परसोहना बी0ए0डी0पी0 में 500 मी0 इण्टरलॉकिंग कार्य कराने विषयक

87-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा परसोहना बी0ए0डी0पी0 में ननकऊ की दुकान से शिवकुमार के घर तक मार्ग दूरी लगभग 500 मीटर का इण्टरलॉकिंग कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य का अनुमानित लागत 25 लाख रुपया है। वर्तमान समय में शासन की उच्च प्राथमिकता वाले कार्य जैसे-सामुदायिक शौचालय पंचायत भवन का निर्माण एवं आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विद्यालयों का कायाकल्प तथा हैण्डपम्प मरम्मत कराये जाने के पश्चात् अवशेष धनराशि से प्रश्नगत कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच, विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा गिरगिट्टी में 300 मी सड़क निर्माण हेतु

88-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा गिरगिट्टी में बुधराम के खेत से नदी तक सड़क मिट्टी पटान का कार्य दूरी लगभग 300 मीटर सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

श्री बुधराम के खेत से नदी तक पटान का कार्य ग्राम पंचायत के कार्य योजना में सम्मिलित है। उपरोक्त कार्य को करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के गांवों में ओलावृष्टि से फसल को नुकसान का आंकलन व भरपाई किये जाने सम्बन्धी

89-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों की रबी की फसल को माह मार्च, 2020 में हुए ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन फसलों के नुकसान का आंकलन कराया गया है तथा कुल कितने किसान ओलावृष्टि से प्रभावित हुए ? क्या सरकार प्रभावित किसानों को मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में ओलावृष्टि से प्रभावित गेहूँ, चना, सरसों, जौ, मटर, मसूर, आलू आदि की फसल का आंकलन कराया गया है। कुल 3131 कृषकों की फसल क्षति 33 प्रतिशत से अधिक पायी गयी है।

कुल रु0 20,32,924.00 की आर्थिक सहायता प्रभावित कृषकों को वितरित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

90-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

[मा0 न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में राजकीय नलकूपों की पाइप लाइनों को ठीक कराने व अधूरी पाइप लाइनों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

91-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ऐसे कितने राजकीय नलकूपों की पाइप लाइन अधूरी व टूटी-फूटी है, जिसके कारण किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार किसानों के हित में टूटी पाइप लाइनों को ठीक कराने के साथ ही अधूरी पाइप लाइनों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत 86 राजकीय नलकूपों पर पाइप लाइन आधारित जल वितरण प्रणाली के माध्यम से कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के किसी भी राजकीय नलकूप की पाइप लाइन अधूरी नहीं है।

राजकीय नलकूपों की पाइप लाइन की मरम्मत का कार्य यथावश्यकतानुसार वार्षिक अनुरक्षण मद के अन्तर्गत कराया जाता है। पाइप लाइन की वृहत् मरम्मत का कार्य प्रदेश स्तरीय परियोजनाओं के अन्तर्गत कराया जाता है। वर्तमान में पाइप लाइन की वृहद् मरम्मत के कार्यों हेतु प्रदेश में कोई परियोजना प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में सितम्बर, 2020 में लगातार बारिश से धान/गन्ना की फसल नष्ट हो जाने से किसानों को मुआवजा दिलाये जाने विषयक

92-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में माह सितम्बर, 2020 में लगातार एक सप्ताह आकस्मिक बारिश होने से धान/गन्ना की फसल नष्ट हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त से पीड़ित किसानों को चिन्हित कर नुकसान का आंकलन कर उनको मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गोपालपुर में माह सितम्बर, 2020 में लगातार एक सप्ताह आकस्मिक वर्षा होने से विभिन्न क्षेत्रों में धान व गन्ना की फसल को 10-12 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 32.7/2014 एन0डी0एम0-1, दिनांक 08-04-2015 द्वारा निर्धारित मानकों एवं दरों में फसलों की 33 प्रतिशत या उससे अधिक की

क्षति होने पर ही कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के अन्तर्गत राहत सहायता वितरित किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में धान/गन्ना की फसल का 10-12 प्रतिशत तक का नुकसान होने के कारण उक्त प्राविधान के आलोक में राहत सहायता वितरित किये जाने का अवसर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0ख0 बिलरियागंज, ग्राम सभा लंगड़पुर में पिच रोड मार्ग का नव निर्माण कराने विषयक

93-श्री नफीस अहमद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज के ग्राम सभा लंगड़पुर में पिच रोड मार्ग दूरी 300 मीटर विगत 5 वर्षों से जर्जर है, जिससे उक्त ग्राम सभा व आस-पास के लोगों के आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पिच रोड का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

ग्राम सभा-लंगड़पुर में पिच रोड मार्ग दूरी 300 मी0 जो पत्थर, गिट्टी युक्त मार्ग है, का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा इस पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 2011 जनगणना की एस0ई0सी0सी0 सूची में छूटे पात्र नागरिकों हेतु धनावंटन करते हुये इनके आवासों का निर्माण कार्य कराने विषयक

94-श्री मनीष असीजा-

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 2011 जनगणना की एस0ई0सी0सी0 सूची में छूटे पात्र नागरिकों की अतिरिक्त पात्रता सूची बनाई गयी है ? यदि हां, तो ब्लाकवार इनकी संख्या कितनी है ? क्या सरकार धनावंटन करते हुये इनके आवासों का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

जी हां।

विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	लाभार्थियों की संख्या (पूर्ण रजिस्ट्रेशन)	वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्राप्त लक्ष्य	स्वीकृत आवासों की संख्या
1	अराँव	3329	395	387
2	एका	6880	654	639
3	फिरोजाबाद	1919	258	246
4	जसराना	2435	418	405
5	हाथवन्त	828	245	244
6	मदनपुर	1033	218	217
7	नारखी	466	192	191
8	शिकोहाबाद	1630	333	325
9	टूण्डला	644	196	194
योगः		19164	2909	2848

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के आवास निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा 2909 का लक्ष्य माह जनवरी में प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष 2848 लाभार्थियों का चयन एवं स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2019-20 में दिनांक 10.11.2020 तक अग्निकाण्ड की घटित घटनायें एवं पीड़ित परिवारों की मदद हेतु किये गये कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखने की मांग

95-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2019-20 में दिनांक 10-11-2020 तक कुल कितने स्थानों पर अग्निकाण्ड की घटनायें घटित हुयी हैं ? क्या सरकार उक्त अग्निकाण्डों से पीड़ित परिवारों की मदद के लिये किये गये कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद फिरोजाबाद के शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2019-20 में दिनांक 10-11-2020 तक दैवीय आपदा के अन्तर्गत अग्निकाण्ड की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरी अग्निकाण्डों में गरीबों/पीड़ितों के पुनर्वास हेतु योजना बनाये जाने विषयक

96-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अग्निकाण्डों में सब कुछ गवां देने वाले गरीबों/पीडितों के पुनर्वास के लिए सहायता राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त गरीब/पीड़ित नागरिकों के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में आगजनी की घटनाओं में जनहानि, पशुहानि, मकान क्षति आदि होने पर पीड़ितों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08-04-2015 द्वारा निर्धारित मानकों/ दरों के अनुसार राहत धनराशि प्रदान की जाती है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 08-04-2015 में मुख्यतः निम्नानुसार राहत सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है :-

क्र0	मद	धनराशि (रु0 में)
1	जनहानि	4,00,000/-
2	किसी अंग अथवा आखों के बेकार हो जाने पर	40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तक शारीरिक अक्षमता होने पर रु0 59,100/- 60 प्रतिशत तक शारीरिक अक्षमता होने पर रु0 2,00,000/-
3	गम्भीर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर	रु0 12,700/- प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती होने पर रु0 4,300/- प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से कम समय तक
4	मकान क्षति	अत्यधिक अथवा पूर्णतः पक्का/कच्चा मकान क्षतिग्रस्त होने पर रु0 95,100/- प्रति मकान मैदानी क्षेत्रों में तथा रु0 1,01,900/- प्रति मकान पहाड़ी क्षेत्रों में। आंशिक रूप से पक्का एवं कच्चा मकान क्षतिग्रस्त होने पर रु0 5,200/- तथा 3,200/- क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी 4,100/-
5	प्राकृतिक आपदा के कारण मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने पर	रु0 1,800 प्रति परिवार कपड़ों के नुकसान पर रु0 2,000/- प्रति परिवार बर्तन/घरेलू सामग्री के नष्ट होने पर।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर में मनरेगा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष भुगतान के सम्बन्ध में

97-श्री संजय गर्ग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितनी धनराशि आवंटित हुयी एवं आवंटित धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि मनरेगा मजदूरों को दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 तक कराये गये कार्य हेतु भुगतान करी गयी है तथा कितनी अवशेष है ? क्या सरकार उक्त अवधि की मजदूरों की अवशेष धनराशि का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

जनपद सहारनपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में नरेगा एमआईएस के अनुसार रुपये 2846.19 लाख धनराशि आवंटित हुई है। नरेगा एमआईएस के अनुसार आवंटित धनराशि के सापेक्ष रुपये 1816.5 लाख की धनराशि मनरेगा मजदूरों को दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 तक कराये गये कार्यों हेतु भुगतान की गई है। कतिपय श्रमिकों के खाते गलत या निष्क्रिय व आधार आधारित न होने के कारण 2.55 लाख रुपये भुगतान हेतु अवशेष है।

जी हाँ।

जिन श्रमिकों के खाते गलत या निष्क्रिय हैं, उन श्रमिकों से ठीक/सक्रिय खाते प्राप्त कर आधार आधारित कराकर भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में मनरेगा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष मजदूरों को भुगतान की धनराशि के सम्बन्ध में

98-श्री संजय गर्ग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितनी धनराशि आवंटित हुई एवं आवंटित धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि मनरेगा मजदूरों को दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 तक कराये गये कार्य हेतु भुगतान करी गयी है तथा कितनी अवशेष है ? क्या सरकार उक्त अवधि की मजदूरों की अवशेष धनराशि का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

जनपद चित्रकूट में मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में नरेगा एमआईएस के अनुसार रुपये 5885.14 लाख धनराशि आवंटित हुई है। नरेगा एमआईएस के अनुसार

आवंटित धनराशि के सापेक्ष रुपये 3914.14 लाख की धनराशि मनरेगा मजदूरों को दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 तक कराये गये कार्यों हेतु भुगतान की गई है। कतिपय श्रमिकों के खाते गलत या निष्क्रिय व आधार आधारित न होने के कारण 99,575.00 रुपये भुगतान हेतु अवशेष हैं।

जी हाँ।

जिन श्रमिकों के खाते गलत या निष्क्रिय हैं, उन श्रमिकों से ठीक/सक्रिय खाते प्राप्त कर आधार आधारित कराकर भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, ब्लाक खुदागंज, ग्राम नवादा दरोबस्त में महाविद्यालय निर्माण में अनियमितता की जांच कराने विषयक

99-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहीद ठाकुर रोशन सिंह के ग्राम नवादा दरोबस्त, ब्लॉक खुदागंज, जनपद शाहजहांपुर में महाविद्यालय के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाला सरिया, सीमेन्ट मानक के अनुसार नहीं लग रहा है ? क्या सरकार उपरोक्त निर्माण कार्य की कमेटी गठित करके जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जनपद शाहजहांपुर में निर्माणाधीन ठाकुर रोशन सिंह राजकीय महाविद्यालय, कटरा, खुदागंज के निर्माण कार्य में मानक के अनुसार सरिया, सीमेण्ट का प्रयोग किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा गठित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स समिति की रिपोर्ट में प्रश्नगत महाविद्यालय के निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गयी है।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रसोइयों की तैनाती व उनका वेतन/मानदेय के बकाया राशि के भुगतान विषयक

100-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में कितने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तथा उन विद्यालयों में कितनी रसोइयों की तैनाती की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त रसोइयों का जनवरी, 2020 तक का वेतन/मानदेय का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का बकाया वेतन का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में कुल 07 विकास खण्ड (कटरा खुदागंज, तिलहर, जैतीपुर, मदनापुर, जलालाबाद, मिर्जापुर तथा कलान) आते हैं, जिसमें कुल 1166 प्राथमिक विद्यालय एवं 474 उच्च प्राथमिक विद्यालय मिड-डे मील योजना से आच्छादित हैं। इन विद्यालयों में कुल 4120 रसोइया कार्यरत हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा गिरगिट्टी में खड़ंजा निर्माण विषयक

101-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा गिरगिट्टी में गिरधारी के घर से मथुरा के घर तक लम्बाई लगभग 100 मीटर खड़न्जा का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

ग्राम पंचायत गिरगिट्टी में गिरधारी के घर से मथुरा के घर तक दूरी लगभग 100 मीटर खड़न्जा का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में स्थलीय सत्यापन में कार्य का नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्राम पंचायत में मथुरा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, जिससे कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा बोटानिया गोपिया में सड़क इण्टरलॉकिंग का कार्य विषयक

102-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा बोटानिया गोपिया में साधूराम के घर से कृष्ण कुमार के घर तक लम्बाई लगभग 100 मीटर तथा इन्द्रसेन के घर से लल्लूराम के घर तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

ग्राम पंचायत गोपिया के मजरा बोटानिया में साधूराम के घर से कृष्ण कुमार के घर तक दूरी 100 मीटर तथा इन्द्रसेन के घर से लल्लूराम के घर तथा इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य की लागत अधिक है। ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य तथा विद्यालयों में कायाकल्प का कार्य कराया जा रहा है। अतः ग्राम पंचायत की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य पर अनुमानित व्यय अधिक होने के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा भगाड़िया के भगाड़िया इंद्रानगर कालोनी में इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण विषयक

103-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा भगाड़िया के भगाड़िया इंद्रानगर कालोनी में माखन के घर से अरुण के घर तक दूरी लगभग 600 मीटर इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य क्या सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

कार्य की अनुमानित लागत रु0 09.50 लाख है। उक्त कार्य को ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में सम्मिलित कराते हुए करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में

104-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना कब और कहां से शुरू की गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि उस समय इस परियोजना की लागत और मुख्य उद्देश्य क्या था ? क्या उक्त परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो अब तक इस परियोजना पर कितना धन व्यय हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त परियोजना को पूर्ण कराने के लिये कोई समय-सीमा तय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना वर्ष 1978 में जनपद-बहराइच से शुरू की गई।

उस समय परियोजना की लागत रु0 78.66 करोड़ थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जनपद-गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं बहराइच में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। परियोजना अभी निर्माणाधीन है।

परियोजना का कार्य अभी प्रगति में है। इस परियोजना पर अब तक रु0 9153.54 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

परियोजना को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा 31 मार्च, 2021 निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के न्यायालयों के अधिवक्ताओं को तत्काल मानदेय जारी करने विषयक

105-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ज0व्य0/विविध/2020-21 दिनांक 22-04-2020 जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं को मानदेय जारी किये जाने के विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों (राजकीय एडेड एवं स्ववित्तपोषित) के विभिन्न पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के परीक्षाफल, मार्कशीट अथवा प्रमाण पत्र को जारी न करने हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

106-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों (राजकीय एडेड एवं स्ववित्तपोषित) के विभिन्न पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले कितने छात्र-छात्राओं के वर्ष 2016-17, 2017-18 2018-19 2019-20 एवं 2020-21 परीक्षाफल, मार्कशीट अथवा प्रमाण पत्र जारी नहीं हुये हैं ? क्या सरकार अवगत है कि उक्त के कारण इन प्रभावित छात्र-छात्राओं की आगामी शिक्षा, नौकरी अथवा अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ बाधित हो गयी हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार रुके हुये परीक्षाफल, मार्कशीट अथवा प्रमाण-पत्र को जारी कराते हुये बिलम्ब के लिए जिम्मेवार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय (राजकीय एडेड एवं स्ववित्तपोषित) के विभिन्न पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 2019-20 एवं 2020-21 सत्र के परीक्षाफल, मार्कशीट अथवा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :-

जनपद-फिरोजाबाद

क्र0	वर्ष	परीक्षा परिणाम की स्थिति	अंकतालिकाओं की स्थिति	प्रमाण-पत्र
1	2016-17	जारी	अंकतालिकायें महाविद्यालय को भेज दी गयी हैं।	अभ्यर्थी के आनलाइन आवेदन पर उसके घर के पते पर भेजी जाती हैं।
2	2017-18	जारी	तदैव	तदैव
3	2018-19	जारी	तदैव	तदैव
4	2019-20	जारी	अंकतालिकायें महाविद्यालय को भेजी जा रही हैं।	तदैव
5	2020-21	परीक्षा होनी शेष है।	परीक्षा होनी शेष है।	परीक्षा होनी शेष है।

यदि नामांकन या अन्य कारण से मूल अंकतालिका जारी नहीं होती है तो भी Statement of Marks, ऑनलाइन विश्वविद्यालय की Website-www.dbrau.org.in पर प्रदर्शित है। ऐसे समस्त सम्बन्धित परीक्षार्थियों से प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) या अन्य अभिलेख मंगाकर परीक्षा परिणाम सतत् पूरा कराया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में खान-पान में हो रहे भ्रष्टाचार विषयक

107-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-18150196106992 जो जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के खान-पान में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री कार्यालय में 15-10-19 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि उपरोक्त पत्र की जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर से प्रश्नकर्ता/

शिकायतकर्ता से कोई साक्ष्य लिये बिना दिनांक 25-10-19 को जांच कर ली है ? क्या सरकार उपरोक्त आई0जी0आर0एस0 संख्या की जांच किसी अन्य विभाग के उच्च अधिकारी से कराकर जांच कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले बी0एस0ए0, शाहजहांपुर के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हाँ।

राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 28-09-2019 द्वारा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली से प्रकरण की जांच करते हुये आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। तत्क्रम में सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली द्वारा अपने पत्र दिनांक 31-10-2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा पत्र दिनांक 04-10-2019 एवं 18-10-2019 द्वारा प्रश्नकर्ता/शिकायतकर्ता तथा उनके प्रतिनिधि से साक्ष्य/जांच में सहयोग करने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु प्रश्नकर्ता/शिकायतकर्ता एवं उनके प्रतिनिधि द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण जांच की कार्यवाही अद्यतन लम्बित है।

उक्तवत्।

जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में कस्तूरबा विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में

108-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जनपद शाहजहांपुर में कितने कस्तूरबा विद्यालय किस संस्था द्वारा किस तिथि से संचालित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि विद्यालयों को दिनांक 01-04-17 से 01-02-19 तक कितनी धनराशि विद्यालय को तथा कार्य करने वाली संस्था को कब वितरित की गई ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त विद्यालयों में खान-पान की सुविधा अत्यधिक खराब है, मेन्यू के अनुसार बच्चों को खाना तथा नाश्ता नहीं मिल रहा है तथा विद्यालय का आर0ओ0 खराब है, जिससे बच्चों को अशुद्ध पानी मिल रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जनपद शाहजहांपुर में स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :-

1- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कलान (संस्था काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान, बदायूं-वर्ष 2008 से)

2- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खुटार (संस्था सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, हरदोई-वर्ष 2008 से)

3- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, निगोही (संस्था स्वजन शिक्षण संस्थान, लखनऊ-वर्ष 2008 से)

4- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जैतीपुर (संस्था दीपजन कल्याण समिति बरेली-वर्ष 2008 से)

जनपद शाहजहांपुर में स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में दिनांक 01-04-2017 से 01-02-2019 तक संचालन करने वाली संस्था का नाम, संचालन वर्ष, अवमुक्त धनराशि की तिथि एवं अवमुक्त धनाशि का विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	के0जी0बी0वी0 का नाम	संस्था का नाम	अवमुक्त धनराशि की	अवमुक्त धनराशि
			तिथि	(लाख)
1	कलान	काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान, बदायूं	11-09-2017 31-01-2018 31-03-2018 08-10-2018	17.756 18.716 4.275 20.8168
2	खुटार	सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, हरदोई	11-09-2017 31-01-2018 31-03-2018 08-10-2018	17.756 18.716 5.628 20.8168
3	निगोहा	स्वजन शिक्षण संस्थान, लखनऊ	11-09-2017 31-01-2018 08-10-2018	17.756 18.716 20.10406
4	जैतीपुर	दीपजन कल्याण समिति, बरेली	11-09-2017 31-01-2018 31-03-2018 08-10-2018	17.756 18.716 5.108 20.8168

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, तृतीय मण्डल, बरेली की जांच आख्या दिनांक 10-07-2019 में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जैतीपुर में मेन्यू के अनुसार भोजन, नाश्ता न दिये जाने, आर0ओ0 खराब होने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध न होने का उल्लेख है।

जी हां।

दो संस्थाओं के विरुद्ध निम्नवत् कार्यवाही की गयी है:-

1- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कलान-

नवीन बेडिंग क्रय की गयी है, मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जा रहा है। आर0ओ0 क्रियाशील है। उक्त विद्यालय स्वंयसेवी संस्था काशी विकास शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित है। संचालन करने वाली संस्था काशी विकास शिक्षा संस्थान को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 03-02-2020 द्वारा नोटिस जारी की गयी। इसके उपरान्त पत्र दिनांक 13-02-2020 द्वारा संस्था को भविष्य के लिए कठोर चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया।

2- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जैतीपुर-

नवीन बेडिंग क्रय की गयी है, आर0ओ0 क्रियाशील है मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जा रहा है। लेखाकार श्री राजू कश्यप की सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) बरेली मण्डल की संस्तुति पर संविदा समाप्त कर पद से हटा दिया गया एवं विद्यालय की संचालक संस्था दीपजन कल्याण समिति को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 13-11-2019 के द्वारा विद्यालय संचालन से पृथक कर दिया गया है।

शेष दो संस्थाओं के विरुद्ध जांच आख्या प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में तालाबों की सफाई व सौंदर्यीकरण के सम्बन्ध में

109-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में सभी ग्राम पंचायतो में तालाबों की सफाई नहीं होने के कारण तालाबों का कीचड़ व पानी गलियों में भर जाने से गन्दगी के कारण संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो उक्त तालाबों का पानी निकासी कराकर सफाई व सौंदर्यीकरण करवाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

जी हाँ।

जी हाँ।

लघु सिंचाई विभाग, बागपत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य भू-जल संरक्षण मिशन योजना के अन्तर्गत जनपद के समस्त 06 विकास खण्डों के 01 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु रुपये 29.57 करोड़ की कार्य योजना मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को प्रेषित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत अग्निशमन केन्द्र रुधौली व भानपुर का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

110-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में स्वीकृत अग्निशमन केन्द्र रुधौली व भानपुर का निर्माण कार्य जो 1 वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था, का 25-30 प्रतिशत ही कार्य पूर्ण हुआ है एवं शेष निर्माण कार्य बजट के अभाव में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अग्निशमन केन्द्र के आगणन के सापेक्ष बजट उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से जनपद बस्ती के अग्निशमन केन्द्र रुधौली (बारीजोत) एवं भानपुर (जोगिया छपिया) के आवासीय/अनावासीय भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु अब तक रुपये पांच-पांच करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर अवशेष धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के तहसील भानपुर व रुधौली में अग्निशमन गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक।

111-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 14-04-2020 का पत्र जो तहसील भानपुर व तहसील रुधौली में अग्निशमन गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

तहसील भानपुर में अग्निशमन कार्य के लिये एक वाटर टेण्डर टाइप बी का फैब्रीकेशन कराया जा रहा है एवं तहसील रुधौली के लिये सीजनल ड्यूटी में अग्निशमन कार्य हेतु एक वाटर टेण्डर लगाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा सर्राकला में 250 मी0 खड़न्जा कार्य कराने विषयक

112-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा सर्राकला 2 नं0 पुरवा मजरा में जयराम पंच के घर से

प्राइमरी स्कूल तक दूरी लगभग 250 मीटर खड़न्जा का कार्य क्या सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उक्त कार्य की लागत लगभग रु 06.00 लाख है, जबकि ग्राम पंचायत निधि में रु0 2.10 लाख शेष है जिससे ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य, विद्यालयों का कायाकल्प कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत की कुल धनराशि के सापेक्ष उक्त कार्य पर अनुमानित व्यय अधिक होने के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा सु0 के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगापुर बेलघाट में सड़क निर्माण कराने विषयक

113-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र-282, बलहा सु0 के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगापुर बेलघाट अशोक के घर से डा0 कौशल के घर तक दूरी लगभग 350 मीटर सड़क का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

उक्त कार्य की अनुमानित लागत रु0 14.00 लाख है। जिसे उक्त कार्य को ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में सम्मिलित कराते हुए धनराशि की उपलब्धता पर करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा गिरगिट्टी में 100 मी0 नाली का निर्माण हेतु

114-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा गिरगिट्टी में जानकी के घर से मथुरा के घर तक दूरी लगभग 100 मीटर तक नाली का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

ग्राम पंचायत गिरगिट्टी में स्थलीय सत्यापन में उक्त कार्य का नाम स्पष्ट नहीं है। ग्राम पंचायत में मथुरा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अतः कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच, तहसील पयागपुर के भवन निर्माण में विलम्ब की जांच विषयक

115-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच, तहसील पयागपुर के भवन निर्माण का कार्य कब और कितने लागत से प्रारम्भ कराया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त भवन के निर्माण में लापरवाही के कारण विलम्ब होने से निर्माण की लागत बढ़ गयी है ? यदि हां, तो उक्त भवन की लागत कितनी बढ़ गयी है और इसका उत्तरदायी कौन है ? क्या सरकार उक्त भवन निर्माण में विलम्ब होने एवं लागत बढ़ जाने के दोषियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करने के साथ भवन निर्माण कराये जाने का निर्देश समय-सीमा तय करते हुए देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बहराइच की नवसृजित तहसील पयागपुर के अनावासीय भवन का निर्माण कार्य दिनांक 30-11-2016 लागत रु0 340.26 लाख तथा आवासीय भवन का निर्माण कार्य दिनांक 18-12-2016 को लागत रु0 264.23 लाख से प्रारम्भ कराया गया है।

जी नहीं।

उक्त प्रायोजना की मूल लागत वर्ष 2011 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर आधारित थी, निर्माण कार्य के दौरान श्रमिक एवं सामग्री की दरों में वृद्धि मिटट्री भराई, जी0एस0टी0 का नवीन प्राविधान इत्यादि कारणों से पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसमें अनावासीय भवन के निर्माण में रु0 546.07 लाख एवं आवासीय भवन के निर्माण में रु0 376.75 लाख की वृद्धि हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद ग्राम विलारा में शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी के निर्माण से सम्बन्धित

116-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सादाबाद के ग्राम विलारा में ग्रामवासियों को शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ। जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद के ग्राम विलारा को वर्ष 2015-16 में पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त पेयजल योजना चालू

हालत में है एवं "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत उक्त योजना में रेट्रोफिटिंग का कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस, ब्लाक सादाबाद के ग्राम सरौठ में शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी के निर्माण सम्बन्धित

117-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लॉक सादाबाद के ग्राम सरौठ में ग्रामवासियों को शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के कस्बा सादाबाद से आगरा रोड पर कुगटई गांव के निकट पेट्रोल एवं डीजल से भरे टैंकरों के खड़ा होने से सम्बन्धित

118-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद हाथरस के कस्बा सादाबाद से आगरा रोड पर गाँव कुगटई के नजदीक पेट्रोल एवं डीजल से भरे हुए सैकड़ों टैंकर प्रतिदिन आकर खड़े होते हैं जोकि क्षेत्र के लिए जानलेवा एवं विस्फोटक बने हुए हैं ? यदि हाँ, क्या सरकार बतायेगी कि उक्त हेतु प्रशासनिक अनुमति प्रदान की गई है ? यदि नहीं तो टैंकर को अनाधिकृत रूप से खड़ा कराने वाले दोषियों के खिलाफ कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठला

उपरोक्तानुसार।

थाना सादाबाद क्षेत्र आगरा रोड पर ग्राम कुगटई के पास वर्तमान में पेट्रोल व डीजल से भरे टैंकर नहीं खड़े होते हैं।

सिंचाई खण्ड निचली माँट शाखा गंग नहर मथुरा के जुगसना राजवाहा में टेल तक पानी पहुँचाने विषयक

119–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड निचली माँट शाखा गंग नहर मथुरा के अन्तर्गत जुगसना राजवाहा में टेल तक पानी सरकार पहुँचायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह–

जी हाँ।

मांट शाखा के कि0मी0 126.468 की बायीं पटरी से निकले रजबहा जुगसना की कुल लम्बाई 27.800 कि0मी0 तथा डिस्चार्ज 97 क्यूसेक है। जुगसना रजवहा कि0मी0 4.800 से 27.800 तक जनपद हाथरस में पड़ता है। रबी 1428 फसली में रजवहा जुगसना की दिनांक 15-12-2020 एवं 05-01-2021 को टेल फीड कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली, ग्राम दाहा ब्लॉक बिनौली में स्थित राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज को अपग्रेड कर राजकीय डिग्री कॉलेज बनाये जाने विषयक

120–श्री सहेन्द्र सिंह चौहान–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम दाहा, ब्लॉक बिनौली में छात्राओं हेतु डिग्री कॉलेज न होने से इण्टर के बाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें गाँव से दूर कस्बा बड़ौत जाना पड़ता है ? यदि हां, तो छात्राओं की उपरोक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम दाहा ब्लॉक बिनौली में स्थापित राजकीय इण्टर कॉलेज को अपग्रेड कर राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज बनवाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम दाहा, ब्लॉक बिनौली में पर्याप्त महाविद्यालय हैं, जहां छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं।

जी नहीं।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में 01 राजकीय महाविद्यालय संचालित है। ब्लॉक बिनौली के ग्राम दाहा क्षेत्र में 03 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र की छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। उक्त के अतिरिक्त मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बागपत में 01 राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।

वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संशाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत ग्राम दाहा, ब्लॉक बिनौली में स्थापित राजकीय इण्टर कालेज को अपग्रेड कर राजकीय कन्या डिग्री कालेज बनाए जाने का अवसर नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के ग्राम सभा अकबरपुर में सरकारी तालाब व पोखरों को कब्जामुक्त कराकर स्थापित कराने विषयक

121-अमन मणि त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम सभा अकबरपुर में कतिपय सरकारी तालाबों व पोखरों पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाबों व पोखरों को चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराकर मूल स्वरूप में स्थापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रकरण में जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार स्थिति निम्नवत् है :-

1- ग्राम सभा अकबरपुर में राजस्व ग्राम अकबरपुर, देवरिया अबूसईद व चकगुलाल सम्मिलित है।

2- ग्राम अकबरपुर में आ0नं0 305 मि0/0.047 हे0, 477/0.038 हे0, 668 मि0/0.051 हे0 व आ0नं0 753/0.037 हे0 पोखरी जो0 च0 आकार-पत्र 41,45 वर्तमान अभिलेख में अंकित है।

3- ग्राम अकबरपुर में आ0नं0 259 मि0/0.058 हे0 आ0नं0 713/0.084 हे0 अभिलेख में गाड़ा व आ0नं0 614/0.258 हे0 सार्वजनिक जलाशय अंकित है।

4- ग्राम सभा अकबरपुर में सम्मिलित राजस्व ग्राम चकगुलाल में कोई पोखरी या तालाब खाते की भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं है।

5- ग्राम देवरिया अबूसईद में स्थित आ0सं0 101 मि0/0.209 हे0 पोखरी व आ0नं0 135 मि0/0.437 हे0 पोखरी खाते में अंकित है।

ग्राम सभा अकबरपुर में पूर्व में तालाब/पोखरी पर अवैध कब्जे के बाबत बेदखली वाद योजित किये गये थे, जिनमें बेदखली आदेश पारित हो चुका है, अवैध अतिक्रमणियों को स्थलीय बेदखली हेतु 10 मार्च, 2021 तक का समय दिया गया है। यदि उनके द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में स्वयं अवैध कब्जा नहीं हटाया जाता है, तो स्थलीय बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त ग्राम सभा अकबरपुर में तालाब व पोखरी की भूमि पर हुये अवैध कब्जे के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध योजित 12 बेदखली वाद विचाराधीन हैं।

वाद निस्तारण के उपरान्त स्थलीय बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये सरकारी तालाब व पोखरों को कब्जा मुक्त कराकर मूल स्वरूप में स्थापित किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की तहसील भानपुर के अन्तर्गत ग्राम अमरौली जनूबी के 300 किसानों की जमीन चकबन्दी विभाग द्वारा वन विभाग के नाम दर्ज जमीन को वापस कराने के सम्बन्ध में

122-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की तहसील भानपुर के अन्तर्गत ग्राम अमरौली जनूबी के 300 किसानों की लगभग 1000 बीघा जमीन चकबन्दी विभाग द्वारा वन विभाग के नाम कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार 300 किसानों की पैतृक एवं बैनामे की जमीन जो चकबन्दी विभाग द्वारा वन विभाग को दर्ज कर दिया गया उसे वापस कराकर किसानों के नाम दर्ज करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। ग्राम अमरौली जनूबी के फसली वर्ष 1323 के बन्दोबस्त में जंगल के मद में दर्ज गाटा संख्या-71, 386, 517, 519 क्षेत्रफल 496-10-10 धुर (496 बीघा 10 बिस्वा 10 धुर) को आधार वर्ष खतौनी में 183 कृषकों के नाम फर्जी दर्ज पाया गया, जिसे उप संचालक चकबन्दी के आदेश दिनांक 04-10-2006 द्वारा नियमानुसार पुनः जंगल के खाते में यथावत दर्ज कर दिया गया।

जी नहीं।

ग्राम अमरौली जनूबी के फसली वर्ष 1323 के बन्दोबस्त में जंगल के मद में दर्ज गाटा संख्या-71, 386, 517, 519 क्षेत्रफल 496-10-10 धुर (496 बीघा 10 बिस्वा 10 धुर) को ग्राम समाज के खातों में यथावत् दर्ज करने हेतु उप संचालक चकबन्दी, बस्ती द्वारा दिनांक 04-10-2006 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-48990/2007 राम मिलन व अन्य बनाम उप संचालक चकबन्दी तथा रिट याचिका संख्या-17994/2007 व्रिकान्त संजय सिंह बनाम उप संचालक चकबन्दी में पारित क्रमशः आदेश दिनांक 09-10-2007 व 05-04-2007 के अनुपालन में उप संचालक चकबन्दी के आदेश दिनांक 11-03-2008, 16-01-2009 एवं 29-01-2020 द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापना प्रार्थना-पत्रों को निरस्त कर दिया गया।

सरयू नहर परियोजना पर 2013 से केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा दिये धन का पूर्ण विवरण पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में

123-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

क्या जल शक्ति मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर परियोजना सरयू नदी से निकलकर पूर्वांचल के श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर गोण्डा, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर आदि जनपदों से होकर गुजर रही परियोजना के पूर्ण होने की समयावधि निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस योजना पर 2013 से 2020 तक कितना धन केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दिया जा चुका है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

परियोजना के पूर्ण होने की समयावधि 31 मार्च, 2021 निर्धारित है।

इस परियोजना पर वर्ष 2013 से वर्ष 2020 तक केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये धन का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि करोड़ रु0 में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	केन्द्र द्वारा	राज्य द्वारा	योग
1	2012-13	67.98	156.49	224.47
2	2013-14	380.75	118.95	499.70
3	2014-15	210.85	412.15	623.00
4	2015-2016	500.00	334.00	834.00
5	2016-17	62.00	238.00	300.00
6	2017-18	-	1000.00	1000.00
7	2018-19	305.00	755.00	1060.00
8	2019-20	358.30	1135.88	1494.18
9	2020-21	358.30	466.95	805.25

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम पंचायत सिंहनगर में भरुही तालाब से खड़न्जा का निर्माण कराने विषयक

124-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महराज सिंहनगर में भरुही तालाब से छोटे लाल यादव के घर तक खड़न्जा मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

ग्राम पंचायत निधि में रु0 1.10 लाख मात्र है जिससे ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय एवं विद्यालयों के कायाकल्प का कार्य कराया जा रहा है। अस्तु ग्राम पंचायत की कुल धनराशि के सापेक्ष उक्त कार्य पर अनुमानित व्यय अधिक होने के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा सेमरी घटही में इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराने विषयक

125-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा सेमरी घटही में याशीन के घर से बाजार तक दूरी लगभग 400 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उक्त कार्य की अनुमानित लागत रु0 10 लाख है। उक्त कार्य की लागत ग्राम पंचायत के बजट से अधिक होने के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

126-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मा0 आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बागपत विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम किरठल में स्थापित आर्य महाविद्यालय किरठल का जीर्णोद्धार (धर्मार्थ योजनान्तर्गत) कराने के सम्बन्ध में

127-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम किरठल मे सम्पूर्णानन्द संस्कृत महाविद्यालय से सम्बन्धित आर्य महाविद्यालय किरठल का शैक्षणिक भवन जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त गुरुकुल का जीर्णोद्धार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

आंशिक रूप से जीर्ण-शीर्ण है।

अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के भवन निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु शासन/विभाग द्वारा कोई योजना सम्प्रति संचालित नहीं है। आर्य संस्कृत महाविद्यालय किरठल जनपद बागपत प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित अनुदानित संस्था है, जिसके भवन का अनुरक्षण/जीर्णोद्धार प्रबन्ध समिति द्वारा उनके निजी स्रोतों से किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ब्लाक बिनौली का विभाजन कर नया ब्लाक बनाने के विषय में

128-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ब्लाक बिनौली की 53 ग्राम पंचायतें एवं 64 ग्रामों में कतिपय ग्राम ब्लाक मुख्यालय से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण ग्रामीणों को अपने कार्य कराने हेतु ब्लाक मुख्यालय जाने के लिए अधिक दूर से आना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्लाक को दो भागों में विभाजित करके कस्बा दोघट, दाहा या पुसार में ब्लाक मुख्यालय बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

विकास खण्डों के सृजन/गठन के उपरान्त विकास खण्डों के संचालन हेतु मूलभूत/ अपरिहार्य अवस्थापना सुविधाओं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा उनको स्थापित कर क्रियाशील बनाने में आ रही व्यावहारिक कठिनाई एवं वर्तमान में खण्ड विकास अधिकारियों की भारी कमी के चलते नवसृजित विकास खण्डों में अलग से खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती एवं आवासीय/ अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वांछित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न होने तथा वर्तमान में सड़क यातायात एवं संचार के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण प्रशासनिक इकाइयों तथा पहले की तुलना में अधिक आबादी एवं दूर के क्षेत्रों तक सुगमता से प्रशासनिक सेवायें उपलब्ध कराया जाना सम्भव हुआ है, के दृष्टिगत जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में नये विकास खण्ड का सृजन किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में खान-पान व अन्य व्यवस्था की जांच कराने विषयक

129-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-06-19 जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तिलहर नगर, तिलहर ग्रामीण, भीरानपुर कटरा, जैतीपुर, खुदागंज, मदनापुर, जलालाबाद, मिर्जापुर, परौर, कलान में खान-पान व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायत के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हाँ।

राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 21 जून, 2019 द्वारा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली मण्डल को स्थलीय निरीक्षण कर जांच हेतु निर्देशित किया गया। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली मण्डल द्वारा दिनांक 10-07-2019 को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नगर तिलहर, तिलहर ग्रामीण, जैतीपुर, दिनांक 17-07-2019 को कलान एवं कटरा खुदागंज की जांच की गयी एवं दिनांक 21-02-2020 को मिर्जापुर का निरीक्षण किया गया। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तृतीय मण्डल, बरेली द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में उक्त सभी विद्यालयों के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत् है :-

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तिलहर नगर-विद्यालय में मेन्यू के अनुसार भोजन न मिलने के कारण विद्यालय की वार्डेन/लेखाकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न करने हेतु चेतावनी दी गयी। विद्यालय अभिलेखों के अव्यवस्थित रख-रखाव हेतु विद्यालय के लेखाकार को सचेत किया गया तथा भविष्य में पुनरावृत्ति होने पर संविदा समाप्त करने की चेतावनी दी गयी। छात्राओं को मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जा रहा है, आर0ओ0 मशीन ठीक करा दी गयी है एवं नवीन बेडिंग का क्रय किया गया है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका तिलहर ग्रामीण-विद्यालय की अंशकालिक शिक्षिका श्रीमती स्वालेहा के दिनांक 01-04-2019 से लगातार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण सम्बन्धित का सत्र, 2019-20 में संविदा नवीनीकरण नहीं किया गया। विद्यालय में मेन्यू के अनुसार भोजन न मिलने के कारण विद्यालय की वार्डेन/लेखाकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न करने हेतु चेतावनी दी गयी। विद्यालय की पुरानी बेडिंग के स्थान पर 2019-20 में नई बेडिंग क्रय कर ली गयी है। छात्राओं को मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जा रहा है, आर0ओ0 मशीन ठीक करा दी गयी है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कटरा खुदागंज-श्री गौरव कुमार, लेखाकार, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कटरा खुदागंज की पदीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता के प्रति लापरवाही बरतने तथा विभागीय कार्यों में अरुचि के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 13-2-2020 द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु संविदा नवीनीकरण न किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसी प्रकार श्रीमती अनीता तिवारी, वार्डेन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कटरा खुदागंज को पदीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता के प्रति लापरवाही बरतने तथा विभागीय कार्यों में अरुचि के प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 13-2-2020 द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु संविदा नवीनीकरण न किये जाने का निर्णय लिया गया।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जैतीपुर-श्री राजू कश्यप, लेखाकार, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जैतीपुर के उपस्थिति कालम में हस्ताक्षर मिलने तथा मौके पर न पाये जाने के कारण सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक की संस्तुति के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 14-1-2020 द्वारा संविदा समाप्त कर दी गयी।

सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक की संस्तुति के आधार पर विद्यालय का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्था दीपजन कल्याण समिति, बरेली को अनियमितता के प्रति जिला शिक्षा परियोजना समिति, शाहजहांपुर के प्रस्ताव के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 13-11-2019 द्वारा विद्यालय संचालन के दायित्व से पृथक कर दिया गया है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मदनापुर-मदनापुर में कोई भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय स्थित नहीं है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जलालाबाद के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं है न ही सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली के द्वारा जांच की गयी है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कलान- विद्यालय का संचालन करने वाली संस्था काशी विकास शिक्षण संस्थान, बदायूं को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 3-2-2020 द्वारा नोटिस जारी कर कमियों के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण मांगा गया तथा पुनः कार्यालय पत्र दिनांक 13-2-2020 द्वारा स्वयंसेवी संस्था को भविष्य के लिये कठोर चेतावनी देते हुये निर्देशित किया गया कि भविष्य में उपरोक्त कमियां पाये जाने पर संस्था को विद्यालय के संचालन से पृथक करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मिर्जापुर-निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा विद्यालय में स्वच्छता एवं सुरक्षा की दृष्टि से छात्रावास के बाहर गैलरी में एक सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाने हेतु निर्देशित किया गया तथा शौचालय एवं स्नानघरों में मरम्मत का कार्य नियमानुसार कराये जाने के निर्देश दिये गये। सहायक शिक्षा निदेशक के निर्देशों के क्रम में के0जी0बी0वी0 मिर्जापुर की वार्डेन के पत्र दिनांक 14-08-2020 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कमियों का निराकरण करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस, ब्लाक सादाबाद, ग्राम तिल्हू (बिसावर) में शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी के निर्माण से सम्बन्धित

130-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लॉक-सादाबाद के ग्राम तिल्हू (बिसावर), मटूरी, पचवारी, तानऊ, नगला, धांधू (दगसह), नन्द का नगला (पचवारी) में ग्रामवासियों को शुद्ध एवं मीठे पानी हेतु पानी की टंकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद के ग्राम तिल्हू (बिसावर), मटूरी, पचवारी, तानऊ, नगला, धांधू (दगसह), नन्द का नगला (पचवारी) सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक सहपऊ के ग्राम नगला ब्राह्मण (भोज) में पीने के पानी की टंकी के निर्माण विषयक

131-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लॉक-सहपऊ के ग्राम नगला ब्राह्मण (भोज) में शुद्ध एवं मीठे पानी हेतु पानी की टंकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा कुड़वा में नाली का निर्माण कराने विषयक

132-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र-282, बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा कुड़वा में बृजमोहन के घर से सरकारी ट्रान्सफार्मर तक दूरी लगभग 400 मी0 नाली का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

ग्राम पंचायत कुड़वा के वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्य योजना में उक्त कार्य सम्मिलित नहीं है। उक्त कार्य पर व्यय होने वाली सम्भावित धनराशि मु0- 1430000/- रुपये है। अतः उक्त कार्य की अनुमानित लागत ग्राम पंचायत के बजट से अधिक होने के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा झुम्मन गांव में नाली निर्माण हेतु

133-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा झुम्मन गांव में रामवचन के घर से खुशीराम के घर तक दूरी

लगभग 100 मीटर नाली का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में ग्राम पंचायत के खाते में मु0-125000/- उपलब्ध है जिससे प्राथमिकता वाले कार्य सामुदायिक शौचालय, अतिरिक्त कक्ष, कायाकल्प आदि कार्य कराये जा रहे हैं। आगामी कार्य योजना में उपरोक्त कार्य को सम्मिलित कराकर करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा मटेही कला में लगभग 500 मीटर इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण हेतु

134-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा मटेही कला में चौधरीगाँव पिच मार्ग से बेगमपुर गाँव तक दूरी लगभग 500 मीटर इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण क्या सरकार कराएगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा मटेही कला में चौधरीगांव पिच मार्ग से बेगमपुर गाँव तक दूरी लगभग 500 मीटर है, जिसमें से 400 मीटर की लम्बाई में खड़न्जा लगा है, जो आवागमन हेतु सुलभ है तथा शेष 100 मीटर मार्ग कच्चा है। मार्ग की औसतन चौड़ाई 4.00-4.50 मीटर है। उक्त मार्ग पर शासनादेश दिनांक 19-02-2021 में निहित प्राविधानानुसार इण्टरलॉकिंग (पेवर ब्लाक) कार्य कराये जाने हेतु आगामी जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा तथा बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में कार्यवाही की जाएगी।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा कुड़वा में नाली निर्माण हेतु

135-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र-282, बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा कुड़वा में लिटिल एंजिल स्कूल से खलिहान तक दूरी लगभग 500 मी0 नाली का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उक्त कार्य की अनुमानित लागत रु0 20.37 लाख है। ग्राम पंचायत की राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त की वार्षिक बजट लगभग रु0 12.26 लाख है। उक्त कार्य की अनुमानित लागत ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट से अधिक है। अतः उक्त कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के तहसील बारा, ग्राम सभा बुंदावा में आराजी सं0-984 क के आवासीय पट्टे की भूमि पर अवैध कब्जा हटवाये जाने विषयक

136-श्री राजकुमार पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-251/आ0द0/2020, दिनांक 19-11-2020 जो जनपद प्रयागराज की तहसील बारा के ग्राम सभा बुंदावा में आराजी सं0-984 क में आवासीय पट्टे की भूमि पर अवैध कब्ज़ा से मुक्ति कराने विषयक है, अपर मुख्य सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

अराजी संख्या-984 क रकबा 0.046 हे0 में से झल्लर पुत्र रामस्वरूप को 0.017 हे0 व बसंत लाल पुत्र बद्री प्रसाद को 0.011 हे0 नचकऊ पुत्र श्री भाई लाल को 0.017 हे0 को आवासीय पट्टा प्राप्त हुआ था, जो मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रयागराज द्वारा दिनांक 15-02-1999, 24-06-1997 व 24-06-1997 को निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पट्टेदारों को उक्त आवासीय पट्टे पर कब्जा दिलाये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उक्त बंजर खाते की आराजी संख्या-984 का रकबा 0.0460 हे0 पर विपक्षी समर सिंह पुत्र राम प्रताप द्वारा किये गये अवैध कब्जे को मौके पर हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में चौधरी चरण सिंह दोआब खरीफ नहर के समतलीकरण कराये जाने विषयक

137-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली मे चौधरी चरण सिंह दोआब खरीफ नहर समतलीकरण न होने के कारण उक्त नहर में छोड़ा गया पानी वापिस आने के कारण इसको बन्द कर दिये जाने के कारण पानी नहर की

टेल तक नहीं पहुंचता, जिसके कारण क्षेत्र के किसानों को सिंचाई में परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार समस्या के निदान के लिए इस नहर के समतलीकरण का कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

चौधरी चरण सिंह दोआब खरीफ नहर परियोजना के कतिपय कार्यों को परियोजना में प्राविधानित भूमि मूल्य में पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः परियोजना के कुछ कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण नहर की टेल पर पानी पहुँचने में कठिनाई है।

उक्त समस्या के निदान हेतु वर्तमान परियोजना को यथास्थिति समाप्त करते हुए अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अलग से परियोजना बनाने की कार्यवाही प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत विधान सभा क्षेत्र छपरौली में नगर पंचायत छपरौली, जनपद बागपत में यमुना नदी के किनारे बाढ़ निरोधक घाट बनवाने के संबंध में

138-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में यमुना नदी के किनारे स्थित नगर पंचायत छपरौली में बाढ़काल के समय भूमि का कटाव से नगर पंचायत छपरौली को वर्ष दर वर्ष विस्थापित होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार यमुना नदी द्वारा भूमि कटान एवं बाढ़ से सुरक्षा हेतु नगर पंचायत छपरौली में यमुना नदी के किनारे बाढ़ निरोधक घाट बनवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में यमुना नदी की मुख्य धारा नगर पंचायत छपरौली की सीमा से लगभग 2.00 किमी0 दूर प्रवाहित हो रही है, इसलिये वर्तमान में नगर पंचायत छपरौली को बाढ़ से खतरे की कोई सम्भावना नहीं है।

जनपद बागपत विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम रमाला में स्थित मनोखर तालाब का जीर्णोद्धार कराने हेतु

139-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम रमाला में प्राचीन शिव मन्दिर के साथ लगा हुआ एक मनोखर तालाब में गाँव

का गन्दा पानी एकत्र होने से तालाब का जल स्तर बढ़ने से तालाब की सारी गन्दगी मन्दिर परिसर में पहुँच जाती है, जिससे मन्दिर परिसर में पूजा-पाठ करने में ग्रासवासियों को असुविधा होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तालाब की सफाई, खुदाई एवं सौंदर्यीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

जी हाँ।

जी हाँ।

जनपद बागपत में विकास खण्ड छपरौली के ग्राम रमाला में शिव मन्दिर के निकट मनोखर तालाब के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 43.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। निविदा स्वीकृत एवं अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद के ग्राम हैली (मिढ़ावली) में शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी के निर्माण सम्बन्धित

140-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लॉक-सादाबाद के ग्राम हैली (मिढ़ावली) में ग्रामवासियों को शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक सहपऊ के अन्तर्गत ग्राम माँगरू से नगला दली तक सड़क निर्माण से सम्बन्धी

141-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सहपऊ के अन्तर्गत ग्राम माँरूग से नगला दली तक मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अन्तर्गत केवल पुराने निर्मित मार्गों को उच्चीकृत किये जाने का ही प्राविधान है। इस प्रकार प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0

के मानकों के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उक्त मार्ग का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस, ब्लाक सादाबाद के ग्राम वासदत्ता में शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी के निर्माण कराये जाने विषयक

142-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लॉक-सादाबाद के ग्राम वासदत्ता, तामसी तथा ताजपुर में ग्रामवासियों को शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद के ग्राम वासदत्ता, तामसी, ताजपुर सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

143-श्री रामवीर उपाध्याय -

[03-बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा मधवापुर में तेज प्रताप की दुकान से लगभग 1 किमी0 आर0सी0सी0 रोड के निर्माण हेतु

144-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा मधवापुर में तेज प्रताप की दुकान से मन्नी फार्म तक लम्बाई लगभग 1 किलोमीटर आर0सी0सी0 रोड का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थलीय निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा मधवापुर में तेज प्रताप की दुकान से मन्नी फार्म तक कुल लम्बाई 1300 मीटर है, जिस पर पूर्व से खड़न्जा लगा हुआ है और आवागमन हेतु सुलभ है। जिला

पंचायत से राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत आर0सी0सी0 रोड बनाये जाने का प्रावधान न होने के कारण आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा बर्दिया में जे0पी0 डाक्टर के घर से परशुराम के घर तक मार्ग का निर्माण विषयक

145-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा बर्दिया में जे0 पी0 डॉक्टर के घर से परशुराम के घर तक दूरी 700 मीटर आर0सी0सी0 रोड का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

ग्राम सभा बर्दिया में श्री जे0पी0 डॉक्टर के घर से श्री परशुराम के घर तक दूरी 700 मीटर आर0सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त की वर्तमान कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। ग्राम पंचायत बर्दिया की राज्य वित्त/ केन्द्रीय वित्त की दिनांक 31-3-2021 तक ग्राम निधि का बजट लगभग 37.21 लाख रुपये है। उक्त कार्य की अनुमानित लागत लगभग 38.54 लाख रु0 है, जोकि ग्राम पंचायत की वार्षिक बजट से अधिक होने के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा भगाड़िया में अजय मण्डल के घर से निरंजन डाले के घर तक 200 मी0 इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य कराने विषयक

146-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करने कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा भगाड़िया में अजय मण्डल के घर से निरंजन डाले के घर तक लम्बाई लगभग 200 मीटर इण्टरलॉकिंग का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

प्रश्नगत कार्य की अनुमानित लागत रु0 12,50,000/- है। उक्त कार्य को वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में सम्मिलित कराकर धन की उपलब्धता की स्थिति में करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम परौर में रामगंगा नदी के क्षेत्र परौर में रामगंगा नदी पर तटबन्ध निर्माण की जांच कराने विषयक

147-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम परौर में राम गंगा नदी के क्षेत्र परौर में रामगंगा नदी का स्वीकृत 9.50 करोड़ रुपये की परियोजना विभाग द्वारा मनमाने तरीके से जनपद तथा मण्डल के बाहर की फर्म को माह जून, 2020 को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त तटबन्ध में मानक के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त सरकारी धन का दुरुपयोग तथा निर्माण कार्य की जांच उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित कर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड व तहसील-कलान में रामगंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम-परौर, ककोरा तथा मंजा आदि ग्राम समूह की बाढ़ से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की एक परियोजना लागत रु0 1179.13 लाख की स्वीकृति हुई थी। परियोजना के कार्य बजट आवंटन के उपरान्त ई-टेण्डरिंग के माध्यम से नियमानुसार प्रथम न्यूनतम निविदादाता राजस्व मण्डल बरेली की फर्म मैसर्स एम0एस0 रोड लाइन्स, सिविल लाइन्स, बरेली के साथ अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ कराया गया। कार्य का समय-समय पर निरीक्षण विभागीय अधिकारियों एवं जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा किया गया तथा समस्त कार्य मानक के अनुरूप कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तिलहर नगर व ग्रामीण तथा जैतीपुर की जांच सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा तृतीय, बरेली मण्डल द्वारा कराये जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

148-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-06-19 जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तिलहर नगर व ग्रामीण तथा जैतीपुर के विरुद्ध मुख्य मंत्री कार्यालय के संदर्भ सं0-18152190068182 के क्रम में जांच सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली के द्वारा 17-07-2019 को की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी

अध्यापिकाओं/अध्यापकों तथा लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हाँ।

राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 21 जून, 2019 द्वारा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली मण्डल को स्थलीय निरीक्षण कर जांच हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम में सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली द्वारा दिनांक 10-07-2019 को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय तिलहर नगर व तिलहर ग्रामीण तथा जैतीपुर का निरीक्षण किया गया। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली द्वारा की गयी संस्तुतियो के क्रम में उक्त सभी विद्यालयों के दोषी अध्यापिकाओं/अध्यापकों तथा लेखाकार के विरुद्ध की गयी कार्यवाही निम्नलिखित है :-

1- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तिलहर नगर-विद्यालय में मेन्यू के अनुसार भोजन न मिलने के कारण विद्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 17-10-2019 द्वारा विद्यालय की वार्डेन श्रीमती शिवा कुशवाहा तथा पत्र दिनांक 17-10-2019 द्वारा लेखाकार श्री सुदेश सक्सेना को चेतावनी दी गयी। विद्यालय अभिलेखों के अव्यवस्थित रख-रखाव हेतु विद्यालय के लेखाकार को सचेत किया गया तथा भविष्य में पुनरावृत्ति होने पर संविदा समाप्त करने की चेतावनी दी गयी।

2- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तिलहर ग्रामीण-विद्यालय की अंशकालिक शिक्षिका श्रीमती स्वालेहा के दिनांक 01-04-2019 से लगातार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण सम्बन्धित का सत्र, 2019-20 में संविदा नवीनीकरण नहीं किया गया। विद्यालय से मेन्यू के अनुसार भोजन न मिलने के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 17-10-2019 द्वारा विद्यालय की वार्डेन श्रीमती स्नेहलता तथा पत्र दिनांक 17-10-2019 द्वारा लेखाकार श्री उदयवीर से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न करने हेतु चेतावनी दी गयी।

3- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जैतीपुर-श्री राजू कश्यप, लेखाकार, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जैतीपुर के उपस्थिति कालम में हस्ताक्षर मिलने तथा मौके पर न पाये जाने के कारण सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक की संस्तुति के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 14-01-2020 द्वारा संविदा समाप्त कर दी गयी।

सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक की संस्तुति के आधार पर विद्यालय का संचालन करने वाली स्वंयसेवी संस्था दीपजन कल्याण समिति, बरेली को अनियमितता के कारण जिला शिक्षा परियोजना समिति, शाहजहांपुर के प्रस्ताव के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा

अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 13-11-2019 द्वारा विद्यालय संचालन के दायित्व से पृथक कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में ग्राम विकास संस्थान बड़ौत में जेम पोर्टल के माध्यम से स्टेशनरी का क्रय करने में भ्रष्टाचार की जांच करने विषयक

149-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान बड़ौत में प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रयोगार्थ कम्प्यूटर, लैपटॉप, साहित्य, पेन, पैड, बैग, स्टेशनरी आदि का क्रय भारत सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप जेम पोर्टल के माध्यम से न कर स्थानीय फर्मों से भारी मात्रा में कमीशन प्राप्त कर खरीददारी की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह'-

क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बड़ौत, जनपद बागपत में दो लैपटाप, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, प्रशिक्षण सत्रों में उपयोग हेतु प्रशिक्षण किट (बैग, पेन, पैड) एवं कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी आदि का क्रय विभिन्न फर्मों से कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम दर पर क्रय किया गया है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान फर्मों के खाते में आर0टी0जी0एस0एन0ई0एफ0टी0/ पी0एफ0 एम0एस0 के माध्यम से किया गया है।

जेम से क्रय न करने के कारण पर जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती शहर में स्थित महिला महाविद्यालय को काम के नाम पर दिये गये धन का बन्दरबांट किये जाने की जांच के सम्बन्ध में

150-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती शहर में संचालित महिला महाविद्यालय को विकास कार्य के लिए यू0जी0सी0 के द्वारा दो किस्तों में दिये गये धनराशि रु0 6 लाख 30 हजार तथा रु0 22 लाख 90 हजार का महाविद्यालय प्रशासन द्वारा बिना किसी निविदा के विकास कार्य में खर्च दिखाकर धन के दुरुपयोग की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

जांच की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सिघनी ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच विषयक

151-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिंघनी कंजास, पोस्ट-पिठावर, ब्लॉक सड़वा चन्द्रिका, जनपद-प्रतापगढ़ के वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा के कार्यों में अनियमितता कर कालोनियों के निर्माण में मानक के अनुसार सामग्री का उपयोग न करने तथा आधा-अधूरा शौचालय का निर्माण एवं नाली खड़न्जा का पुराना कार्य को नया दिखाकर तथा मानक के अनुसार कार्य न कराये जाने की जानकारी सरकार की हो ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान प्रधान के कार्यकाल के समस्त कार्यों की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथापि प्रश्न में संदर्भित कार्यों में इंगित अनियमितता एवं संबंधित ग्राम प्रधान के कार्यकाल में कराये गये कार्यों की जांच खण्ड विकास अधिकारी, सड़वा चन्द्रिका से करायी गयी, जिसमें कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी।

मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ से प्राप्त आख्या दिनांक 05-02-2021 के अनुसार मनरेगा कार्यों का सत्यापन कराया गया जिसमें कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है। कॉलोनियों (प्रधानमंत्री आवास-ग्रामीण) का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाता है, निरीक्षण में सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी। स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत कुल 332 शौचालय स्वीकृत किये गये थे। सभी शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 320 शौचालय का जी0ओ0टैग0 करा दिया गया है। एन0एल0ओ0बी0 के अन्तर्गत सीधे 19 लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा गया है, जिनमें से 11 लाभार्थियों द्वारा शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष 08 शौचालय निर्माणाधीन हैं। ग्राम पंचायत में पुराने नाली, खड़न्जे को नया दिखाकर भुगतान नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड भरावन, ग्राम पंचायत कटियार में पंचायत भवन निर्माण कराने विषयक

152-पं0 राधा कृष्ण शर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत कटियार विकास खण्ड भरावन, जनपद हरदोई में पंचायत भवन ग्राम कटियार के स्थान पर अन्यत्र बनवाये जाने की कारवाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पंचायत भवन का निर्माण ग्राम कटियार में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन की ग्राम पंचायत कटियार में पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि गाटा संख्या-113 रकबा 0.370 हे0 राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित की गयी है। उक्त भूमि पर पंचायत भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद हरदोई के ग्राम पंचायत कटियार, विकास खण्ड भरावन में वर्ष 2018-19 रैंकवारखेड़ा नगर पुलिया से कटियार तक नहर की सफाई (सिल्ट) मद में धनराशि का गबन किये जाने विषयक

153-पं0 राधा कृष्ण शर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत कटियार, विकास खण्ड भरावन, जनपद हरदोई में वर्ष 2018-19 रैंकवार खेड़ा नहर पुलिया से कटियार तक नहर की सफाई (सिल्ट) के मद में स्वीकृत धनराशि से कार्य न कराकर बी0एल0ओ0 ग्राम प्रधान पंचायत कर्मियों द्वारा आपस में बांट लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर उत्तरदायित्व निर्धारित कर धनराशि की वसूली करायेगी ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

ग्राम पंचायत कटियार, विकास खण्ड भरावन, जनपद हरदोई में वर्ष 2018-19 में रैंकवार खेड़ा नहर पुलिया की सफाई (सिल्ट) का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहर विभाग की अनापत्ति (एन0ओ0सी0) प्राप्त करते हुए मनरेगा योजनान्तर्गत कराते हुए श्रमिकों के खातों में मजदूरी का भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के सुभाष तिराहा, बरी का नगला चौराहों में लगे हुये सी0सी0टी0वी0 कैमरों की गुणवत्ता एवं प्रभावी अनुसरण कराये जाने विषयक

154-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के सुभाष तिराहा, बरी का नगला चौराहों पर लगे हुये सी0सी0टी0वी0 कैमरे खराब होने के कारण रिकार्डिंग नहीं हो

रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर के प्रमुख मार्गों पर पड़ने वाले मुख्य चौराहों/बाजारों में लगे हुये सी0सी0टी0वी0 कैमरों की गुणवत्ता एवं प्रभावी अनुरक्षण कराये जाने का कार्य करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

नगला बरी चौराहा पर लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे मय सहवर्ती उपकरण सी0ए0ए0/एन0आर0सी0 विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा नष्ट कर दिये गये, जिसके सम्बन्ध में थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद में मु0अ0सं0-812/2019, धारा-147/427/436 भा0द0वि0 एवं 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम पंजीकृत है, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

सुभाष तिराहा एवं नगला बरी चौराहा के अतिरिक्त नगर के प्रमुख मार्गों पर पड़ने वाले मुख्य चौराहों/बाजारों में लगे हुए सी0सी0टी0वी0 कैमरे सही कार्य कर रहे हैं एवं उनकी रिकार्डिंग हो रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक अनुरक्षण/मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु जनपद फिरोजाबाद को कुल रु0 24,00,000/- का अनुदान आवंटित किया गया है। सी0सी0टी0वी0 कैमरों के मरम्मत आदि की कार्यवाही नियमानुसार कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र दिनांक 28-01-2021 द्वारा पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को पृथक से निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वाद सं0-T 201910690500353 के निस्तारण विषयक

155-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-34 के अन्तर्गत प्राविधानित निस्तारण अवधि में नायब तहसीलदार, बीघापुर, उन्नाव द्वारा वाद सं0- **T** 201910690500353 बेनी प्रसाद बनाम राम सहाय निस्तारित नहीं किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रश्नगत वाद को तीन माह में निस्तारित करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा बेनी प्रसाद बनाम प्रमुख सचिव, राजस्व, उ0प्र0 सरकार अपील सं0-4476/2020, दिनांक 17-02-2020 में आदेश दिये गये है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रकरण का निस्तारण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जी हाँ।

नायब तहसीलदार, बीघापुर के न्यायालय में विचाराधीन उक्त नामान्तरण वाद संख्या-टी 201910690500353 बेनी प्रसाद बनाम रामसहाय में विक्रेता रामसहाय के पुत्रगण नागेन्द्र कुमार व रामकुमार, निवासीगण ग्राम गयाबक्स खेड़ा, म0 लखमदेमऊ, परगना पुरवा, तहसील बीघापुर, जिला उन्नाव द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है तथा प्रश्नगत वाद वरासत के एक अन्य वाद सं0-टी 201910690502022 महाबली पुत्र बुधई बनाम महाबली पुत्र बुधई बादहू कथित रामसहाय पुत्र महाबली न्यायालय तहसीलदार, बीघापुर, उन्नाव के आधार पर निर्णीत होना है जिसमें तत्कालीन तहसीलदार, बीघापुर के आदेश दिनांक 23-10-2019 द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध रामसहाय द्वारा अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ मण्डल, लखनऊ के न्यायालय में अपील संख्या-सी 201910000002729 अन्तर्गत धारा-219, उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 "राममसहाय बनाम महाबली कथित आदि" योजित की गयी है। उक्त अपील लम्बित होने के कारण प्रश्नगत नामान्तरण वाद संख्या-टी 201910690500353 बेनी प्रसाद बनाम रामसहाय में नामान्तरण आदेश पारित नहीं किया जा सका है। जी नहीं। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं की गयी है, अपितु उपर्युक्तानुसार अपील लम्बित होने के कारण प्रश्नगत वाद का निस्तारण नहीं हो सका।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना, ब्लाक कोतवाली व किरतपुर में महिला कालेज की स्थापना कराने विषयक

156-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक कोतवाली एवं किरतपुर में सरकारी महिला डिग्री कालेज (महिला कालेज) न होने के कारण छात्राओं को उच्च शिक्षा का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में महिला कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-नगीना के ब्लाक कोतवाली एवं किरतपुर में पर्याप्त महाविद्यालय हैं, जहाँ छात्र/छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक कोतवाली में कुल 07 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जिसमें 02 महिला महाविद्यालय हैं। ब्लाक किरतपुर में 02 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संशाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक

कोतवाली एवं ब्लाक किरतपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का अवसर नहीं है।

157-श्री मनोज कुमार पारस-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा में 400 मी0 इण्टरलॉकिंग मार्ग के निर्माण हेतु

158-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र-282, बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा कुड़वा में बृजमोहन के घर से सरकारी ट्रान्सफार्मर तक दूरी लगभग 400 मी0 इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उक्त कार्य पर व्यय होने वाली सम्भावित धनराशि मु0 1430000/- रु0 है। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक पंचम वित्त आयोग एवं 15वें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि लगभग मु0 1226000/- रु0 है। अतः कार्य की अनुमानित लागत ग्राम पंचायत के बजट से अधिक होने के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महराज सिंह नगर में सड़क निर्माण सम्बन्धी

159-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र-282, बलहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महराज सिंहनगर में श्याम मनोहर यादव के घर से राम प्रवेश के घर तक खड़न्जा का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

उक्त कार्य को आगामी वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर धनराशि की उपलब्धता होने पर प्राथमिकता के आधार पर करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा बखारी में मोती मास्टर के घर से केजी बाग रोड तक लम्बाई लगभग 250 मी0 इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य कराने विषयक

160-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत कम सभा बखारी में मोती मास्टर के घर से केजी बाग रोड तक लम्बाई लगभग 250 मीटर इण्टरलॉकिंग का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

ग्राम सभा बाखारी में श्री मोती मास्टर के घर से कंजीबाग रोड तक लगभग 250 मीटर इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य की अनुमानित लागत रु0 10.00 लाख है। वर्तमान में ग्राम पंचायत के खाते में रु0 1.61 लाख मात्र अवशेष है। उक्त कार्य ग्राम पंचायत के बजट से अधिक होने के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा मटेहीकलां के कमलापुरी में मोती के घर से रामबदन के घर होते हुए सर्राकलां पिच मार्ग तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराने विषयक

161-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा मटेहीकलां के कमलापुरी में मोती के घर से रामबदन के घर होते हुए सर्राकलां पिच मार्ग तक दूरी लगभग 700 मीटर आर0सी0सी0 रोड का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उक्त कार्य की अनुमानित लागत रु0 34.00 लाख आंकलित की गयी है, जोकि ग्राम पंचायत की वार्षिक बजट से अधिक होने के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा मटेहीकलां में 500 मी0 इण्टरलॉकिंग सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में

162-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा मटेहीकलां में मटेही से अहिरन गौड़ी उपकेन्द्र तक लम्बाई

500 मीटर इण्टरलॉकिंग का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उक्त कार्य के निर्माण का अनुमानित लागत रु0 15.00 लाख है। वर्तमान में ग्राम पंचायत के खाते में रु0 03.00 लाख शेष है जिससे वर्तमान में सामुदायिक शौचालय निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प तथा पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत की कुल धनराशि के सापेक्ष उक्त कार्य पर अनुमानित व्यय अधिक होने के कारण प्रश्नगत कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के तहसील मुख्यालय बिलारी में ग्राम न्यायालय संचालन हेतु अधिवक्ता हाल की मरम्मत कराने सम्बन्धी

163-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय के संचालन हेतु अधिवक्ता हाल की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अगले वित्तीय वर्ष में अधिवक्ता हाल की मरम्मत करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में ग्राम पंचायत कटियार, वि0ख0 भरावन में हैण्डपम्पों के रि-बोर मद में गबन की जांच व कार्रवाई विषयक

164-पं0 राधा कृष्ण शर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत कटियार वि0ख0 भरावन, जनपद हरदोई में वर्ष 2017-18, 2019-20 तथा वर्ष 2020-2021 में हैण्डपम्पों के रि-बोर के मद में स्वीकृत धनराशि से रि-बोर न कराकर खण्ड विकास अधिकारी भरावन, पंचायत कर्मी व ग्राम प्रधान ने अनियमितता की है यदि हां, तो उक्त वर्षों में आवंटित धनराशि व कार्यों की जांच कराकर कार्य न करने वाले बी0डी0ओ0/कर्मियों/ग्राम प्रधान कटियार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

ग्राम पंचायत कटियार में वर्ष 2017-18 में 04, वर्ष 2019-20 में 03 तथा वर्ष 2020-21 में 05 हैण्डपम्प रि-बोर कराये गये हैं, जो चालू हालत में हैं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन, ग्राम पंचायत कटियार में शौचालय हेतु धनराशि में भ्रष्टाचार की जांच व दोषियों पर कार्रवाई विषयक

165-पं0 राधा कृष्ण शर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत कटियार, वि0ख0 भरावन, जनपद हरदोई में वर्ष 2017 में 201 शौचालय लाभार्थियों में से 68 पात्र व एम0आई0एस0 सूची में सम्मिलित नामों को शौचालय की धनराशि न देकर बी0डी0ओ0 भरावन पंचायत कर्मी व ग्राम प्रधान द्वारा अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

शिकायत की जांच अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, हरदोई से करायी गयी। अनियमितता पाये जाने पर संबंधित सचिव एवं ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर अग्रतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन, ग्राम पंचायत बहुती में भ्रष्टाचार की जांच व कार्रवाई विषयक

166-पं0 राधा कृष्ण शर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत बहुती, वि0ख0 भरावन जपनद हरदोई मे व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक श्री सरल द्विवेदी, सदस्य, जिला पंचायत हरदोई के प्रार्थना-पत्र के साथ मा0 मंत्री ग्राम्य विकास का पत्रांक-2588 /मंत्री/ग्रा0वि0/2020, दिनांक 10-08-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

प्रकरण की जांच करायी गयी है, जिसमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज, ग्राम सभा छीछोरी (यादव बस्ती) में जल निकासी का प्रबन्ध कराने विषयक

167-श्री नफीस अहमद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में ग्राम सभा छीछोरी (यादव बस्ती) में जल निकासी का प्रबन्ध न होने के कारण गन्दे पानी के इकट्ठा होने से वहां के जनमानस संक्रमित बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जल निकासी का प्रबन्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

समस्त ग्रामवासियों का पानी ग्राम के बीच में स्थित पोखरी में जाता है। उक्त पोखरी का पानी ग्राम सभा के बाहर स्थित नाले से जोड़ा जाना है, परन्तु ग्रामवासी अपने घर के सामने से नाला निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सहमत नहीं हैं। अतः उक्त कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम सभा देवारा कदीम में पुलिया निर्माण विषयक

168-श्री नफीस अहमद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम सभा देवारा कदीम (खन्जरपुर) में पुलिया का नव निर्माण न होने से वहां के स्कूली बच्चे, गर्भवती महिलायें इत्यादि को अवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम सभा देवारा कदीम (खन्जरपुर) में पुलिया के नव निर्माण के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण में प्रस्तावित स्थल पर नाले के दूसरी तरफ कोई सम्पर्क मार्ग निर्मित न होने, नाले के दूसरी तरफ बसावट से हटकर मात्र एक मकान बने होने तथा उक्त कार्य की लागत लगभग रु0 50 लाख होने, उक्त स्थान पर ग्रामवासियों का

सामान्य रूप से आवागमन न होने, प्रस्तावित स्थल से 400 मीटर दूरी पर ही लघु सेतु निर्मित होने, जहाँ से देवारा कदीम (खन्जरपुर) के ग्रामवासियों का आवागमन सुचारु रूप से आरम्भ है, के कारण उक्त स्थल पर पुलिया का नव निर्माण कराये जाने का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

प्रदेश के परिषदीय व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु स्वेटर वितरण कार्य में नियमों की अवहेलना विषयक

169-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को ठंड में वितरित होने वाले अधिकांश स्वेटर 32 नम्बर माप के ही हैं जबकि प्रविधान के अनुसार 32, 34, 36, 38 नम्बर के स्वेटर दिये जाने चाहिए, एक ही माप के स्वेटर होने के कारण वे छात्रों के लिये अनुपयुक्त हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

शासनादेश संख्या-895/68-5-20-810/2017 टी0सी0, दिनांक 02-09-2020 द्वारा शैक्षिक सत्र, 2020-21 के लिए प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को निःशुल्क उच्च गुणवत्तायुक्त स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के लिए स्वेटर का क्रय गत वर्ष 2019-20 की भांति भारत सरकार द्वारा विकसित आनलाइन प्लेटफार्म जेम पोर्टल के माध्यम से जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

शैक्षिक सत्र 2020-21 में छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ विन्टर यूनीफार्म (स्वेटर) की विशिष्टियां निम्नवत् निर्धारित की गयी हैं :-

श्रेणी	स्वेटर का आकार
I	स्माल
II	मीडियम
III	लार्ज
IV	एक्स एल
V	एक्स एक्स एल

उक्त शासनादेश दिनांक 02-09-2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही छात्र-छात्राओं को गुणवत्तायुक्त विन्टर यूनीफार्म (स्वेटर) उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच व रिकवरी किये जाने विषयक

170-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018-2019 में कराये गये मनरेगा कार्यों में कितने घोटालों का पर्दाफाश हुआ है तथा कितने अधिकारियों से रिकवरी

करायी गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, "मोती सिंह"-

वर्ष 2018-19 में मनरेगा कार्यों में अनियमितता सम्बन्धी कुल 43 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें 37 प्रकरण निस्तारित एवं 06 प्रकरण कार्यवाही हेतु विभिन्न स्तरों पर लम्बित है।

उक्त प्रकरणों में 58 सचिव, 47 तकनीकी सहायक, 03 अवर अभियन्ता एवं 01 खण्ड विकास अधिकारी अर्थात् कुल 109 अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली की कार्यवाही की गई है।

उपरोक्तानुसार।

आई0जी0आर0एस0 संख्या-18150190106992 जनपद शाहजहांपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की जांच में दोषियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई की जानकारी

171-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में मुख्य मंत्री संदर्भ आई0जी0आर0एस0 सं0-18150190106992 द्वारा जनपद शाहजहाँपुर के जैतीपुर, कलान, परौर, मिर्जापुर, जलालाबाद नगर तिलहर एवं ग्रामीण कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के विरुद्ध जॉच दिनांक 25/09/2019 जो सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा तृतीय बरेली मण्डल बरेली द्वारा की गयी शिकायत सही पायी गयी ? यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त आवासीय विद्यालय तथा बी0एस0ए0 शाहजहाँपुर के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवही की हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

कई शिकायतें प्रमाणित पायी गयी।

जांच में जो शिकायतें प्रमाणित पायी गयीं उनके आधार पर निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :-

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कटरा खुदागंज -श्री गौरव कुमार, लेखाकार एवं श्रीमती अनीता तिवारी, वार्डेन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कटरा खुदागंज को पदीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता के प्रति लापरवाही बरतने तथा विभागीय कार्यों में अरुचि के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु संविदा नवीनीकरण न किये जाने का निर्णय लिया गया।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जैतीपुर श्री राजू कश्यप, लेखाकार, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जैतीपुर के उपस्थिति कालम में हस्ताक्षर मिलने तथा मौके पर न पाये जाने के कारण सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक की संस्तुति के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 14-1-2020 द्वारा संविदा समाप्त कर दी गयी।

सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक की संस्तुति के आधार पर विद्यालय का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्था दीपजन कल्याण समिति, बरेली को अनियमितता के प्रति जिला शिक्षा परियोजना समिति, शाहजहांपुर के प्रस्ताव के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय-पत्र दिनांक 13-11-2019 द्वारा विद्यालय संचालन के दायित्व से पृथक कर दिया गया है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कलान-विद्यालय का संचालन करने वाली संस्था काशी विकास शिक्षण संस्थान, बदायूँ को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 3-2-2020 द्वारा नोटिस जारी कर कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया तथा पुनः कार्यालय-पत्र दिनांक 13-2-2020 द्वारा स्वयंसेवी संस्था को भविष्य के लिये कठोर चेतावनी देते हुये निर्देशित किया गया कि भविष्य में उपरोक्त कमियां पाये जाने पर संस्था को विद्यालय के संचालन से पृथक करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मिर्जापुर-निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा विद्यालय में स्वच्छता एवं सुरक्षा की दृष्टि से छात्रावास के बाहर गैलरी में एक सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाने हेतु निर्देशित किया गया तथा शौचालय एवं स्नानघरों में मरम्मत का कार्य नियमानुसार कराये जाने के निर्देश दिये गये। सहायक शिक्षा निदेशक के निर्देशों के क्रम में के0जी0बी0वी0 मिर्जापुर की वार्डेन ने अपने पत्र दिनांक 14-08-2020 द्वारा अवगत कराया कि उक्त कमियों का निराकरण करा लिया गया है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तिलहर नगर-विद्यालय में मेन्यू के अनुसार भोजन न मिलने के कारण विद्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 17-10-2019 द्वारा विद्यालय की वार्डेन श्रीमती शिवा कुशवाहा तथा पत्र दिनांक 17-10-2019 द्वारा लेखाकार श्री सुदेश सक्सेना को भविष्य में पुनरावृत्ति न करने हेतु चेतावनी दी गयी। विद्यालय अभिलेखों के अव्यवस्थित रख-रखाव हेतु विद्यालय के लेखाकार को सचेत किया गया तथा भविष्य मे पुनरावृत्ति होने पर संविदा समाप्त करने की चेतावनी दी गयी। छात्राओं को मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जा रहा है, आर0ओ0 मशीन ठीक करा दी गयी है एवं नवीन बेडिंग का क्रय कर लिया गया है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तिलहर ग्रामीण-विद्यालय की अंशकालिक शिक्षिका श्रीमती स्वालेहा के दिनांक 01-04-2019 से लगातार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण संम्बन्धित का सत्र 2019-20 में संविदा नवीनीकरण नहीं किया गया तथा वर्तमान में वह कार्यरत नहीं है। विद्यालय में मेन्यू के अनुसार भोजन न मिलने के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 17-10-2019 द्वारा विद्यालय की वार्डेन श्रीमती स्नेहलता तथा पत्र दिनांक 17-10-2019 द्वारा लेखाकार श्री उदयवीर से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न करने हेतु चेतावनी दी गयी। विद्यालय की पुरानी बेडिंग के स्थान पर 2019-20 नई बेडिंग क्रय कर श्री गयी है। छात्राओं को मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जा रहा है, आर0ओ0 मशीन ठीक करा दी गयी है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जलालाबाद की जांच मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली मण्डल द्वारा नहीं की गयी है और न ही किसी कार्यवाही की संस्तुति की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा कुड़वा में 500 मी0 खड़ंजा निर्माण हेतु

172-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अंर्तगत ग्राम सभा कुड़वा में उदयराज के खेत से गौतम के खेत तक दूरी लगभग 500 मीटर खड़न्जा इण्टरलॉकिंग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उक्त कार्य की अनुमानित लागत रु0 20.150 लाख है। दिनांक 31-3-2021 तक पंचम वित्त आयोग एवं 15वां वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि लगभग रु0 12,26000/- है। उक्त कार्य की अनुमानित लागत ग्राम पंचायत के बजट से अधिक है। अतः उक्त कार्य कराया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा सेमरी घटही में 500 मी0 सड़क निर्माण हेतु

173-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अंर्तगत ग्राम सभा सेमरी घटही में गिरधरपुरवा हेमराज के घर से प्राथमिक विद्यालय तक लम्बाई लगभग 500 मीटर मिट्टी पटाई व खंड़जा का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

उक्त कार्य की अनुमानित लागत रु0 9,75,000/- होगी। वर्तमान समय में उपलब्ध धनराशि रु0 7,75,000/- है। उक्त कार्य को वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में सम्मिलित कराते हुए धनराशि की उपलब्धता होने पर करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज, ग्राम सभा फुलेहरा में जर्जर मार्ग का नव निर्माण कराने विषयक

174-श्री नफीस अहमद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज ग्राम सभा फुलेहरा में उमाकान्त के खेत से रघुनाथ यादव के घर तक मार्ग दूरी 300 मीटर र्जजर हो जाने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का सी0सी0/इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

ग्राम फुलेहरा में श्री उमाकान्त के खेत से श्री रघुनाथ यादव के घर तक कच्चा सम्पर्क मार्ग है, जिसे ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। धनराशि की उपलब्धता होने पर निर्माण कार्य करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में ग्राम सभा गढ़वल श्रीपति के खेत से 300 मी0 मार्ग का नवनिर्माण कराने विषयक

175-श्री नफीस अहमद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में ग्राम सभा गढ़वाल श्रीपति के खेत से श्रीपति के घर तक का मार्ग लम्बाई 300 मीटर जर्जर/गड्ढा मुक्त होने से आमजनमानस को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पिच रोड का मरम्मतीकरण/ नवनिर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

विकास खण्ड बिलरियागंज में ग्राम सभा गढ़वाल श्रीपति के खेत से श्रीपति के घर तक का मार्ग लम्बाई 300 मीटर कार्य पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद के ग्राम मन्स्या कला में पेयजल की व्यवस्था हेतु पानी की टंकी के निर्माण विषयक

176-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लॉक सादाबाद के ग्राम मन्स्या कला नगला बनारसी तथा नगला बाग नौगवां में ग्रामवासियों को शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई खण्ड निचली मांट शाखा गंग नहर मथुरा के अन्तर्गत मुरसान राजवाहा में टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में

177-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड निचली माँट शाखा गंग नहर मथुरा के अन्तर्गत मुरसान राजवाहा में टेल तक पानी सरकार पहुँचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

मांट शाखा के कि0मी0 82.210 की बायीं पटरी से निकले राजवाहा मुरसान की कुल लम्बाई 29.800 कि0मी0 तथा डिस्चार्ज 80 क्यूसेक है। मुरसान राजवाहा कि0मी0 27.000 से 29.800 तक जनपद हाथरस में पड़ता है। रबी 1428 फसली में राजवाहा मुरसान की दिनांक 08-12-2020 एवं 15-12-2020 को टेल फीड कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के अन्तर्गत कोटा ऐवरनपुर माइनर व किसान राजवाहों में टेल तक पानी पहुंचाने विषयक

178-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड हाथरस के अन्तर्गत कोटा ऐवरनपुर माइनर तथा किसान राजवाहों में टेल तक पानी नहीं पहुँचाया जा रहा है ? यदि

हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर में टेल तक पानी पहुँचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

जी हाँ।

सिंचाई खण्ड हाथरस के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत खरीफ 1428 फसली वर्ष 2020-21 में कोटा माइनर की टेलफीड दिनांक 29-11-2021 को, एवरनपुर माइनर की टेलफीड दिनांक 24-12-2020 को तथा बिसाना राजवाहा की दिनांक 08-01-2021 को टेलफीड कराकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के शहबाजपुर माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में

179-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड हाथरस के अन्तर्गत शहबाजपुर माइनर में टेल तक पानी सरकार पहुँचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

सिचाई खण्ड, हाथरस के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सहपऊ राजवाहा के कि0मी0 4.699 पटरी दायीं से शहबाजपुर माइनर निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 5.600 कि0मी0 है। खरीफ 1428 फसली वर्ष 2020-21 में शहबाजपुर माइनर की दिनांक-10-12-2020 की टेलफीड कराकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गुरसराय मुख्य नहर में सिंचाई हेतु पानी न छोड़े जाने पर कार्यवाही किये जाने विषयक

180-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झाँसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुरसराय मुख्य नहर में वर्तमान में सिंचाई हेतु कम पानी छोड़े जाने के कारण किसानों की रबी फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर में सिंचाई हेतु क्षमतानुसार पानी छोड़ने की कार्यवाही करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

गुरसराय मुख्य नहर को पूर्ण क्षमता से चलाया जा रहा है। गुरसराय मुख्य नहर प्रणाली कुल 19230 हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु परिकल्पित है, जिसके सापेक्ष विगत 5 वर्षों में गुरसराय मुख्य नहर प्रणाली से औसतन 25419.40 हे0 क्षेत्र में सिंचाई करायी गयी है।

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुरसराय मुख्य नहर में सिंचाई हेतु पूर्ण क्षमता से नहरें चलाई जाती हैं। वर्तमान में नहरों का संचालन हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के रामनगर ब्लाक ग्राम बेलभरिया, असनहरा, कुतुबपुर खत, रामनगर विकास खण्ड रुधौली के करमहिया माइनर पर करमहिया, अन्देउरी गांव से गुजरने वाली नहरों पर पुल का निर्माण करने विषयक

181-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रामनगर ब्लाक के ग्राम बेलभरिया, असनहरा, कुतुबपुर खत, रामनगर विकास खण्ड रुधौली के करमहिया माइनर पर करमहिया, अन्देउरी गांव से होकर गुजरने वाली सरजू नहर खण्ड 4 के दूसरी तरफ कृषि कार्य के लिए जाने वाले कृषकों को लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है ? यदि हां तो क्या सरकार किसानों की सुविधा के लिए उक्त ग्रामों में नहरों पर पैदल मार्ग के लिए पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त चारों ग्रामों में से ग्राम-बेलभरिया में 600 मी0, ग्राम असनहरा में 200 मी0, ग्राम-कुतुबपुर खत में 500 मी0 एवं ग्राम-रामनगर में 200 मी0 की दूरी पर पुल निर्मित है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा सेमरी घटही में सुबेदार के घर से 300 मी0 इण्टरलॉकिंग मार्ग के निर्माण हेतु

182-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा समरी घटही में सुबेदार के घर से अस्पताल एनम सेन्टर तक लम्बाई लगभग 300 मी0 इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

जनपद बहराइच, विकास खण्ड मिहीपुरवा के उक्त कार्य की अनुमानित लागत 1250000/- रु0 होगी। उक्त लागत के सापेक्ष ग्राम पंचायत के पास धनराशि उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा कुड़वा में पिन्टू के घर से 400 मी0 इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने विषयक

183-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा कुड़वा में पिन्टू के घर से होलिका दहन होते हुए श्री प्रताप के घर तक दूरी लगभग 400 मी0 इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण क्या सरकार करायेगी ? यदि हां तो, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य का अनुमानित लागत रु0 1785000.00 है। वर्तमान में ग्राम पंचायत के खाते में रु0-4.23 लाख शेष है। जिसमें वर्तमान में सामुदायिक शौचालय निर्माण, विद्यालयें कायाकल्प तथा पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत की कुल धनराशि के सापेक्ष उक्त कार्य पर अनुमानित व्यय अधिक होने के कारण प्रश्नगत कार्य कराया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

ग्राम पंचायत भरावन विकास खण्ड भरावन जनपद हरदोई में 13वें व 14वें राज्य वित्त योजना में अन्य स्त्रोतों से दी गई धनराशि के प्रयोग में भ्रष्टाचार की जांच व दोषियों पर कार्रवाई विषयक

184-पं0 राधा कृष्ण शर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत भरावन विकास खण्ड भरावन जपनद हरदोई में 13वें व 14वें राज्य वित्त योजना में अन्य स्त्रोतों से शौचालयों, मनरेगा (गारन्टी योजना), आवासों व हैण्डपंपों के मरम्मत आदि दी गई गुणवत्ता व मानक के अनुरूप न कराकर बी0डी0ओ0 भरावन, ग्राम प्रधान व पंचायत के कर्मचारी द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रकरण की जांच खण्ड विकास अधिकारी, भरावन द्वारा सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) से करायी गयी। जांच आख्या के अनुसार ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में खान-पान व अन्य व्यवस्था की जांच कराने विषयक

185-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करने कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 06/09/2019 जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नगर तिलहर एवं ग्रामीण कलान, मिर्जापुर, जैतीपुर, मीरानपुर कटरा, खुदागंज में बच्चों को मेन्यू के अनुसार खाना न मिलने तथा पीने का पानी आर0 ओ0 खराब होने तथा गद्दा विस्तर तीन वर्षों से न बदले जाने विषयक शिकायत उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हाँ।

राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ द्वारा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तृतीय मण्डल बरेली को स्थलीय निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तृतीय मण्डल बरेली द्वारा दिनांक 10-07-2019 को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नगर तिलहर एवं तिलहर ग्रामीण, जैतीपुर, दिनांक 17-07-2019 को कलान एवं कटरा खुदागंज एवं दिनांक 21-02-2020 को मिर्जापुर का निरीक्षण किया गया। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तृतीय मण्डल, बरेली द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में उक्त सभी विद्यालयों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है :-

1- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तिलहर नगर विद्यालय में मेन्यू के अनुसार भोजन न मिलने के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 17-10-2019 द्वारा विद्यालय की वार्डेन श्रीमती शिवा कुशवाहा तथा पत्र दिनांक 17-10-2019 द्वारा लेखाकार श्री सुदेश सक्सेना को भविष्य में पुनरावृत्ति न करने हेतु चेतावनी दी गयी। विद्यालय अभिलेखो के अव्यवस्थित रख-रखाव हेतु विद्यालय के लेखाकार को सचेत किया गया। तथा भविष्य में पुनरावृत्ति होने पर संविदा समाप्त करने की चेतावनी दी गयी। छात्राओं को मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जा रहा है, आर0ओ0 मशीन ठीक करा दी गयी है एवं नवीन बेडिंग का क्रय कर लिया गया है।

2- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तिलहर ग्रामीण विद्यालय की अंशकालिक शिक्षिका श्रीमती स्वालेहा दिनांक 01-04-2019 से लगातार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण सम्बन्धित का सत्र 2019-20 में संविदा नवीनीकरण नहीं किया गया तथा वर्तमान में वह कार्यरत नहीं है। विद्यालय में मेन्यू के अनुसार भोजन न मिलने के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 17-10-2019 द्वारा विद्यालय की वार्डेन श्रीमती स्नेहलता तथा पत्र दिनांक 17-10-2019 द्वारा लेखाकार श्री उदयवीर ने स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न करने हेतु घेतावनी दी गयी। विद्यालय की पुरानी बेंडिंग के स्थान पर 2019-20 नई बेडिंग क्रय कर ली गयी है। छात्राओं को मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जा रहा है, आर0ओ0 मशीन ठीक करा दी गयी है।

3- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कलान विद्यालय का संचालन करने वाली संस्था काशी विकास शिक्षण संस्थान, बदायूं को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र दिनांक 3-2-2020 द्वारा नोटिस जारी कर कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण में संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि खराब खाद्य सामग्री विद्यालय से हटाते हुये गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री विद्यालय में उपलब्ध करा दी गयी है। नवीन बेडिंग विद्यालय को प्राप्त करा दी गयी है। विद्यालय का आर0 ओ0 ठीक करा दिया गया है व छात्राओं की सुरक्षा हेतु 02 पी0आर0डी0 कार्मिकों की तैनाती कर दी गयी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र दिनांक 13-2-2020 उपरांत स्वयंसेवी संस्था को भविष्य के लिये कठोर चेतावनी देते हुये निर्देशित किया गया है कि भविष्य में उपरोक्त कमियां पाये जाने पर संस्था को विद्यालय के संचालन से पृथक करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

4- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जैतीपुर श्री राजू कश्यप, लेखाकार, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जैतीपुर के उपस्थिति कालम में हस्ताक्षर मिलने तथा मौके पर न पाये जाने के कारण सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक की संस्तुति के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 14-1-2020 द्वारा संविदा समाप्त कर दी गयी है। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक की संस्तुति के आधार पर विद्यालय का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्था दीपजन कल्याण समिति, बरेली को अनियमितता के प्रति जिला शिक्षा परियोजना समिति, शाहजहांपुर के प्रस्ताव के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय-पत्र दिनांक 13-11-2019 द्वारा विद्यालय संचालन के दायित्व से पृथक कर दिया गया है।

5- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मिर्जापुर निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा विद्यालय में स्वच्छता एवं सुरक्षा की दृष्टि से छात्रावास के बाहर गैलरी में एक सी0सी0 टी0वी0 कैमरा लगवाने हेतु निर्देशित किया गया तथा शौचालय एवं स्नानघरों में

मरम्मत का कार्य नियमानुसार कराये जाने के निर्देश दिये गये। सहायक शिक्षा निदेशक के निर्देशों के क्रम में के0जी0बी0वी0 मिर्जापुर की वार्डेन द्वारा अवगत कराया कि उक्त कमियों का निराकरण करा लिया गया है।

6- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कटरा खुदागंज में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा लेखाकार के अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने तथा विभागीय कार्यों में रुचि न लिये जाने के कारण लेखाकार तथा वार्डेन की संविदा का वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण न करने का निर्णय लिया गया है। छात्राओं को मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जा रहा है, आर0ओ0 मशीन ठीक करा दी गयी है एवं नवीन बेडिंग का क्रय कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद से धनैटा में मन्स्या बम्बा तथा नौगावाँ में टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में

186-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद से गुजरने वाले धनैटा मन्स्या बम्बा तथा नौगावाँ बम्बा में टेल तक पानी सरकार पहुंचायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

निचली मांट शाखा खंड गंगा नहर मथुरा के अन्तर्गत राजवाहा कुरसण्डा (नौगावाँ बम्बा) मांट शाखा के कि0मी0 118.100 के बायें किनारे से निकलता है, जिसकी कुल लम्बाई 36.800 कि0मी0 तथा डिस्चार्ज 79 क्यूसेक है। रबी 1428 में राजवाहा कुरसण्डा (नौगावाँ बम्बा) की दिनांक 03-01-2021 को टेल्फीड करा दी गयी है।

राजवाहा दघैटा मांट शाखा के टेलभाग कि0मी0 128.800 के बायें किनारे से निकलता है जिसकी कुल लम्बाई 30.100 कि0मी0 है तथा डिस्चार्ज 120 क्यूसेक है। राजवाहा दघैटा की रबी 1428 फसली में दिनांक 17-12-2020 एवं दिनांक 10-01-2021 को टेलफीड कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

राजवाहा सादाबाद मांट शाखा के कि0मी0 97.243 के बाये किनारे से निकलता है, जिसकी कुल लम्बाई 46.300 कि0मी0 तथा डिस्चार्ज 242 क्यूसेक है। राजवाहा सादाबाद कि0मी0 35.400 से आगे क्षतिग्रस्त है। कि0मी0 35.400 तक दिनांक 31-12-2021 से 03-02-2021 तक निरन्तर पानी उपलब्ध कराया गया है।

ग्राम मन्श्या सादाबाद राजवाहा के कि0मी0 40.000 पर पड़ता है। राजवाहा के कि0मी0 35.400 से 46.300 तक पुनर्स्थापना हेतु परियोजना धनराशि रु0 559.55 लाख की मुख्य अभियन्ता समिति से अनुमोदित है। परियोजना पर धनावंटन उपरान्त पुनर्स्थापना का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद में ग्राम रैपुरा सरौठ व ब्लाक सहपऊ के ग्राम नगला प्राण (भोल) में ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण विषयक

187-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लॉक-सादाबाद के ग्राम रैपुरा सरौठ तथा ब्लाक सैहपऊ के ग्राम नगला प्राण (भोल) में ग्रामवासियों को शुद्ध जल हेतु पानी की टंकी का निर्माण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस ब्लाक सासनी अन्तर्गत अखईपुर मंदिर से दरकौली तक मार्ग का निर्माण कराने विषयक

188-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लॉक सासनी के अन्तर्गत अखईपुर मन्दिर से दरकौली (अखईपुर की सीमा) तक व ब्लॉक मुरसान में बगुली से कमालपुर तक मार्ग कच्चा है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

जी हाँ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अन्तर्गत अब केवल पुराने निर्मित मार्गों के उच्चीकरण का ही कार्य किया जा रहा है। अतः वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्णित मानकों से आच्छादित न होने के कारण प्रश्नगत मार्गों का निर्माण इस योजना के अन्तर्गत कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के के0जी0एम0यू0 में भ्रष्टाचार व सरकारी कार्यों में बाधा डालने के प्रकरण पर थाना चौक लखनऊ द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज न किये जाने के दोषियों पर कार्रवाई विषयक

189-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के के0जी0एम0यू0 में भ्रष्टाचार एवं सरकारी कार्यों में बाधा डालने आदि के प्रकरण पर के0जी0एम0यू0 की मा0 कार्य परिषद् के निर्णय एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों के क्रम में चीफ प्राक्टर द्वारा दिनांक 12/06/2020 के पत्रांक-1486-87/प्रा0/2020 के माध्यम से तहरीर देने के छः माह के बाद भी थाना चौक लखनऊ द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त प्रकरण पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रकरण के सम्बन्ध में पत्र संख्या-1486-87/प्रा0/2020, दिनांक 12-06-2020 के माध्यम से प्रो0 आर0ए0एस0 कुशवाहा, चीफ प्राक्टर, केजीएमयू, लखनऊ द्वारा प्रभारी निरीक्षक, चौक को सम्बोधित करते हुए श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी, कुलसचिव, केजीएमयू, लखनऊ के पत्र संख्या-3086/जी0ए0 सम्पति/2020, दिनांक 12-06-2020 व मा0 कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 08-06-2020 के lny otherAgenda (15)- item No-01 पर किये गये विनिश्चय पर मा0 कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त केजीएमयू, लखनऊ की प्रथम परनियमावली, 2011 के परिनियम 2.09(13) तीन में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की ओर से डा0 आशीष बाखलू, पदच्युत प्रोफेसर पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु पत्र उपलब्ध कराया गया था।

चीफ प्राक्टर, केजीएमयू लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 12-06-2020 की प्रारम्भिक जांच तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त, चौक, लखनऊ द्वारा की जा रही थी, जिसके क्रम में प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर चीफ प्राक्टर, केजीएमयू, लखनऊ द्वारा दिनांक 31-07-2020 को प्रभारी निरीक्षक, चौक, लखनऊ को प्रेषित-पत्र के द्वारा यह अवगत कराया गया कि मा0 कार्य परिषद् द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा कोई निर्णय लिये जाने के पश्चात् प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

इस सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक, चौक, लखनऊ द्वारा चीफ प्राक्टर, केजीएमयू, लखनऊ से दिनांक 17-02-2021 को स्थिति स्पष्ट कराने के उपरान्त प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक

18-02-2021 को थाना चौक, लखनऊ में मु0अ0सं0-56/2021, धारा-409/420 भादवि बनाम आशीष बाखलू के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग की विवेचना सम्पादित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग में स्टार्टअप योजना के अन्तर्गत जिलेवार पंजीकृत लोगों की संख्या व उक्त योजना में पंजीकरण हेतु बुंदेलखण्ड व पूर्वांचल क्षेत्रों हेतु विशेष उपाय विषयक

190-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीआईपीपी) में स्टार्टअप योजना के अन्तर्गत प्रदेश से जिलेवार पंजीकरण कराने वालों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार ने उक्त स्टार्टअप योजना में पंजीकरण कराने हेतु प्रदेश में बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्रों के लिए विशेष उपाय किये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

अद्यतन सूचना के अनुसार भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग में स्टार्ट-अप योजना के अन्तर्गत प्रदेश से पंजीकरण कराने वालों की कुल संख्या-3666 है। जी हाँ। प्रदेश शासन द्वारा घोषित नई "उ0प्र0 स्टार्ट-अप नीति 2020" के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रों के सापेक्ष पूर्वान्चल अथवा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय/परिचालन वाले स्टार्टअप्स को अतिरिक्त 50 प्रतिशत भरण-पोषण तथा विपणन सहायता- दोनों प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार स्टार्ट-अप्स को सहायता/ मार्गदर्शन देने वाले पूर्वान्चल अथवा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के निजी क्षेत्र के इन्क्यूबेटर्स के लिए भी विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली सल्टौवा गोपालपुर क्षेत्र में स्वच्छ जल योजनान्तर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने विषयक

191-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास क्षेत्र सल्टौवा गोपालपुर क्षेत्र में स्वच्छ जल योजना के तहत संचालित पाइप लाइन पेय जल योजना के अन्तर्गत 3 माह से पेय जल आपूर्ति का कार्य बाधित है ? यदि हां,

तो उक्त के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति हेतु विभाग को आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

ग्राम पंचायत सल्टौवा गोपालपुर में बने स्वच्छ पेयजल हेतु ओवर हेड टैंक में पानी पहुंच रहा है। ग्राम पंचायत के एक परिक्षेत्र में पानी पहुंच रहा है और दूसरे परिक्षेत्र में हैवी लीकेज होने के कारण सप्लाई बाधित है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम बस्ती द्वारा सही कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पंचायत में स्थापित कुल 45 हैण्डपम्प चालू हालत में है, जिससे ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा विश्वनाथगंज गोसाईगांव में विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु

192-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा विश्वनाथगंज गोसाईगांव में जमुना के खेत से रामनिवास के खेत तक, ग्राम सभा बोटानिया गोपिया में फूलचंद के घर से रंगीलाल के घर तक दूरी 150 मीटर, ग्राम सभा झाला में विनोद दंकी से कतर्निया में दुर्गा मंदिर तक दूरी लगभग 3 किलोमीटर, ग्राम सभा झाला में माखनलाल नेता के घर से जालिमनगर रोड तक दूरी लगभग 2 किलोमीटर तथा ग्राम सभा गिरगिट्टी में झुर्रा के घर से शिव मंदिर तक दूरी लगभग 100 मीटर सड़क निर्माण का कार्य न होने से लोगों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नही।

उपरोक्त कार्यों की अनुमानित लागत ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट से अत्यधिक होने के कारण कराया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा में प्रधानमंत्री रोड से मौरहवा में बाबूलाल के खेत तक सड़क निर्माण विषयक

193-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा बड़खड़िया में प्रधानमंत्री रोड से मौरहवा में बाबूलाल के खेत तक दूरी लगभग 4 किलो मीटर आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा बडखडिया में प्रधानमंत्री रोड से मौरहवा में बाबूलाल के खेत तक के स्थलीय निरीक्षणोपरान्त प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 1700 मीटर एवं मार्ग की औसत चौड़ाई 6.00 मीटर पाई गई है। जिला पंचायत द्वारा आर0सी0सी0 मार्ग का निर्माण नहीं किया जाता है, किन्तु आर0सी0सी0 के स्थान पर खडन्जा, सी0सी0 एवं लेपन कार्य कराये जाने का प्राविधान है। मार्ग की उपलब्ध चौडाई के दृष्टिगत उक्त मार्ग पर जिला पंचायत द्वारा खड़न्जा निर्माण हेतु नवीन जिला पंचायत बोर्ड के गठन के पश्चात् प्रस्ताव सदन के विचारार्थ रखा जाएगा एवं तत्पश्चात् सदन के निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा परसौना में ननकऊ की दुकान से शिवकुमार के घर तक सड़क का इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने विषयक

194-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा परसौना में ननकऊ के दुकान से शिवकुमार के घर तक 500 मीटर सड़क का इण्टरलॉकिंग का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उक्त कार्य ग्राम पंचायत की कार्य योजना वर्ष 2020-21 में सम्मिलित नहीं है। ग्राम पंचायत में शासन की प्राथमिकता के कार्य पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, प्राथमिकता विद्यालय, कायाकल्प एवं हैण्डपम्प मरम्मत/ रि-बोर आदि कराये जा रहे कार्यों के भुगतान के पश्चात् अवशेष धनराशि से कराया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत अपात्रों को लाभान्वित किये जाने विषयक

195-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अपात्रों को आवास दिये जाने कि शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार योजनान्तर्गत आवास प्राप्त लाभार्थियों के पात्रता, अपात्रता की जांच पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्डों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत अपात्रों को आवास दिये जाने की आईजीआरएस/आनलाइन 18 एवं आफलाइन 07 कुल 25 शिकायत प्राप्त हुयी है। उक्त शिकायतों की जांच करायी गयी जिसमें पाया गया कि पूर्व में ही जाँच कर नियमानुसार पात्र परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अपात्र को आवास दिये जाने का कोई प्रकरण नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

[12:21] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनायें ले रहा हूँ।

(सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लाल जी वर्मा-

कम से कम इतनी हाजिरी तो हो कि जो माननीय सदस्य मौजूद हों, उन्हीं का ध्यानाकर्षण लिया जाय। इसलिये कि वह सदन की प्रापर्टी बनती है। सदन में बिना रहे उनका कार्यवाही में आ जायेगा, यह उचित नहीं है।

(श्री विरेन्द्र कुमार यादव, श्री राम अचल राजभर एवं श्री संजय गर्ग के द्वारा कहने पर कि मान्यवर, हमारी भी नियम-301 में सूचना है।)

श्री अध्यक्ष-

अभी जुड़वा देंगे।

आज दिनांक 02-03-2021 को कुल 45 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिसमें 29 मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं एवं शेष सूचनाएं अस्वीकृत हैं।

पहली सूचना श्रीमती निर्मला संखवार की जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद अन्तर्गत झींझक स्थित सिकन्दरा बिल्हौर राज्य मार्ग के बीच में पड़ने वाले जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बम्ध में है, दूसरी सूचना श्री विजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर अन्तर्गत एन0आर0ई0सी0 महाविद्यालय खुर्जा को विश्वविद्यालय बनाने तथा विश्वविद्यालय का नाम प्रो0 राजेन्द्र सिंह उर्फ रज्जू भैया कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली अन्तर्गत ग्राम अहलादपुर से धराँवा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र कैन्ट में हुसैनगंज से डी0ए0वी0 कालेज तक बने उपरिगामी सेतु के दोनों तरफ सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पाँचवीं सूचना डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विकास खण्ड फरीदपुर अन्तर्गत टिसुआ से शिवपुरी होते हुए नगरिया कला मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्राम उमरी कला में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद अन्तर्गत आल्ट्राटेक सीमेन्ट तथा ए0पी0एस0 अपोलो के सामने तिराहे पर अन्डरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहाँपुर के तहसील तिलहर अन्तर्गत ग्राम चित्तीवोझी घनश्यामपुर में कतिपय भू-खण्डों पर अवैध कब्जा रोके जाने एवं भू-स्वामी को कानूनी संरक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री सुरेन्द्र मैथानी की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर अन्तर्गत कतिपय बस्तियों एवं गाँवों में सामुदायिक केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री आनन्द शुक्ला की जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर अन्तर्गत ग्राम ऊँचाडीह मजरा चमरौहा में बरदहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चतरा में स्वीकृत इण्टर कालेज का बाधित निर्माणाधीन कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत चिलकहर विद्युत स्टेशन एवं सब-स्टेशन से विभिन्न ग्रामों में जाने वाली जर्जर विद्युत लाइन को बदले जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद अन्तर्गत ग्राम ताहरपुर इशाक में मकानों के ऊपर से 11 हजार एच0टी0 विद्युत लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट अन्तर्गत ब्लाक मुजफ्फराबाद में स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर सदर अन्तर्गत ग्राम उमाही से ग्राम कोटा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा अन्तर्गत मौरावां, मोहनलालगंज, उन्नाव मुख्य मार्ग से

बाबा बिलेश्वरधाम तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चंदौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा अन्तर्गत मुगलसराय, भुपौली, चहनियाँ मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ अन्तर्गत ग्राम राजेपुर में होमियोपैथिक चिकित्सालय की नई बिल्डिंग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी के ग्राम सभा धौरहरा अन्तर्गत डॉ0 भीम राव अम्बेडकर रैन बसेरा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में अधिग्रहीत जनपद सुल्तानपुर एवं जनपद अमेठी के किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा यू0पी0पी0सी0एस0 2021 में एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री मोहम्मद फईम इरफान की जनपद मुरादाबाद अन्तर्गत मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाई-वे पर गतिरोधक लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री विजय कुमार राजभर की जनपद प्रयागराज के न्यायनगर में सड़क पर इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना पं0 रत्नाकर मिश्र की जनपद मिर्जापुर एवं जनपद भदौही के बीच पड़ने वाले जोपा रामपुर घाट-गोपीगंज के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र यादव की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत महमूदपुर चट्टी से मानपुर कहोतरी तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर विद्युत व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम मंशापुर में बाबा डम्मर दास तपोस्थली एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना डॉ0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड दानपुर अन्तर्गत ग्राम डीरौरा में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा उन्तीसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की ई-कामर्स के विस्तार के कारण छोटे-बड़े स्टोर और पराम्परिक दुकानों को चलाने वालों का व्यापार बन्दी के कगार पर पहुँचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :-

श्री प्रेमसागर पटेल, श्री सत्यवीर त्यागी, श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया, श्री कमल सिंह मलिक, श्री ओमकुमार, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री प्रेम नरायण पाण्डेय, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री सुभाष पासी, श्री अबरार अहमद, श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री बम्बा लाल, श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री श्रीकान्त कटियार तथा श्री बैजनाथ रावत।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद अन्तर्गत झींझक स्थित सिकन्दरा बिल्हौर राज्य मार्ग के बीच में पड़ने वाले जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराये जाये के संदर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती निर्मला संखवार-

[महोदय, मेरी विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले झींझक टाउन एरिया में सिकन्दरा बिल्हौर राज्य मार्ग के बीच में पड़ने वाली नहर पर एक पुल जो आजादी के पूर्व में बना था उसकी समय सीमा 100 वर्ष के ऊपर हो चुकी है इस पर विभाग द्वारा पुल के जर्जर होने का बोर्ड भी लगा दिया गया है। इस पर कभी भी हादसा हो सकता है, अतः आपके माध्यम से मेरा कहना है कि इस पुल को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा निर्माण कराये जाने का आदेश करें।]

जनपद बुलन्दशहर अन्तर्गत एन0आर0ई0सी0 महाविद्यालय खुर्जा को विश्वविद्यालय बनाने तथा विश्वविद्यालय का नाम प्रो0 राजेन्द्र सिंह उर्फ रज्जू भैया कराये जाने से संदर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजेन्द्र सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खुर्जा जनपद बुलन्दशहर में एन0आर0ई0सी0 कालेज स्थित है जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी यह विश्वविद्यालय बनने के सारे मानक पूरे करता है। 2012 में यू0जी0 से नैक में ए0 ग्रेड प्राप्त है। मेरठ विश्वविद्यालय से पांच संकाय बी0एड0 विधि संकाय, विज्ञान, कला, वाणिज्य अनुमोदित है व एन0आर0ई0सी0 कालेज की लगभग 55 एकड़ भूमि है। खुर्जा की सी0सी0एस0 विश्वविद्यालय, मेरठ से 95 किलो मीटर दूरी है। प्रत्येक वर्ष कालेज में दस हजार संस्थागत व व्यक्तिगत विद्यार्थी अध्ययन करते है। खुर्जा शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एम0आर0ई0सी0 कालेज में गौतमबुद्धनगर व अलीगढ़ के भी छात्र-छात्राएं अध्ययन करने आते हैं। खुर्जा जिला गौतमबुद्धनगर व अलीगढ़ की सीमाओं से लगा हुआ है यह भी अनुरोध है कि कालेज की विभागीय जांच इस दृष्टि से कराने की कृपा करें क्योंकि कालेज सभी मानक पूर्ण करता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत ग्राम अहलादपुर से धराँव मार्ग का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में नियम-301 के अंतर्गत सूचना

डा0 अनिल कुमार मौर्य-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली ग्राम अहलादपुर से धरावॉ तक सड़क अभी तक कच्ची है, अहलादपुर गाँव सीतापुर रोड से 6 किलोमीटर अन्दर हैं, मुख्य मार्ग तक आने के लिए अहलादपुर ग्रामवासियों को लगभग 2 किलोमीटर तक कच्चे मार्ग से होकर

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम धरावां तक आना पड़ता है। बरसात के दिनों में मार्ग में पानी भर जाने के कारण मुख्य मार्ग तक आने के लिए बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं।

उक्त सड़क को डामर रोड बनाये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र कैन्ट में हुसैनगंज से डी0ए0वी0 कालेज तक बने उपरिगामी सेतु के दोनों तरफ सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने से संदर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कैन्ट लखनऊ की प्रमुख समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ निर्वाचन क्षेत्र कैन्ट लखनऊ में गुरूगोविन्द सिंह मार्ग पर हुसैनगंज से डी0ए0वी0 कॉलेज तक **श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेई** उपरिगामी सेतु का निर्माण हुआ जिस कारण से हुसैनगंज से लेकर डी0ए0वी0 कॉलेज तक उपरिगामी सेतु के नीचे दोनों तरफ सड़क जर्जर हो चुकी है जिस कारण से दुर्घटनाएं हो रही हैं।

अतः इस गंभीर समस्या के निराकरण हेतु पुल के दोनों तरफ सड़क का पुनर्निर्माण तत्काल कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के विकास खण्ड फरीदपुर के अन्तर्गत टिसुआ से शिवपुरी होते हुए नगरिया कलां मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-122 फरीदपुर जनपद बरेली के विकास खण्ड फरीदपुर के टिसुआ से शिवपुरी होते हुए नगरिया कलां मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। इस मार्ग से लगभग 100 गांवों का आवागमन होता है। नगरिया कला में लगने वाले रामगंगा के मेले में आने वाले श्रद्धालुओं का भी इसी मार्ग से आवागमन होता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्राम उमरी कलां में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुर मनिहारन के ग्राम सभा उमरी कलां मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। जिसके लिए ग्राम सभा की 100 बीघा सरकारी जमीन भी उपलब्ध है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम सभा उमरी कलां में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद अन्तर्गत आल्ट्राटेक सीमेन्ट तथा ए0पी0एल0 अपोलो के सामने तिराहे पर अण्डर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-34 (91) पर औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में मेसर्स आल्ट्राटेक सीमेन्ट तथा ए0पी0एल0 अपोलो के सामने तिराहे पर अण्डरब्रिज न होने के कारण वाहनों के मुड़ने तथा लोगों के सड़क पार करने पर अत्यधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें काफी संख्या में मृत्यु हुई है। पिछले माह में वहाँ पर दो पी0ए0सी0 के जवानों की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। मानव क्षति को रोकने के लिए वहाँ पर अण्डरब्रिज बनना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद शाहजहाँपुर के तहसील तिलहर के अन्तर्गत ग्राम चित्तीवोझी धनश्यामपुर में कतिपय भू-खण्डों पर अवैध कब्जा रोके जाने एवं भू-स्वामी को कानूनी संरक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि हरिपाल एवं अन्य लोग समस्त निवासीगण ग्राम चित्तीवोझी घनश्यामपुर, तहसील-तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर के **ग्राम में स्थित गाटा संख्या कमशः 195, 200, 211/1, 211/7, 43/15, 127 व 126 पर दबंग भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, जिससे उक्त लोग दहशत में है।** पीड़ित पक्ष द्वारा जिला स्तर के अधिकारियों से शिकायत की गयी, परन्तु उसकी कोई सुनवाई नहीं है और सम्बन्धित अधिकारियों का संरक्षण भूमाफियाओं को प्राप्त होना प्रतीत हो रहा है। जनहित में दबंग व भूमाफिया को पीड़ित पक्ष हरिपाल उपरोक्त की भूमि पर कब्जा करने से रोका जाना, पीड़ित पक्ष को कानूनी संरक्षण दिलाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत कतिपय बस्तियों एवं गांवों में सामुदायिक केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

[महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि, गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अत्यधिक मलिन बस्तियां/गाँव आते हैं। बस्तियों/गाँव के नाम निम्न हैं-मसवानपुर बस्ती, दबौली गाँव, गुजैनी गाँव, अम्बेडकर नगर मलिन बस्ती, दादा नगर कच्ची बस्ती, जमुई गाँव, सरांयमीता आदि और यहाँ लाखों की आबादी है, परन्तु इन क्षेत्रों में सामुदायिक केन्द्र नहीं है। समुचित स्थान न होने के कारण कार्यक्रम को सम्पन्न करने हेतु लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है। जिसके कारण किसी भी सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रम एवं विवाह आदि के लिये क्षेत्रवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित के आधार पर गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण होना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर अन्तर्गत ग्राम ऊँचाडीह मजरा चमरौहा में बरदहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आनन्द शुक्ला-

[महोदय, जनपद चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र 237-मानिकपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-ऊँचाड़ीह, मजरा-चमरौंहा, वि0खं0 मानिकपुर में बरदहा नदी पर ऊँचा/पिलरदार पुल बनाया जाना आवश्यक है। वर्तमान में बने पुल पर बरसात के दिनों में पानी पुल के ऊपर बहता है और उस दौरान कई गाँव प्रभावित हो जाते है। जिसमें जनमानस को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त पुल का निर्माण होने से जनमानस को आवागमन में सुगमता होगी। उक्त कार्य हेतु मेरे द्वारा शासन प्रशासन स्तर पर प्रयास किया गया परन्तु अब तक कार्य निष्पादित नहीं हो पाया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चतरा में स्वीकृत इण्टर कालेज का बाधित निर्माणाधीन कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भूपेश चौबे-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के स्थित ब्लाक चतरा अन्तर्गत ग्राम खुज्झा में सरकार द्वारा एक राजकीय इण्टर कालेज स्वीकृत किया गया है जिसके

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिए सरकार द्वारा धन आवंटित कर कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया। परन्तु कतिपय कारणों से निर्माण कार्य रोक दिये जाने से इस कालेज का निर्माण पूर्ण न होने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जनहित में निर्माणाधीन कालेज में उत्पन्न बाधा को दूर करते हुए समयबद्ध सीमा में कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ किया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद सोनभद्र के स्थित ब्लाक चतरा अन्तर्गत ग्राम खुज्झा में सरकार द्वारा एक राजकीय इण्टर कालेज स्वीकृत निर्माणाधीन कालेज की बाधाओं को दूर करते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत चिलकहर विद्युत स्टेशन एवं सब-स्टेशन से विभिन्न ग्रामों में जाने वाली जर्जर विद्युत लाइनों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि रसड़ा विधान सभा के चिलकहर ब्लाक में विद्युत आपूर्ति हेतु रसड़ा मेन फीडर से चिलकहर 33 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन तक एवं विद्युत सब-स्टेशन से विभिन्न ग्राम सभाओं में विद्युत आपूर्ति हेतु लगे लगभग 50 वर्ष पुराने जर्जर तारों के टूटने की वजह से आये दिन विद्युत दुर्घटनायें कारित हो रही हैं जिससे कई लोगों घर/मवेशी आदि जल गये तथा हर समय दुर्घटना के कारण जन-धन हानि की प्रबल संभावना बनी रहती है और प्रायः घटनायें होती भी रहती है जिससे यहां की जनता आक्रोशित है। विद्युत सम्बन्धी दुर्घटनायें न कारित हों इस हेतु लगभग 50 वर्षों पुराने लगे समस्त जर्जर तारों का बदला जाना अति आवश्यक है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर उपरोक्त रसड़ा फीडर से चिलकहर विद्युत सब-स्टेशन एवं सब-स्टेशन से विभिन्न ग्रामों में जाने वाली लगभग 50 वर्षों पूर्व लगी जर्जर विद्युत लाइनों को बदले जाने हेतु शासन से कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम ताहरपुर इशाक में मकानों के ऊपर से 11 हजार एच0टी0 विद्युत लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद -

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम-ताहरपुर इशाक में विद्युत विभाग ने गाँव के बीचो-बीच मकान के ऊपर से 11 हजार एच0टी0 विद्युत लाइन जबरदस्ती निकाल दी जिसके

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण 6 माह पहले एक लड़का 15 वर्ष का अपने छत पर खड़ा होने के कारण करेन्ट लगने से मृत्यु हो गयी थी। जिसका नाम फैसल था। इसके पूर्व भी इसी 11 हजार विद्युत लाइन का तार टूटने के कारण घेर में बंधी दो भैस व दो बकरी की बिजली का तार टूटकर गिरने के कारण मृत्यु हो गयी थी एवं मकान मालिक का भी काफी नुकसान हुआ था। बार-बार विद्युत विभाग से शिकायत करने पर भी यह विद्युत लाइन हटाई नहीं जा रही है। जिसके कारण आम जनमानस को हानि हो रही है। ऐसी दशा में उपरोक्त लाइन का मकानों के ऊपर से जनहित में हटना बहुत जरूरी है। जिससे कि भविष्य में होने वाली जनहानि को बचाया जा सके।

मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत ब्लाक मुजफ्फराबाद में स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी-

[महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 01 बेहट जनपद सहारनपुर अन्तर्गत पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किये गये थे जिनमें ग्राम ननौली ब्लाक मुजफ्फराबाद में निर्माणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का कार्य अधर में लटका हुआ है, इसी तरह मेरे क्षेत्र अन्तर्गत ही ब्लाक मुजफ्फराबाद में भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त भी बजट के अभाव में निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उपरोक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सुचारू रूप से पूर्ण न होने के कारण क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जनप्रतिनिधियों को जनता की जबावदेही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर उक्त दोनों स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को पूर्ण निर्माण किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर सदर के अन्तर्गत ग्राम उमाही से ग्राम कोटा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[महोदय, जनहित में अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 4, सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम उमाही से ग्राम कोटा तक सड़क न होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रकरण जनहित से जुड़ा हुआ है। अतएव जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम उमाही से ग्राम कोटा तक सड़क का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत मौरावां मोहनलालगंज-उन्नाव मुख्य मार्ग से बाबा बिलेश्वर धाम तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र-167, पुरवा उन्नाव के अन्तर्गत मौरावां मोहनलालगंज-उन्नाव (एम0एम0यू0) मुख्य मार्ग से प्राचीन एवं ऐतिहासिक बाबा बिलेश्वर धाम को जाने वाला रास्ता अति जर्जर एवं गड्ढायुक्त है। उक्त जर्जर मार्ग होने के कारण क्षेत्रीय एवं अन्तर्जनपदीय बाबा भोले नाथ के भक्तों को दर्शन हेतु आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं सावन मास में लगने वाले मेले में श्रद्धालुओं की भारी-भरकम भीड़ को इसी जर्जर रास्ते से जोखिमों से गुजरना पड़ता है। उक्त मार्ग न बनवाये जाने के कारण क्षेत्रीय जनता में जनाक्रोश व्याप्त है। उक्त रोड बनवाये जाने को लेकर शासन एवं सरकार से अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत मुगलसराय, भुपौली, चहनियां मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत मुगलसराय, भुपौली चहनियां मार्ग बना हुआ है। यह मार्ग वर्तमान समय में बहुत ही खराब हो गया है। जिसका सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण किया जाना जनहित में आवश्यक है। एशिया का माना जाना रेलवे स्टेशन जो पूर्व में मुगलसराय के नाम से जाना जाता था, उसको परिवर्तन कर वर्तमान समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। गंगा नदी में बलुआ घाट एवं सैदपुर घाट पर बने पुल को भी जोड़ता है। ऐसी स्थिति में मुगलसराय, भुपौली चहनियां मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम राजेपुर में होम्योपैथिक चिकित्सालय की नई बिल्डिंग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ के ग्राम राजेपुर में होम्योपैथिक

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चिकित्सालय का भवन खण्डहर होकर गिर चुका है। भवन किराये के कमरे में चल रहा है। यह माँ गंगा और कल्याणी के मध्य 20 किलोमीटर के क्षेत्र में लाखों आबादी के बीच मात्र एक होम्योपैथिक चिकित्सालय है। यह जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए होम्योपैथिक चिकित्सालय राजेपुर की नई बिल्डिंग बनवाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद वाराणसी के ग्राम सभा धौरहरा के अन्तर्गत डा0 भीमराव अम्बेडकर रैनबसेरा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

[महोदय, आपके माध्यम से जनपद वाराणसी के ग्राम सभा धौरहरा की ओर सदन का ध्यान अकृष्ट कराना चाहता हूँ, जहां अनुसूचित जाति की बस्ती के निराश्रितों एवं गरीबों के लिए रैनबसेरा नहीं होने के कारण गरीब, असहाय व निराश्रित लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण उक्त लोगों के रहने के लिए डा0 भीमराव अम्बेडकर रैनबसेरा का निमार्ण कराये जाने हेतु शासन/प्रशासन से कई बार अनुरोध करने के बाद भी अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है, जिस कारण आम-जनमानस में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त स्थान पर डा0 भीमराव अम्बेडकर रैनबसेरा का निमार्ण कराये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में अधिग्रहीत जनपद सुल्तानपुर एवं जनपद अमेठी के किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[महोदय, जनपद अमेठी तथा सुल्तानपुर के किसानों की जमीन (खेत) पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे में ले ली गयी है, परन्तु उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। उदाहरणार्थ मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राम जरईकला, परगना इसौली, तहसील बल्दीराय, जिला सुल्तानपुर में खाता संख्या-132 गाटा संख्या-788 रकबा 0.1010 के सह-भूमिधर श्री चरन सिंह पुत्र श्री विन्देश्वर सिंह, ग्राम मऊऊ परगना अमेठी, तहसील गौरीगंज, जनपद अमेठी को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। खेती का मुआवजा न मिलने से जनता में रोष है।

अंत मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये सरकार से मांग करता हूँ कि पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे में ली गयी जनपद-सुल्तानपुर और अमेठी के किसानों की जमीन का मुआवजा शीघ्र प्रदान किया जाय।]

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा यू0पी0पी0सी0एस0-2021 में एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि वर्ष 2020 कोरोना महामारी से प्रभावित होने के कारण अधिकांश परीक्षार्थी पी0सी0एस0 परीक्षा, 2020 में सम्मिलित नहीं हो

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सके तथा कई ओवरएज हो गये है। कुछ पीड़ाए हैं यथा-परिजनों का कोरोना से पीड़ित होना, तैयारी का पर्याप्त अवसर न मिल पाना, कोविड गाइडलाइन के कारण समुचित यातायात का अभाव रहा है।

1- महोदय, कोरोना प्रकृति जन आपदा से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। सरकार प्रतिबंधों की लम्बी फेहरिस्त थी, जो भी जिस जगह था उस जगह फंस गया। गति एवं मति कुन्द हो गयी। पठन-पाठन शूय हो गया। अपने अजीज को खोने का दुख एवं डर के महौल में किसी तरह से जीवन सुरक्षित रखना सर्वोपरि रहा है। ऐसे भयावह स्थिति में किसी के ज्ञान का परीक्षण कितना प्रासंगिक था। परीक्षार्थियों के जीवन को कोरोना महामारी के भेंट चढ़ा देना कहां तक तर्कसंगत था।

2- विभिन्न प्रदेशों के सरकारों द्वारा यथा उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड इत्यादि ने परीक्षार्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी संघ लोक सेवा आयोग को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया है।

3- वर्ष 2020 में आयोजित अधिकांश परीक्षाओं में उपस्थिति अत्यल्प रही है, समीक्षा अधिकारी 2016 में मात्र 36 प्रतिशत उपस्थिति रही है। अतः इस वर्ष जो परीक्षार्थी ओवरएज हो गये हैं एवं कैरियर पूरी तरह से खराब हो गया है, उनको अतिरिक्त अवसर देना न्यायसंगत होगा।

अतः माननीय सदन से विनम्र प्रार्थना है कि मानवीय संवेदन एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए सागर समान विशाल हृदय का परिचय देते हुए 2020 में पीड़ित परीक्षार्थियों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का कष्ट करें।

उपरोक्त स्थिति के कारण परीक्षार्थियों में भारी आक्रोश है। अतः सदन में इस लोक महत्व के विषय की गम्भीर स्थिति पर अविलम्बनीय चर्चा कराने की कृपा करें।]

जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाई-वे पर गतिरोधक लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

मो0 फईम इरफान-

[महोदय, मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाई-वे (एन0एच0-93) मुरादाबाद जनपद के तहसील बिलारी से होकर निकला है। उक्त हाई-वे पर वाहनों की गति अति तीव्र होती है। उक्त नेशनल हाई-वे पर नगर बिलारी में ही डाकबंगला, तहसील, थाना, ब्लाक और सरकारी एवं सहकारी बैंक थोड़ी-थोड़ी दूरी पर स्थित हैं। उक्त नेशनल हाई-वे पर कई मुख्य चौराहे जैसे- गांधी मूर्ति का चौराहा, शाहाबाद चौराहा आदि है। हाई-वे पर वाहनों की गति तेज होने के कारण नगर बिलारी में हादसों के दौरान लोगों के अलावा पुलिस कर्मियों की भी हाई-वे पर

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो चुकी है। उक्त हाई-वे पर न तो कोई गतिरोधक बने हुये हैं और न ही दुर्घटना सम्भावित और न ही स्पीड सम्बन्धी सूचना लगी है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सम्बन्धित तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद के अन्तर्गत मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाई-वे (एन0एच0-93) पर गतिरोधक लगवाये जाने की व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के न्याय नगर में सड़क पर इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार राजभर -

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि न्याय नगर अब्बु बक्करपुर मस्जिद के पीछे वाली गली, घुमनगंज स्थित मनीष कुमार रावत 11के/5वाई/3जेड के मकान से विकास गुप्ता के मकान तक सड़क बहुत जर्जर स्थिति में है। जिससे वहाँ निवास कर रहे लोगों को अत्यन्त असुविधा होती है।

अतः मैं सदन के माध्यम से उक्त सड़क पर इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर एवं जनपद भदोही के बीच पड़ने वाले जोपा रामपुर घाट-गोपीगंज के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रत्नाकर मिश्र-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अविलम्बनीय विषय में कराना चाहूँगा कि जनपद मिर्जापुर एवं जनपद भदोही के बीच में पड़ने वाले जोपा रामपुर घाट-गोपीगंज के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना जनहित के कार्य हेतु अति आवश्यक है। पुल न बने होने से आयेदिन वहाँ के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर जनपद मिर्जापुर एवं जनपद भदोही के बीच में पड़ने वाले जोपा रामपुर घाट-गोपीगंज के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत महमूदपुर चट्टी से मानपुर कहोतरी तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का गम्भीर विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत महमूदपुर चट्टी से मानपुर कहोतरी होते हुए भडसर अविसहन मार्ग तक चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराया जाना है। इस मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन बना रहता है। जिसके कारण आयेदिन यह मार्ग खराब हो जाता है। जिस पर चलने

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लायक नही रहता है। ऐसी स्थिति में उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त प्रकरण पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर विद्युत व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

[महोदय, आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि खड्डा विधान सभा क्षेत्र में जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के उपरान्त हमारी सरकार ने निरन्तर विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु सकारात्मक पहल की है, जिसका लाभ हमारे क्षेत्रवासियों को भी प्राप्त हो रहा है, 18 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ ही साथ जर्जर तार, पोल व ट्रांसफार्मर बदले गए, परन्तु कुछ क्षेत्र में बुनियादी विकास के साथ ही विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसके संदर्भ में लगातार पत्राचार के माध्यम से निवेदन/आग्रह किए गए हैं, परन्तु इसके अतिरिक्त कोई जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो इस प्रकार है, कृपया बताने का कष्ट करें कि-

- खड्डा विधान सभा क्षेत्र में रेता उस पार में पिछले 6 महीने से विद्युत आपूर्ति बन्द है उसे कब तक प्रारम्भ करा दिया जाएगा ?
- खड्डा विधान सभा क्षेत्र में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना के लिए क्या किसी योजना पर कार्य किया जा रहा है ?
- खड्डा विधान सभा क्षेत्र में जर्जर तार और पोल कब तक बदल दिया जायेगा ?
- ग्रामीणों के बकाए गलत बिल का सुधार का कार्य कब तक पूर्ण कराया जाएगा। क्या इस दिशा में कोई विशेष अभियान चलाये जाने की योजना है ?
- खड्डा विधान सभा क्षेत्र में स्थित विद्युत व्यवस्था सुधार हेतु ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ?
- नवसृजित नगर पंचायत छितौनी में विद्युतीकरण कार्य हेतु कोई विशेष योजना प्रस्तावित है ?

माननीय मंत्री जी के माध्यम से उपरोक्त के संदर्भ में जानकारी प्रदान करने की कृपा करें।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम मंशापुर में बाबा डम्मर दास की तपोस्थली एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, जिला अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मंशापुर में बाबा डम्मर दास की तपोस्थली स्थित है। उनकी तपोस्थली में ही 6 बीघा की भूमि पर तालाब स्थित है। वर्तमान में उक्त तालाब की दशा अत्यन्त खराब है। जिसका सौन्दर्यीकरण होना अति आवश्यक है, क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से उक्त तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार शासन से अनुरोध किया गया है, जबकि सरकार द्वारा इस प्रकार के कई तपोस्थली धामों का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जा रहा है, परन्तु अभी तक उक्त तपोस्थली में स्थित तालाब आदि का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने हेतु कोई कार्रवाई नही हो सकी है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराते हुए अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मंशापुर में बाबा डम्मर दास की तपोस्थली में स्थित तालाब का जनहित में सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड दानपुर के अन्तर्गत ग्राम डिरौरा में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनीता लोधी राजपूत-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबई, विकास खण्ड-दानपुर अन्तर्गत ग्राम डिरौरा में पेयजल की अत्यन्त समस्या है। यहाँ के ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए दूर-दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। यहाँ की आबादी लगभग ढाई हजार के करीब है। जनहित में पेयजल की समस्या का समाधान एवं पानी की टंकी का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

ई-कॉमर्स के विस्तार के कारण छोटे-बड़े स्टोर और पारम्परिक दुकानों को चलाने वालों का व्यापार बन्दी के कगार पर पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[महोदय, लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है कि प्रदेश में छोटे-बड़े स्टोर और पारम्परिक दुकानों पर व्यापार करने वाले व्यापारी को ई-कामर्स के बढ़ते प्रभाव से बहुत परेशानी है। उसे अपने परिवार का पालन-पोषण करना दूभर

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हो रहा है। नीति आयोग के सी0ई0ओ0 श्री अमिताभ कान्त जी का बयान आया है कि 8 वर्ष में मोहल्ले के दुकानदार गायब हो जायेंगे। न दुकानें दिखेंगी और न ही सामान बेचते दुकानदार। प्रदेश में अपनी छोटी-छोटी पूंजी लगाकर स्वरोजगार के जरिये व्यापारी अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा है। उसके पास कोई दूसरी आय की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है।

अतः प्रदेश की मानवीय ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग के मद्देनजर ई-कामर्स को हतोत्साहित करना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए निर्देशित करने का कष्ट करें।]

[12:24] उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2021 को पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 फरवरी, 2021 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 फरवरी, 2021 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021 जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 फरवरी, 2021 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु

अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2021 को पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 फरवरी, 2021 को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-3 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-4 लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप ही हाजिरी कराते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि उपस्थित किया हुआ मान लिया जाये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो खड़े हो जायें, उनका प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाये। आप नाम बोलें और सदस्य खड़े हो जायें और उसके बाद उनका मान लें।

***श्री विजय कुमार राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है कि सारे सदस्य पढ़ना चाहते हैं। क्षेत्र की जनता सुनती है, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग आये हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। वर्मा जी चाहते थे कि इन्हीं की फोटो जाये, आपकी न जाये। (हंसी)

(इस समय अपराह्न 12 बजकर 27 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता-

अब मद संख्या-4 लेते हैं।

[12:27] श्री बृजेश कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित छः याचिकाएं†

श्री बृजेश कुमार रावत-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड औरास के ग्राम सीमा में सरकारी भूमि लगभग 60 बीघा में चावल से बनने वाले उत्पादों हेतु औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किए जाने विषयक श्री विपिन मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापी नही गयीं।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हसनगंज की ग्राम सभा घूरामऊ में आम से बनने वाले उत्पाद हेतु औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कराये जाने विषयक डा0 रामेश्वर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हसनगंज के ग्राम इब्राहिमपुर में सम्पर्क मार्ग से ग्राम फिरोजाबाद तक 7 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत सिंह, निवासी जनपद उन्नाव की याचिका,

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम मकूर में राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण दीक्षित, निवासी जनपद उन्नाव की याचिका,

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के कतिपय ग्रामों की सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राघवेन्द्र सिंह, निवासी जनपद उन्नाव की याचिका तथा

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज व हसनगंज के कतिपय ग्रामों की सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सत्यपाल सिंह, निवासी जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अपनी एक-एक याचिका को पढ़ दें, शेष याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी जाएगीं।

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन से संबंधित पाँच याचिकाएं[†]

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र-कालपी के ग्राम रायड़ दिवारा में लक्ष्मणदास आश्रम को यमुना के कटाव से बचाने के सम्बन्ध में श्री रामसेवक व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र कालपी, विकास खण्ड कुठौंद के ग्राम जुगराजपुर में चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु एक उप स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने के सम्बन्ध में श्री विपिन सिंह सेंगर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र कालपी, विकास खण्ड कुठौंद के ग्राम जुगराजपुर में जल संग्रहण करने हेतु तालाब का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री विपिन सिंह सेंगर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम रैपुरा, पंचायत मड़ोरी में ग्राम सम्पर्क मार्ग को पक्का कराने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

[†] छापी नही गयीं।

5-जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र कालपी, विकास खण्ड कुठौंद के ग्राम जुगराजपुर में छात्राओं हेतु एक कन्या इण्टर कालेज बनवाने के सम्बन्ध में श्री विपिन सिंह सेंगर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं†

श्री मो0 फईम इरफान-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम रसूलपुर गौसर से ग्राम खाबरी गन्दू होते हुए मैनाठेर तक लगभग 2 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम देवरी से ग्राम रतनपुर रोड तक लगभग 500 मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशुपाल, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम बिचौला कुन्दरकी से राजा का सहसपुर स्टेशन रोड सम्पर्क मार्ग तक लगभग 1 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री माजिद हुसैन, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम रूस्तमनगर सहसपुर तक लगभग 2 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र चौधरी, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

5-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम मिलक नगलिया जट से ग्राम खाबरी अब्बल तक लगभग 3 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गईं।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री मूलचन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत उमरी पतराही जगम्मनपुर मार्ग पर पतराही आबादी भाग में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/सी0सी0 व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित उन्नीस याचिकाएं†

श्री विजय कुमार राजभर-

1. मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के विकास खण्ड परदहां के अन्तर्गत ग्राम सभा रणवीरपुर में सुरेन्द्र राजभर के घर से सुबच्चन के घर तक नाली, पटिया एवं आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भुजारथ राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नही गयीं।

2. जनपद मऊ के विकास खण्ड परदहां के अन्तर्गत ग्राम भार में अम्बेडकर मूर्ति से खरगमेपुर भार हरिजन बस्ती होते हुए पिचरोड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री श्रीकान्त यादव व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

3. जनपद मऊ के विकास खण्ड परदहां के अन्तर्गत पं0 पुरा चौहान बस्ती से इटौरा प्राइमरी स्कूल तक पिचरोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्हकू व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

4. जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत सरायगनेश और करमा महरूमपुर के पास नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोरख चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

5. जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत सरायगनेश माइनर पर सरयूपुर और रसूलपुर गांव के पास स्कूल के सामने पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दूधनाथ चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

6. जनपद मऊ, तहसील घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा माउरबोझ में पिढवल मार्ग से शिवमुनी चौहान के घर तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवमुनी चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

7. जनपद मऊ, तहसील घोसी के विकास खण्ड बडरांव के अन्तर्गत मीरपुर माइनर पर शहाना के घर से कमाल के घर तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

8. जनपद मऊ, तहसील सदर के विकास खण्ड परदहां के सिहांव हरिजन बस्ती से मोहन के ट्यूबवेल से होते हुए अहिलाद गांव तक पिच रोड व पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालता व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

9. जनपद मऊ, तहसील सदर के विकास खण्ड रतनपुरा के अन्तर्गत ग्राम सभाखोहिया में शिवप्रकाश राजभर के घर से बल्ली राजभर के घर तक नाली, पटिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री आरूषी व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

10. जनपद मऊ, तहसील सदर के विकास खण्ड रतनपुरा के अन्तर्गत ग्राम सभा मुबारकपुर में बल्ली राजभर के घर से जूनियर स्कूल तक नाली, पटिया एवं पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री राहुल गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

11. जनपद मऊ, तहसील सदर के विकास खण्ड रतनपुरा के अन्तर्गत ग्राम सभा खोहिया में श्री प्रकाश के घर से शेषनाथ गुप्ता के घर तक नाली, पटिया एवं आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेषनाथ गुप्ता अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

12. जनपद मऊ, तहसील सदर के विकास खण्ड रतनपुरा के अन्तर्गत ग्राम सभा खोहिया में नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबहादुर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

13. जनपद मऊ, तहसील घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा पिढ़वल में मुख्य सड़क से राम नारायन की चक्की तक नाली, पटिया एवं आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भागीरथी व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

14. जनपद मऊ, तहसील घोसी के नगर पालिका घोसी के अन्तर्गत नरोखर में स्थित पोखरे का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

15. जनपद मऊ तहसील घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा लाखीपुर में स्थित लखीरा बाबा मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

16. जनपद मऊ के विकास खण्ड परदहां के अन्तर्गत रैकबारडीह बाजार में बढ़ुआ गोदाम कांझा मार्ग से लालता के खेत होते हुए भर बस्ती तक मार्ग पर डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री आदित्य सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

17. जनपद मऊ के तहसील घोसी के विकास खण्ड बडरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा कपरियाडीह में मीरपुर माइनर पर शहाना के घर से कमाल के पर तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराने के सम्बन्ध श्री राजू प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

18. जनपद मऊ के तहसील घोसी के विकास खण्ड बडरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा कपरियाडीह में मीरपुर माइनर पर राजू प्रजापति के मकान के पास पुलिया का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री राजू प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका तथा

19. जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड रतनपुरा के अन्तर्गत थाना हलधरपुर से शाहूपुर चौराहे तक सड़क मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से संबंधित दो याचिकाएं[†]

श्री विनोद कटियार-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के विकास खण्ड सरवन खेड़ा के कतिपय ग्रामों की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल यादव व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित करता हूं तथा

2-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के विकास खण्ड मलासा के कतिपय ग्रामों की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर नवीनीकरण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप सचान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

[†] छापी नही गयीं।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से संबंधित पाँच याचिकाएं†

श्री हाकिम लाल बिन्द-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड हण्डिया के अन्तर्गत अमरबहादुर भारतीय इण्टरमीडिएट कालेज दीलीपचन्द्रपुर से बिन्द एवं मौर्या बस्ती का अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य इण्टरलॉकिंग कराने के सम्बन्ध में श्री अभयेन्द्र बहादुर भारती व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत अमरनाथ बिन्द के दुकान के सामने से कांगापुर बिन्द बस्ती होते हुए होलापुर सम्पर्क मार्ग तक लम्बाई लगभग 1 कि0मी0 तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड हण्डिया के नब्बे चौराहे से राजबली बिन्द के दुकान के सामने से होते हुए बिन्द बस्ती तक लम्बाई लगभग 1 कि0मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरजूमनी बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड सैदाबाद के अन्तर्गत पवन ढाबा से मर्दापुर बिन्द बस्ती तक लगभग 1 कि0मी0 तक नव निर्माण/इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालसाहब बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड हण्डिया के अन्तर्गत बेलनाथ मंदिर के पीछे से छोटेलाल बिन्द के घर होते हुए रेलवे स्टेशन तक लगभग 1 कि0मी0 तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

अपराह्न भोजन की सूचना

श्री अधिष्ठाता-

एक सूचना है कि सभी मा0 सदस्यों के लिए आज कैंटीन में भोजन की व्यवस्था है।

श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से संबंधित चार याचिकाएं†

श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत 15 मील-बोदरवार मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजन यादव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-जनपद कुशीनगर में जोल्हनिया से लक्ष्मण किला कुटी तक की सड़क का चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री भोला चौहान व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद कुशीनगर के ग्राम पट्टन में स्पोर्ट स्टेडियम व तरण ताल बनवाने के सम्बन्ध में श्री विश्वास सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका, तथा जनपद कुशीनगर के बंचरा सुकवासी मार्ग स्थित क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नया पुल बनवाने के सम्बन्ध में श्री भोला जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से संबंधित दो याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री पल्टूराम-

1. जनपद बलरामपुर के प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में परिसर में बन रहे भवन के गुणवत्ता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

2. जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा घूघुलपुर में स्वीकृत पॉलीटेक्निक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

श्री प्रेमसागर पटेल, सदस्य विधान सभा की जनपद महराजगंज से संबंधित तीन याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री प्रेमसागर पटेल-

1-जनपद महराजगंज के विकास खण्ड सिसवां बाजार के शहर में राजकीय महिला इण्टर कालेज में राजकीय इन्टर कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री हरि भालोटिया व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

2-जनपद महराजगंज के विकास खण्ड मिठौरा के अन्तर्गत नर्सरी 24, 26, 28 में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरि भालोटिया व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका तथा

3-जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां विकास खण्ड निच्लौल, मिथैरा एवं सिसवां के कतिपय ग्रामों की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

---

† छापी नही गयीं।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा से संबंधित पाँच याचिकाएं†

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील एवं विकास खण्ड तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धौरहरा में धौरहरा इलाहाबाद बैंक से गौहानी अकबरपुर, रामपुर, टेगरहा होते हुए प्रधानमंत्री सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-जनपद गोण्डा की तहसील एवं विकास खण्ड तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामापुर में तरबगंज बाजार से करनीपुर रानीपुर होते हुए झझरी तरबगंज मार्ग का चौड़ीकरण/उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यप्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज, विकास खण्ड बेलसर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-मुकुन्दपुर में प्रस्तावित विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरा सिंह मधुर व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज, विकास खण्ड नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोकुला में महरमपुर गोकुला के मध्य नाले पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका, तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज, विकास खण्ड वजीरगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भोपतपुर में सी0बी0एन0 मार्ग तरबगंज से राजमनि पिपरी सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य विधान सभा की जनपद बाराबंकी व जनपद लखनऊ से संबंधित एक-एक याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री श्रीराम सोनकर-

1-जनपद बाराबंकी के थाना कोतवाली हैदरगढ़ में युवराज का पुरवा मजरे बबुआपुर में मुख्य मार्ग खड़न्जे पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह, निवासी जनपद बाराबंकी की याचिका तथा

2-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बख्शी का तालाब के अन्तर्गत भैसामऊ के वार्ड संख्या-9 के भीखा माहरा के घर से एस0आर0 कालेज की बाउन्ड्री तक सी0सी0 रोड निर्माण विषयक श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

---

† छापी नही गयीं।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से संबंधित नौ व जनपद हरदोई से संबंधित एक याचिकाएं†

श्री राम अचल राजभर-

1- मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा राजेपुर धावां के कृपा नन्द राजभर के खेत से ग्राम दाउदपुर के राजेन्द्र प्रसाद सिंह के खेत तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित करता हूं,

2- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा असौवापार लक्ष्मण वर्मा के खेत से राम केवल के आवास तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग 500 मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र, बी0डी0सी0 व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा असरफाबाद धौरहरा दलित बस्ती से मुबारकपुर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग 700 मी0 पर खड़न्जा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेर बहादुर यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा हसनपुर जलालपुर से राजमणि के आवास तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजमणि व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

5- जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साण्डा दखिलौल में स्थित अंजली धर्मकांटा से ग्राम गड़रिया खेड़ा होते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय साण्डा दखिलौल तक ऊबड़-खाबड़ मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध श्री रामखेलावन व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका,

6- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा राम नगर नरसिंहपुर नन्दलाल के आवास से टोंस नदी तिरवाहे घाट तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतराम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

7- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा ताराखुर्द बाजार से उसमापुर मार्ग तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क पिच मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीराम प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

8- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा फत्तेपुर ककरडिल्ला मुख्य मार्ग से राजभर बस्ती पंचायत भवन तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का

---

† छापी नही गयीं।

मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रसाद राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

9- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा बनगाँव डीहवा अखण्ड प्रताप के खेत से ग्राम सभा छितूनी तक जर्जर/क्षतिग्रस्त पिच सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामलौट राजभर, प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका, तथा

10- अम्बेडकरनगर के विकास सम अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा माउख शारदा सहायक नहर की पुलिया से ग्राम महराजगंज शारदा सहायक पुलिया तक जर्जर/क्षतिग्रस्त पिच सम्पर्क मार्ग (500 मी0) का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आज्ञाराम प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य श्री राम फेरन पाण्डेय इस समय उपस्थित नहीं हैं।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं[†]

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

1- मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर, विकास खण्ड पडरौना में कुबेरस्थान मंदिर परिसर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री दुर्गादयाल तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित करता हूं,

2- जनपद कुशीनगर, विकास खण्ड कसया में मैनपुर कोट माता जी का स्थान के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री डेविड राय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3- जनपद कुशीनगर, विकास खण्ड पडरौना में नरसर शिव मंदिर परिसर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री चन्दन शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4- जनपद कुशीनगर, विकास खण्ड कसया में कुलकुला देवी स्थान के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री शम्भू कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका, तथा

5- जनपद कुशीनगर, विकास खण्ड हाटा में सतगुड़ही माता जी का स्थान को सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुभाष पासी, सदस्य विधान सभा की जनपद गाजीपुर व जनपद अम्बेडकरनगर से संबंधित पाँच-पाँच याचिकाएं (व्यपगत)[†]

1- जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत एन0एच0-29 के बगल में गंगा तट औरिहार, बराह रूप मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं स्ट्रीट लाइट लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

---

[†] छापी नही गयीं।

* श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की याचिका आगे पृष्ठ सं0 186 पर है।

2- जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के ग्राम सभा अमुआरा के सामने गांगी नदी में चेकडैम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

3- जनपद गाजीपुर के सैदपुर तहसील परिसर में लेखपाल भवन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

4- जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड देवकली के प्रांगण में राजकीय पशु चिकित्सालय के भवन एवं परिसर के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में श्री मोतीचन्द पासी व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

5- जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत रामपुर माँझा (बूढ़े महादेव) मंदिर के सामने पोखरे का सौन्दर्यीकरण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

6- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव के अन्तर्गत हाफिजपुर से करीमनगर नहर पटरी का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्दर यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

7- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम जगतूपुर बिल्टई से भिसवां चितौना मार्ग लम्बाई लगभग 700 मी0 को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगभवन व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

8- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम गौरामहमदपुर सम्पर्क मार्ग से फूलेराज यादव गौरामहमदपुर के घर तक लम्बाई लगभग 1.20 कि0मी0 मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फूलेराज यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

9- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव के अन्तर्गत चैनपुर बाजार से रन्नूगंज नहर की पटरी का अवशेष भाग लम्बाई लगभग 500 मी0 का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पारस नाथ कनौजिया व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका, तथा

10- जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील जलालपुर के ग्राम सरखूपुर से नोनहर सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 1.50 कि0मी0 का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दयाराम मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं†

श्री सत्यवीर त्यागी-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ब्लॉक खरखौदा में ग्राम धनोटा में मेरठ-हापुड़ रोड से प्राथमिक स्कूल तक रास्ते का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-जनपद मेरठ के अन्तर्गत ब्लॉक माछरा ग्राम रहदरा में नरेश पुत्र संगत के खेत से शमशानघाट तक रास्ते का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

3-जनपद मेरठ के अन्तर्गत ब्लॉक खरखौदा में ग्राम नंगला कबुलपुर से आश्रम तक रास्ते का डामरीकरण कराये जाने को सम्बन्ध में श्री सत्यवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

4-जनपद मेरठ के अन्तर्गत ब्लॉक खरखौदा में ग्राम अतराड़ा नलकूप 86 से नलकूप 13 बधौली वाली रोड पर रास्ते का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री विनय त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका, तथा

5-जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम दवथला में महेश पाल के खेत से ओमपाल सिंह के खेत तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कर्मवीर व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री उमाशंकर सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री उमाशंकर सिंह-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलिया की आदर्श नगर पालिका रसड़ा में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पम्मी अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित करता हूं, तथा

2-जनपद बलिया की आदर्श नगर पालिका रसड़ा में राजकीय महिला चिकित्सालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इश्तियाक अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री उपेन्द्र नाथ पासवान, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्री उपेन्द्र नाथ पासवान-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर पालिका परिषद् घाटमपुर में आसरा आवास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

---

† छापी नही गयीं।

2-कानपुर नगर की नगर पालिका परिषद् घाटमपुर, नवेडी में जाजपुर पुलिस चौकी का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अरुणेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

3-कानपुर नगर की नगर पालिका परिषद् घाटमपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री रणविजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

4-कानपुर नगर की नगर पालिका परिषद् घाटमपुर में पुलिस स्टेशन की स्थापना कराये जाने विषयक श्री संदीप त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य विधान सभा की जनपद सहारनपुर से संबंधित पाँच याचिकाएं†

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर की तहसील एवं विकास खण्ड रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्राम टपरी में हिण्डन पर रपटा का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ठा0 मिलाफ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-जनपद सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारन के विकास खण्ड बलियाखेड़ी के अन्तर्गत ग्राम चांदनपुर में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौ0 करण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

3-जनपद सहारनुपर की तहसील रामपुर मनिहारन के विकास खण्ड नागल के अन्तर्गत कस्बा नागल में तालाब की सफाई कराकर नाले निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल डाबर व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

4-जनपद सहारनपुर की तहसील एवं विकास खण्ड रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्राम जधेडा समसपुर में तालाब की सफाई कराकर सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद पंवार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका तथा

5-जनपद सहारनुपर की तहसील रामपुर मनिहारन के विकास खण्ड नागर के अन्तर्गत ग्राम पिरड में तालाब की सफाई कराकर नाले के निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बालचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री अधिष्ठाता-

प्रिंस वीर विक्रम सिंह जी अपनी याचिका उपस्थित करें।

(प्रिंस वीर विक्रम सिंह जी उपस्थित नहीं हैं।)

---

† छापी नही गयीं।

1-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड मदनापुर में ग्राम निजामपुर नगरिया में श्री तुंगपाल सिंह पूर्व प्रधान के मकान से श्री श्यामपाल सिंह के मकान तक सी0सी0 मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हिन्दपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका, तथा

2-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में ग्राम उभौरा सिमरा खादर में श्री राजकुमार के खेत में राजकीय नलकूप का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य विधान सभा की जनपद हाथरस से संबंधित पाँच याचिकाएं[†]

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत रोडवेज बस स्टैण्ड के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत कलूपुरा से चरणपुरा तक लम्बाई 3 कि0मी0 सड़क का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन पुण्डीर व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

3-जनपद हाथरस के विकास खण्ड मुरसान के ग्राम बिसाना में सिद्धपीठ माँ तारागढ़ के प्रसिद्ध मंदिर के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चरण सिंह सिसौदिया व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

4-जनपद हाथरस के विकास खण्ड मुरसान के ग्राम गम्भीर पट्टी बिसाना में जल निगम की जमीन पर पानी की टंकी के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीकम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका तथा

5-जनपद हाथरस के विकास खण्ड मुरसान के अन्तर्गत ग्राम बिसाना में पशु चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम फेरन पाण्डेय-

मननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं लघु शंका के लिए चला गया था इसलिए अनुरोध है कि मेरी याचिका उपस्थित कराने की कृपा करें।

श्री अरूण कुमार यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका[†]

श्री अरूण कुमार यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मै आपकी अनुमति से फूलपुर के अन्तर्गत कतिपय पट्टेधारकों के अवैध कब्जों के सम्बन्ध में श्री सुनील पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

[†] छापी नही गयीं।

श्री अनिल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं[†]

श्री अनिल सिंह-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध श्री विवेक त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत लखनऊ के मोहनलालगंज, मौरावां, पुरवा एवं उन्नाव रोड को सही और मानक एवं गुणवत्तापूर्ण बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुजीत कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड बिछिया अन्तर्गत ग्राम तौरा स्टेडियम का मरम्मत कार्य एवं नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा विकास खण्ड बिछिया अन्तर्गत ग्राम तौरा में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का नवीनीकरण सहित 50 शैय्यायुक्त का चिकित्सालय के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका, तथा

5-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम अकोहरी में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री आजाद अरिमर्दन, सदस्य विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं[†]

श्री आजाद अरिमर्दन-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज के अन्तर्गत पिचरोड डीहबाबा के स्थान से बरसेरवा राजभर बस्ती तक 1 कि0मी0 तक नव निर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज एवं पल्हना के अन्तर्गत रामू राजभर के चक व घर के पास से दुर्गा माता मंदिर तक लगभग 1 कि0मी0 तक नव निर्माण/ डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका, तथा

3-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज के अन्तर्गत नहर के पास बाबूलाल के खेत से डा0 भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास तक लगभग 1 कि0मी0 तक नव निर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजीत व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

[†] छापी नही गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री आनन्द शुक्ला जी अपनी याचिका उपस्थित करें।

(श्री आनन्द शुक्ला जी उपस्थित नहीं हैं)

श्री गंगा, सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री गंगा-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर के विकास खण्ड फाजिलनगर कुकृत्था घाट का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री मुकुल पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर की नगर पंचायत फाजिलनगर में सीवर लाइन एवं नाली के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मुकुल तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका, तथा

3-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर की नगर पंचायत दुदही में सीवर लाइन एवं नाली के निर्माण के सम्बन्ध में श्री गिरिजेश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं†

श्री गौरी शंकर-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के तहसील उरई के विकास खण्ड डकोर के ग्राम मड़ौरा एवं उसरगांव के बीच में पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री प्रदीप निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-जनपद जालौन के अन्तर्गत ग्राम खनुआ से धनौरा रोड तक पहुंचने के बीच में सिंचाई विभाग की नहर की पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के तहसील व विकास खण्ड कोंच के अन्तर्गत ढेरी छिरावली माइनर सिंचाई हेतु चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री रिंकू चौहान व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के तहसील व विकास खण्ड कोंच के ग्राम बसोब पिरौना मार्ग पर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका, तथा

5-जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के अन्तर्गत ग्राम अजनारा, मिनौरा, कालपी के बीच नाले पर पड़ने वाली पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री महेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

---

† छापी नही गयीं।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से

1. जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी मुख्यालय को जिला घोषित किए जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक कुमार शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका उपस्थित करता हूं,

2. जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी मुख्यालय के अन्तर्गत ट्रामा सेन्टर की स्वीकृति किए जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका,

3. जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका, तथा

4. जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र की स्वीकृति प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्योतिर्मय भरतरिया व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जिला अम्बेडकरनगर के मया-टाण्डा राज्य मार्ग को फोर लेन में परिवर्तित कर नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषि कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्रीमती मनीषा अनुरागी-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हमीरपुर की तहसील राठ के अन्तर्गत ग्राम मगरौठ मोड़ से जिगनी तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित करता हूं, तथा

2-जनपद हमीरपुर के तहसील राठ के अन्तर्गत ग्राम चिकासी से हरदुआ तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

---

† छापी नही गयीं।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से संबंधित पाँच याचिकाएं[†]

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मिर्जापुर की तहसील मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम सभा आंही में अजय पाण्डेय के घर से हरिजन बस्ती होते हुए लोहरान बस्ती तक पिच रोड 800 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीकान्त गिरी व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-जनपद मिर्जापुर की तहसील मिर्जापुर के अन्तर्गत जंगी रोड बैरहवा चौराहा से गोपालपुर राजापुर तक 4 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका,

3-जनपद मिर्जापुर की तहसील मिर्जापुर के अन्तर्गत डगमगपुर रेलवे स्टेशन से गणेश गुप्ता के आवास तक लम्बाई 1 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री सरिता सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका,

4-जनपद मिर्जापुर की तहसील मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम किरतारतारा के मेन रोड से पं0 श्रीकांत पाण्डेय जी के आवास तक कोल युक्त सड़क को गड्ढामुक्त करने हेतु सड़क का नवीन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीकांत पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका, तथा

5-जनपद मिर्जापुर की तहसील मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम कटका सम्पर्क मार्ग से अकेला वीर बाबा से होते हुए कनकसराय सेमरी सम्पर्क मार्ग तक 1 कि0मी0 पिच रोड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरायन मौर्या निवासी जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री आनन्द शुक्ला-

मान्यवर, मद संख्या-29 छूट गया है, इसको ले लें।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य विधान सभा की जनपद बहराइच से संबंधित चार याचिकाएं (व्यपगत)[†]

(श्रीमती सरोज सोनकर का नाम पुकारे जाने पर सदस्या उपस्थित नहीं थीं।)

श्रीमती सरोज सोनकर-

1- जनपद बहराइच की तहसील नानपारा के विकास खण्ड बलहा के ग्राम सभा जगन्नाथपुर बेचईपुरवा में भारत माता का एक प्राचीन मन्दिर को पुनर्जीवित किये जाने के सम्बन्ध में श्री गणेश शंकर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिक,

2- जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के विकास खण्ड-मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ग्राम सभा सुजौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

[†] छापी नही गयीं।

(सी0एच0सी0) बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

3- जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के विकास खण्ड बलहा के ग्राम सभा बगहा के मजरा गुड़ियानपुरवा में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में धनीराम लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका, तथा

4- जनपद बहराइच की तहसील एवं विकास खण्ड मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ग्राम सभा घुम्मना भारू एवं ग्राम सभा चितलाहवा में एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मानवेन्द्र गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका व्यपगत।

श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से संबंधित याचिका (व्यपगत)[†]

(श्रीमती जय देवी का नाम पुकारे जाने पर सदस्या उपस्थित नहीं थीं।)

श्रीमती जय देवी-

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के श्री सुनील कुमार के लखनऊ स्थित घर पर अवैध कब्जे को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत।

श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद अमेठी से संबंधित याचिका[†]

श्रीमती गरिमा सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अमेठी के विकास खण्ड भादर के अन्तर्गत पीपरपुर लहना सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित करती हूँ।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से संबंधित पाँच याचिकाएं[†]

डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

1- मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊ आइमा के ग्राम सभा लेहरा में लेहरा सम्पर्क मार्ग से पटेल के घर तक ल0-600 मी0 का इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाम व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित करता हूं,

2- जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड सोरांव में कलन्दरपुर में वीरांगना ऊदादेवी गेट तथा विकास खण्ड बहरिया में महाराजा बिजली पासी गेट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम बहादुर सरोज व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3- जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊ आइमा के ग्राम सभा भीखू का पूरा में सरदार ठाकुर के घर से फरमूद के घर तक काली रोड ल0 1 कि0मी0

[†] छापी नही गयीं।

का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आतिफ व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4- जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊ आइमा के ग्राम सभा गदियानी में सोरांव-कल्याणपुर सम्पर्क मार्ग से धनवारी का पूरा असगर के घर तक ल0-1 कि0मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 रिजवान व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका, तथा

5- जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊ आइमा के ग्राम सभा जमखुरी में तिरंगा चौराहे से स्व0 अल्ताफ के घर तक काली रोड ल0-1 कि0मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरताज व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सन्बन्धित पाँच याचिकाएं[†]

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

1- मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद में ग्राम इटौआ में दतावली मटसेना मार्ग से भुवनेश शर्मा के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने विषयक श्री नरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित करता हूं,

2- जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम पिलुआ में विजयपाल सिंह के घर से कृष्णपाल सिंह के घर होते हुए लोकेन्द्र पाल सिंह के घर तक सी0सी0 निर्माण कराये जाने विषयक श्री लोकेन्द्र पाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3- जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम सटकई में प्रताप सिंह के घर से माता मन्दिर तक मार्ग का सी0सी0 निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4- जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम मालीपट्टी में तारा सिंह बघेल की दुकान से शंकर लाल की ठार होते हुए मालीपट्टी-2 तक मार्ग का सी0सी0 निर्माण कराने जाने विषयक श्री शंकर लाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका, तथा

5- जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम सोफीपुर में लिंक रोड से फिरोजाबाद-फतेहाबाद मार्ग तक सी0सी0 निर्माण कराये जाने विषयक श्रीमती रज्जो देवी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

डा0 संगीता बलवन्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सन्बन्धित दो याचिकाएं[†]

डा0 संगीता बलवन्त-

1. मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर की नगर पालिका गाजीपुर नक्खास से लौटन इमली पुलिस चौकी होते हुए छतरी तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजीव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित करती हूं तथा

[†] छापी नही गयीं।

2. ग्राम सिसौड़ा (नीलडीह) चकरोड से फूलचन्द्र पाल की मशीन तक सड़क निर्माण कराये जाने विषयक श्री मनोज कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ की एक व जनपद बरेली की दो याचिकाएं[†]

डॉ0 डी0सी0 वर्मा-

1- मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के नगर क्षेत्र ऐशबाग में स्थित दो ऐतिहासिक झीलों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालू व अन्य निवासीगण ऐशबाग जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित करता हूं,

2- जनपद बरेली के अन्तर्गत कुड़का नगरिया में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नेमचन्द्र, निवासी जनपद बरेली की याचिका तथा

3- जनपद बरेली के अन्तर्गत गोराघाट पुल के पास राम गंगा घाट को विकसित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकास कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद शर्मा, निवासी जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

डॉ0 अरूण कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद बरेली से संबंधित आठ याचिकाएं[†]

डा0 अरूण कुमार-

1- मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के नगर क्षेत्र वार्ड संख्या-29 के रहपुरा चौधरी में साईं धर्मकांटे के सामने वाली गली में अनिल जैन के घर से रमेश जी के घर तक सड़क, नाली निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनिल जैन व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित करता हूं,

2- जनपद बरेली के नगर क्षेत्र वार्ड संख्या-29 के रहपुरा चौधरी में बाबा क्लाथ हाउस से वीरपाल के घर होते हुए जायसवाल जी के घर तक सड़क, नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रवेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3- जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र शहर, बरेली के वार्ड-3 के तुलाशेरपुर में प्रमोद राणा के घर से होते हुए जितेन्द्र के घर से भूपराम के घर तक सड़क, नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनाथ राणा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4- जनपद बरेली नगर के वार्ड-34 के परतापुर चौधरी महलऊ में गली संख्या-01 में रोशनलाल के घर से रामसहाय की दुकान व गली नम्बर-2 में बाबू बाल्मीकि के घर से तालाब तक सड़क, नाली निर्माण कराये जाने विषयक श्री रवि कुमार, निवासी जनपद बरेली की याचिका,

5- जनपद बरेली नगर के वार्ड-3 के छोटी विहार के बनूबाल में सौ फिटा रोड, सूद धर्मकांटे के पास वाली गली न्यू लाइफ अस्पताल से शुभम् मेडिकल स्टोर तक सड़क, नाली

[†] छापी नही गयीं।

निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

6- जनपद बरेली के बेलापीर में सुरेश चन्द्र शर्मा के मकान से अवनेश यादव के मकान तक सड़क, नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

7- जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र शहर बरेली के वार्ड-65 में सुरेश शर्मा के मकान से मेगासिटी के पीछे विकास सीमेन्ट वाली कच्ची सड़क का पक्का व नाली निर्माण कराये जाने विषयक श्री स्वतंत्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका, तथा

8- जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र शहर बरेली के वार्ड-03 के तुलाशेरपुर में आदित्य के घर से राहुल राणा के घर होते हुए बृजलाल के घर तक सड़क, नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल राणा अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

आनन्द शुक्ला जी अपनी याचिका उपस्थित करें।

श्री आनन्द शुक्ला, सदस्य विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका†

श्री आनन्द शुक्ला-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत ऊँचाडीह, मजरा-टेढ़वा में अत्यन्त क्षतिग्रस्त कारीबराह पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री सुशीला पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

राम फेरन पाण्डेय जी, आप भी अपनी याचिका उपस्थित करें।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से संबंधित दो याचिकाएं†

श्री राम फेरन पाण्डेय-

1. मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद श्रावस्ती में सिंचाई विभाग का एक कार्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित करता हूं तथा

2. जनपद श्रावस्ती के ग्राम मलावा में महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज/महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

---

† छापी नही गयीं।

[12:44] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूँ कि आपने कार्य-स्थगन की ग्राह्यता पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। प्रदेश इस समय महंगाई की मार से कराह रहा है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां महंगाई न हो, महंगाई से लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, दवाइयों के दाम विगत 04 वर्षो में कई गुना बढ़ गये हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के दाम सबसे अधिक बढ़ गये हैं। लखनऊ में वर्ष 2020 में रसोई गैस का मूल्य रु0 589 था जो फरवरी, 2021 में मूल्य रु0 807 हो गया है। 1 मार्च, 2021 को पूरे 25 रु0 बढ़कर 832 रुपये हो गये हैं, सब्सिडी भी लोगों के खाते में बहुत कम आ रही है, जिनके खाते में आती है तो 38 या 40 रुपये आती है। रसोई गैस के दाम अलग-अलग शहरों में अलग-अलग हैं। हमारे जनपद बलिया में 899 रुपये 50 पैसे यानी लगभग 900 रुपये का सिलेण्डर हो गया है। विगत 10 माह में रसोई गैस के दाम रुपये 243 बढ़ गये हैं। इसी तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आज की डेट में पेट्रोल 89.23 रुपये प्रति लीटर है और डीजल 81.86 रुपये पहुंच गया है। डीजल-पेट्रोल की महंगाई का प्रभाव किसानों को सिंचाई, जुताई, परिवहन पर पड़ रहा है। परिवहन भाड़ा बढ़ने से वस्तुएं महंगी हो रही हैं। यात्रा किराया भी महंगा हो रहा है, परन्तु सरकार जनता को राहत देने के लिए अपना टैक्स कम नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार पेट्रोल पर 18 रुपये 74 पैसे अर्थात् 19 रुपये, डीजल पर 10 रुपये 41 पैसे का कर वसूलती है। केन्द्र सरकार 32.98 रुपये का टैक्स ले रही है। केन्द्र/राज्य टैक्स और डीलर कमीशन मिलाकर डीजल पर 46 रुपये और पेट्रोल पर 96 रुपये जनता से वसूले जा रहे हैं। अगर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार अपना ही टैक्स कम कर दे तो जो डीजल-पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे किसान कराह रहा है, यात्रायें भारी पड़ रही हैं, वह समस्यायें नहीं आयेंगी, लेकिन इनको तो धन वसूलना है, किसी भी तरह से जनता के हाथ से पैसा छीन करके कारपोरेट घरानों को पहुंचाना है, उनको और पैसे वाला बनाना है, जनता को गरीब बनाना है। वाणिज्य कर उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नॉन फूड कैटेगरी में महंगाई की दर दिसम्बर, 2020 में 4.16 प्रतिशत दर्ज की गयी थी, जबकि मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स की थोक कीमतों में वृद्धि दर 4.24 से बढ़कर 5.13 फीसदी हो गयी है। थोक महंगाई दर इंडेक्स में मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 64.23 फीसदी रहती है, यानी इस कैटेगरी में कीमतें यदि थोड़ी भी बढ़ेंगी तो इसका महंगाई पर बहुत बड़ा असर पड़ता है।

(इस समय अपराह्न 12 बजकर 49 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

दवाइयों के मूल्य लगभग तीन गुना बढ़ गये हैं। साधारण व्यक्ति अपना इलाज ठीक से नहीं करा पा रहा है। बढ़ती महंगाई से जनता आक्रोशित है। एल0पी0जी0 के बारे में मैंने आपको बताया है। मेरे पास पूरी लिस्ट है। 10 महीने की हर जनपद की लिस्ट है। अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूँ। देर तो बहुत होगी।

श्री अध्यक्ष-

आप केवल बलिया का बता दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपकी आज्ञा से बता रहा हूँ कि 10 महीने में 243 रुपए एल0पी0जी0 का दाम बढ़ा। मई, 2020 में 589 रुपए था, फरवरी, 2021 में 832 रुपए हो गया। 832 में से 589 निकालिए 243 रुपए दस महीने में गैस में बढ़े। इसी तरह से डीजल में आज डीजल 81.86 रुपए में मिल रहा है यह भी 10 महीने में काफी बढ़ गया, डीजल आज आम जनता की आवश्यक चीजों में है। यह भी आसमान छू रहा है, कैसे ट्रैक्टर चलेगा, कैसे किसान के ट्यूबवेल चलेंगे। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम जनता कराह रही है। पेट्रोल का आज का दाम है 89.23 रुपए। इसका कारण हुआ कि बस का किराया बढ़ गया, मुख्य मंत्री जी के जनपद से जो बस लखनऊ आती हैऊ पुराना उसका किराया था 349 रुपए आज हो गया 546 रुपए क्यों बढ़ा क्योंकि डीजल का दाम बढ़ गया, बस में कौन बैठता है आम आदमी, साधारण आदमी, गरीब आदमी जिसके पास अपनी गाड़ी न हो वही तो बस में यात्रा करता है। डीजल पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का टैक्स है 31.83 रुपए और पेट्रोल पर है 32.98 रुपए राज्य सरकार का टैक्स है 10.85 पेट्रोल पर 19.32 रुपए। डीलर कमीशन है 2.53 रुपए डीजल पर और पेट्रोल पर 3.67 रुपए मायने डीजल पर 46 रुपए और पेट्रोल पर 56 रुपए यह इनका कारनामा है राज्य सरकार का। बस का किराया बढ़ जाता है, टैक्सी का किराया बढ़ गया, आटो का किराया बढ़ गया आटो का किराया कि0मी0 के हिसाब से एक कि0मी0 पर 25, 29, दो कि0मी0 पर 33, तीन कि0मी0 पर 37, चार कि0मी0 पर 41, पाँच कि0मी0 पर 45, 6 कि0मी0 पर 49 आटो पर कौन बैठता है, जो बिल्कुल गरीब हो, असहाय हो, बेबस हो, लाचार हो, टैक्सी का किराया बढ़ गया जो उससे ऊपर है उसका भी किराया बढ़ गया। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से बस का किराया बढ़ गयाऊ ओला का किराया बढ़ गया, आटो का किराया बढ़ गया और जो माल आता है ट्रक से, ट्रेन से उसका भी भाड़ा बढ़ गया, ट्रेन का किराया भी बढ़ गया। यह गाजियाबाद सकूरपुर बस्ती वाया दिल्ली पहले 10 रुपए था अब 30 रुपए बढ़ गए, गाजियाबाद बस्ती वाया निजामुद्दीन पहले 20 रुपए था अब 40 रुपए हो गया। परवल गाजियाबाद पहले 25 था अब 45 हो गया, दिल्ली बरेली वाया मुरादाबाद पहले 55 था अब 95 हो गया। दिल्ली-कुरुक्षेत्र बाया सब्जी मंडी पहले 35 था अब 70 रुपए हो गए।

दिल्ली-सहारनपुर वाया शामली पहले 40 था अब 70 हो गया। किराया बढ़ोत्तरी की जानकारी नहीं दी गयी, रेलवे ने गुपचुप तरीके से किराया बढ़ा दिया, लेकिन मेरे पास जो प्रमाण है वह ॲथेन्टिक है। मा0 अध्यक्ष जी, यही नहीं, 03 माह के दौरान दवाओं के दाम कितने बढ़ गये। महिलाओं के उपयोग में आने वाली डफ्स्टान का पहले मूल्य 652 था अब मूल्य 685 हो गया, 33 रुपये बढ़ गये। तीन महीने के अन्दर मूल्य बढ़ गये। लीवर के लिये यूडीलिव का पहले मूल्य 591 था अब 631 हो गये, 40 रुपये बढ़ गये। इन्सुलिन कार्टेज का

पहले मूल्य 1610 था अब 1770 हो गया, 160 रुपये बढ़ गये। इन्सुलिन लेन्ट्स कार्टेज का पहले मूल्य 650 था अब 722 रुपये हो गया, 72 रुपये बढ़ गये। ह्यूमन मिक्सटार्ड-30 पेनफिल का पहले मूल्य 1450 था अब 1595 हो गया, 145 रुपये बढ़ गये। शुगर की दवा ग्लूकोनार्म जी-3 का पहले मूल्य 195 था अब 215 रुपये हो गया, 20 रुपये बढ़ गये। ग्लूकोनार्म जी-3 (गिलीप्राइड) का पहले मूल्य 187 था अब 206 रुपये हो गया, 19 रुपये बढ़ गये। म्लेच्छमाव का पहले मूल्य 125 रुपये था अब 138 रुपये हो गया, 13 रुपये बढ़ गये। ग्लूकोनार्म टी-15 का पहले मूल्य 490 था अब 515 हो गया, 25 रुपये बढ़ गये। ट्रेजेंटा-5 का पहले मूल्य 490 था, अब 515 रुपये हो गया, 25 रुपये बढ़ गया। जोर्डिएन्स-25 का पहले मूल्य 570 था, अब 622 हो गया, 52 रुपये बढ़ गये। अमरजीत-2 का पहले मूल्य 179 था अब 190 हो गया, 11 रुपये बढ़ गये। अमरजीत-3 का पहले मूल्य 362 था अब 398 हो गया, 36 रुपये बढ़ गये। इन्सुलिन पर सीधे-सीधे 15 से 20 प्रतिशत दाम बढ़ा दिये गये हैं। डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, दवा का दाम बढ़ गया, रोडवेज बस का किराया बढ़ गया, ओला गाड़ी का किराया बढ़ गया, ऑटो का किराया बढ़ गया।

श्री अध्यक्ष-

बढ़ गया तो अब क्या करना है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, अब खाने वाली चीज अर्थात् खाद्यान्न के जनवरी से दिसम्बर के बीच में दाम देख लें। सरसों का तेल जनवरी में 85, दिसम्बर में 155, रिफाइंड जनवरी में 82 से 85, दिसम्बर में 135, वनस्पति घी जनवरी में 75, दिसम्बर में 110, मूंगफली तेल जनवरी में 115, दिसम्बर में 185, अरहर दाल जनवरी में 70 और दिसम्बर में 90-95 और तत्काल में 100 रुपये तक भी है। उरद दाल जनवरी में 80 और दिसम्बर में 170, मूंग की दाल जनवरी में 72 और दिसम्बर में 110 से 120, मसूर की दाल जनवरी में 55 और दिसम्बर में 70, चना की दाल जनवरी में 58 और दिसम्बर में 70 से 72 रुपये तक हो गयी। आटा 21 से 25 रुपये और अब 25 से 28 हो गया, चीनी जनवरी में 32 और दिसम्बर में 37 से 38 हो गयी। यह महंगाई का हाल है। ऑटो का मैंने आपको बता ही दिया, रेल का बता ही दिया। श्रीमान, यह सरकार किसलिये है ? जन कल्याणकारी सरकार कही गयी है। जन कल्याणकारी अर्थात् हम जनता का कल्याण करेंगे।

कैसे कल्याण करेंगे ? कैसे गरीबी मिटायेंगे ? कैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति को ऊपर उठायेंगे ? कैसे किसी गरीब व्यक्ति के बच्चे को पढ़ायेंगे ? कैसे गरीब आदमी को दवा की व्यवस्था करेंगे ? दवा, तेल, आटा, चावल, चीनी, डीजल, पेट्रोल, गैस और रेल आदि का किराया महंगा कर दिया गया है। यह कौन सी कल्याणकारी सरकार है ? इसलिए मैं अपनी ग्राह्यता पर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रदेश का बेरोजगार बेहाल, महंगाई से जनता बेहाल, गरीब आदमी यात्रा करने में बेहाल और आम आदमी खाने वाली चीज

खरीदने में बेहाल है तो फिर यह सरकार किसलिए बनी है, महंगाई बढ़ाने के लिए ? लोगों को कष्ट में डालने के लिए ? आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए ? इस सरकार को जन कल्याणकारी सरकार कभी भी नहीं कहा जा सकता है। मा0 अध्यक्ष, जी मैं कृपापूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार हर-हाल में महंगाई कम करे, लेकिन यह इनके बूते की बात नहीं है क्योंकि यह सरकार गरीबों के हितों की रक्षा के लिए नहीं है प्रदेश और देश के पूँजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए है। जनता से सबकुछ छीन करके, जनता कंगाल हो जाय पूंजीपति मालामाल हो जाय इस सरकार की यही नीति है। मा0 अध्यक्ष जी आपने कभी फिल्म देखी है या नहीं देखी है ? देखे जरूर होंगे क्योंकि हम और आप टकराते रहते थे। मनोज कुमार की एक फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान आई थी इस फिल्म को आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है। मनोज कुमार जी ने जो फिल्में बनायी हैं वह देश के लिए गौरव की बात है। फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान में एक गाना था मा0 अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी आँख मिला लीजिए।

"उसने कहा कि तू कौन है मैंने कहा उल्फत तेरी
उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी
उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी
मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी
एक हमें आँख की लड़ाई मार गई
दूसरी यार की जुदाई मार गई
तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई
चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई
बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई।"

श्री अध्यक्ष-

इस फिल्म में एक गाना और भी था जिसे आपने नहीं बताया कि **"100 रुपये की नौकरी पे मेरा लाखों का सावन जाए रे"** (सदन में हंसी)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, एक बार फिर से कह दीजिए मैंने अभी सुना नहीं है। एक बार और बोल दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, अब आप बोलिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि हम और आप टकराते थे (सदन में हंसी) मा0 अध्यक्ष जी इस प्रदेश की बड़ी विषम परिस्थिति है। यह सरकार हर मोर्चे पर फेल

हो गयी है। उत्तर प्रदेश का किसान तीन महीने से आन्दोलन कर रहा है, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान अपनी रोजी-रोटी और नौकरी मांगता है तो वह लाठी खाता है और क्रिमिनल धाराओं में जेल जाता है। जो भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सरकार से अपनी मांग मांगने के लिए आता है और कहता है कि हमारा पेट खाली है, हमारा पेट भरो, लेकिन इस सरकार ने कहा कि हम तुम्हारा पेट तो नहीं भरेंगे, लेकिन तुम्हारा पैर जरूर तोड़ेंगे और क्रिमिनल धाराओं में जेल भेजेंगे।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री आईं पीटी गयीं जेल गयीं, आशा बहू आईं पीटी गयीं जेल गयीं, होमगार्ड आये पीटे गये जेल गये, अनुदेशक आये पीटे गये जेल गये, स्वरोजगार आये पीटे गये जेल गये। श्रीमान बी0टी0सी0 बेकार लड़के, बी0एड0 बेकार लड़के आये पीटे गये जेल भेजे गये इनकी तानाशाही रवैये के कारण कितनी भीषण महंगाई पड़ी है। डर के मारे लोग हिस्सा मांगने नहीं आ रहे हैं, देश में आतंक का वातावरण छा गया है लोग डर गये हैं सरकार ने डराया है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार नहीं चेती तो साइलेन्ट क्रांन्ति होगी बाइस में, क्रांति होगी सारी परिस्थितयां मौजूद हैं जिसमें अहिंसक क्रान्ति की सम्भावनायें बढ़ रही हैं, क्योंकि यह देश अहिंसा का पुजारी है। हमारे नेता आचार्य नरेन्द्र देव, राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, गांधी जी के सबसे नजदीक थे, आजादी की लड़ाई में और जब सोशलिस्ट पार्टी अलग हुई कांग्रेस से, पटना में सम्मेलन हुआ आचार्य नरेन्द्र देव ने अध्यक्षता की लोक नायक जय प्रकाश ने प्रस्ताव पेश किया और वहीं से लाल टोपी पहनी गयी, जय प्रकाश जी ने सबसे पहले पहना और इसी लाल टोपी से मुख्य मंत्री जी के पसीने तार-तार होने लगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तात्कालिक है, आवश्यक है, अविलम्वनीय है इसलिए मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस विषय पर गम्भीर चर्चा कराने की कृपा करें, यही मेरा आपसे आग्रह है।

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने पूरे महीने के अखबार खरीद लिये हैं और किसी की आज रोजी-रोटी का इन्तेजाम हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन अखबार विक्रेता का इन्होंने पूरा कल्याण कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर एक शायर ने कहा है उन्होंने पूछा कि जबान में हड्डी क्यों नहीं होती है तो उसने जवाब क्या दिया मान्यवर अनुमति हो तो सुना दें-

"कुदरत को नापसन्द है सख्ती जबान में, पैदा हुई न इसलिए हड्डी जबान में।"

हम तो सामने ही देखते हैं, दांये-बांये नहीं देखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर समय का दुरुपयोग सही मायने में किसी ने किया है तो माननीय नेता विरोधी दल ने किया है। आपने इनको ग्राह्यता पर बोलने को कहा एक बार में खड़े हुए तो पूरा सिजरा अखबारी पढ़ा और दूसरी बार जब खड़े हुए तो उसी बात को फिर से दोहरा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आज पब्लिक परसेप्शन क्या है ? पब्लिक परसेप्शन चुनाव से तय होता है। चुनाव में दशा क्या है, दिशा क्या है यह तय होता है चुनाव से। मान्यवर, कल्याणकारी सरकार है जिसका पैमाना केवल

एक यह है कि जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिले वह कल्याणकारी काम करे, कल्याणकारी काम कर रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वर्ष 2014 में इनकी सरकार थी, तब महंगाई शून्य पर थी, लेकिन उस समय यह अखबार वालों का भला नहीं कर पाये और आज इनको सब तरफ महंगाई दिखी रही है। महाराष्ट्र में जीत दूसरी पार्टी की होती है, लेकिन यह लोग वहां जाकर उनके हाथ से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हम सब लोग एक हो गये हैं, पूरा विपक्ष एक महागठबन्धन बनायेगा और मिलकर बीजेपी के विरुद्ध चुनाव लड़ा जायेगा। जब वहां पर वर्तमान सरकार बनी तो ऐसा लगा कि जैसे समाजवादी पार्टी की उसमें भागीदारी हो। महाराष्ट्र का हाल क्या है यह हम आपको सुना दें। मान्यवर, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस का रेट इंटरनेशनल मार्केट से नियंत्रित होता है और यह आज से नहीं वर्षों से हो रहा है। हम बाहर से बहुत अधिक क्रूड आयल मंगाते हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

क्रूड आयल की कीमतें आज आधे से भी कम हो गई हैं फिर भी आप देश के अन्दर इसके रेट बढ़ाते जा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं राजस्थान का बताता हूँ और दूसरे प्रदेशों का भी बताता हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने इसका उदाहरण इसलिए नहीं दिया क्योंकि यह पार्लियामेण्ट नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा है। उत्तर प्रदेश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी नहीं हैं, बल्कि यहाँ के वित्त मंत्री आप हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं करते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि आपके घर पुआ कैसा बना था तो बताते हैं कि नाना के घर पुआ बहुत मीठा बना था। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप दूसरे राज्यों पर चले जा रहे हैं। आपको ग्राह्यता पर बोलना चाहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां डीजल का मूल्य 81.33 रुपये है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, लखनऊ में डीजल का आज सुबह का रेट 81.80 रुपये है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हो सकता है कि माननीय सदस्य सही कह रहे हों, इसलिये हम उनकी बात काटेंगे नहीं, क्योंकि आज का मूल्य हमारे पास नहीं है। महाराष्ट्र में डीजल का मूल्य

88.05 रुपये है, राजस्थान में 89.42 रुपये है, आंध्र प्रदेश में 89.60 रुपये, छत्तीसगढ़ में 87.86 रुपये है, तेलंगाना में 88.29 रुपये है।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, क्रूड ऑयल की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से डील होती हैं। श्रीालंका में पेट्रोल का रेट 60.29 रुपये और डीजल का रेट 38.91 रुपये, नेपाल में पेट्रोल का रेट 59.01 रुपये और डीजल का रेट 58.32 रुपये, पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट 51.12 रुपये और डीजल का रेट 53.02 रुपये, बांग्लादेश में पेट्रोल का रेट 76.45 रुपये और डीजल का रेट 55.78 रुपये है। जब पड़ोसी देशों में तेल की कीमतें इतनी कम हैं तो फिर अपने देश में रोज क्यों बढ़ती जा रही हैं।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि इस कोरोना महामारी में बहुत बड़ा बजट जो जरूरतमन्द लोग थे उनके ऊपर खर्च किया गया, जिनको वास्तव में इसकी जरूरत थी। उसके बाद भी हमने उत्तर प्रदेश में इसके पैसे नहीं बढ़ाये। इसके लिए इन लोगों को सरकार को बधाई देना चाहिए कि जब पूरे देश ने और हर प्रांत ने इसके ऊपर पैसे बढ़ाये तो भी हमारी सरकार ने उस अनुपात में इसके ऊपर पैसे नहीं बढ़ाये। आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17.23 प्रतिशत डीजल के ऊपर टैक्स था, यानि वैट था, जब जी0एस0टी0 नहीं थी और इस समय 17.48 प्रतिशत है। यह हमारी स्थिति है। मान्यवर, हम लोगों ने क्या-क्या किया, इन लोगों को तुलनात्मक यह भी देख लेना चाहिए कि हम लोगों ने क्या-क्या किया ? कितने बड़े पैमाने पर लोगों को अनाज बांटा गया। बड़े पैमाने पर उज्जवला गैस के कनेक्शन बांटे गये। आठ करोड़ रुपये बंट गये हैं और एक करोड़ का इस साल वादा किया है। 18 करोड़ लोगों को राशन दिया गया। चाहे वह प्रधानमंत्री योजना के तहत शहरी आवास हो या ग्रामीण आवास हो। किसान सम्मान निधि, यह लोग किसानों की बहुत बड़ी बात करते हैं। यह छोटी बात नहीं है। छोटे-छोटे से कास्तकारों को जो दो-दो बीघा, चार-चार बीघा, छः-छः बीघा के एक-एक एकड़ के जोत थी, उन्हें महाजन से मोटे ब्याज पर लोन लेना पड़ता था, कर्ज देना पड़ता था और उनकी ब्याज में ही पूरी पैदावार चली जाती थी। आज उनके एकाउण्ट में जब छः हजार रुपये आते है तो पूरे गांव का माहौल ही बदला हुआ है, जिसकी यह बात कर रहे हैं। आज तक बेसिक शिक्षा जो हमारे विकास की सबसे बड़ी रीढ़ है। जितना फोकस, जितना ध्यान इस सरकार ने दिया है आज तक किसी भी सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया है। चाहे वह कायाकल्प योजना हो। चाहे वह शिक्षकों को नियुक्ति हो, चाहे स्कूलों की दशा का सुधार करना हो।

हमारे विकास की जो बुनियाद है उसमें हर तरह से हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। आखिरकार पैसा कहाँ से आयेगा ? कहीं न कहीं से तो हमको टैक्स देना पड़ेगा ? मान्यवर, इन्होंने जिन चीजों के ऊपर ध्यान दिलाया है आज सब्जी की महंगाई को

रोकना क्या ठीक है ? अगर सब्जी की महंगाई के ऊपर ज्यादा आलोचना होगी तो कल इसका नतीजा क्या होगा? कल वह लोग पैदावार और कम करेंगे और जब पैदावार कम होगी तो उसका दाम और बढ़ेगा। यह भी सोच लेना चाहिए कि हम किस चीज को आमंत्रित कर रहे हैं ? हम किस चीज को बढ़ावा देना चाहते है ? क्या यह प्रदेश के हित में होगा ? मान्यवर, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो इलाज हो रहा है क्या यह छोटी योजना है ? मान्यवर, आज तक जितनी सरकारें रही हैं, पांच लाख रुपये तक का इलाज, जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र सरकार का है और 40 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार का है। हर अच्छी योजना में हम उन लोगों का हाथ बंटा रहे हैं, उन गरीबों का साथ दे रहे हैं, जिनको जरूरत है। आज जिनके घर में लीवर, किडनी, कैंसर या हार्ट पेशेंट हो जाता था तो उसकी जमीन-जायदाद और सब गिरवी पड़ जाता था, लेकिन अब उसके सामने आयुष्मान योजना के तहत आशा की एक किरण है। यह छोटी बात नहीं है कि हमारी मंशा क्या है ? नीयत क्या है ? हमारी पार्टी का जो अन्त्योदय नारा है उसके तहत समाज में जो सबसे पीछे बैठा हो, जो समाज की सबसे अन्तिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति हो उसके चेहरे पर हंसी लाना, उसके चेहरे पर मुस्कान लाना यह हमारी पार्टी का आज से नहीं शुरू से नारा है। उसी की याद में आज देखिए चाहे शौचालय हो, आवास हो, चाहे गैस का कनेक्शन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। केवल उन्हीं लोगों को वितरित करने के लिए कहा गया जो लोग वास्तव में जरूरतमन्द थे। मान्यवर, हम जबसे आये तबसे हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। आपने बस किराये की बात कही। मान्यवर, 2017 में बस का किराया 95 पैसे प्रति कि0मी0 था। अभी हमने एक साल पहले केवल 10 पैसा बढ़ाया है। 95 पैसे के स्थान पर 01 रुपये 05 पैसे किया। आपने ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत जोर दिया, इसलिए हमने जवाब दिया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह है। (समाचार पत्र की कटिंग दिखाते हुए)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप यह अखबार की कटिंग मत दिखाइये। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सारी गलत सूचनायें इनके पास हैं। यही बार-बार दिखाते रहते हैं मान्यवर, इतनी बड़ी आपदा से प्रदेश गुजरा है, हमने हर प्रकार से इस बात की कोशिश की जिससे लोगों की जेब पर बोझ न पड़े। खासतौर से गरीब और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर बोझ न पड़े। इसलिए चाहे अनाज का वितरण हो, चाहे दवाई की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, हर प्रकार से इस बात की कोशिश की गयी कि गरीब आदमी पर इस महंगाई का बोझ न पड़े। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति में पब्लिक परसेप्शन क्या है। अभी जो उप चुनाव हुए थे। इन्होंने पूरे प्रदेश में हल्ला मचा दिया कि सातों सीटें जीत रहे हैं जीती कितनी, एक सीट जीती। मान्यवर, जो सरकार 2017 में 325 सीटें लेकर आयी आज साढ़े तीन साल के बाद जब उप चुनाव हुआ तो लोग उसे मिनी इलेक्शन कह रहे थे। उसका नतीजा क्या हुआ।

मान्यवर पब्लिक परसेप्शन, लोक मानदण्ड से बड़ा कोई पैमाना नहीं है, किसी की रेपोटेशन आंकने का। मान्यवर, सबसे बड़ा पैमान सिर्फ चुनाव होता है और चुनाव में जनता ने हमारे जो भी क्रिया कलाप थे उसके ऊपर यह मुहर लगायी कि हम सही हैं। हमारी नीतियां सही हैं, हमारी नीतियाँ जनहित में हैं और किसी भी प्रकार से हम महंगाई बढ़ने नहीं देना चाहते। हम कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से महंगाई का बोझ उस गरीब आदमी के ऊपर न पड़े। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से जो चीजें हैं मान्यवर, जो मजबूरी है उसके लिए तो हम भी मजबूर हैं और जो भी हम टैक्स का पैसा लेते हैं उसको पूरी मितव्ययता के साथ खर्च करते हैं। राशन वितरण में कितनी शिकायतें होती थीं। जबसे इसमें मशीन सिस्टम लागू किया गया तो उसमें लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा सेविंग की है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लोगों को अनाज भी मिलता है और लोग इससे सैटिसफाई भी हैं। मान्यवर, इसमें इन लोगों को कहना चाहिए कि इस सरकार का प्रबंधन इनकी सरकार के मुकाबले में एक लाख गुना बेहतर है। इसलिए हमारी कोशिश है कि जो मा0 नेता विरोधी दल ने चिंता व्यक्त की है कि हम उस वर्ग के ऊपर महंगाई का बोझ न पड़ने दें। लेकिन कहीं-कहीं हमारी मजबूरी है, उसको आपको भी समझना चाहिए और मैं समझता हूँ कि जनता भी उसको समझती है। यह जानबूझ कर अनजान बने रहते हैं वह और बात है, लेकिन हमारी हर तरीके से यह कोशिश होगी कि किसी भी प्रकार से लोगों को किसी तकलीफ में गुजारा न करना पड़े। मान्यवर, यह नियम-56 में नहीं आता है, इसलिए इसको अग्राह्य करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं तो यह सोचता था कि आप वित्त मंत्री के साथ संसदीय कार्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री और उसके साथ-साथ जनता के प्रतिनिधि एम0एल0ए0 हैं। इनको इस बात को जरूर कहना चाहिए कि हाँ महंगाई बढ़ी है।

मान्यवर, हर वर्ग का आदमी परेशान है, हम इसको कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह जोर देकर कह रहे हैं कि हमने महंगाई बढ़ाकर बहुत बढ़िया किया है और जीत-हार की बात बता रहे हैं। अगर हम जीत की बात बता देंगे तो फिर आप तुरन्त खड़े हो जायेंगे। ऐसी जीत समाजवादियों को नहीं चाहिए जैसी आप जीतते हैं। इस सरकार ने हर स्तर पर महंगाई को बढ़ाया है, जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और यह कह रहे हैं कि हमको जनता ने बहुमत से जिताया है। संसदीय कार्य मंत्री जी आप जेल में रहे और मैंने कभी आपसे पूछा कि आप वर्ष 1975 में जेल में रहे या नहीं रहे तो आपने कहा कि जेल में थे। मैंने आपसे पूछा कि आप इमरजेन्सी में जेल में थे तो आपने कहा जेल में थे। आप जेल में थे और मैं भी जेल में था, हम भी लोकतंत्र सेनानी और आप भी लोकतंत्र सेनानी, क्यों इमरजेन्सी लगी, क्यों जेल में थे ? जो बात आपने कही उसी के तहत इमरजेन्सी लगी। वर्ष 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीत कर आई थीं और वर्ष 1974 आते-आते महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इस तरह बढ़ गयी कि गुजरात विद्यापीठ से छात्रों ने आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया,

बिहार आते-आते उत्तर प्रदेश आया। इमरजेन्सी लगानी पड़ी, जिसमें हम और आप जेल गये और हिन्दुस्तान की सारी एजेंसियों ने उस समय इंदिरा गांधी को बताया कि अब चुनाव हो जायेगा तब यह कहते कि सभी भारी बहुमत में जीत के आयेंगी और जब इमरजेन्सी हटी और चुनाव हुआ तो कांग्रेस का उत्तर भारत से सूपड़ा साफ हो गया। वही आपका बहुमत है और वर्ष 1974 से आज तक लाख गुना महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अगला चुनाव वर्ष 2022 में आयेगा तो आपका भी सूपड़ा साफ हो जायेगा। मा0 संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री जी ने महंगाई को कम करने के विषय में, जनता के कल्याणकारी योजनाओं के विषय में कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं गरीब विरोधी, जन विरोधी एवं महंगाई की पक्षधर सरकार के खिलाफ अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से वॉकआउट करता हूँ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारी सरकार ने हर तरह से कोशिश की है कि किसी भी तरह से महंगाई को न बढ़ने दें, लेकिन हमें इण्टरनेशनल मार्केट के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए यह हमारी विवशता है और हर तरह से जिलाधिकारियों को निर्देश देकर सभी प्रकार से कोशिश की और अपने आप नया टैक्स न लगाकर, इस बजट में भी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स न प्रपोज करके, यह साबित कर दिया कि हम किसी भी तरीके से महंगाई नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। लेकिन हमारी इण्टरनेशनल मार्केट पर निर्भरता है, इसलिए हमारी वहां पर मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना मा0 लालजी वर्मा जी की है। हमारा अनुरोध है कि जो भी सूचनाएं हैं उनमें सभी मित्र कम समय में बोल दें, जिसमें तमाम मा0 विधायकों को बोलने का मौका मिल सके।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जबसे भा0ज0पा0 की सरकार आई है और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के ऊपर आक्रमण किया है। अभी 69000 शिक्षकों की भर्ती आयोजित कराई गयी थी और उसमें परिणाम के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं। इसमें से 1100 पद अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व थे, लेकिन वह पद भरे नही गये हैं और उसी के सम्बन्ध में वर्ष 2007 में एक शासनादेश हुआ था। "यदि किसी भर्ती में यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, वहां ऐसी भर्ती में उसके लिए आरक्षित रिक्ति यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों से भरी जा सकती है।" अब अनुसूचित जनजाति के 1100 पद रह गये हैं तो उक्त शासनादेश के अनुसार उसको अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जानी चाहिए थी।

लेकिन सरकार द्वारा उस भर्ती को नहीं किया गया, वह रिक्त पद खाली रह गये जिसके कारण पूरे प्रदेश का अनुसूचित जाति समाज का अभ्यर्थी है उनमें आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह की स्थितियां हर जगह हैं, मैं उसका विस्तार नहीं करना चाहूंगा। लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें इस तरह की गलतियां हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण विषय है, अनुसूचित के हित में है, पूरे 21 प्रतिशत से ज्यादा पूरे प्रदेश में है, उस पूरी आबादी के हित में यह प्रश्न है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज सदन की कार्यवाही रोककर, जिससे जो यह 1100 रिक्तियां रह गयी हैं, जो अभ्यर्थी उसके लिए पात्रता रखते हैं उनको उसमें नियुक्ति मिल सके तो निश्चित रूप से यह लोकहित का विषय है, तात्कालिक है, उस वर्ग के लोग आन्दोलित हैं और अविलम्बनीय है, नियम-56 के जितने भी कारण हैं वह इस पर लागू होते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी)-

मा0 अध्यक्ष जी, बड़ी विनम्रता के साथ आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ, एक तो कोई बात कहने पर कई बार आपत्ति होती है कि यह नहीं कहना चाहिए तो मैं पहली बार का विधायक हूँ और मा0 सदस्य से और तमाम लोगों से बहुत कनिष्ठ हूँ, इसलिए कोई बात बुरी लगेगी तो मुझे क्षमा करेंगे। बड़ा भ्रम पैदा होता है कि कई बार कहेंगे कि पिछड़ा, दलित, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सबके अधिकारों का पोषण होना चाहिए, उनका उन्नयन होना चाहिए। आज जब कार्य-स्थगन के माध्यम से यह प्रश्न रखा जा रहा है तो यह भूल जा रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति के लोग ही हमारे समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं जिनके अधिकारों के संरक्षण उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना अनुसूचित जाति का। हमारी सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास के नारे को लेकर काम करती है और मैं बहुत ही विश्वास के साथ तथ्यात्मक रूप से कह रहा हूं कि किसी भी तरह से सरकार की मंशा किसी भी वर्ग के, किसी भी सीट को, न करने की नहीं है। 69000 जो शिक्षक भर्ती की हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू की, उसमें मा0 अध्यक्ष जी, अनारक्षित श्रेणी में, जिसमें सामान्य, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति/जनजाति सभी के मेरीटोरियस छात्र जिसमें चयन पाते हैं, ऐसे 34,589 पद भरे गये। अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत 18,598 पदों पर नियुक्ति हुई, अनुसूचित जाति के अन्तर्गत 14,469 पदों पर नियुक्ति हुई, अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत 1354 पद थे केवल 245 ही अनुसूचित जनजाति के क्वालीफाइड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, उनमें से 24 की मेरिट ज्यादा थी तो अनारक्षित पद पर वह चयनित हो गये। इस तरह से 1354 के सापेक्ष केवल 221 अभ्यर्थियों का अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में चयन हुआ, इस तरह से 1133 पद रिक्त हैं। मान्यवर, अभी यह प्रक्रिया चल रही है, लगभग 1200 ऐसे अभ्यर्थियों का मामला काउंसिलिंग के बाद आया था जिनमें कुछ-न-कुछ अशुद्धियां थीं, किसी की माता का नाम गलत था, किसी के पिता का नाम गलत था, किसी का डेट ऑफ बर्थ भरने में कठिनाई थी, ऐसी तमाम सारी अशुद्धियां थीं, सामान्यतया

ऐसे लोगों को तुरन्त रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार की मंशा थी कि मेरीटोरियस स्टूडेंट छोटी-सी कमी के कारण चयन की सूची से बाहर न जायें, जनपदवार सूची जारी हुई थी, सारे मामले हम लोगों ने मुख्यालय मंगाये, केस-टू-केस स्टडी हुई, उसमें से अधिकांश को नियुक्त करने की प्रक्रिया हम लोगों ने की। कुछ मामले ऐसे रह गये थे जिन पर निर्णय लेना विधिक रूप से हमारे लिए मुश्किल था, उसे न्याय विभाग को सुपुर्द किया है और उनकी राय आने के बाद हम फाइनल करेंगे कि इस पूरी मेरिट सूची में से कितने लोगों का अभ्यर्थन निरस्त करना है। इसके बाद तब हम आंकड़े मंगायेंगे कि जनपदवार कितने पद रिक्त रह गये हैं, पिछला जो हमारा 1954 का आरक्षण का अधिनियम था, उसमें ये था कि एस0सी0 कैटेगरी की सीट को एस0टी0 से भरना चाहते हैं तो हमको 3 बार बैकलॉग की भर्ती करनी पड़ती थी, मैं मा0 सदस्य की उस बात से सहमत हूँ।

मैं माननीय सदस्य की उस बात से सहमत हूँ, बाद में इसमें 2007 में संशोधन हुआ, अब हम कर सकते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, जब तक रिक्त रह गए पदों की अधिकृत सूचना हमारे पास नहीं आती, तब तक हम किसी भी संवर्ग के पद पर दूसरे संवर्ग के लोगों की भर्ती सम्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वतः स्वीकार किया कि 1133 पद अनुसूचित जनजाति के रिक्त रह गए हैं, उसके लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिले। तो निश्चित रूप से जो 2007 का शासनादेश है कि अगर एस0सी0 के पद रिक्त रह जायें तो एस0टी0 के जो अभ्यर्थी हैं, तो उससे भर लिए जायें और यदि एस0टी0 के पद रिक्त रह जायें तो एस0सी0 से भर लिया जायेगा। जब वह शासनादेश वर्तमान में कार्यरत है, उसको बदला भी नहीं गया, तो जब नही बदला गया है तो उस शासनादेश के अनुसार वह रिक्तियाँ रह नहीं जानी चाहिए थीं, वह अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों से भरी जानी चाहिए थीं और आप स्वीकार भी कर रहे हैं कि यह शासनादेश है तो जब शासनादेश है, उसको आपने रोका भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

वह कह तो रहे हैं कि आगे भरेंगे।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने बताया कि अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कितने पद अन्ततः रिक्त रह गए हैं, उनकी संख्या आते ही कार्मिक विभाग से परामर्श करके, अगर कार्मिक विभाग से अनुमति मिलती है, तो हमको करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर मा0 सदस्यों को सुना, मा0 मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, अतः इसे अग्राह्य करता हूँ।

तीसरी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की है। आराधना जी, आज आपका भाषण भी है, इसलिए आप संक्षेप में अपनी बात कह लीजिए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, हम संक्षेप में ही अपनी बात रखेंगे।

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी एक सूचना थी। कल आपसे मैंने अनुरोध किया था।

श्री अध्यक्ष-

किस विषय पर आपकी सूचना है ?

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, जेल के अन्दर जो बन्दी हैं, उनसे मिलाई करने के सम्बन्ध में मेरी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। पहले मोना जी बोल लें।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के यमुनापार इलाके में फूलपुर थाना क्षेत्र के बसवार गाँव में 4 फरवरी, 2021 को बालू खनन को ले करके पुलिस प्रशासन और वहाँ के निषाद समाज के जो नाविक थे, जिस तरह से उनके बीच में प्रशासन ने ताण्डव किया है, जिसमें निषाद समाज के कई पुरुष और उसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चियाँ शामिल थीं, जिनको गम्भीर चोटें भी आयी हैं। यह काफी दुःखद मामला है। यहाँ जो नदियाँ हैं, खास कर गंगा और यमुना नदी, इनके दोनों तटों पर निषाद समाज के लोग रहते हैं। उनकी रोजी-रोटी पूरी तरह से इस पर आधारित है।

श्री अध्यक्ष-

तो हम सरकार से कह दें कि सरकार इसकी ठीक से जाँच करा ले और कार्यवाही कर ले।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर विषय है। यह सरकार के संज्ञान में आना चाहिए कि उस समाज के साथ कितनी बर्बरता की गयी है। खास करके जिस तरह से वहाँ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उस समय वहाँ एक भी महिला पुलिस नहीं थी और ज्यादातर जो घायल हुए, वह महिलाएँ और बेटियाँ थीं। मान्यवर, मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, क्योंकि एन0जी0टी0 की भी जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से खनन पर पूरी तरह से रोक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगी है। फिर भी क्या वजह है, एक कम्पनी है राजरतन, जो वहाँ पर अवैध खनन कर रही है, जिसको रोकने के लिए निषाद समाज के लोग वहाँ गए, पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की। उन्होंने मारपीट भी की और उनकी जो नावें थीं, जो उनकी रोजी-रोटी का एक मात्र साधन है, उनको भी जे0सी0बी0 लगा करके क्षतिग्रस्त किया और जला भी दिया। मैं मानती हूँ कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता और लगभग 200 से ज्यादा लोगों पर पुलिस ने मुकदमा भी कायम कर दिया। तो मैं आपसे सिर्फ यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि नियम-56 में ग्राह्यता योग्य यह प्रकरण है। आप इस पर चर्चा करायें, क्योंकि यह निषाद समाज और मछुआरों से जुड़ा हुआ सवाल है, अवैध खनन से भी जुड़ा हुआ है। इस पर आप सदन में चर्चा करायें और सरकार इस पूरे प्रकरण का संज्ञान ले।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारे क्षेत्र का प्रकरण है। मुझे भी अपनी बात कहने का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आज चर्चा हो जाने दीजिए, आज का ही दिन बचा है, कल माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, जो विषय नहीं आ पाए हैं, मैं उनको उठाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ जाए तब आप कहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी हमारे कांग्रेस के नेता ने नियम-56 की सूचना के माध्यम से एक जानकारी आपके माध्यम से सदन के लिए यह काम रोको प्रस्ताव के रूप में यह सूचना आई है इसमें दो बातें विशेष रूप से हैं, जिसकी आपको जानकारी दे दें। एन0जी0टी0 के द्वारा 670/18 अतुल सिंह चौहान बनाम एम0ओ0ई0एफ0 व अन्य में पारित आदेश में जनपद प्रयागराज की नदियों में जल धारा से खनन कार्य को प्रतिबंधित किए जाने एवं उसकी निगरानी हेतु पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में ओवरसाइड कमेटी का गठन किया गया है। ओवरसाइड कमेटी द्वारा नियमित रूप से जनपद प्रयागराज के खनन कार्यों की समीक्षा की जाती है। वर्तमान में संदर्भित क्षेत्र में कोई बालू खनन पट्टा संचालित नहीं है, इसलिए मा0 अधिकरण के आदेश के कारण नदी में हो रहे खनन को वैधानिकता प्रदान नहीं की जा सकती। जो भी यह खनन की बात की गई है, तो उस क्षेत्र में एन0जी0टी0 के द्वारा प्रतिबंधित है और किसी भी तरीके से उसकी वैधानिकता नहीं है। 4 फरवरी की घटना आपने जो कोड की है उसके बारे में जो हमारे पास प्रयागराज से रिपोर्ट आई है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आप अनुमति दें तो हमारे पास

पांच-सात लाइनें हैं हम उसे पढ़ दें। जो कुछ सदन में कहा गया है वह सत्य नहीं है। मान्यवर, यह 04-02-2021 को अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं जिला खनन अधिकारी के सहयोग हेतु पुलिस बल गया था। करीब 125-150 गांव से नागरिकों एवं स्थानीय लोगों द्वारा बहती जल धारा से बालू को अवैध तरीके से निकाला गया और मौजूद अधिकारियों द्वारा उन लोगों को ऐसा करने से मना किया गया और मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा भी उनको अवैध बालू को निकालने से मना किया गया। जिला प्रशासन/ खनन विभाग द्वारा जब पुलिस का सहयोग प्राप्त करने हेतु नावें एवं जे0सी0बी0 मंगवाई गई थी।

समझाने-बुझाने के उपरान्त उन लोगों के न मानने पर अधिकरण अधिकारी द्वारा जे0सी0बी0 मशीन से अवैध रूप से निकाली गई बालू को जलधारा में डलवाया जाने लगा। वहां पर मौजूद नागरिकों एवं ग्रामीणों द्वारा पथराव किया जाने लगा और जे0सी0बी0 मशीन को क्षतिग्रस्त किया जाने लगा। इस पर शांति व्यवस्था हेतु मौजूद पुलिस बल द्वारा न्यूनतम विधिक बल का प्रयोग कर राजस्व एवं खनन विभाग के अधिकारियों और सरकारी सम्पत्ति की रक्षा की गई। जिसके सम्बन्ध में थाना जनपद प्रयागराज में मुकदमा अपराध संख्या-123/2021, धारा-147, 148, 149, 307, 332, 353, 186, 336, 504, 506, 389 आई0पी0सी0 4/21 खाद्य एवं खनिज विकास का विनिमय अधिनियम, 1957 यह बनाम चन्द्र निशाद आदि आठ नामित व 150 से 200 व्यक्ति का नाम, पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। स्थानीय व्यक्ति एवं नामित द्वारा की जा रही अवैध खनन कार्यवाही को रुकवाने हेतु प्रशासन एवं खनन विभाग के अधिकारी गए थे एवं वहां पर पुलिस शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु मौजूद, किंतु स्थिति बिगड़ने पर पुलिस द्वारा सूझबूझ एवं संयम बरतते हुए कार्यवाही की गई। मौजूद पुलिस बल द्वारा किसी की गिरफ्तारी यह जानते हुए नहीं की गई कि यह लोग गरीब मजदूर व नाविक हैं। इसलिए उनको समझा बुझाकर वहाँ से जाने दिया।

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि एन0जी0टी0 के द्वारा वहाँ पर किसी भी प्रकार का खनन प्रतिबन्धित है और एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी उसकी लगातार मॉनीटरिंग करती है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर पहले बालू खनन किया गया और वहाँ जो भी अधिकारी लोग आए थे, अगर सभी लोग उनको वापस बालू पानी में बहाने देते, गंगा में डालने देते तो शायद यह घटना नहीं होती। घटना यहाँ से बढ़ी कि जब वे लोग उनकी निकाली हुई बालू को वापस नदी में डालने लगे तो उस वक्त इन लोगों ने रेसिस्ट किया। मान्यवर, अब जब कोई कार्य गैर कानूनी तरह से किया जाएगा तो कोई पुलिस बल पर हाथ रख कर तो बैठेगा नहीं, मजबूरी है। मैंने यह इसीलिए पढ़ा है।

(सदस्य श्री उज्जवल रमण सिंह एवं श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने एवं बोलते रहने पर व्यवधान की स्थिति)

(व्यवधान के मध्य)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, ऐसा कतई नहीं है, मैंने वहाँ पर नाम समेत बताया है। राज रतन कन्सट्रक्सन यहाँ पर अवैध खनन लगातार कर रहा है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, इलाहाबाद में बन्द है। एक आदमी की नाव जो आपने तोड़ी है तो वह नाव बंधी हुई नाव थी और बंधी हुई नाव को प्रशासन ने तोड़ा है। पुलिस ने बर्बरता की है, पुलिस ने औरतों को मारा है। इस मामले की गम्भीरता को देखकर इसकी जाँच करवा लें। आप इसकी जाँच करवा लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।

श्री अध्यक्षता-

यही हो वे कह रहे हैं।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

आप इसकी जाँच करवा लें। इसमें निषाद बिरादरी के साथ जो अन्याय है, निषाद बिरादरी के साथ जो ज्यादती की गई है तो आप इस मामले की जाँच करवा लें, क्योंकि आपको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह गलत रिपोर्ट भेजी है। वहाँ एक भी नाव जलधारा में नहीं पकड़ी गई और अगर पकड़ी गई तो उसकी वीडियोग्राफी कहाँ है ? वहाँ पर लोगों की नाव बंधी हुई थी, उनको प्रशासन ने तोड़ा है। औरतों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा है तो यह कहाँ का कानून है ? मैं आपसे सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस मामले की निष्पक्ष जाँच करवा लें और जो भी दोषी व्यक्ति हो, जो भी पुलिस कर्मी दोषी हों, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करवाएँ। जितनी धाराएँ आपने कही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम इसमें जाँच करवा लेंगे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मेरा बस इसमें यही कहना है कि इसकी एक जाँच करा लें और जाँच कराने के बाद जो भी सम्बन्धित अधिकारी दोषी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करें और जिन लोगों की नाव टूटी है, उनको मुआवजा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

हम इस सूचना को अग्राह्य करते हैं। श्री उमाशंकर सिंह जी की सूचना पर हमने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है कि सरकार कार्यवाही करे। इसी प्रकार श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी वाली सूचना को भी हमने शासन को सन्दर्भित किया है। श्री इकबाल महमूद, श्रीमती सुषमा पटेल, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री लकी यादव जी की सूचनाओं पर हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

अब मैं सदन को एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ।

[01:47] विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित प्रकरणों की जाँच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दिया गया है :-

1. श्री अमिताभ बाजपेई, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री प्रेम प्रकाश, तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर नगर (सम्प्रति अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयाग) के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक शून्य,
2. श्री नन्द किशोर गुर्जर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा खाद्य निरीक्षक, लोनी, गाजियाबाद, श्री सुधीर सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद, श्री नीरज जादौन, एस0पी0 देहात, गाजियाबाद, श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक, लोनी, गाजियाबाद तथा श्री आदित्य प्रजापति, तत्कालीन एस0डी0एम0, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 एवं
3. श्री अगयश राम सरन वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री वैभव श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, जनपद पीलीभीत के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 24 जनवरी, 2020।

उपर्युक्त मामलों में दी गई सूचना आज दिनांक 02 मार्च, 2021 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग मानी जाएगी।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

***श्री इकबाल महमूद-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं, बस एक मिनट लूंगा। हम आपके संरक्षण में हैं और आपने हमसे कहा था कि आप आगे दो मिनट बोल लेंगे। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है और आज जेलों के अन्दर जो निरुद्ध कैदी हैं, वे बहुत परेशान हैं और अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें मेरी सूचना थी, इसलिए सिर्फ दो मिनट में मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपका एक मिनट तो हो गया।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, आपने हमको अभी इजाजत दी है। यह तो मैंने आपको बताया है। मैं यह कह रहा हूँ कि एक साल हो गया, कोविड चल रहा है और इसमें हर चीज के ऊपर रोक थी। सारी बसें, ट्रेनें और जनसभाएँ सब बन्द थीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलेक्शन भी हो गया नहीं हुआ तो बंदियों से मिलना और मुलाकात करना। एक साल से बंदियों से उनका परिवार नहीं मिल पा रहा है। एक साल का समय हो गया है। बड़ी परेशानी है और सब लोग जानते हैं और यह समस्या केवल मेरी नहीं है सदन के हर विधायक की है और हर परिवार के लोग इन लोगों से मिलते होंगे, इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन मिल जाए कि उनकी जल्दी मुलाकात हो जायेगी। इनसे आश्वासन दिलवा दें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। हमने ध्यानाकर्षण करा दिया है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, यह सभी की समस्या है। सारे विधायकों की समस्या है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

इसको हम आज ही दिखवा लेंगे।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्यय पर साधारण चर्चा[†]

श्री अध्यक्ष-

अब हम बजट पर चर्चा शुरू करते हैं। हमसे किसी आवश्यक कार्यवश घर जाने के सम्बन्ध में श्री कमल सिंह मलिक जी मिले थे, अतः इनको अब 5 मिनट में सदन में अपनी बात रखनी है।

श्री कमल सिंह मलिक-

जय गंगा मैय्या, जय गढ़मुक्तेश्वर धाम मा0 अध्यक्ष जी एवं सदन में उपस्थित पूज्य महानुभावों को मेरा प्रणाम।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 सदस्य पीठ को सम्बोधित करते हुए अपनी बात शुरू करें।

***श्री कमल सिंह मलिक-**

मा0 अध्यक्ष महोदय तथा सदन में उपस्थित पूज्य महानुभावों को मेरा प्रणाम। मा0 योगी जी की सरकार का वर्ष 2021-22 का बजट जिसे मा0 वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया उसके समर्थन के प्रस्ताव पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ किसी भी सरकार का बजट जनता के प्रति उस सरकार की इच्छाशक्ति व संवेदनाओं को दर्शाता है। हमारा यह बजट उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। इस बजट के अन्दर कोई नया कर नहीं लगा है, इसलिए यह बजट उत्तर प्रदेश के प्रत्येक किसान के लिए, मजदूर के लिए, शोषित के लिए, वन्चित के लिए और दलित के लिए, युवाओं के

[†] दिनांक 25 फरवरी, 2021 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए, व्यापारियों के लिए और डॉक्टरों के लिए समर्पित है। इस बजट के अंदर सबको राहत दी गयी है। कोरोनाकाल के उपरान्त वैश्विक और मानवीय जो आपदा आयी है उसके बाद भी इस बजट को दुनियां के प्रत्येक अर्थशास्त्री ने सराहा है। जिस समय पूरी दुनिया के देश, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गयी उसके बाद भी यह बजट पिछले बजट से बड़ा बजट है। मैं इस बजट का अपने पूज्य मुख्य मंत्री को समर्पित करता हूँ, सरकार को समर्पित करता हूँ, मैं इसे वित्त मंत्री को समर्पित करता हूँ। कोरोनाकाल के अंदर मेरी विधान सभा.....

श्री अध्यक्ष -

आपका आधा समय व्यतीत हो होगा है।

श्री कमल सिंह मलिक -

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, मुझे थोड़ा समय और दे दिया जाए।

आय व्ययक 2021-2022 की साधारण चर्चा में भाग लेने वाले दलीय नेताओं एवं मंत्रीगण हेतु समय-सीमा का निर्धारण

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना दे दें कि इसके बाद कांग्रेस की नेता श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी बोलेंगी, सभी दलों के नेताओं के लिए 20-20 मिनट का समय तय हुआ था, विश्वास है कि वह समय के भीतर ही अपनी बात समाप्त करेंगी। इसी प्रकार मा0 मंत्रीगण भी बीच-बीच में बोलेंगे उनके लिए भी 15-20 मिनट की अवधि पर्याप्त होगी और भी मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि वह समय का पालन करें।

[01:50] वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्यय पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री कमल सिंह मलिक-

मेरी विधान सभा में हम लोगों ने कोरोना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ी है, बिहार तक की लड़ाई लड़ी है, मेरी विधान सभा एन0सी0आर0 में आती है। मैं धन्यवाद दूँगा अपने परिवहन मंत्री को और अपनी सरकार को जहाँ उन्होंने एक परिवहन विभाग का डिपो बनाने का काम किया। मेरी विधान सभा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, प्रशासन ने रात-दिन लग कर लगभग पौने दो महीने हम लोगों ने उनको भोजन देने का काम किया, उनको सारी सुविधायें देने का काम किया।

(इस समय 01 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए)

जहाँ तक किसान की बात होती है। किसान का हित सरकार की प्राथमिकता है उसकी प्रतिबद्धता है। जमीन अधीग्रहण का प्रस्ताव हेतु हम और हमारी सरकार जो बिल लेकर आई है, पहले जहाँ दूसरी सरकारें औने-पौने दामों में जमीन का अधिग्रहण कर लिया करती थीं वहीं हमारी सरकार ने चार गुना सर्किल रेट के दाम से देने का काम किया उससे किसान अब यह कहता है कि मेरी जमीन निश्चित रूप से किसी योजना में आ जानी चाहिए, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खतौनी के स्थान पर एक घरौंदी देने का काम किया है, प्रत्येक किसान

के पास आज अपने जो उसके घर होते हैं, खेत होते हैं, उसके भी पेपर मिलेंगे और वह उसका मालिक होगा। आज जहां हम 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये किसान क्रेडिट कार्ड से ही लिया करते थे और करोड़ों की जमीन को बंधक बनाया करते थे, आज उससे निजात मिलने का काम हुआ है। आज हम अपने घर के पेपर रख कर बैंक से लोन ले सकते हैं। मेरी विधान सभा के अंदर एक सिम्भावली मिल आती है, दूसरी सरकारों में जहाँ सिम्भावली मिल के प्रबंधक और बैंकों के द्वारा हजारों किसानों को भूमि को बंधक बनाकर 4 सौ करोड़ रुपये निकालने का काम किया गया। हजारों किसान मेरे पास आए, मैं अपने पूज्य मुख्य मंत्री जी को नमन करता हूँ जिनके आदेश से सी0बी0आई0 लगी और उसमें जांच हुई। इसमें 4 सौ करोड़ रुपये जमा हुए। उनकी जमीनें बैंकों से मुक्त करायी गयीं। मैं भी किसान का बेटा हूँ और किसान के सारे दुख-दर्द जानता हूँ। आज किसान के नाम पर उनको बहकाने का काम हो रहा है। किसान वर्ग ऐसा लुभावना है कि जल्दी से प्रतिपक्ष उसको बहका लिया करता है। आज किसान सड़कों पर है परन्तु बहुत जल्दी ही वह किसान समझ जाएंगे कि हमारा किस प्रकार से देश के विरुद्ध दुरुपयोग हो रहा है। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि 'लेने का कोई नाम है तो राम का और करने का कोई काम है तो राम का'।

आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। मेरे प्रतिपक्षी लोग भगवान राम का नाम लेने में दिक्कत अनुभव करते हैं। उसी का कारण है कि आज पूज्य योगी जी पूज्य प्रधानमंत्री व महामहिम ने जबसे शिलान्यास किया है, उससे पूरी जनता प्रफुल्लित है और पूरी जनता का रोम-रोम खिला हुआ है। आज वही भगवान राम का मंदिर अयोध्यापुरी में हैं और यह वही अयोध्यापुरी है, जहां से पुष्पक विमान उड़ा करते थे। आज वहाँ पर एक विशाल अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। यह वही अयोध्यापुरी है, जो सारे भू-मण्डल पर राजधानी हुआ करती थी। भगवान राम के वंशज, जो ब्रह्मा जी से प्रारम्भ होकर, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए फिर विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए, फिर इक्ष्वाकु वंश आया और सारा इक्ष्वाकु वंश यहां से भू-मण्डल पर राज किया। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षि हुए, कुक्षि के पुत्र विकुक्षि हुए, विकुक्षि से राजा बाण, अनरण्य, पृथु, त्रिशंकु, धुंधुमार हुए, युवनाश्व हुए, मान्धाता, सुसन्धि हुए। सुसन्धि के दो पुत्र हुए ध्रुवसन्धि एवं प्रसेनजित हुए। ध्रुवसन्धि के पुत्र भरत हुए जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा। असित हुए, सागर हुये, असमंज, अंशुमान, दिलीप हुए। दिलीप, भगीरथ के पुत्र ककुत्स्थ, रघु, प्रवृद्ध, शंखण, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, मरू, प्रशुश्रुक, अम्बरीष, नहुष, ययाति, नाभाग, अज, अज के पुत्र दशरथ हुए और उनके पुत्र श्रीराम हुए। ऐसा श्रीराम का मंदिर बन रहा है। श्रीराम का नाम लेने से निश्चित रूप से हमारे पाप कटते हैं। तुलसीदास जी ने कहा था कि भगवान राम कहते हैं, जो मेरे सन्मुख होता है, उसके पाप कट सकते हैं'। निश्चित रूप से हमें भगवान को याद करना चाहिए। आज मेरी सरकार भगवान के लिए समर्पित है, उनके काम के लिए समर्पित है।

अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधान सभा युगों का एक इतिहास समेटे हुए है। मेरी विधान सभा का सतयुग से लेकर कलयुग तक का इतिहास है। मेरे यहां राजा नहुष जिनको छिपकली बनने का श्राप मिला था, मेरी विधान सभा के अंदर ही उन्होंने वह श्राप काटा। परशुराम की

तपोस्थली है। मेरे गढ़ मुक्तेश्वर का यह अपभ्रंश है, गढ़। मेरा जो गढ़ है, भगवान महादेव के जो गढ़ जय और विजय थे, उनकी मुक्ति का स्थान है। द्वापर में भगवान आए जिन्होंने महाभारत के उपरान्त जो उत्तर भारत का मिनी कुम्भ कहा जाता है, वहां मेला लगता है। इसके लिए मैं अपने पूज्य मुख्य मंत्री योगी जी को उनके चरणों में पुनः नमन करता हूँ। दूसरी सरकारों में किसी ने हमारे गढ़ पर ध्यान नहीं दिया। हमारी जो आदिकाल की यह सृष्टि का इतिहास समाये हुए विधान सभा है, उसको छिपाने का काम किया। उन्होंने हमारे मेले को राजकीय करने का काम किया। लोकतांत्रिक इतिहास में किसी सरकार ने हमें कुछ देने का काम नहीं किया। शिक्षा की कोई संस्था, कोई स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पताल नहीं था। मैं अपने शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें एक डिग्री कालेज देने का काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को, जिन्होंने ट्रॉमा सेन्टर देने का काम किया। मैं अपने परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा। जब हमारा डिपो बना था, जहाँ पर हम नित्य बसें कोरोना के दौरान भेजा करते थे, उन्होंने यहां एक पी0पी0पी0 मॉडल पर एक बड़ा बस अड्डा देने का काम किया है। मैं अपने मा0 पूज्य मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें 4 सौ के0वी0ए0 का पावर ट्रान्समिशन देने का काम किया है। जो मेरे विधान सभा के अन्दर बन रहा है। जहाँ मेला लगता है वहां 40-50 लाख लोग तम्बू लगाकर रहते हैं, वहां धरातलीय वातावरण इस प्रकार का है कि गंगा जो इधर चली जाती है, उधर चली जाती है। मैं चाहूँगा मेरी सरकार वहां तटबन्ध बनाकर गंगा जी की धारा को, उसकी गति को रोक करके वहां पक्के घाट बनाये जायें। मेरी विधान सभा क्षेत्र दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर है, मैं अपने पूज्य योगी जी से आग्रह करूंगा कि आज जितने भी रास्ते दिल्ली से निकलते हैं, राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, उन सारे रास्तों पर मेट्रो लगभग 70 से 80 किलोमीटर दौड़ती है, लेकिन मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में आकर मेट्रो रुक जाती है। मैं आग्रह करूंगा कि मेट्रो को आगे तक बढ़ाया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त कर दीजिये।

श्री कमल सिंह मलिक-

मैं आग्रह करूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के बहादुरगढ़ और सिम्भौली को नगर पंचायत बनाया जाये, इनकी आबादी लगभग 20 से 25 हजार की है। मैं अपनी सरकार से आग्रह करूंगा कि मेरे यहां नेचुरल रिर्सोसेस का बहुत बड़ा भण्डार है, उसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाय। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। जय हिन्द।

श्री आराधना मिश्रा 'मोना'-

आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए अधिष्ठाता महोदय आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय वित्त मंत्री जी ने दिनांक 22 फरवरी, 2021 को बजट भाषण जोरदार पेश किया पर असरदार पेश नहीं कर पाये। पिछले 04 बजटों की तरह यह

बजट भी आकड़ों की बाजीगरी था। आज उत्तर प्रदेश में जमीनी हालात ज्यो-का-त्यों है। पिछले बजट की तरह यह बजट भी सच्चाई से परे रहा। माननीय वित्त मंत्री जी ने और स्वयं मुख्य मंत्री जी ने महिला सुरक्षा, किसान, युवा, रोजगार, कानून-व्यवस्था की बड़ी-बड़ी बातें कीं, आंकड़ों को हमें समझाने का प्रयास भी किया, प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हो गयी ऐसा दिखाने का भी प्रयास किया, पर सच्चाई वास्तविकता से बहुत दूर है। भाषणों से ऐसा लगता है कि मानों आज उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है वह सब इन्हीं की देन है। बाकी किसी सरकार ने न कुछ किया है और न कुछ करने योग्य थी। हमारे सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं उनका भाषण सुनने से यही प्रतीत होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। एक बात कहूंगी की "गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझी पर टिकी है।" ये पेपरलेस बजट, बड़ी पीठ ठोंकी गयी। मैं कहूंगी कि ये पेपरलेस बजट ही नहीं, ये वुथलेस बजट है, ये सच्चाई विहीन बजट है, इसमें सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है। इतना दिशाहीन, तथ्यों से परे बजट, मैं मानती हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी पेश कर सकती है और दूसरा कोई पेश नहीं कर सकता। इसमें उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए कोई भी रोडमैप मौजूद नहीं है। हम रोज सुबह जब अखबार पढ़ते हैं तो लूट, डकैती, बेटियों के साथ बलात्कार, भ्रष्टाचार की नई-नई खबरें छपती हैं। मैं नहीं जान पाती कि सरकार के पास कहां से आंकड़े आते हैं, पर ये सच है कि उत्तर प्रदेश के अपराधी रोज नया अपराध करके सरकार को सलामी देते हैं और सरकार घुटने टेके बैठी रहती है उन अपराधियों के अपराध रोक नहीं पा रही है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि "जिस देश का अन्नदाता खुश होगा वही देश खुशहाल हो सकता है" और आज परिस्थितियां क्या हैं अधिष्ठाता महोदय, 12 हफ्ते से भी ज्यादा समय बीत चुका है, किसान उत्तर प्रदेश की सरहद पर बैठा हुआ है। 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं जिसमें बहुत सारे उत्तर प्रदेश के थे, पर उस पर सरकार मौन है। क्या वजह है कि ये 03 काले कानून सरकार वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश की विधान सभा से प्रस्ताव क्यों नहीं ले जाती, केन्द्र में भी तो इनकी सरकार है, अगर इच्छा शक्ति होती तो उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी ये प्रस्ताव ले करके आती कि ये तीनों काले कानून किसानों के हित में वापस लिये जायें। पर मैं इतना ही कहूँगी कि किसानों के साथ खड़े होने के बजाय उनके ऊपर दोषारोपण किया गया, उनको ही तरह-तरह की बातों से प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर आरोप लगाये गये। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास किसानों के लिये कोई रोडमैप इस बजट में नहीं है। डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी इसके पहले हमारे माननीय नेता विरोधी दाल ने महंगाई के ऊपर नियम-56 में चर्चा कराई। पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि डीजल के दाम की बढ़ोत्तरी सीधे किसान की कमर तोड़ देती है। बुवाई, कटाई, मड़ाई, सिंचाई यह सारी चीजें डीजल पर आधारित हैं, पर जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार उसको नियंत्रित करने के लिये जो स्टेट टैक्स है, उसको कम करने के लिये इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिये सीधा यह प्रतीत होता है कि किसानों के प्रति यह सरकार संवेदनशील नहीं है। पेट्रोल के दाम जो बढ़ते चले जा रहे हैं आखिर क्या वजह है कि

जब अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत आधी हो गयी है तो डीजल और पेट्रोल के दाम दोगुने क्यों हो गये हैं। क्या मध्यमवर्गीय परिवार पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान नहीं है।

जिस तरह गैस के दाम बढ़ रहे हैं, अभी 25 रुपये कल बढ़ा। यह वही उज्ज्वला योजना है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेताओ ने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था और इस सदन में मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि महिलाओं के आँसू पोछने के लिये यह योजना लाई गयी है, पर क्या आज यह सच नहीं है कि इस गैस के बढ़ते हुए दाम से उत्तर प्रदेश की महिलाओं के आँसू निकल रहे हैं। पूरी तरह से सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में असफल रही है।

छुट्टा जानवर की बात कहना चाहती हूँ। आज जिस गौ-वंश की रक्षा की हम बात करते थे, मैं भी धर्म से हिन्दू हूँ ब्राह्मण हूँ हमारे पास भी गौशाला है, मैं गौ-वंश की रक्षा करती हूँ और बहुत सारे सदस्य जो यहाँ बैठे हैं वह भी करते हैं। पर एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहती हूँ कि आज से चार साल पहले जिन्हें हम गौ-माता कहते थे गौ-वंश की रक्षा करने की बात करते थे आज उसे छुट्टा जानवर की श्रेणी में लाकर किसने खड़ा कर दिया। किसानों की आज अगर फसल नष्ट हो रही है तो क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि क्या सरकार ने किसानों को एक भी पैसे का मुआवजा देने की बात की और सबसे बड़ी धृष्टता यह है कि इस सदन में सरकार यह कह रही है कि किसी भी किसान की कोई फसल की क्षति नहीं हुयी। मैं मानती हूँ कि इससे बड़ा झूठ और किसानों के साथ धोखा दूसरा कोई हो नहीं सकता।

आज गन्ना किसान जिनका लगभग 10 हजार करोड़ से भी ज्यादा बकाया है इनसे भी सरकार ने वायदा किया था कि इसको जल्दी से जल्दी हम समयबद्ध तरीके से चुकायेंगे, पर वह अभी भी नहीं हो पाया। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते मगर फिर भी वह चलता खूब है।

प्रदेश में बनाई गयी गौशालाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात लगातार समय-समय पर सामने आई है, यह अधिष्ठाता महोदय बड़े दुख की बात है। जिनकी सुरक्षा की बात करें, जिनके लिये मैं पूरी तरह माननीय मुख्य मंत्री जी से सहमत हूँ। उन्होंने एक बड़ा बजट उसके लिये रखा है, पर क्या वह बजट उन गौ-शालाओं तक उन गौ-वंश की रक्षा के लिये पहुंच पा रहा है और मैं जिम्मेदारी से इस सदन में कहना चाहती हूँ कि जो भ्रष्टाचार गौ-शालाओं के नाम पर हो रहा है, आने वाले समय में यह भारतीय जनता पार्टी के लिये काल बन करके सामने आयेगा।

जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के लिये कहीं भी कोई बड़ी योजना इस बजट में सामने नहीं आई। न ही कोई नया अस्पताल, न ही कोई एम्स कोई भी बड़ी योजना इस बजट में नहीं आई। कोरोनाकाल का संकट हम सबके सामने आया। अगर पिछले ढाई से तीन सालों में सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ की होती तो शायद हम कोरोना में एक बेहतर लड़ाई लड़ सकते थे।

मैं इससे इन्कार नहीं करती कि हमने प्रयास नहीं किया, सरकार ने बहुत प्रयास किया और कहना चाहती हूँ कि सभी सदस्यों ने सरकार के साथ खड़े होकर चाहे वह किसी भी पार्टी का भी हो, हम सबने भी साथ दिया, पर मैं एक आँकड़ा आपके सामने पेश करना चाहती हूँ जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार कितनी गम्भीर है ? जनता के सामने सबसे बड़ा संकट चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। कल वेंटीलेटर की बात हो रही थी। वेंटीलेटर तो खरीदे जा सकते हैं, पर उनको चलाने के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए, उनका अभाव कहाँ से पूरा होगा ? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक डाक्टर के जिम्मे एक हजार मरीज होने चाहिए, यह देश के मानक हैं। पर उत्तर प्रदेश में वास्तविकता क्या है ? आज हमारे पास प्रत्येक डाक्टर पर 3812 मरीजों का बोझ है। क्या यह सम्भव है, मानवता को अगर ध्यान में रखें तो क्या कोई डाक्टर इस अनुपात में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ दे सकता है। यह स्पष्ट है कि पूरी तरह से 4 सालों में सरकार ने न डाक्टरों की भर्ती की और न पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की, जिसकी वजह से यह अभाव हमारे सामने आया है। कोरोनाकाल में बहुत काम हुआ, लेकिन और बेहतर किया जा सकता था, पर जो विषमता सबसे बड़ी सामने आयी, वह क्वारेंटाइन सेन्टर्स की थी, जहां पर कोरोना के मरीजों को रखा गया। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हम सबने भी उन्हें देखा कि किस तरह से क्वारेंटाइन सेण्टर में न पानी था, न बिजली थी, न वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ थीं, खाने का अभाव था। इन सारी समस्याओं को झेलते हुए भी, इस प्रदेश की जनता ने कोरोना में लड़ाई लड़ी, पर सरकार पूरी तरह से उस लड़ाई को लड़ने में असफल रही। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई दिखायी दी।

मैं कोरोना योद्धाओं के जज्बे को जरूर सलाम करती हूँ और इसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कहा कि मीडिया कर्मियों को भी कोरोना योद्धाओं की श्रेणी में लाना चाहिए। मैं यह मानती हूँ कि यह चौथा स्तम्भ है, जिसने लगातार हमें वास्तविकता दिखायी, रूबरू कराया और अगर कोई मदद करना चाहा तो इन्हीं मीडिया कर्मियों के माध्यम से वहाँ पर पहुँच पाया। बहुत सारे मीडिया के साथियों को भी हमने कोरोनाकाल में खोया है। मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि 25-25 लाख की आर्थिक सहायता इन मीडिया कर्मियों के परिवार को दी जाए, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, अपने प्राणों की आहुति दी। अवस्थापना की सुविधाओं का जिक्र करें सरकार की मंशा, लोक निर्माण विभाग का जो बजट है, उससे स्पष्ट दिखायी देती है। पिछले वर्ष जितनी योजनाएं चल रही थीं, जितने एक्सप्रेस-वे बन रहे थे, पर 4 साल से बजट भाषण में लगातार वह योजनाएँ दिखायी देती हैं, पूरी होती नहीं दिखायी दे रही हैं, क्योंकि बजट का पूरी तरह से अभाव है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि गड्ढामुक्त सड़कें हों या फिर नई योजनाएँ हों, सरकार को पूरी तरह से अवस्थापना के और सड़कों के इन्फास्ट्रक्चर पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जितने भी बजट की आवश्यकता हो, उतना बजट दे करके, उत्तर प्रदेश की सड़कों को और जो वायदे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए थे, उसको पूरा करना चाहिए। औद्योगिक विकास की बात करें, इन्वेस्टर्स समिट में एक नहीं तीन-तीन ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। मुझे तो अफसोस होता है, अधिष्ठाता

महोदय कि जितना पैसा सरकार ने इन इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में खर्च किया, अगर उतना पैसा भी इन्वेस्टमेंट में आ जाता तो शायद प्रदेश का कुछ भला हो गया होता। नौकरी तो आयी नहीं, पर 4 साल से लगातार हम यह कहानी सुनते हैं कि इतने का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया है। वास्तविकता क्या है ? कितना रोजगार मिला, कितना इन्वेस्टमेंट, जिससे उत्तर प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो सके, कितने उद्योग लगे, सवाल यह है ? आज बेरोजगारी को लेकर हमारा नौजवान सड़कों पर खड़ा है, आप उसको रोजगार तो नहीं दे पाये, पर जब उसने रोजगार की बात की तो आपने उसको लाठियाँ दीं, उसको जेल में बन्द कर दिया। यह बेरोजगारी, 45 वर्ष की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर आई है तो इस दौर में आई है।

हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, बहुत मेहनती हैं और इन्होंने बहुत काम किया है पर मैं जरूर कहना चाहती हूँ, मुझे अफसोस है कि बिजली की कोई बड़ी योजना इस बजट में नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि बिजली की आपूर्ति हो। जो भी धन की आवश्यकता हो, जिस भी चीज की आवश्यकता हो, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूँगी कि किसी भी योजना को पूरा करने लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण है, विद्युत आपूर्ति प्रदेश लिए महत्वपूर्ण है, यह हमारे उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ कि सरकार हमेशा "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं" की बात करती है। मैंने लगातार सदन में एक मांग उठायी कि महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। क्यों नहीं इसका प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधान सभा से किया जाता है कि बेटियों को जिस तरह से अन्य पंचायत में और सभी चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण जो कांग्रेस के समय दिया जाता था वैसे ही 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को आगे भी मिलना चाहिए। दूसरी बात, जिस वर्ग की महिला हो, आज नौकरी में भी अगर उसी वर्ग की महिला को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा तो मैं मानती हूँ कि उस वर्ग की महिला की भागीदारी बेहतर हो सकती है। सरकार राम राज्य की बात करती है जिस प्रदेश में बेटियों को जिन्दा जलाया जाता हो, मैं उन्नाव की घटना का जिक्र कर रही हूँ, क्या इसको राम राज्य कहते हैं। राम राज्य लाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत होती है और वह इच्छाशक्ति मुझे इस सरकार में दिखाई नहीं देती है। बजट में तो राजस्व का घाटा दिखाया है उसको पूरा करने के लिए सरकार की कोरी कल्पनाएं हैं, कोई हकीकत नहीं है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि नतीजा यह होगा कि अन्त में योजनाओं की कटौती की जायेगी तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका बोझ जनता को झेलना पड़ेगा। आर्थिक रूप से ईमानदारी नहीं होगी, महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा तो की जा सकती है परन्तु सच्चाई से उसको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अन्त में मैं एक बात कहूंगी कि-

उड़ने दो मिट्टी को, कहाँ तक जायेगी।
हवा का साथ छूटेगा, तो जमीन पर तो आ ही जायेगी।

न्याय विभाग की एक बात का जिक्र मैं करना चाहती हूँ आज बड़ी बहस हुई, हमारे जो अधिवक्ता हैं, लगातार कई घटनाएं हुईं जिसमें अधिवक्ताओं की हत्या हुई और बड़ी बात

यह है कि न्यायालय परिसर में भी कई घटनाएं सामने आईं। मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि आकस्मिक और अप्राकृतिक निधन अगर अधिवक्ताओं का होता है तो उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए सरकार मुआवजे की घोषणा करे और बजट में इसको शामिल करे। पुलिस को चुस्त-दुरुस्त बनाने की आवश्यकता पूरे प्रदेश में है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपराधी कर रहे हैं उसी तरह की टेक्नोलॉजी को ट्रेनिंग हमारी पुलिस को भी देनी चाहिए और इसके लिए जिस भी चीज की आवश्यकता हो उसे सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र की एक-दो बातें आपके सामने रखकर बात को समाप्त करूंगी। मेरा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है और अविकसित क्षेत्र है। मंगापुर उदयपुर नाम का एक विकास खण्ड है, विकास खण्ड का सृजन हुआ था पिछली सरकार में, उसका गजट भी हो गया था, लेकिन वह अभी क्रियाशील नहीं हुआ है तो मैं अनुरोध करूंगी कि उसको क्रियाशील किया जाय। भोजपुर में एक लिफ्ट कैनाल की आवश्यकता है और मुस्तफाबाद में एक पक्के पुल की आवश्यकता है। अन्त में, माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत आवश्यक है. कह लेने दीजिये, यह मेरी अपनी बात नहीं है, 403 सदस्य जो बैठे हैं, उनके बारे में है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चले गये हैं लेकिन हम सबकी बातों को वहाँ तक पहुंचा दीजिएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक ही चीज पूछना चाहती हूं कि जब कभी सदन के सत्र का आह्वान होता है, हम सभी सदस्य अपने क्षेत्र को, अपने परिवारों को और सारे कामकाज को छोड़ करके सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी हैं, पर जब हम यहाँ से जाते हैं 10-15 दिन के बाद तो क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जनता होती है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपसे भी पूछते होगे कि का लाया, कुछ मिला, तो हम भी सब बताते हैं। जैसे इधर के जायेंगे तो बतायेंगे कि अरे! हवाई जहाज उड़ेगा, इतने सारे हवाई अड्डा बन गये हैं। वह वहाँ से उड़ेगा मेरठ से और गोरखपुर तक जायेगा। गंगा एक्सप्रेस-वे बन गया है अब टाइम नहीं लगेगा, सीधे पहुंच जायेंगे। हम भी बतायेंगे कि सरकार हमारी नहीं है, हमे कुछ नहीं मिला तो मालूम है कि वह क्या कहेंगे, कहेंगे कि झुट्ठे हो तुम सब, हवाई जहाज उड़ेगा तो हमको क्या बिठायेगा, यह बताया कि सरकार और मुख्य मंत्री जी हमारे बारे का दिये है। क्या जवाब देंगे ये और क्या जवाब देंगे हम। हम लोग तो विपक्ष के हैं जब हम कहेंगे कि कुछ नहीं मिला तो यह कहेंगे, या देखा एक और झूठ अरे! इतने बड़े महात्मा, इतने दयालु हमारे मुख्य मंत्री, जिनका हाथ हमेशा ऐसे ही रहता है, ऐसे कभी रहता ही नहीं है तो कैसे कुछ नहीं मिला, ठीक से मांगा नहीं होगा।

तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि यह अन्तिम वर्ष है, चुनाव का वर्ष है, हमारे सदन के सभी साथी जब जाएं तो कम से कम दो-दो सौ हैण्डपम्प हम सभी लोगों को मिल जाना चाहिए और कम से कम 10-10 किलोमीटर सड़क मिलनी चाहिए। सड़क के लिए इतना बड़ा अभाव कैसे है, सरकार ने इतना बड़ा बजट दिया है, सब कुछ तो लुटा दिया है, थोड़ा विधायकों के बारे में सदन के सदस्यों के बारे में भी सोच लें। 10-10 किलोमीटर सड़क और दो-दो सौ हैण्डपम्प कोई बड़ी चीज नहीं है। कोरोनाकाल में जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुरोध किया तो माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता बसपा और हम सभी लोगों ने बात की और सहज रूप से विधायक निधि कोरोनाकाल के लिए दे दी। मैंने माननीय मुख्य मंत्री

जी का भाषण सदन में सुना है कि हम कोई चीज उधार नहीं रखते तो इसको क्यों उधार रख रहे हैं। ब्याज समेत इसको वापस कर दें, जो पिछली वाली थी उसको भी दे दें और कुछ जोड़ करके इस बार भी दे दें। यह अन्तिम वर्ष है, सारे सदन के हमारे साथी चाहते हैं कि जिस ईमानदारी से हम जीत करके आये हैं, जनता के प्रति वही ईमानदारी दिखायें और जीत करके दोबारा आना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। महंगाई की बात पर हमारे नेता विरोधी दल ने एक बड़ा जोरदार भाषण दिया, मैं बहुत प्रभावित हूँ आज उनसे, महंगाई केवल जनता के लिए ही नहीं है, महंगाई सदस्यों के लिए भी है, इनका भी परिवार है। तो जो पैसा, जो खर्च माननीय सदस्यों को मिल रहा है, मैं मानती हूँ कि वह अपर्याप्त है उसको भी बढ़ाने पर सरकार को विचार करना चाहिए और जो पूर्व सदस्य हैं उनकी भी राशि को बढ़ाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। मैं बहुत-बहुत आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे 2021-22 के बजट के समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का है, जिसमें 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख की नई योजनाएं सम्मिलित हैं। महोदय, यह बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवानों का बजट है। यह बजट हर घर नल "जल जीवन मिशन" के लिए समर्पित है। हर घर नल, हर घर बिजली, हर गांव में सड़क, अच्छी शिक्षा, युवाओं को रोजगार के लिए हमारी सरकार ने यह बजट दिया है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार का यह पांचवां बजट है। हमारी सरकार लगातार गाँव, गरीब और किसानों के लिए कार्य कर रही है। मैं मा0 प्रधानमंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि बीते वर्ष कोरोनाकाल में देश और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहने का कार्य किया है। कोरोना की बहुत चर्चा हो चुकी है, मैं उसके आगे बढ़ना चाहता हूँ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। उत्तर प्रदेश के लगभग हर जनपद में मेडिकल कॉलेज देने का कार्य किया है। गोण्डा जनपद के देवीपाटन मण्डल में भी मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। हमारी सरकार ने कोरोनाकाल में पूर्वांचल का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल गोण्डा में देने का काम किया और कोरोनाकाल में ही उसका उद्घाटन भी किया। इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। हमारे विरोधी दल के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं है। हम लोगों का चार साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के इसी सदन में हम लोग चर्चा करते थे। शुरू में जब हम लोग विधायक चुनकर आये थे, तो गोण्डा में जाने के लिए जहाँ

सड़कें नहीं थीं, वहीं आज गोण्डा जनपद में चारों तरफ से सड़कों का जाल बिछाया गया है। इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री/ लोक निर्माण मंत्री मा0 केशव प्रसाद मौर्या जी को बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह से हमारी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में हाई-वे, टू-लेन, फोर-लेन बनाकर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का कार्य किया है। आज गोण्डा जनपद फोर-लेन से जुड़ा है। गोण्डा मुख्यालय से हमारा गौरा विधान सभा क्षेत्र 70-80 किमी0 की दूरी पर है। मा0 मौर्या जी ने वहाँ पर टू-लेन सड़क देने का काम किया है। उसी के साथ हमारी विधान सभाओं को डुमरियागंज से लेकर गौरा चौकी होते हुए कटरा-अयोध्या तक सड़कों से जोड़ने का कार्य किया है।

महोदय, हम किसानों की बात करते हैं। हमारी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दो गुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 मे "आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना" संचालित की है। इसके लिए सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, "मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" के अन्तर्गत छः सौ करोड़ रुपये की बजट की व्यवस्था की है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए इस बजट में सात सौ करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। उसी तरह से रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण/अनुदान उपलब्ध कराने के लिए चार सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान" के अन्तर्गत इस बजट में 15000 सोलर पम्प की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अधिष्ठाता महोदय, महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने "मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना" लागू किया है, इसके लिए 12000 करोड़ रुपये की बजट की व्यवस्था है। महिलाओं और बच्चों के कुपोषण निदान के लिए "मुख्य मंत्री सक्षम सुपोषण योजना" को लागू किया है, इसके लिए सौ करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की है।

श्री अधिष्ठाता-

वर्मा जी, संक्षेप कर दीजिये।

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, युवाओं के लिए जहाँ "मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना" के अन्तर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। "गुरुकल पद्धति" से संस्कृत विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क भोजन आदि की व्यवस्था देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

वर्मा जी, संक्षेप कर दीजिये।

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

महोदय, हमारी सरकार "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत 15 हजार करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने "आरोग्य पेयजल योजना" हेतु 22 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में सरकार के इस चार साल के कार्यकाल में बहुत काम हुए हैं। अभी कांग्रेस के नेता किसानों के गन्ना भुगतान की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में दो-दो चीनी मिलें बभनान चीनी मिल और मनिकापुर चीनी मिल है। जहाँ 3 फरवरी तक किसानों का भुगतान इस साल का हो गया है। 68 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। हमारे सहकारिता मंत्री जी बैठे हैं मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ विपक्षी लोगों के कार्यकाल में सहकारी समितियाँ बन्द पड़ी थीं आज उन सारी समितियों पर यूरिया, डी0ए0पी0, कीटनाशक दवाओं की पूरी व्यवस्था है और इन समितियों से किसानों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

माननीय समाज कल्याण मंत्री जी बैठे हैं, सामूहिक विवाह योजना के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, गरीबों की बच्चियों को शादी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गयी है और इस योजना के तहत उन गरीब बच्चियों की शादी हो रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र की दो-तीन माँगें हैं। आपके माध्यम से उसको भी बता देना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। कूकनगर ग्रन्ट में राजकीय डिग्री कॉलेज की माँग करता हूँ। माननीय खेल मंत्री जी बैठे हैं, खेलो इण्डिया खेलो के तहत एक स्टेडियम बनाये जाने की माँग करता हूँ। माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में मेरे यहाँ बहुत काम हुआ है। दो-तीन विद्युत सब-स्टेशन बनने हैं तो इनका काम जल्दी शुरू हो जाये, ताकि जल्दी से जल्दी 2022 में पूरा हो जाये। अन्त में माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस बजट के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्रीमती संगीता यादव-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ व धन्यवाद देती हूँ। इस सदन में उपस्थित सभी मा0 मंत्रिगण और माननीय सदस्य को संगीता यादव का सादर प्रणाम। मैं चौरी-चौरा से विधायक हूँ। इस समय चौरी-चौरा को माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में एक अलग मुकाम दिया जा रहा है, तो सबसे पहले चौरी-चौरा से ही शुरू करना चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष जी, 4 फरवरी, 2021 को चौरी-चौरा घटना का शताब्दी वर्ष हो रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की संवेदनशीलता को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि चौरी-चौरा के कार्यक्रम को दो दिन में खत्म किया जा सकता था, लेकिन यह माननीय मुख्य मंत्री जी की संवेदनशीलता है, उनका राष्ट्र प्रेम और शहीदों के प्रति तड़प हैं जो उन्होंने दिखाया। इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है और माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज पूरे वर्ष कार्यक्रम केवल प्रदेश में ही नहीं माननीय मोदी जी ने इसे पूरे देश में संचालित कर दिया है। मैं यहाँ बैठे हुए माननीय सदस्यों को भी

धन्यवाद देना चाहूँगी कि चौरी-चौरा महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप सभी ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह नहीं कहती कि इसके पहले प्रदेश में मुख्य मंत्री नहीं रहे, मुख्य मंत्री तो रहे क्योंकि कभी प्रदेश खाली नहीं रहा, लेकिन शहीद स्मारक का वो हाल था कि वह जुए का अड्डा था। लेकिन जब मा0 योगी आदित्यनाथ जी 2017 में प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं आज वह पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होते जा रहे हैं, मैं इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।) चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष चलेगा, के लिए इस बजट में 15 करोड़ रुपये की राशि भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपलब्ध करायी है, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगी। चौरी-चौरा एक क्रांतिकारी धरती है, लेकिन उसको वह मुकाम नहीं मिला जो माननीय मुख्य मंत्री जी के सहयोग से मिला है। मै श्रद्धेय अटल जी की दो लाइनें कहना चाहूँगी। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। यह मैं आपनी क्रांतिकारी धरती चौरी-चौरा के लिए बोलना चाहूँगी।

"भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। यह वन्दन की धरती है, यह अभिनन्दन की धरती है। यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका नदी-नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़-कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जियेंगे तो इस भारत के लिये, मरेंगे तो इस भारत के लिए और हमारे मरने के बाद जब हमारी अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित होंगी और कोई ध्यान से उन्हें सुनना चाहेगा तो उसमें से एक ही आवाज सुनाई देगी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।" अगर इस लाइन को किसी ने चरितार्थ किया है, क्रांतिकारी धरती चौरी-चौरा के लिए तो वह मेरे अभिभावक भी हैं, मैं उस जिले की विधायक भी हूँ। माननीय योगी जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से मैं उनको बहुत-बहुत धन्याद देना चाहूँगी। अभी चर्चा में कोरोनाकाल पर तो बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नही कहूँगी। मैं अपने कुछ अनुभव बताना चाहूँगी कोरोनाकाल के। पिछले साल यही मार्च का महीना था जब लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन का एक हफ्ता तो ठीक से बीता, लेकिन उसके बाद से जगह-जगह से हमारे माननीय विधायकगण यहाँ बैठे हैं, सभी के पास अलग-अलग राज्यों से हमारे श्रमिक भाइयों ने फोन करना शुरू कर दिया। कहीं भोजन की समस्या थी, कहीं और समस्या थी, लेकिन उसके लिए इतनी तत्परता हमारी प्रदेश सरकार ने दिखाई। कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिसका वैश्विक स्तर पर भी कोई अनुभव नहीं था, देश स्तर पर भी कोई अनुभव नहीं था, जो संवदेनशीलता सबने दिखाई उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और उस धन्यवाद के लिए जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनको भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करूँगी। उन कोरोना योद्धाओं के लिए मै देख रही थी कि जगह-जगह हमारे माननीय विधायकगण ने उनको सम्मानित किया। हमने भी अपने विधान सभा क्षेत्र में सम्मानित किया। कई लोगों ने मुझे भी फोन किया माननीय अध्यक्ष जी और जब यह फोन कॉल मैं लखनऊ में कर रही थी, जो 11 लोगों की टीम बनी थी, मैंने देखा कि उन लोगों ने कॉल सेन्टर बना दिया था और तुरन्त 24 घण्टे के अन्दर वहाँ राशन और सब चीज उपलब्ध हो जा रही थी।

माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूँगी कि श्रम विभाग में पंजीकृत 20 लाख श्रमिकों को एक-एक हजार रुपये की भरण-पोषण सहायत दी गई। शहर में स्ट्रीट वेन्डर्स और ठेला, खोमचा, साप्ताहिक कार्य के दिहाड़ी मजदूर का भी हम लोगों ने डाटा बेस तैयार किया था और उनको भी धनराशि उपलब्ध करवाई गई। जो हमारी गरीब जनता थी उनको कहीं भूखों न मरना पड़े उसके लिये मैंने देखा कि महीने में दो-दो बार राशन प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से यहाँ सभी सम्मानित विधायकगण बैठे हैं और सभी ने बाँटा है अपने यहाँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना बताना चाहूंगी कि जब यह जो श्रमिक हमारे वापस गये अपने क्षेत्रों में, कहीं उनको और संकट न हो, मनरेगा में एक बड़ी धनराशि माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई और श्रमिक दिवसों का, मानव दिवसों का वहाँ पर सृजन किया गया। 40 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जनपद भेजा गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये जो हमारे बच्चे, चाहे प्रयागराज, चाहे कोटा में थे उनको भी उनके घर पहुंचाया गया। अभी मैं कई बार से सुन रही थी जबसे कोरोना का वैक्सीन आया है। एक लाइन सुन रही थी कि मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे हैं। छोटे-मोटे कार्यक्रम को भी आप लोग इवेन्ट बनाते हैं पर इसको नहीं। परसों मोदी जी ने उनका भी जवाब दे दिया है। मोदी जी ने खुद वैक्सीन लगवाई और यह भी बताया कि हमने पहले अपने कोरोना वॉरियर्स को लगवाया उसके बाद जब बुर्जुगों की बारी आई तो सबसे पहले माननीय मोदी जी ने लगवाया (मेजों की थपथपाहट) यह जवाब जो सबको मिला है, उसके लिये भी मैं आभार प्रकट करूंगी।

मान्यवर, चूँकि मैं महिला विधायक हूँ, महिलाओं के लिये बोले बिना मेरा बैठना उचित नहीं रहेगा। मैं ज्यादा नहीं क्योंकि मुझे टाइम लिमिट पता है, लेकिन महिला विधायक होने के नाते मैंने महसूस किया है। अभी जो हमारी महिला विधायक जी ने कहा है। महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में मैं भी हमेशा रहती हूँ। मैं चाहूंगी कि हम सब महिलाओं की तरफ से महिला आरक्षण जो 33 प्रतिशत का है, उसकी माँग रखी जाय और इसको मेरी भी मांग मानी जाय। मैं अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और तत्परता जो दिखाई जा रही है। मैं अपनी बहिन से तो सहमत नहीं हूँ जो उन्होंने आँकड़े प्रस्तुत किये। मैं उसी के सन्दर्भ में कहना चाहूँगी कि अभी हम लोगों ने देखा कि मिशन शक्ति के रूप में माननीय मुख्य मंत्री योगी जी ने 1 नवम्बर, 2020 को कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को यहाँ सभी माननीय विधायकगण बैठे हैं, हर स्तर पर स्कूल पर, ब्लाक पर हर स्तर पर किया जा रहा है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे सामाजिक दायित्व निभाने वाली समाजसेवी संस्थाएं हैं वह भी बहुत तेजी से इसमें भाग ले रही हैं। मैंने खुद अपने विधान सभा क्षेत्र में इस मिशन शक्ति को स्वच्छता अभियान से जोड़कर एक कार्यक्रम सभी स्कूलों में शुरू किया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने खुद अपनी विधान सभा क्षेत्र में मिशन शक्ति को स्वच्छता अभियान से जोड़कर कार्यक्रम सभी स्कूलों में शुरू किया है। हर बालिका को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ सशक्त बनाया जा रहा है। महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। मैं उस रोजगार के बारे में ज्यादा नहीं जो मेरी विधान सभा क्षेत्र में हुआ है, उसके बारे में बता

रही हूँ। खादी ग्रामोद्योग में इतनी अच्छी योजनाएं जो चल रही हैं, महिलाओं को उसमें लोन दिया जा रहा है, उस लोन में 35 प्रतिशत की छूट दी जा रही है और बड़ी संख्या में महिलायें इसको ले रही हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र में काफी महिलाओं ने लिया भी है। अभी जो पुष्टाहार कार्यक्रम था, उसमें भी स्व-सहायता समूह के माध्यम से आंगनबाड़ी में महिलाओं के द्वारा ट्रेंड किया जा रहा है। इससे डबल काम हो गया है, एक तो महिलाओं को रोजगार भी मिला है और जो इससे पहले पुष्टाहार मे बन्दरबांट चलती थी, उसको भी समाप्त करने का काम हुआ है। मैं आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के बारे में बताना चाहूंगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप संक्षेप कर दीजिए।

श्रीमती संगीता यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में पहले हम लोगों को बहुत कम लड़किया मिल पाती थी, अब तो इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां आ रही हैं कि उनसे कहना पड़ता है आपका अगली बार में रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री को, आपने माननीय मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्रीमती संगीता यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, युवाओं के लिए मैं केवल दो लाइन बोलना चाहूंगी, चूंकि हमारे बहुत सारे मा0 सदस्य इससे सहमत भी थे। हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने दो लाइन बहुत अच्छी बोली थी। "जो होता है वह होने दो, यह फोरनशील कथन है। हम जो चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में ही जीवन है।" यह हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था और मैं इस बात से अपने आपको जोड़ती हूँ। मै इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना हो, कैरियर काउंसलिंग योजना हो, नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट हो, उत्तर प्रदेश कौशल विकास हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास हो, रोजगार मेला हो, स्टार्टअप हो इन सबके माध्यम से जो हमारा विपक्ष हमेशा कटाक्ष करता है कि आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, यह उसका जवाब है। आपने मुझे सदन में बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2021-22 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही अपनी बात शुरू करने से पहले मा0 नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी जो संशोधन का प्रस्ताव लाए हैं, उस पर मैं बल देता हूँ। 2021-22 का जो बजट है, वह पेपरलेस बजट है। यह पेपरलेस बजट नहीं, बल्कि फीलिंग लेस बजट है। इसमें नौजवानों के अहसास को नहीं समझा गया, किसानों

के दर्द को नहीं समझा गया। उत्तर प्रदेश में जो गरीब आदमी है, वह महंगाई की मार झेल रहा है, उसके अहसास को नहीं समझा गया। यह बजट सिर्फ किताबी रह गया है। जबसे यह सरकार बनी है, लगातार यह किताबों में सिर्फ बजट को बढ़ाते जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि जो बजट पेश होता है, जो पैसा खर्च करना चाहिए, वह पूरा पैसा यह खर्च नहीं कर पाते हैं। जहां तक आदरणीय नेता सदन कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की इकोनामी को एक ट्रिलियन इकोनामी बनायेंगे। आप बतायें कि जब हमारे बजट में जो हमारी जी0डी0पी0 है, वह 21 लाख करोड़ है तो आप कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जिस लक्ष्य की आप बात करते हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि आज इस बजट से नौजवानों को जो उम्मीद थी, प्रदेश के किसानों को जो उम्मीद थी, वह उम्मीद टूटी हुई है। "तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़े झूठे हैं, यह दावा किताबी है"। आज प्रदेश के नौजवान को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब इस सरकार को नौजवानों ने वोट देकर बनाया था तो उनसे यह कहा गया था कि सरकार बनते ही आपको नौकरी दी जायेगी। सरकार बनते ही आपको 90 दिन के भीतर जितने भी सरकारी पद हैं, उनको भर दिया जायेगा। इनके संकल्प-पत्र में लिखा हुआ है कि हम नौजवानों को 70 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अभी हमारे श्रम मंत्री ने दो दिन पहले इसी सदन में बयान दिया कि अब तक 4 साल होने जा रहा है, 30 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार दे पाये हैं। साथ ही इन्होंने कहा था कि हम गरीब नौजवानों को बिना जाति, धर्म के भेदभाव से लैपटाप देने का काम करेंगे, जिससे वह अच्छी पढ़ाई कर सकें, उनको फ्री नेट देने का काम करेंगे, लेकिन आज यह किताबों में रह गया है, उन नौजवानों को सिर्फ मायूसी मिली है।

कोरोनाकाल में जो हमारे नौजवान बाहर कहीं स्किल लेबर थे उनको वहाँ नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आज वह बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं उनको मनरेगा में काम करने को कहा जा रहा है, इस उम्मीद से माँ-बाप अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलाते हैं। इंजीनियर बनाते हैं उनको एम0बी0ए0 कराते हैं तो वह उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा अडानी और अम्बानी के बच्चों की तरह टाई और सूट पहनकर नौकरी करेगा, लेकिन अफसोस कि सरकार उनको मनरेगा में मिट्टी ढुलाने के कार्य को ही काम बताती है। कितनी शर्म की बात है। हुकूमत में माल की हेरा-फेरी इस कदर की बनाई जो इमारत हमने उसको दर-बदर की है। तमाशा कर दिया है तुमने वतन के जवानों का जो जीते थे खुशी से आज वह बर्बाद बैठे हैं। बजट बढ़ाने का मकसद यह नहीं होता कि हम अपनी जनता की सेहत से खिलवाड़ करें बजट में इनकम बढ़ाने के लिए, शराब नीति में इतने कानून बना रहे इस तरह से कि शराब को फ्री कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पिएं और आपकी इनकम बढ़े। आज आपके पास इतनी मेडिकल फैसिल्टीज नहीं हैं आज लिवर से, किडनी फेल्योर से मौतें हो रही हैं अभी बनारस में कल ही कच्ची शराब से चार लोगों की मौत हो गयी आप किस चीज को बढ़ावा देते हैं कहीं आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश में हम गुजरात मॉडल बनाएंगे, यही गुजरात मॉडल है कि शराब आप खुलेआम बिकवाना चाहते हैं शराब से आप इनकम पैदा करना चाहते हैं आपको तो चाहिए कि इनकम के स्रोत कहीं और से जनरेट करें जिससे हमारे प्रदेश का नौजवान, हमारे प्रदेश का गरीब उस बीमारी से बच सके, जिस बीमारी की लत आप लगाना चाहते हैं।

मान्यवर साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि आप तो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन आप कहाँ सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। आप बताएं आप किताबों में बजट अल्पसंख्यक समुदाय को दे देते हैं, लेकिन सच्चाई हकीकत आपने जमीन पर उतर कर देखी है। उनके नौजवानों को वजीफे मिल रहे हैं कि नहीं, राजा के दरबार में सभी प्रजा बराबर होती है वही रामराज कहलाएगा। जब उसे राम के राज में सभी धर्म-जातियों के बच्चों को एक समान देख कर इन्साफ की बात कही जाए। अगर आप इन्साफ पसन्द हैं, तो आप इन्साफ करिए, लेकिन आपकी इन्साफ की तराजू में कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कि किसी एक बड़े समुदाय के साथ आप ज्यादती करते हैं, नजरन्दाज करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए आप राजा हैं आप सबके लिए बराबर हैं लेकिन आज अल्पसंख्यक समुदाय अपने आपको एहसासे कमतरी का शिकार समझ रहा है, आज उसको लगता है कि इस प्रदेश के अन्दर उसकी बात सुनी नहीं जाती है, इससे आप रामराज कायम नहीं कर सकते। आप क्यों ऐसा करते हैं जिससे लोगों को दुख पहुँचे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।

मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ सुबह हमारे मंत्री जी यहाँ पर बोल रहे थे, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ पिछड़ा इलाका है, बाढ़ ग्रस्त इलाका है हर साल बाढ़ से तबाही मचती है हमारे मंत्री जी कह रहे थे डा0 महेन्द्र सिंह जी कि हमारे पास कोई कमी नहीं है सब कुछ हमने ले लिया हमारे यहाँ उन्हीं के विभाग से एक पुल अधूरा था चिकनवा डाला देवारा क्षेत्र का वहाँ से लिखकर आता है कि आम-जन मानस को दिक्कत हो रही है, लेकिन साथ ही यह भी लिखा जा रहा है कि बजट के अभाव में वह बनाया नहीं जा सकता। आप एक तरफ कहते हैं कि गरीबों के लिए खजाना खुला हुआ है दूसरी तरफ एक गरीब किसान वहाँ से डिमाण्ड करता है तो आप बनाते नहीं हैं। हमारा क्षेत्र एक ग्रामीण अंचल है जहाँ पर सड़क के लिए मैं बराबर लिखता रहता हूँ, लिखकर आता है कि वहाँ जरूरत नहीं है तीन कि0मी0 का रास्ता गौरिया बाजार से इस्माइलपुर जहाँ पर हजारों की तादात में लोग रहते हैं गरीब मांएं रहती हैं रात में उनको कहीं जाना होता है तो सड़कें नहीं हैं, लेकिन उसको बनाने का काम नहीं हो रहा। मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वह बाढ़ग्रस्त इलाका होने के नाते हर साल बाढ़ में इलाज के अभाव में पचास से लेकर 100 तक जानें जहरीले जानवर, साँप के काटने से मौतें हो जाती हैं मैं बार-बार यहाँ डिमाण्ड करता हूँ कि वहाँ पर 100 बेड का सुपर हास्पिटल बनाया जाए, जिससे हमारे वह किसान जो खेती के दौरान उसके शिकार होते हैं उनको सही इलाज मिल सके।

मान्यवर, साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में कन्धरापुर-जोलहापुर सड़क पूरी तरह से खत्म हो गयी है, उसको बना दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अधिष्ठाता जी, मेरे बस दो-चार प्वाइंट और हैं। कन्धरापुर से सीयरहा होते हुए गुलवर तक का रास्ता, नसीरपुर से छीही होते हुए फुलवरिया तक का रास्ता, सरदहा बाजार से

भीमबर को जाने वाली सड़क, सेहदा जंगल से आजमपुर तक का रास्ता, सरदहा से भीमबर होते हुए रुद्रपुर, चिकनहवा ढाला से कुड़ही ढाले तक की सड़क का जो अप्रोच है उसको बनाने का काम किया जाये। परशुरामपुर से कुड़ही ढाले तक की सड़क, महराजगंज से सहदेवगंज तक की सड़क यह तमाम ऐसे रास्ते हैं जहाँ से किसान अपने खेतों की उपज लेकर मार्केट में जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद। अब आप समाप्त करें।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं फिर से एक बार इस शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा-

हुजूम देखकर रास्ते नहीं बदलते हम,
किसी के डर से तकाजे नहीं बदलते हम,
हजार जेरा कदम रास्ता हो काँटों का,
जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम।

मान्यवर, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर से मा0 नेता प्रतिपक्ष की बातों से अपनी बात को जोड़ते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद। फतेह बहादुर सिंह जी।

श्री फतेह बहादुर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से मा0 वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट के पक्ष में अपनी बात को रखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का अभी तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री परम् पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एवं वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो यह लोक कल्याणकारी प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से प्रदेश के किसानों के हित में और उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके हित में यह बजट लाया गया है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम जन्म भूमि पर मन्दिर धाम के निर्माण के लिये जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, खासतौर से ब्रह्मलीन महन्त अवैद्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह, स्वर्गीय अशोक सिंहल जी एवं ब्रह्मलीन नाना साहब आदि महापुरुषों ने जो योगदान दिया उसको भुलाया नहीं जा सकता। कोविड-19 के प्रबन्धन में हम सब जानते हैं कि टीम-11 का गठन करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने रात-दिन एक करके 11 सदस्यों की टीम बना करके उसका परीक्षण करके और स्वयं बैठक में उपस्थित रह करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कोविड-19 के प्रबन्धन का कार्य किया, जिस कारण डब्ल्यू0एच0ओ0 ने भी उत्तर प्रदेश

राज्य की सराहना की है, इसके लिये मैं इस सदन के माध्यम से आदरणीय परम् पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बधाई देना चाहता हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व में कोविड-19 का प्रबन्धन हो सका। आज हम कोरोना वैक्सीन की तरफ बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन् पूरा देश बढ़ रहा है और निश्चित रूप से मैं कोरोना वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों के प्रति भी आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, निश्चित रूप से उनका भी योगदान सराहनीय रहा है।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश की बन्द चीनी मिलें जो मरणासन्न स्थिति में थीं, मैं गन्ना मंत्री रहा तो मेरे जनपद में पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में मैंने चीनी मिल को चलाने का प्रयास भी किया और मैंने एक बार उसको चलवाया भी, लेकिन उसकी क्षमता कमजोर होने के नाते हम उसको चला नहीं पाये, संचालित नहीं कर पाये, चूंकि रिकवरी रेट कम था और निश्चित रूप से उस मिल की वॉयबिलिटी नहीं बन पा रही थी, इसलिये उस समय हमारे सामने एक समस्या थी। हमने और हमारे साथी विधायक महेन्द्र पाल सिंह ने जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से उस पर चर्चा की तो इतने बड़े पैमाने पर उस नई चीनी मिल जोकि सल्फरलेस चीनी मिल है, को बना करके पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक बड़ा उद्योग देने का काम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने और मा0 गन्ना मंत्री जी ने किया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, हम सब जानते हैं कि वन विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में दो चिड़ियाघर हैं एक लखनऊ में और दूसरा कानपुर में। लेकिन जब मैं वन मंत्री था तो मैंने गोरखपुर चिड़ियाघर का शिलान्यास किया था और उसके बाद मैंने देखा कि उस पर पिछली सरकारों ने कोई भी कार्य नहीं किया है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से मिलने गया और उनसे निवेदन किया कि मा0 मुख्य मंत्री जी मैंने चिड़ियाघर का शिलान्यास कर कार्य प्रारम्भ कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की जो सेन्ट्रल इम्पॉवर्ड कमेटी है उसने अनुमोदन दे दिया और सेन्ट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इण्डिया ने भी अनुमोदन दे दिया है कि चिड़ियाघर खोल दिया जाय। मान्यवर, मैं पुनः मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ही दिन में जितनी भी धनराशि की आवश्यकता थी, पिछले बजट में प्राविधानित करके चिड़ियाघर को बनाने का काम किया है और बहुत ही जल्द मुख्य मंत्री जी उद्घाटन भी करने जा रहे हैं।

मैं अपने विपक्ष के साथियों को सुन रहा था ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, यह कानून व्यवस्था पर क्या चर्चा करेंगे ? जब पी0सी0एस0 स्तर के अधिकारी सी0ओ0 हजरतगंज को समाजवादी पार्टी के लोगों ने गाड़ी के बोनट पर लाद कर गोमती नगर तक उठा कर ले गये थे वह लॉ एण्ड ऑर्डर का जमाना भी मैंने देखा है। पिछली सरकार के समय की मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं हजरतगंज में टहलता था तो एक समुदाय के लोग पिस्टल लगा करके खुलेआम मोटर साइकिल पर घूमते थे और कोई माई का लाल उन्हें छू नहीं सकता था। मैंने उस समय को भी देखा है। इनकी सरकार के समय में रोज सिपाही और दरोगा पीटे जाते थे, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन कोई सिपाही या दरोगा पिट करके अपने धाने या कप्तान को रिपोर्ट करने न जाता हो। इस सदन को मैं 27 साल से देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि कौन कितने पानी में है। मुझे बताने और सुनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मा0 योगी जी का त्याग है, वह मात्र चार घन्टे सोते हैं, इस प्रदेश को यदि कोई अपना सारा कीमती समय देता है तो वह उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी देते हैं। मैं जानता हूँ कि वह कितना त्याग और तपस्या कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

महोदय, जहां तक उद्योगों की बात है अभी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी उत्तर प्रदेश आए थे और विश्व के तमाम देशों के लोग भी आए थे, एम0ओ0यू0 साइन हुए तमाम उद्योगों की स्थापना की बात हुई यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के माध्यम से उसमें तमाम उद्योग आ रहे हैं, हमारी जो अन्य संस्थायें उद्योग गीडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा डीडा, मोडा और उद्योग के क्षेत्र में सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हमारा बन रहा है उसके किनारे उद्योग गलियारा बनाने की जो योजना परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने दी है उससे आने वाले समय में प्रदेश ही नहीं देश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने जा रहा है और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ। महोदय, रोजगार की बात कही गयी है, मैं जानता हूँ कि पहले जमाने में पुलिस भर्ती कैसे होती थी और उस भर्ती में सूची कहां से जाती थी ? हम लोग सब जानते हैं, कहां के लोग भरे जाते थे, कौन लोग भरे जाते थे और किस वर्ग के लोग भरे जाते थे यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब प्रदेश की जनता जानती है कि कैसे लोगों को नौकरी मिलती थी, कहाँ से सूची जाती थी किस चेयरमैन और किस आयोग में, किस निगम में यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आज बजट पर चर्चा हो रही है इसलिए मैं उसी पर सीमित रहना चाहता हूँ। महोदय प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी थी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

काशी विश्वनाथ मन्दिर, अगर यही किसी साउथ के क्षेत्र में होता, किसी साउथ इण्डियन बेल्ट में होता तो उसका विकास किस तरह का हुआ होता। आज देश के प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री जी की देन है जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम को श्रेष्ठ धाम बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। माता विंध्याचल स्थान का भी विकास बड़ी तेजी से होने जा रहा है। शाकुम्भरी देवी जो सहारनपुर में हैं माता शाकुम्भरी देवी जिनका दुर्गा सप्तशती में वर्णन है हम सब पढ़े हैं जानते हैं कि उनका जो प्रताप है उनका जो आशीर्वाद है निश्चित रूप से वहां का भी विकास होने जा रहा है। हम नैमिषारण्य को भूल गये थे, नैमिषारण्य का चौमुखी विकास होने जा रहा है। जब मैं वहाँ पर परिक्रमा करने जाता था तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, मथुरा वृन्दावन का जो स्वरूप बदला है, बरसाने का जो स्वरूप बदला है यह कोई मामूली परिवर्तन नहीं है यह परिवर्तन योगी जी और मोदी जी की देन है, मैं यह कहना चाहता हूँ सदन के माध्यम से माननीय अधिष्ठाता महोदय उत्तर प्रदेश में एक वातावरण बन गया है। जनता समझ गयी है अब आप लोग भी समझ लो जो इधर लोग बैठे हैं, ये परमानेन्ट अब बैठेंगे। उधर वाले अब अपनी गिनती देखें कितनी संख्या में बचकर आओगे 22 के बाद यह तो आप समझे, लेकिन जनता अब समझ चुकी है जनता को समझाने की जरूरत नहीं है।

मान्यवर, वन विभाग में चूंकि मैं वन मंत्री रहा हूँ अभी पिछली 5 जुलाई, 2020 तारीख को एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौधों का रोपण हुआ 23 करोड़ कुछ का बड़े पैमाने

पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में उसका नाम भी दर्ज हो चुका है और जहां तक क्षमता है लगभग 90 प्रतिशत जीवित पौधे आज भी पाये गये हैं और चर्चा के दौरान जब आप लोग चाहेंगे तो वन मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, लेकिन जो मुझे जानकारी विभाग द्वारा दी गयी वह यही दी गयी कि 90 प्रतिशत पौधे उसमें से जीवित हैं जो वन विभाग द्वारा रोपित किये गये। इसके साथ-साथ जो हम लोगों ने सड़क के किनारे वृक्षारोपण का अभियान चलाया था। सड़क के किनारे वृक्षारोपण में कैम्प के माध्यम से इस वर्तमान बजट में 600 करोड़ रुपये वृक्षारोपण में बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिससे यहाँ का वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर बढ़ सके। यह पहले कभी नहीं हुआ। माननीय अधिष्ठाता महोदय वन विभाग में यह 600 करोड़ अतिरिक्त कैम्प के माध्यम से आया है और 400 करोड़ रुपये वन विभाग को वृक्षारोपण के लिए अलग से दिया गया है। लगभग 1000 करोड़ रूपयों की व्यवस्था वनों और वृक्षों के रख-रखाव के लिए किया गया है। मैं इसके लिए भी अपने वन मंत्री जी के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सड़कों के मामले में माननीय अधिष्ठाता महोदय नेशनल हाई-वे के माध्यम से हम लोगों के क्षेत्र जुड़ चुके हैं मेरी विधान सभा क्षेत्र का जो पहला ग्राम सभा पड़ता है वह गांव नेशनल हाई-वे पर आ गया है और नेपाल बार्डर तक सीमायें उसको टच कर रही हैं। हमारे क्षेत्र से नेपाल सीमा लगभग लगी हुई है। तमाम योजनायें सड़कों की हमारे आदरणीय उप मुख्य मंत्री केशव मौर्या जी ने अभी पिछले दिनों बड़े पैमाने पर सड़कों की स्वीकृति हमारे यहां दी है, मैं उनके प्रति भी आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती सरिता भदौरिया-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा लाया हुआ बजट इसके समर्थन में मुझे केवल दो-तीन बातें कहनी हैं जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया वह निश्चित ही उत्तर प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए गरीब और नौजवानों के कल्याण के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी के द्वारा यह बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है। माननीय अधिष्ठाता जी मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में 600 करोड़ रुपये का प्राविधान, आवास योजना में 700 करोड़ रुपये का प्राविधान, आरोग्य योजना में 100 करोड़ रुपये का प्राविधान, किसानों के खाते में सीधे 6000 करोड़ रुपये भेजने का निर्णय, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इन सबसे किसको लाभ होगा। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि इससे पहले किसके आवास बने थे, किसका इलाज होता था। माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूँ कि पिछली सरकारों की एक बार जांच कराई जाये और यह तय किया जाये कि उत्तर प्रदेश के किसानों की जमीनों पर सर्वाधिक कब्जा करवाने वाली कौन सी सरकार थी। कौन सी ऐसी सरकार थी जिसने उत्तर प्रदेश के किसानों की सर्वाधिक खेती पर, उनके प्लाट पर, उनके घर पर, उनके मकान पर कब्जा कराने का काम किया था। यह लोग भट्टा परसौल की घटना भूल गये हैं। वहाँ के हमारे विधायक बैठे होंगे जेवर की घटना स्मरण नहीं है। मुझे तो लगता है कि यह सारी बातें हमारे विपक्ष के लोगों के मुंह में कतई शोभा नहीं देती है। जब भट्टा परसौल और जेवर के किसानों के साथ पूर्ववर्ती सरकारों मे अत्याचार किया था तो

आदरणीय कलराज जी, शाही जी और प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं भी उस टीम में उन किसानों के बीच में गई थी और उनकी पीड़ा आज तक किसी को दिखाई नहीं दी, सुनाई नहीं दी, स्मरण में नहीं है तो मैं हरिवंश राय बच्चन जी की केवल एक लाइन आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसान यह कह रहे हैं कि हम जान गये हैं और पहचान गये हैं तुम्हारे मन में क्या है और तुम्हारे मुंह में क्या है यह हम ठीक से जानने का काम करते हैं।

जब आपकी सरकारें बनती हैं तो आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। पत्रकारों की बात अभी हमारे नेता विपक्ष ने बहुत जोरदार तरीके से कही थी। निश्चित ही पत्रकार समाज का चौथा स्तम्भ है। पत्रकारों की पीड़ा हम सबको समझनी चाहिये, लेकिन जब अपना समय आये तो प्रयागराज में हाई कोर्ट के सामने पत्रकारों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा जाये। पत्रकारों पर उत्तर प्रदेश में हल्ला बोल किया जाये, इटावा में समाचार-पत्रों की प्रतियां जलाई जायें, पत्रकारों को घरों से उठाकर प्रताड़ित किया जाये और जब हमारा समय आये तो "पर उपदेश कुशल बहुतेरे।" निश्चित ही हमारे सामने हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता बैठे हैं और मैं घण्टों सदन में केवल उनको सुनने के लिए बैठा करती हूँ। उन्होंने अपने वक्तव्य में उस दिन कहा था कि मैं कोविड के समय मुख्य मंत्री को पत्र लिख रहा था, रक्षा मंत्री को पत्र लिख रहा था, स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख रहा था, उन्होंने यह भी देखा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की गोद मे किस तरह से बच्चों ने दम तोड़ दिया। निश्चित ही घर पर बैठकर पत्र लिखते समय उनको दिखाई दिया होगा और उन्होंने देख लिया होगा, लेकिन मैं एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि जिस ग्यारह सदस्यीय कोविड टीम का जिक्र हमारे पूर्व वक्ता कर रहे थे। प्रतिदिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री उस टीम के साथ बैठक किया करते थे और केवल बैठक ही नहीं करते थे। मैंने तो दूरदर्शन पर यह भी देखा कि उत्तराखण्ड में उनके पिता की चिता जल रही थी और उत्तर प्रदेश के योगी जनता की चिंता करने के लिए बैठक में खड़े थे। यह आपको दिखाई नहीं दिया और आपको दिखाई भी कैसे देता। यह हम सब लोगों को दिखाई दिया, क्योंकि आप सदन में शल्य की भूमिका का निर्वहन करते हैं। शल्य की भूमिका जो लगातार दुर्योधन के मनोबल को गिराने का काम करती थी और हम सब लोग अर्जुन के रथ के सारथी श्रीकृष्ण की भांति आदरणीय मुख्य मंत्री जी के मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा एक-एक विधायक और अमारा एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार उत्तर प्रदेश में कोविड से ग्रसित लोगों की चिंता करने का काम कर रहा था। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी गरीब भूख का शिकार न हो।

ऐसा न हो कि उसको कहीं कोई चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध न हो। हम लगातार चिंता करने का काम कर रहे थे और चिंता करते क्यों न ? क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता थी। जैसा राजा होता है। हमारे यहां कहा गया है कि "यथा राजा तथा प्रजा"। शुरू में हमें लगा शायद कोविड कोई भयंकर समस्या है। हमको भी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जब हमने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री नोएडा में मीटिंग कर रहे हैं, पश्चिम में मीटिंग कर रहे हैं, लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं। वह लगातार चिंता करने का काम कर रहे हैं तो अपने राजा के कार्यों का अनुसरण करना हमारा धर्म था और हमारी आत्मा ने भी आवाज दी की हम

बाहर निकलेंगे और कृष्ण-अर्जुन के रथ के सार्थी की तरह कृष्ण बनकर अपने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे और बढ़ाया भी (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

आप उत्तर प्रदेश में महिलाओं की चिंता कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की चिंता आपके मुख से मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने इटावा और मैनपुरी में वह दृश्य देखा है जहां पर दो-दो, तीन-तीन, चार-चार बेटियां ऐसे गायब हो जाती थीं और आज तक उनका पता नहीं है कि वह कहाँ गयी हैं ? सरकार तब भी थी। सरकार के लोग तब भी थे और आज आप महिलाओं की चिंता की बात कर रहे हैं। मैं आपको गांव के नाम सहित बताना चाहती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि उनका संदेश यह है कि "कह दो जाकर उन मौत के सौदागरों से कि हम तुम्हारी कोई चाल चलने नहीं देगें और हमारा ही खून तुमने दिया बनाकर जलाया था, लेकिन अब हम तुम्हारी कोई मशाल जलने नहीं देंगे।" उत्तर प्रदेश की महिलाओं का यह संदेश है (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों को थपथपाहट) हम लगातार अपनी मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए जनता को यह विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं कि जनता के उत्थान के लिए काम करेंगे और हमें अगर कोई टिप्पणी पीड़ा देती है तो हमें भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी की वह लाइनें याद आती हैं कि "बाधाएं आती हैं तो आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, सर पर भी बरसे ज्वालाएं, कदमों के नीचे अंगारे, लेकिन हम सबको कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।" हम कदम मिलाकर चलेंगे। अपने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन्हें पुनः वर्ष 2022 के चुनाव में बड़े बहुमत के साथ इधर बैठाने का काम करेंगे। मैं केवल आपको इतना ही कहना चाहती हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिए।

श्रीमती सरिता भदौरिया-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ठीक से समझ गयी है। अब आपकी किसी भी बात को सोचने और समझने की शक्ति नहीं है। कोविड में जो अव्यवस्था हुई है उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो वह आपको जाता है, क्योंकि आपकी सरकार ने कभी कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने तेरह मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने की बात की है और मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम सब उनके साथ हैं। वह आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए काम करें। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

सुहेलदेव पार्टी, कैलाश नाथ सोनकर।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

चले गये।

श्री अधिष्ठाता-

अमिताभ बाजपेई।

श्री अमिताभ बाजपेई-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट भाषण पर अपने विचार रखने का मौका दिया है। मैं अपने आपको नेता विरोधी दल से सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि इस बजट में नया कुछ भी नहीं। सिवाय इसके कि हर साल बजट लेस पेपर्स आते थे। इस बार बजट पेपर लेस भी है और बजट लेस भी है। यह इस अहंकारी सरकार का जो आखिरी बजट है हम लोग उम्मीद करते है) कि इसके ताबूत की यह आखिरी कील भी साबित होगा। इसको ऐसे समझें कि **"एक मां रात भर पत्थर उबालती रही, बच्चे फरेब खा कर रेत पर सोते रहे।**" यह फरेबी दस्तावेज पिछले चार सालों से मोटी-मोटी योजनाओं के नाम से भरे रहे हैं। कोई भी योजना हकीकत में जमीन पर नहीं उतरी।

सरकार जब सत्ता में आयी थी तो बड़ा डंका बज रहा था कि गड्ढामुक्त हो जायेगा सड़कें सपाट हो जायेंगी, लेकिन हकीकत यह है कि जब सत्तापक्ष के विधायक पांच मिनट में पूरी चापलूसी करने के बाद आखिरी में जब अपना दर्द बताते हैं, उस दर्द को सुन लें तो समझ में आ जायेगा कि सड़कों की हकीकत क्या है। इस सरकार के बजट को पढ़कर कभी ऐसा नहीं लगा कि यह इकोनामिक या अर्थशास्त्र का कोई डाक्यूमेंट है। इसको पढ़ने से लगता है कि यह इतिहास का कोई दस्तावेज है। इसमें इतिहास का वर्णन ज्यादा है और अर्थशास्त्र का वर्णन कम है। प्रदेश सरकार की अपनी कोई योजना भी नहीं है। यह केंद्र सरकार की योजनाओं के बोझ से दबा हुआ बजट है। **हर तरफ हरियाली है, हर तरफ खुशहाली है, बात तो बहुत अच्छी है मगर ख्याली है, ये ठाठ-बाट, ये ऐशोआराम, सब तुम्हारे लिये, जनता के हिस्से में तो बस बदहाली है। अंधकारों को मिटाने का ठेका तुम दियों का था ना, मगर जंग तो हम जुगनुओं ने संभाली है।** शहरी विकास की बात करते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन छलावे के अलावा और कुछ नहीं है। एक भी उल्लेखनीय काम दिखायी नहीं पड़ता। पता नहीं हजारों करोड़ का पिछला बजट कहाँ खर्च कर दिया। शहरों में आज भी कूड़े के अम्बार हैं। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती हैं पर आप बताइये स्वच्छ भारत मिशन की परिकल्पना कैसे पूरी हो सकती है जब तक सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं की जायेगी। बगैर सफाई कर्मियों की भर्ती किये आप कैसे स्वच्छ भारत मिशन को बना लेंगे। आप सफाई कर्मियों की भर्ती का बजट नहीं दे रहे हैं। भर्ती की कोई योजना आप नहीं ला रहे हैं। स्वच्छ भारत के भाषण करते हैं। स्थिति यह है कि भारत के 10 सबसे गंदे शहरों में पांच उत्तर प्रदेश के गंदे शहर हैं जो भारत के टॉप के गंदे शहर हैं। पेयजल की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की परियोजनायें जो अधूरी पड़ी हैं। हमारे कानपुर में 870 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी पेयजल उपलब्ध नहीं है। आगे परियोजना पूर्ण करने के लिए बजट का इन्तजाम नहीं किया है। आज स्थिति यह है कि आपकी ई0ई0एस0एल0 कम्पनी है। जो शहरों में मार्ग प्रकाश लाइट लगाती है उसका 38 करोड़ रूपया बकाया है आपने बजट में देने का प्राविधान नहीं किया है। एक भी रोड लाइट नगर क्षेत्र का

कोई विधायक लगवा नहीं सकता। यह उसकी स्थिति है। बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। आज नौकरियों की मांग के मामले में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नम्बर पर है। बिजली के दाम बेइन्तहा बढ़ रहे हैं। कल फिर खबर आयी हैं कि नियामक आयोग फिर बिजली के दाम बढ़ाने जा रहा है। नये कनेक्शन की भी फीस बढ़ा दी गयी है। स्मार्ट मीटर खून चूस रहे हैं। सरकार ने स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दी। स्मार्ट मीटर में कमियां है, लेकिन सरकार उसका निराकरण करने को तैयार नहीं है। आम जनता की कमर टूट रही है। यह जी0डी0पी0 की बात करते हैं। दो जी0डी0पी0 है। एक जी0डी0पी0 है गैस, डीजल, पेट्रोल, वह लगातार ऊपर जा रही है और एक जी0डी0पी0 है जो विकास दर होती है वह लगातार नीचे जा रही है।

मान्यवर, ऐसा इसलिए है क्योंकि ए0वाई0 अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ वाई0ए0। ए0वाई0 विकास है और वाई0ए0 उसका उल्टा है। इस बात को मैं आंकड़े में बताना चाहूँ तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में पांच बार बजट पेश किया। जो पहला बजट था वह दो लाख करोड़ का था और जो आखिरी बजट था वह साढ़े तीन लाख करोड़ का था। पांच साल में 73 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी। हमने आपका भाषण बार-बार सुना, बड़ा बजट, सबसे बड़ा बजट, बहुत बड़ा बजट। आपने पांच साल में कुल 43 प्रतिशत बजट बढ़ाया है जबकि, अखिलेश यादव जी ने पांच साल में 73 प्रतिशत बजट बढ़ाया था। मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि कोरोनाकाल में जनता मांग कर रही थी कि स्कूलों की फीस माफ की जाये लेकिन आपने उनकी इस समस्या का निराकरण करने का कोई काम नहीं किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीति आयोग की रिपोर्ट है, यू0पी0 सबसे निचले पायदान पर है। एक डॉक्टर पर 3812 मरीजों का अनुपात है। सामान्य, पिछड़े, दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि **पूर्वजों पर अभिमान व्यर्थ है, यदि अपने में नहीं समर्थ है, अरे बातों का क्या अर्थ है, यदि करनी में असमर्थ है।** मान्यवर, इसी के साथ हम अपने क्षेत्र की कुछ समस्यायें बताना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में धनकुट्टी का अस्पताल है मैं चाहता हूँ कि उसका पुनर्निर्माण किया जाये। हमारे क्षेत्र में एक महोत्सव पंडाल का निर्माण किया जाये। एक शिवाला की चूड़ी मार्केट है उसका सुन्दरीकरण किया जाये। बिरहाना रोड का सुन्दरीकरण किया जाये। एक हाइजेनिक मीट और फिश मार्केट बनायी जाये, पार्कों में ओपेन जिम बनाये जायें, जाम से निपटने के लिए परेड से घंटाघर तक एलीवेटेड रोड बनायी जाये।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे शहर कुली बाजार कांड में 23 बेघर परिवारों को आवास दिए जायें, झकरकटी पानी की टंकी चालू की जाये और उर्सला की पानी की टंकी की छत डाली जाये। इन सभी मांगों के साथ अपनी बात यह कहकर समाप्त करते हैं कि-

"ये गम के और चार दिन सितम के और चार दिन,
ये दिन भी जायेंगे गुजर, गुजर गये हजार दिन।"

डा0 श्याम बिहारी लाल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज के इस बजट चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बजट के पक्ष में कुछ बातें रखना

चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बाकी चीजों को रिपीट न करके आधी आबादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा दुनियां में पीड़ित होता है, तो वह महिलाएं होती हैं। चाहे वह कोविड-19 हो या कोई अन्य आपदा हो। जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में घटित होता है उससे महिलाएं प्रभावित हुए बिना नहीं रहती हैं और मेरा मानना है कि जब कभी उनके ऊपर कोई विपत्ति आए, कोई परेशानी आए और उनके कानून में अधिकारों का हनन हो तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें किसका दरवाजा खटखटाना है। पिछली सरकारों में और मैं कहूँगा कि आजादी के बाद जेण्डर इश्यूज पर काम हुआ, विश्वविद्यालय में ह्युमन स्टडीज के डिपार्टमेंट खुले, ह्यूमन इम्पॉवरमेंट के डिपार्टमेंट खुले, लेकिन जो काम मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया वह अद्वितीय है। उन्होंने एक प्रैक्टिकल के तौर पर बजाय सैद्धान्तिक काम करने के, उन्होंने व्यवहारिक काम किया और व्यवहारिक काम यह है कि उन्होंने जो मिशन शक्ति चलाया उसके माध्यम से नवम्बर, 2020 में पूरा पखवाड़ा काम किया है और बच्चियों, बालिकाओं एवं महिलाओं को जगह-जगह रैलियो एवं सेमिनार के द्वारा यह बताने की कोशिश की और मैं देखता था कि हर स्कूल में मिशन शक्ति के तहत काम हो रहा है और लोग उससे जागृत हो रहे हैं, महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जान रही हैं। सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि जब भी कोई महिला जब थाने में जाती थी तो उसको बाहर से ही टरका दिया जाता था, लेकिन थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाई गयी तो अब जब कोई पुरुष भी थाने जाता है तो मेरी विधान सभा क्षेत्र के थाने के इंस्पेक्टर ने यह कर दिया है कि महिलाएँ ही पुरुषों की शिकायत भी सुनेंगी। इस तरह से उन्हें सीधे-सीधे मेन लाइन में लाने की कोशिश की गयी है और अभी आपने देखा कि फिर से 26 फरवरी से मिशन शक्ति का अभियान शुरू हुआ और उसमें तहसील स्तर पर विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली पाँच....

(इस समय 03 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री फतेह बहादुर पीठासीन हुए)

महिलाओं का सम्मान करने की बात की गयी है। जिस दिन महिला दिवस (08 मार्च, 2021) को होगा, तब यह कार्यक्रम होंगे और फिर से हर जगह तहसील में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है, बालिकाओं के नाम से पौधा रोपण किया जायेगा, हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा के नाम पर एक तालाब का नामकरण किया जायेगा। विरासत अभियान के दौरान दर्ज महिला खातेदारों और सह खातेदारों को खतौनी की नकल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उत्कृष्ट कार्य हेतु महिला राजस्व कर्मियों व महिला लेखपालों का सम्मान किया जायेगा। प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह सब काम जेण्डर इश्यूज के बजाय या ह्यूमन स्टडीज या ह्यूमन इम्पॉवरमेंट की बजाय सीधे मैदान में उतारने की कोशिश की है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो सामूहिक विवाह योजना थी वह लग तो रही थी कि एक सामूहिक विवाह योजना है, लेकिन वीमेन इम्पॉवरमेंट बहुत बड़ा काम है, पहले लोगों को रुचि नहीं थी कि सामूहिक विवाह में जायेंगे और वहां पर अपनी बेटी की शादी करायेंगे, लेकिन बाद में भीड़ उमड़ती चली गयी और यह प्रयोजन बहुत सफल रहा।

इसे और ज्यादा वर्गों में आच्छादित करने के लिए काम को बढ़ाया गया। महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रॉविजन किया गया। महिलाएं

जब न्यायालय जाती थीं, अपने पति से अलग होने के बाद, उसी बीच का जो अंतराल होता था, जो गरीब बेसहारा महिलाएं थीं उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता था, तो राज्य सरकार ने व्यवस्था की उस बीच में जब तक भत्ता नहीं मिलेगा, मा0 मुख्य मंत्री जी उसके लिए पैसा उपलब्ध कराएंगे और इसी तरीके से अन्य कार्य भी किये गये। दूसरा इश्यू बहुत संक्षेप शब्दों में कहना चाहूंगा कि कुपोषण की समस्या के लिए भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने काम किया, वैश्विक भूख सूचकांक 2019 एवं उसके बाद के आंकड़े बताते हैं कि बच्चों में पतला होना और कमजोर होना, बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए भी मा0 मुख्य मंत्री जी एक योजना लाये हैं जिसमें 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को चिन्हित करके, उन्हें ड्राई राशन और सुपोषण से संबंधित जो चीजें हैं, वह दी जाएंगी। इसके अलावा, एनीमिया से ग्रस्त 11 से 14 साल की बच्चियां जो स्कूल नहीं जाती हैं उन्हें भी भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। मैं इसके बाद एक बात और कहना चाहता हूँ कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने उन गरीब लोगों के लिए जो गांवों से आते हैं या पिछले 15 सालों की नकल की व्यवस्था में, उससे सिर्फ हाशिये के लोग प्रभावित हुए।

नेता विपक्ष यहां बैठे हुए है, मैं भी उन्हें बहुत गम्भीरता से सुनता हूँ, लेकिन यह भी इस बात को मानेंगे कि पिछले 15 सालों में जो पढ़ाई हुई है, इस रिज्यूम से पहले जो पढ़ाई हुई है उसमें इतनी नकल का प्रयोग हुआ था कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसको भी समझा और मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के तहत एक कोचिंग की शुरुआत की है। गरीब बच्चा कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकता था, लेकिन अब सभी के पास टैबलेट है, मोबाइल है, जिसके माध्यम से वह चीजों को समझ सकता है। बन्द चीनी मिलों को प्रारम्भ कराया गया, टी0सी0डी0 क्षमता बढ़ाई गयी, बन्द कताई मिलों के स्थानों पर उन जमीनों को उपयोग में लाया गया। उसके बाद मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के कुछ बिदुओं को रखना चाहता हूँ और कुछ प्रदेश की समस्या है उसको रखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में बंजारों का बहुत बुरा हाल है। लगभग 40 विधान सभाओं में वे प्रमुखता से और मैं चाहता हूँ कि बंजारों टाण्डों का डेवलेपमेण्ट करने के लिए बंजारा टाण्डा डेवलेपमेण्ट बोर्ड का गठन किया जाये और अन्य राज्यों में ऐसा किया गया है। चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो और उनकी भाषा एवं संस्कृति को, ऐसा करके बचाया जा सकता है। इसके बाद राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर में बी0एस0सी0 एवं स्नातकोत्तर की कक्षाओं के लिए शैक्षणिक पद उपलब्ध कराये जायें। फरीदपुर नगर पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर जनहानि रोके जाने हेतु ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

डा0 श्याम बिहारी लाल-

मान्यवर, दो सेकेण्ड में पूरी बात समाप्त कर लूंगा। फरीदपुर तहसील के किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलाने के लिए मण्डी स्थल का निर्माण कराया जाये। लखनऊ बरेली हाई-वे पर दुर्घटनाओं के मद्देनजर फरीदपुर नगर में ट्रामा सेण्टर बनाया जाये। नगरिया कलां

से शेराखान से बदायूँ को जोड़ता है वहाँ पर रामगंगा का पुल बनाया जाये। फतेहगंज पूर्वी से दातागंज-बदायूँ मार्ग पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाया जाये, फरीदपुर नगर पालिका से दूषित जल निकास की व्यवस्था कराई जाये। कल्यानपुर बिलउवा के मध्य नाले पर पुल का निर्माण कराया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे उत्तर प्रदेश के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रदेश के विकास को आगे जाने वाला है, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। इस बजट में समाज की मूलभूत आवश्यकताएं चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आवास हो, नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, कानून व्यवस्था हो, सभी विषयों पर बजट में अच्छा-खासा धनावंटन किया गया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे जनपद से आता हूँ, मैं रायबरेली जनपद से आता हूँ कि शायद ही उत्तर प्रदेश के किसी जनपद का नाम देश के लोग जानते हों, न जानते हों, लेकिन रायबरेली जनपद का नाम पूरा देश और विश्व जानता है और किस नाते जानते हैं, यह सारे लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास की जो गति है, उसका एक आइना दिखाना चाहता हूँ। सरेनी विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूँ, मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष, जिनका हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि हम भी छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं और आपने इस प्रदेश के बजट को बताया था "काठ का लोला" कि पूर्वांचल में काठ का लोला होता है और जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ उस बच्चे के मुंह में काठ का लोला डाल देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसी उत्तर प्रदेश ने आपको भी बजट प्रस्तुत करते देखा है और हमारी सरकार को भी बजट प्रस्तुत करते देख रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप हमारे अग्रज हैं, लेकिन "आप जब भी आइना अपना उठाया करो, पहले खुद को देखो और उसके बाद दिखाया करो" (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) मैं समझता हूँ कि अभी तो यहाँ पर ये लोग दल हैं, अधिष्ठाता महोदय जी, और जब रायबरेली जनपद में ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ दलदल हो जाते हैं, एक में जाकर मिल जाते है।

गंगा, यमुना, सरस्वती जितनी नदियाँ हैं, राजनैतिक रूप से रायबरेली में एक हो जाती हैं। चाहे केन्द्र में सरकार बनी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी हो, एक दूसरे का सबको सहयोग रहता है, लेकिन एक बानगी दिखाना चाहता हूँ कि रायबरेली को उस सरेनी विधान सभा क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति थी, हमारी सरकार के पहले। सड़कों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। हमारी विधान सभा क्षेत्र का नाम सरेनी विधान के नाम से है। सरेनी वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है और सरेनी ब्लाक के जितने मार्ग थे, जितने प्रमुख मार्ग थे, 30-30 किमी0 के मार्ग हैं, वह आज तक 3 मीटर की चौड़ाई के हैं, लगभग 7-8 हजार वाहन प्रतिदिन निकलते हैं, आज तक सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो पाया वी0आई0पी0 जिले में सरेनी, रायबरेली का नाम गिना जाता है। हमारी सरकार बनने के बाद लालगंज से सरेनी को

जो रोड जाती है, वह हाई-वे की तरह बन गयी है और आम जनमानस उसमें चल रहा है। एक और सड़क हमारे क्षेत्र की है, जो सरांय गैरिया खेड़ा से तेजगाँव पूरे पाण्डेय होते हुए भोजपुर और दौलतपुर जाती है, पं0 हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम पर हिन्दी का युग चला था, उस सड़क को भी मैंने पास करा लिया है और उसका भी टेण्डर हो गया है और बहुत जल्द ही वह सड़क भी हाई-वे की तरह बन जायेगी, ऐसा विकास हमारी सरकार कर रही है। क्या किया है, आप लोगों ने ? आप विकास की चर्चा करते हो ? जिसके नाम से विधान सभा का नाम है, उस ब्लाक की सारी सड़कें जर्जर पड़ी हैं और मैं आज सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूँ तो मैं कोई मांग नहीं करूंगा, अपनी विधान सभा क्षेत्र के लिए और मैं सरकार के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को और प्रदेश के उप मुख्य मंत्री आदरणीय केशव मौर्या जी, जिनकी झोली में पता नहीं कितना धन है कि जितना चाहता हूँ, उतना मिलता है। मैं उन दोनों लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, यहाँ किसी माँग की आवश्यकता नहीं है, सारे काम हो रहे हैं और जो शेष काम बचे हैं। वह लाइन पर हैं, वह भी सब काम हो जायेंगे। आप नहरों की चर्चा करते हो कि नहरों में पानी नहीं आया है। आप खोखली नारेबाजी करते हैं, सदन में आपके सारे नेता बोलते हैं। मैं जब छात्र राजनीति से विधान सभा में चुनाव लड़ने के लिए गया तो सरेनी में नहरें तो थीं, रायबरेली में नहरें तो थीं, लेकिन नहरों में पानी नहीं था और वहाँ पर आपके नेता लोग जनता को बताया करते थे कि उन्नाव और हरदोई की तरफ से नहर बन्द कर दी गयी है, अब जीवन में नहर नहीं आयेगी और लोग जब हमसे पूछते थे तो मैंने कहा था कि मैं नहरों में पानी ला करके रहूँगा। जनता वहाँ की कहती थी कि यहाँ के नेता लोग कहते हैं कि उन्नाव और हरदोई से नहर बन्द कर दी गयी है, इस नहर में पानी कैसे आयेगा ? तो हमने कहा कि जहाँ पानी नहीं आता है, वहीं तो पानी लाने का काम हम लोग करते हैं और हमारी सरकार करती है। आज मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि प्रदेश की नहरों में पानी चल रहा है। हमारी विधान सभा क्षेत्र की नहरों में पानी चल रहा है और डलमऊ की पम्प नहर जो उन्नाव के बार्डर से आती है, उसमें 78 करोड़ रूपया स्वीकृत होने के लिए गया है। पम्प वहाँ के खराब हो गए हैं और मुझको सूचना मिली है कि दो-तीन महीने के अन्दर पम्प की धन स्वीकृत हो जाएगा और इतनी मात्रा में पानी आएगा कि किसान मालो-माल हो जाएगा और सरकार की जय-जय, योगी जय-जय करते रहोगे, आप चर्चा करते हो।

स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय बेसिक शिक्षा के मंत्री थे, शिक्षा का स्तर कितना गिर गया था आप लोगों की सरकारों में, सार्वजनिक कामों पर आपका ध्यान नहीं था, सार्वजनिक कामों की चिंता आप लोगों को नही थी। अगर चिंता थी तो इस बात की कि किस-किस को मोरंग का ठेका मिल जाए, किस-किस को बालू का पट्टा मिल जाए और कैसे सिंडिकेट बैठा दिया जाए, जिसके माध्यम से सरकार का धन आपकी झोली में जा सके, और इसकी बानगी में मै अध्यक्ष जी देखता हूँ, मैं भी छात्र राजनीति से निकला हूँ और मेरे ऊपर भी संघर्ष के दौरान मुकदमे लगे थे और एम0पी0, एम0एल0ए0 कोर्ट में जाता हूं तो आपके कई नमूने वहां पर दिखाई देते हैं जो व्हील चेयर से मुकदमा लड़ने आते हैं, उनकी भी थोड़ा आप लोग चिंता कर लिया करिए, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ दिया है। कचहरी में

आते हैं और उनकी दशा देखकर मुझे कष्ट होता है, यह काम आप लोगों ने किया। हमारी सरकार ने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में। हम भी प्राइमरी विद्यालय से पढ़ कर आए हैं और लगभग सदन में जितने सदस्य बैठे हैं, अधिकांश सदस्य प्राइमरी विद्यालय से पढ़कर इस सदन में आए हैं और वहां की क्या स्थिति थी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष महीने के तीन दिन सर्दियों में गांव-गांव का दौरा करता हूं, गांव-गांव का दौरा करके विद्यालय के अन्दर भी जाता हूँ। एक बार मैं गांव का दौरा करते हुए एक विद्यालय में जा रहा था और दोपहर का समय था बाहर से सौ मीटर की दूरी पर दिखाई पड़ रहा था कि तीन से छः छात्र बैठे हुए थे। मैंने शिक्षिकाओं से पूछा कि क्या लंच हो गया है, बच्चे नहीं हैं उन्होंने शर्माते हुए कहा कि नहीं इतने ही बच्चे हैं। मन बड़ा क्षुब्ध हुआ और लगा कि इसी विद्यालय से पढ़कर हम लोग भी यहां से विश्वविद्यालय की राजनीति करने गए और आज विद्यालयों की यह स्थिति हो गई है। हमारी सरकार ने तय किया कि कायाकल्प के माध्यम से हम शिक्षा की गुणवत्ता भी सही करेंगे और शिक्षा को सही दिशा में ले जाएंगे, दशा भी बदलेंगे और दिशा भी बदलेंगे और उसके माध्यम से कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों की बाउण्डीवॉल भी बनाई जा रही है, वहाँ हैण्डपम्प और नलकूप लगाया जा रहा है, मॉडल विद्यालय बनाए जा रहे हैं। कॉपी, किताब, स्वेटर, मोजा मुफ्त में दिया जा रहा है। यह है योगी की सरकार, यह है भाजपा की सरकार, आप चर्चा करेंगे। हमारी पिछली भी सरकार जब थी, उत्तर प्रदेश जब भाजपा की सरकार थी और आदरणीय कल्याण सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे, शिक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे आज रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि नकल अध्यादेश लागू किया था इतना कड़ा कानून लागू करना हर आदमी के बस की बात नहीं होती है। हम नकल से लोगों को पास नहीं कराएंगे, योग्यता से पास कराएंगे यह भाजपा की सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि-

हमने संघर्षों से लिखी है, दास्तां अपनी जिंदगी की,
तुम्हारी साजिशों से बुझ जाएं, हम वह चिराग नहीं।
और आस्मां को जिद है, जहां बिजलियां गिराने की,
हमारी भी जिद है, वहीं आशियां बनाने की।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, कई विषयों पर चर्चा करने का समय नहीं है, पांच मिनट का समय मुझे मिला है आपका संरक्षण मिला है तो मैं बोल लिया हूँ, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सदन को गुमराह करने का काम न किया जाए, सदन में सच्चाई की बात की जाए। आज अट्ठारह घण्टे गांव में बिजली आती है तो आपको भी कहना पड़ेगा कि अट्ठारह घण्टे गांव में बिजली आती है। अगर गांव का किसान अपने घर जाता है तो उसको चमचमाती हुई बिजली अपने घर में दिखाई पड़ती है, इसके पहले क्या स्थिति थी। चार-पांच जनपदों को आप बिजली देते थे, जिन गांवों में घरो में बिजली नहीं थी, जहाँ तार नहीं था वहाँ पर तार पहुंचाया गया। मान्यवर, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(मा0 अधिष्ठाता द्वारा सदस्य श्री रफीक अंसारी का नाम लिए जाने एवं उनके द्वारा बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था यह दी गई है। देखिए ये नेता प्रतिपक्ष सबके हैं और ये इनको बोल रहे हैं कि बोला हो बोला। इसके पहले भी इनके दो हुए यह तीसरा नाम हो गया।

श्री अधिष्ठाता-

आप दोनों लोग बैठ जाइए। कृपया स्थान ग्रहण करें। मेरी बात सुनें पहले स्थान ग्रहण कर लें। मा0 सदस्य आप स्थान ग्रहण करें, मैंने सुन ली आपकी बात।

श्री उमाशंकर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दी है और व्यवस्था यह दी है कि दो सत्ता पक्ष से और फिर एक विपक्ष से। पहले तो सपा से एक विपक्ष का, फिर सत्ता पक्ष, फिर उसके बाद बसपा, फिर उसके बाद सत्ता पक्ष और फिर इधर जाएगा। मा0 अध्यक्ष की यही व्यवस्था है।

श्री अधिष्ठाता–

मुझे यह व्यवस्था मालूम है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आपने कहा और सत्ता पक्ष के बाद अभी तीन इधर से हो गए तो क्या बसपा चली गई ?

श्री अधिष्ठाता-

यह आप दोनों तय कर लीजिए।

श्री लालजी वर्मा–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जैसे इसके पहले सपा के मा0 सदस्य बोले थे और कल भी सपा के बोल चुके थे। मान्यवर, कल भी सपा के बोले थे, आज भी सपा के ही बोले।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैंने इनको बुला लिया है, इसके बाद मैं आपको मौका दे दूंगा।

श्री रफीक अंसारी-

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया।

(सपा तथा बसपा के कतिपय सदस्यों द्वारा लगातार आपस में बातचीत करते रहने पर)

***श्री रफीक अंसारी–**

भाई आप लोग जरा एक सेकण्ड रुक जाइए। अब तो बात हो गई। अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ और अपने नेता विपक्ष की बातों पर बल देते हुए जो मेरे करम फरमाँ भी हैं, मैं दिल की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गहराइयों से नेता विपक्ष का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज यहाँ पर हम जो कुछ भी बोल रहे हैं क्योंकि आज यह आखिरी बजट सत्र है। यकीनन हमारी अगली पारी उधर से होगी और ये इधर होंगे। यह निश्चित रूप से तय हो गया है।

(सत्ता पक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

अरे, हम मिठाई खाएंगे, लड्डू नहीं खाएँगे। आप पुराने लोग हो इधर आओगे, हम नये उधर जाएँगे। अध्यक्ष जी, बजट में किसान के बाद बुनकर समाज का नम्बर आता है। बुनकर समाज और किसान, किसान भारत की जान है और बुनकर हिन्दुस्तान की धड़कन है। आज बुनकर समाज के लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया है। सब किसानों को भी लाइन में लगा दिया है। बुनकर समाज का इस बजट में कुछ नहीं है। यह कैसी सरकार है और यह सरकार भारत के प्रधानमंत्री जहाँ से चुनकर आते हैं बनारस से, वहाँ बुनकर समाज बहुत है। जब प्रधानमंत्री के घर में उत्पीड़न हो रहा हो बुनकर का तो बताइए कहाँ विकास हो रहा होगा ? आज बुनकर आन्दोलन के लिए तैयार हैं, बुनकर समाज को इस बजट में कुछ नहीं दिया गया है। साल 2006 में मा0 मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने बुनकर को नया जीवन और नई जिन्दगी देने का काम किया था। बिजली फिक्स रेट पर दी थी, लेकिन इस सरकार ने एक झटके में बुनकरों का गला घोंटने का काम कर दिया है। यह वही जाली सरकार है। अध्यक्ष जी, जब-जब इस देश और प्रदेश के अन्दर जुल्म बढ़ा है तो जुल्म फनाँ हुआ है, यह सरकार भी फनाँ हो जाएगी। ऐसा मेरा यकीन है, मेरा मानना है। आज बुनकर समाज कहता है कि-

गाँधी जी अब आकर देख लो अपना हिन्दुतान
कैसे-कैसे आपके चेले हो गए बेईमान।

ये लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार विश्वासघात कर रही है, विश्वासघाती सरकार है यह। यह वो संस्कार है जिसने आपको, हमको, सबको कपड़ा देने वाले बुनकर समाज, जो कपड़ा बुनने का काम कर रहा है, उसको कुछ नहीं दिया। आज पूरे प्रदेश के अन्दर बुनकर को बिजली नहीं है। मैं स्मार्ट मीटर को लुटेरा मीटर कहता हूँ और इस सरकार ने लुटेरा मीटर लगाने का काम कर दिया है। आज बिजली के बारे में हमारे कई साथी दावा कर रहे थे कि हमने 18 घण्टे बिजली दी है। अरे, यह किसकी देन है, यह अखिलेश यादव की देन है।

एक यूनिट का कारखाना इन्होंने नहीं लगाया है, अखिलेश यादव की देन है जो आज बिजली पर बोल रहे हैं, लेकिन बिजली के रेट कितने कर दिये यह तो इनसे पूछो सब उम्मीद कर रहे थे कि ये आखिरी बजट है, चुनावी बजट है, इसको कागजी बजट बना दिया। बिजली के रेट पूरे हिन्दुस्तान में सबसे महँगे योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि सबसे महंगी बिजली पूरे देश में सबसे महँगी बिजली उत्तर प्रदेश के अन्दर है और फिर दुहाई दे रहे हैं बिजली हम दे रहे हैं वह भी इतनी महंगी दर से 7.76 पैसे यूनिट सब जगह मिल रही है और ये 9 रुपये यूनिट दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज बुनकर

समाज आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। कोरोना के समय तीन महीने का लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन बुनकर बेचारों से जो भुखमरी के कगार पर हैं उनसे भी बिल लेने का काम इन्होंने किया। उनकी मशीनें बन्द हो गयी थीं, धागा महंगा हो गया था उसके बन्द होने के बाद भी इन्होंने बिल लेने का काम किया। सरकार का यह कानून है कि सरकार ही बन्द कराएगी और बन्द के बाद भी बिल वसूल करेगी यह बी0जे0पी0 की सरकार है, ये योगी की सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ कि-

"कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आयेगा।
आपका तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आयेगा।।"

ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर तबाही मचा रखी है, लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार फैला रखा है, आतंक मचा रखा है। कोई भी थाना देख लीजिए, जेलों में माइनॉरिटी के लोगों को भरने का काम किया गया है और ये लोग अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। इतनी लूट मचाने का काम, इतना भ्रष्टाचार, गुण्डाराज और जंगलराज। अधिष्ठाता महोदय, टोटल इस सरकार में हमने गुण्डाराज सुना था, लेकिन असली गुण्डाराज देखने का काम किया है, सब पर एकतरफा मुकदमें, गैर जमानती वारंट निकालने का काम इन्होंने किया है। हद तो इतनी हो गयी कि हमने सुना था कांग्रेस सरकार ने देश में इमरजेन्सी लगाई थी, लेकिन इन्होंने तो इमरजेन्सी से भी ज्यादा खराब हालात कर दिये हैं। धारा-144 लगाने का काम इन्होंने किया है और किसी को भी धरने-प्रदर्शन करने का और किसी को भी आवाज उठाने पर इन्होंने आवाज को बन्द करने का काम किया यह देश की जनता देख रही है, चुनाव वर्ष 2022 में मुझे पूरा यकीन है कि इंशा अल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव इस उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बनेंगे और इन लोगों का सूपड़ा साफ करने का काम करेंगे। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं मेरठ के अन्दर की बात बताना चाहता हूँ। मैं भेदभाव की बात कर रहा हूँ भेदभाव तो इन्होंने ऐसे किया है कि मेरठ शहर से मैं जीतकर आया हूँ और इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी को धूल चटाने का काम मैंने किया है, लेकिन भेदभाव इन्होंने शहर में यह किया है जहाँ सड़कों पर ये भी चलते हैं और हम भी चलते हैं। ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन मेरठ के अन्दर हमारी विधान सभा के अन्दर इन्होंने सड़कें नहीं बनाने का काम किया। इन्होंने सिर्फ अपनी-अपनी सड़कें बनायीं और इसलिए बनायीं कि रफीक को हराना है-

"ये ताकतें तुम्हारी है खुदा हमारा है।
अपने अक्शों पर न इतराओ आइना हमारा है।।"

इंशा अल्लाह हम हर हालत में जीतकर आएंगे। हमारी विधान सभा के अन्दर आजाद रोड पर तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं, हमारे सद्दीक नगर की सड़क टूटी पड़ी है, हमारे करीम नगर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, खैर नगर के अन्दर बहुत बुरा हाल है, भिसारी गेट पर सड़कें जर्जर पड़ी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने हमें कृपापूर्वक बोलने का अवसर प्रदान किया हम आपके बहुत आभारी हैं आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश का मतलब भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश, मतलब गुण्डों और माफियाओं की छाती पर बुल्डोजर चलाने वाला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मतलब प्रदेश में सड़कों और एक्सप्रेस-वे का जाल फैलाने वाला एक्सप्रेस-वे वाला उत्तर प्रदेश। हमारे परम पूज्य मुख्य मंत्री कर्म योगी सन्त योगी जी की सरकार के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में और पुरजोर समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, अभी हमारे जो पुराने वक्ता थे, यह को-इंसीडेन्स है कि जब मैं पिछली बार बोल रहा था तो हमसे पहले यहाँ बोले थे। मैं अभी अपने साथी से चर्चा कर रहा था कि हमारा इनका कुछ ऐसा सम्बन्ध है कि पिछली बार भी इनके बाद मेरा नम्बर आया था और इस बार भी ऐसे ही नम्बर आया। पिछली बार इन्होंने चलते-चलते एक चर्चा की थी कि वर्ष 1947 में जब देश का विभाजन हो रहा था तो गांधी जी ने हम लोगों से कहा कि "अरे! मुसलमान भाइयों, आप कहाँ जा रहे हो, यह हिन्दुस्तान हमारा है" और हम लोग लौट आए थे। मैं उस दिन इस बात का जवाब नहीं दे पाया था, परन्तु आज मैं जवाब दे देता हूँ कि निश्चित रूप से गाँधी जी ने कहा था कि 'ऐ ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, तुम जैसे लोग कहाँ जा रहे हो, यह हिन्दुस्तान तुम्हारा है' और यह भी कहा था कि 'ऐ अफजल गुरू, तुम्हारे जैसे लोगों की धरती हिन्दुस्तान नहीं है, हिन्दुस्तान के बाहर तुम्हारी धरती है'।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बजट पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। अगर यह कदाचित देश होता तो विश्व का 5वाँ सबसे बड़ा देश होता। इसलिए उत्तर प्रदेश का बजट अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है और देश के जनमानस का इस पर ध्यान रहता है। बजट केवल आय-व्यय का आंकड़ा नहीं होता है, बजट सरकार की रीति-नीति, नियत, सोच और प्रतिबद्धता का एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। बजट में सरकार के द्वारा जनता के प्रति क्या सोच है, क्या इरादे हैं, प्रदेश की दशा एवं दिशा की स्पष्ट झलक बजट में दिखायी देती है। महोदय, परम पूज्य योगी जी द्वारा प्रस्तुत यह 5वाँ बजट है। मैं अपने परम पूज्य मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा और विशेष बधाई इसलिए देना चाहूँगा कि यह उनका 5वां बजट है और अब तक का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले ऐसे मुख्य मंत्री हैं, जिनका 5वाँ बजट है, इसलिए मा0 मुख्य मंत्री जी को विशेष रूप से हम लोग बधाई देते हैं। महोदय, यह बजट 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये (5,50,270.78 करोड़ रुपये) का है, जिसमें 27 हजार 598 करोड़ की नयी योजनाएं हैं। महोदय, यह 5 वर्ष का बजट है और अगर हम 5 वर्ष के बजट को जोड़ लें तो लगभग 24 लाख करोड़ का यह बजट होता है। यदि इसकी तुलना हम पूर्ववती सरकारों से करें तो समावादी पार्टी की 5 साल की सरकार के बजट का यह दोगुना है और बहुजन समाज पार्टी के 5 साल की सरकार के बजट का यह 4 गुना है। महोदय, यह बजट केवल पिछली सरकार

के बजट का दोगुना तो है ही, परन्तु पिछले 5 सालों के और 4 सालों के बजट पर कार्य का हिसाब यदि करेंगे तो देखेंगे कि इनकी सरकार के विकास से 2 नहीं, 10 नहीं, 50 गुना ज्यादा विकास हम लोगों ने किया है। चूंकि हम बहुत ज्यादा विपक्ष पर नहीं बोलना चाहते लेकिन मैं थोड़ी बातें जरूर कहूँगा कि इनकी भी सरकार बनी थी और सरकार बनते ही किस प्रकार लोगों ने जश्न में थानों को फूँक दिया था। किस प्रकार की अराजकता फैली थी ? 5 वर्ष का कार्यकाल इनका केवल दंगों और पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटने में ही बीत गया। हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे थे, अभी उठ गये हैं, पिछली बार वह कुछ आँकड़े रख रहे थे। मैं सी0ए0जी0 की रिपोर्ट देख रहा था। इनके समय में बेरोजगारी भत्ता योजना आयी थी जिसमें 20 करोड़ 58 लाख रुपये का बेरोजगारी भत्ता इन्होंने 69 जिलों में बाँटा और जिस भत्ते को डायरेक्ट एकाउण्ट में डी0बी0टी0 के माध्यम से भेजा जा सकता था, उसे न करके चेक के माध्यम से भेजा और 20 करोड़ के बेरोजगारी भत्ते को बाँटने में 16 करोड़ रुपये इन्होंने व्यय कर दिये। यह इनकी सोच थी।

महोदय, पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि पिछले 4 सालों में परम पूज्य योगी जी की सरकार ने जो काम किया है वह धरातल पर दिखने लगा है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइये, आप सड़कों की बात कर लीजिये, हमारे नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण में कह रहे थे, हम लोग उनसे बहुत सीखते हैं, यह बहुत विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में एक भी पुल नहीं बना। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा में 15-15 करोड़ के 03 पुल बने हैं, 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की नई सड़क बनी है और जो पुरानी सड़कें हैं उनका रिपेयर सामान्य तरीके से चल रहा है। अभी पूर्व वक्ता ने बिजली के बारे में भी कहा। मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि आज निर्बाध रूप से पूरे प्रदेश में बिजली मिल रही है और मेरी विधान सभा में उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा विद्युत केन्द्र 930 करोड़ में बन करके तैयार हो गया है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया है और मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 930 करोड़ से जो विद्युत केन्द्र बनकर तैयार हुआ है कृपापूर्वक उसका लोकार्पण करें। महोदय स्वास्थ्य की बात लें, कितने एम्स और मेडिकल कालेज पूरे प्रदेश में खोले गये ? गोरखपुर में एम्स के लिए जमीन नहीं मिल रही थी, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। लेकिन योगी जी की सरकार बनते ही वहां पर एम्स आज ऑपरेशनल हो गया है, वहाँ पर ओ0पी0डी0 चालू हो गयी है। बस्ती जनपद को भी एक मेडिकल कालेज मिला है।

मुझे ध्यान है कि विधायक बनने के बाद मुझे सूचना मिली कि प्राइमरी स्कूल के जो विद्यालय हैं उसमें लोग पढ़ाने नहीं जाते हैं। मैं एक विद्यालय पर गया जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर कोई छात्र मुझे नहीं मिला, कोई अध्यापक नहीं मिला, पता लगा कि उसकी जो प्रिन्सिपल हैं वह 12 साल से उस विद्यालय में नहीं आयी थीं, उनकी जगह पर जाकर कोई दूसरा दस्तखत करता था। मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई करायी। लेकिन आज जिस प्रकार पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि चाहे बेसिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, हर तरफ कायाकल्प हो गया है। आप विद्यालय में चले जाइये, बच्चों को उनकी रुचि की पाठ्य सामग्री और ड्रेस

उपलब्ध हो रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय,ये बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर को समर्पित बजट है, यह बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर को आवास, शौचालय, गैस सिलेण्डर, मुफ्त चिकित्सा तथा किसान सम्मान निधि जैसी विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़कर उसके जीवन स्तर को उठाने का काम कर रहा है। महोदय किसान की बात करते हैं किसान की आय दोगुना करने के लिए इस बजट में अच्छा-खासा प्रोविजन किया गया है। लगभग 1800 करोड़ रुपये की नई योजना, आत्म निर्भर किसान समृद्ध योजना भी शुरू की जा रही है। किसान दुर्घटना कल्याण योजना, जन आरोग्य योजना, मुफ्त में सिंचाई के लिए पानी, रियायती ऋण जैसी सुविधाओं के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

महोदय, इस प्रकार हमारा यह बजट हर वर्ग को समर्पित है ऐसे ही इनके समय में वर्ष 2015-16 का जो बजट था, उसको इन्होंने किसान वर्ष घोषित किया था। मैं सी0ए0जी0 की रिपोर्ट देख रहा था। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में मैंने देखा कि 2015-16 को किसान वर्ष घोषित करते हुए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 373 करोड़ रुपये का इन्होंने प्रोविजन किया था और उसका उपयोग किसानों के लिए नहीं हुआ और सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में ऑडिटर ने लिखा कि आप समझ सकते हैं कि इनकी नीति और नियत में कितना फर्क है। सी0ए0जी0 ने लिखा कि यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने इस योजना को गम्भीरता से नहीं लिया और उदासीन रही जिसके कारण इस योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है। किसानों की बात करने वालों का इससे ज्यादा खुलासा और क्या हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों और विद्यार्थियों के लिए एक नई 'अभ्युदय योजना' के माध्यम से उनको निःशुल्क कोचिंग की सुविधा, उनको निःशुल्क टैबलेट की सुविधा और विभिन्न प्रकार के लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही है। महोदय, जब बेटी पैदा होती थी तो माँ बाप से कोई पूछता था कि क्या पैदा हुई ? तो गरीब माँ-बाप कहता था कि लक्ष्मी पैदा हुई, लेकिन वो द्रवित होता था कि इसकी शादी कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे ? लेकिन मैं तो समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारी बेटियों के धर्म पिता हमारे पूज्य योगी जी हैं, उन्होंने बेटी को कन्या सुमंगला योजना' के माध्यम से लक्ष्मी को धन लक्ष्मी बनाने का काम किया है और वही बेटी जब पढ़-लिखकर बड़ी हो गयी, शादी का अवसर आया तो मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उस धन लक्ष्मी को गृह लक्ष्मी बनाकर दूसरे घर भेजने का भी काम किया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतना ही नहीं, अगर हम औद्योगिक विकास और अवस्थापना की बात करें तो पूरे प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का जाल बिछा हुआ है। चाहे आप पूर्वांचल का नाम ले लें, चाहे आप बुन्देलखंड का ले लें, गोरखपुर एक्सप्रेस-वे को ले लें, गंगा एक्सप्रेस-वे ले लें, डिफेन्स कॉरीडोर को ले लें, हर तरफ एक्सप्रेस-वे का जाल बिछ गया है। यही नहीं, जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके नाम पर कुछ लोगों को चिढ़ होती है, अयोध्या के प्रति हमेशा जिनका दुर्व्यवहार रहा है उस अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसलिये मैं प्रमाणिक रूप से कह सकता हूँ कि यह बजट निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान के लिये यह बजट है, महोदय, मुझे विश्वास

है कि मेरी इस बात का समर्थन पूरा सदन करेगा। महोदय, 2014 के पहले इस देश में और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता था कि जैसे हम मुगलकाल में औरंगजेब के शासन में जी रहे हैं, हमारी आस्था पर हमारी पूजा पद्धति पर अघोषित कर्फ्यू लगा होता था। दुर्गा पूजा के लिये हमको थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन जबसे योगी जी की सरकार आई है, जबसे देश में मोदी जी की सरकार आई है तबसे लगता है कि हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता के समय में जी रहे हैं। महोदय, मुझे याद है कि कांवड़ियों पर लाठी बरसाई जाती थी, लेकिन आज कांवड़ियों पर फूल बरसाया जाता है। महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे इस बजट में केवल आँकड़े ही नहीं दिखाई पड़े, केवल आय-व्यय का लेखा जोखा ही नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, अध्यात्मिक और पौराणिक सोच की आत्मा भी दिखी। इस बजट में मुझे राम दिखे और राम की अयोध्या भी दिखी। इस बजट में मुझे कृष्ण दिखे और कृष्ण का मथुरा-वृन्दावन भी दिखा। इस बजट में मुझे शिव दिखे और शिव का काशी विश्वनाथ दिखा। इस बजट में माँ विन्ध्यवासिनी दिखीं और माँ विन्ध्यवासिनी का विन्ध्याचल दिखा। इस बजट में मुझे नैमिषारण्य दिखा, चित्रकूट दिखा, सनातन संस्कृति सभ्यता दिखी, वैदिक रीति नीति दिखी और सबसे बड़ी बात कि एक बार फिर रामराज्य की कल्पना को साकार करने की प्रबल इच्छाशक्ति दिखी, इसलिये यह बजट एक आदर्श बजट है। यह बजट स्वावलम्बन से सशक्तिकरण को समर्पित जाति, मत मजहब से ऊपर उठकर गाँव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, महिलाओं, बच्चों के उत्थान के लिये संकल्पित भारतीय सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित और गौरवान्वित करने बाला बजट है।

मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के बारे में कुछ कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ, महोदय, हमारे क्षेत्र में 70 साल में उतना कुछ नहीं हुआ, जितना चार साल के कार्यकाल में विधान सभा हुआ है। दो चीज कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। महोदय, संस्कृत देव वाणी है और वर्तमान में बहुत बड़ी संख्या में धर्मग्रन्थों का ज्ञान रखने वाले आचार्य, पुरोहित, कर्मकांडी विद्वान समाज में जीविका की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें 30 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं है और यह पूरी तरह से असंगठित क्षेत्र है। संस्कृत में वेदों के धनपाठी आचार्य होते हैं जिनकी पूरे देश में संख्या लगभग तीन हजार है और एक धनपाठी चार वर्ष की उम्र से तैयारी और पढ़ाई करता है तब जाकर 20 वर्ष की उम्र में वह धनपाठ में पारंगत होता है। वर्तमान में ऐसे विद्वान रोजगार और काम न मिलने से अयोध्या, काशी, मथुरा के घाटों पर 100-50 रुपये के लिये जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे विद्वानों को आचार्य को कर्मकांडी विद्धानों के जीविकोपार्जन के लिये सरकार कोई वृहद् योजना बनाये जिससे कि हमारी देववाणी संस्कृत, वेद पुराण और उपनिषद् के संवाहक बचे रह पायें। माननीय अधिष्ठाता जी, एक और मांग करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो बी0पी0एल0 कार्ड धारक हैं, जो अन्त्योदय कार्डधारक हैं, जो दो रुपये, तीन रुपये में राशन लेते हैं मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उनको उत्तर प्रदेश परिवहन में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जाय। मेरे यहाँ एक वेला ताल है बहुत बड़ा 200 एकड़ का ताल है उसके सुन्दरीकरण का प्रस्ताव प्रेषित है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उसके सौन्दर्यीकरण से बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध

होंगे। अन्त में तीन सड़कों की बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जुगौला से पचपेड़वा, पचपेड़वा से महेशगंज यह दोनों सड़कें जल्दी से जल्दी बन जायें। गौर को तहसील बनाने और जुगौला को नया ब्लाक बनाने की मांग करते हुये मैं माननीय अधिष्ठाता जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती संगीता चौहान का नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थीं)

श्री सौरभ श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका हृदय से आभार। माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत भाजपा सरकार का बजट राज्य के सुनियोजित और संतुलित विकास का एक सफल प्रयास है।

जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी अंगों के समन्वित और समग्र विकास की रूप रेखा प्रस्तावित की गई है। मान्यवर, किसी भी राज्य के या देश के विकास के लिए जरूरी होती है, निवेश के लिए आवश्यक पूँजी। हमारे सुयोग्य मुख्य मंत्री जी ने निजी पूँजी निवेश हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं द्वारा 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश सुनिश्चित किया है। इस निवेश को सफल बनाने के लिए हमें कुशल शारीरिक व मानसिक श्रमिक चाहिए, जो तकनीकी रूप से दक्ष हो और हमारा कौशल विकास विभाग इस हेतु लगातार कार्यरत है। मान्यवर, हमारी सरकार इस बजट में मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि विविध प्रकार की योजनाओं द्वारा रोजगार बढ़ाने का सफल प्रयास कर रही है। साथ ही इसके तकनीकी उन्नयन के लिए आवश्यक उच्च शिक्षा की व्यवस्था इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, अटल आवासीय विद्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास मिशन, इस सरकार के प्रशंसनीय कदम हैं।

मान्यवर, प्रदेश के विकास के लिए आधारभूत संरचना की स्थापना करना जरूरी है, जिसके लिए सरकार प्रदेश में विभिन्न एक्सप्रेस-वे परियोजनायें, नागरिक उड्डयन हेतु हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा, बिजली की उपलब्धता आदि को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके साथ ही प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर, अपराधियों पर काफी हद तक नकेल कसी जा चुकी है, जिससे आज उत्तर प्रदेश में एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण हुआ है। मान्यवर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ किया जा रहा है। हमारी योग्य और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली सरकार प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, संसाधन, श्रम शक्ति व संगठन का निर्माण कर रही है। दूसरी तरफ इसके लिए आवश्यक बाजार का भी विस्तार किया जा रहा है। आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, परिवहन, सुगम यातायात व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है। मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश के निवासी भाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में पुनः एक बार एक राम भक्त मुख्य मंत्री बने हैं, जो अयोध्या नगरी को भव्य श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बनाने को कृत संकल्पित हैं। तुलसी स्मारक भवन का निर्माण, धार्मिक स्थलों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना, अगर आय बढ़ाने

का साधन है तो प्रदेश की जनता को धार्मिक भावना से ओत-प्रोत करने का उपाय भी है, अर्थात् जनता की सुख-समृद्धि के लिए भौतिक साधनों की वृद्धि के साथ-साथ उनमें आध्यात्मिक चेतना का जागरण और चरित्र निर्माण करने का प्रयास भी सरकार कर रही है। जिससे सामाजिक बुराइयों को दूर करने का एक सार्थक प्रयास सफल होगा।

मान्यवर, प्रदेश में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु दो एम्स गोरखपुर और रायबरेली में स्थापित कर पठन-पाठन तथा आउट-डोर सेवायें प्रारम्भ कर दी गई हैं। वाराणसी में भी एम्स की तर्ज पर चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है। ग्रामीणों में अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना इस सरकार की प्राथमिकताओं में है। मान्यवर, मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित क्षेत्र में बच्चों के प्रभावी उपचार हेतु व्यापक व्यवस्था की गई है। जिसके कारण इस बीमारी से मृत्यु की दर घट गई है। हमारी प्रदेश सरकार आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों को भी विकसित करने के लिए प्रयासरत् है। इस हेतु जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। मान्यवर, प्रदेश के असहाय, सुविधाविहीन, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं। दिवयांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं। मान्यवर, मैं वाराणसी कैण्ट का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो प्रदेश और केन्द्र की सरकारों ने विकास की गंगा बहाई है। बी0एच0यू0 में मल्टी स्पेशियल्टी अस्पताल, बाढ़ से बचाने के लिए ज्ञान प्रवाह का स्लूस गेट, जल परिवहन के लिए रामनगर में बंदरगाह। मान्यवर, बंदरगाह शब्द हम लोग सुनते थे तो समुद्र किनारे अहमदाबाद, मुम्बई और विशाखापत्नम की याद आती थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बन्दरगाह बन गया है, जल परिवहन प्रारम्भ हो गया है।

मान्यवर, अभी एक सदस्य कह रहे थे कि सरकार ने पुल नहीं बनाया, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2002 में एक पुल का शिलान्यास हुआ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार चली गई, बहन मायावती जी की सरकार चली गई, अखिलेश जी की सरकार चली गई, 15 वर्ष में जो पुल नहीं बन पाया वह पुल भाजपा की सरकार बनते ही रिकार्ड आठ महीने में बनकर तैयार हो गया। 110 करोड़ रुपए की लागत से अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम हमारी विधान सभा क्षेत्र में बनने जा रहा है। सबसे बड़ी बात कैंसर के इलाज के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली और मुम्बई जाना पड़ता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से होमी जहांगीर भाभा अस्पताल मेरे विधान सभा क्षेत्र में कैंसर के इलाज के लिए बनकर तैयार हो गया है और आस पास के क्षेत्र के सभी लोग वहीं इलाज करा रहे हैं। मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की बची हुई दो चार कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र वाराणसी कैंट के पाँच गांव भगवानपुर, लहरतारा, आदित्यनगर, उत्तरी ककरमत, भिखारीपुर को नगर निगम क्षेत्र में ले लिया गया है, इससे ग्राम प्रधानों के अधिकार तो समाप्त हो गये हैं, लेकिन नगर निगम के द्वारा मूलभूत सुविधाओं का संयोजन नहीं किया गया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसका अविलम्ब प्रबन्ध करे। मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र

के बहुत बड़े हिस्से में अस्सी घाट से संतरविदास घाट तक, सामने घाट और राम नगर में माँ गंगा के तट पर घाट का निर्माण नहीं हुआ है, कटान के कारण आवासीय कॉलोनियाँ खतरे में हैं। मान्यवर, रामनगर में हमारे पूजनीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर एक घाट बनने की आवश्यकता है। मान्यवर, 2012 में दो गहरी सीवर लाइन स्वीकृत हुई थी, बिरदोपुर से रथयात्रा और विनायका से कमच्छा, उसका कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप करें।

श्री सौरभ श्रीवास्तव-

मान्यवर, भिखारीपुर तिराहे से चितईपुर चौराहे तक गहरी सीवर लाइन परियोजना की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा समग्र विकास की योजनाओं में लिंग, धर्म, रूप, रंग के भेदभाव के कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलम्बन पर गरीब, पीड़ित, दलित, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा पर सरकार द्वारा प्रशंसनीय कदम उठाये जा रहे हैं। अन्त में मान्यवर, मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि सरकार के इस बहुआयामी प्रयास से हमारा उत्तर प्रदेश निःसंदेह एक मजबूत, सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनकर देश और विदेश में अपना परचम लहरायेगा। जय भारत जय उत्तर प्रदेश।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय,

चौ0 उदयभान सिंह-

अपनी भाषा बोलना।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

यस, पक्का माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ी देर कर दी, बुलाते-बुलाते, बहुत देर से पाइप लाइन में था। मान्यवर, दौर साधुवाद का चल पड़ा है, उधर से जितनी वाणी के बाण चल रहे हैं, उधर से बोला गया कि फलाने मंत्री जी को साधुवाद, फलाने मंत्री जी को धन्यवाद। इधर से नेता विरोधी दल द्वारा और बहुजन समाज पाटी द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव है, उस पर बल देने के लिए बाण चल रहे हैं, मैं भी अधिष्ठाता महोदय संशोधन के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं वाणी से, हृदय से, नाभि से आपका साधुवाद करता हूँ। बजट के बारे में सभी लोगों ने कहा कि बजट जो है वह पहली बार हिस्ट्री में पेपरलेस है। इसके लिए तो हम कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू कान्ग्रेचुलेट, लेकिन पेपरलेस बजट जरूर है इससे पहला बजट, उससे पहला बजट, पहली सरकारों के बजट क्या किसी में कोई मद चेंज हुई है। रत्ती भर भी किसी बजट में कोई मद चेंज नहीं हुई है, केवल मदों का रि-एप्रोप्रिएशन है। कल मैं पंकज जी का भाषण सुन रहा था तो कह रहे थे कि योगी जी का योग। सब मद एक ही जैसे हैं तो तीन बीसी साठ का योग साठ, माननीय मंत्री जी थ्री इन-टू

बीस साठ और बीस इन-टू थ्री यानी बीस तियां साठ, सबका योग बराबर है, टोटल का योग बराबर है। तो आलोचना हमारा मकसद नहीं है, आलोचना न मकसद है, न टारगेट है, न गोल है, न संकल्प है, बल्कि समालोचना हमारी प्रतिबद्धता है। समालोचना के चिन्तन और मन्थन के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं और जब समालोचनात्मक चिन्तन और मन्थन हम यहाँ कर रहे हैं तो उसमें ऐसा न समझ लेना, खास तौर से सरकार का पक्ष कि बोले तो बगावत और चुप रहे तो फिर कयामत। ऐसा मत समझना। आज हम सारी चीजों पर इसलिए बात रखना चाहते हैं कि "रामराज्य" पर बड़ी देर से भाषण हो रहा है। "रामराज्य" में ही रहकर। हमारी मोना जी चली गयीं, कोई भूखा न रहे, नंगा न रहे, प्यासा न रहे। रात के 12:00 बजे हमारी बहन-बेटियां अगर कहीं जाएं तो उन्हें कोई खतरा न हो। हमारी उधर की बहन-बेटी कह रही थी कि पुराने जमाने में ये था, उससे पहले जमाने में ये था और अब योगी जी की सरकार के में ये है। हम पुराने पापों को झेलते-झेलते यहाँ आ गये और तुम कहां जाओगे ? अभी विधायक जी कह रहे थे कि अबकी बार उधर जाएंगे, उधर के बाद फिर इधर आएंगे, भगवान जाने, तुम कहाँ जाओगे ? यहाँ भी रहोगे कि बाहर जाओगे, यह भी पता नहीं है।

"रामराज्य" की परिभाषा को समझो। भगवान "राम" मर्यादा पुरुषोत्तम थे और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि उन्होंने कभी भी राज्य का उपभोग नहीं किया। आप तो कभी-कभी तो नारा देते हो कि "जो हिन्दू की बात करेगा, वह दिल्ली पर राज करेगा", ऐसा कहते हो। भगवान "राम" बनवास से लेकर सीता जी के गबन से लेकर कभी भी एक सेकन्ड राज का भोग नहीं किया। तुलसीदास जी ने कहा है कि "नाहि न राम, राज के भूखे" और ये राज्य के भूखे हैं, आज यह दुर्भाग्य है। भगवान "राम" की कुछ मर्यादा भी समझो। अगर मर्यादा नहीं समझोगे, तो दिक्कत हो जायेगी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यहाँ थोड़ी देर पहले श्री फतेह बहादुर जी बैठे थे (सदन में हंसी)।

अधिष्ठाता महोदय, हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारी "ऊधौ की सी पाती" उन्हें पहुँचा देना। इसलिए पहुँचा देना कि मैं और मेरे पिता जी वीर बहादुर जी के बहुत नजदीक रहते थे। मैं स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि टूटे-फूटे शब्दों से श्रद्धांजलि। महोदय, मेरे अन्दर श्रद्धांजलि की अटूट श्रद्धा है जो कहूँगा, सच कहूँगा और सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं वही कहूँगा जो वीर बहादुर सिंह जी बोला करते थे।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, वह कभी भी जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, गोत्रवाद और संकीर्णतावाद इन सबसे ऊपर उठकर बात करते थे। राजनीति में जातिवाद और धर्मवाद का कोई स्थान नहीं है। क्यों न हम लोग ममता और समता से इस सारी लक्ष्मण रेखा को तोड़ करके एक प्रेम और स्नेह की राजनीति शुरू करें। इसलिए मैंने कहा कि श्री फतेह बहादुर जी यहाँ बैठ करके कह रहे थे कि हमारी चीनी मिल बाबा ने चला दिया। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी चला दी। हम कैसे दुर्भाग्यशाली हैं, हमारे चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह जी चले गये, इन्ही के क्षेत्र का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जितनी बार चुनाव में गये उतनी बार अपनी वाणी से शंखनाद किया कि अबकी बार छाता चीनी मिल जरूर चलेगी। कितनी बार झूठ बोलोगे। आपकी गोरखपुर की चीनी मिल गयी आप साधुवाद दे रहे हैं, हमारी नहीं चली तो हम क्या कहें, यह बताइये ?

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

हम क्या कहें ? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार में इतनी हेरा-फेरी मैंने कभी नहीं देखी।

कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

आप भरोसा रखें, अगली बार जब आयेंगे तो आपका सपना जरूर पूरा होगा।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

अभी शिक्षा मित्र के बारे में बात हो रही थी कि चिंता मत करिये अगली बार जब आयेंगे तो ये हो जायेगा, वो हो जायेगा। तो न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। समुद्र के मन्थन के बाद जो अमृत निकला और बाँटने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु को मिली, भगवान विष्णु ने कहा अमृत बँटेगा, मात्र देवताओं में बँटेगा। (हंसी)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य समाप्त करिये।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

भगवान विष्णु से भी ज्यादा हेरा-फेरी यह सरकार कर रही है। उधर 05 करोड़ रुपया मिला, इधर (विपक्ष की तरफ) अंडा, उधर पूरे 05 करोड़। (हंसी) हम इसलिए कह रहे है कि इतना हेरा-फेरी बन्द करो। आप सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हो, तो आप हमारा भी विश्वास अर्जित करो हम छाती पीट-पीट कर कहते हैं कि हम 24 करोड़ जनता का हिस्सा हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

अब ऐसा अनर्थ, अन्याय मत करो। आप कह रहे हो कि यमुना एक्सप्रेस-वे चलाया, एक्स्प्रेस-वे बनाया तो बहिन कु0 मायावती जो ने बनाया, आपने बनाया ? (सत्तापक्ष के किसी सदस्य द्वारा टोका-टाकी करने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया मेरी तरफ सम्बोधन करें।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

गंगा एक्सप्रेस-वे बना रहे हैं, फलॉना बना रहे हैं। यह तो हम जानते हैं कि खरबूजे को देखकर, खरबूजा रंग बदलता है। बहिन कु0 मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेस-वे बना दिया

तो अखिलेश जी ने बनाया, अखिलेश जी ने बनाया तो आप भी बना रहे हो। आपने डेट ऑफ स्टार्टिंग तो दे दिया, लेकिन कम्प्लीशन की कोई डेट नहीं दी है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि कम्प्लीशन की डेट है।) कम्प्लीशन की कोई डेट नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त कर दें।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, आप भी बोले थे।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आपको निर्देश दिया समाप्त करने का, अब कृपया समाप्त कर दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

जितना समय आपने लिया था, उतना समय तो दे दीजिए।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

जो यमुना एक्सप्रेस-वे बना, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। आज भी सबसे सस्ता टोल-टैक्स वहाँ पर है। अखिलेश जी को साधुवाद कि उन्होंने 100 नं0 चला दिया, 100 नम्बर दबाओ पुलिस हाजिर और 100 रुपये का नोट दे दो, पुलिस गायब.....

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

अब नम्बर हो गया 100 से 112 और पुलिस का रेट क्या हो गया जरा पता कर लेना।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

अब आपका आदेश है। डिस्ओबिडिऐंसी जीवन में कभी की नहीं है मैंने, न कभी करूँगा लेकिन आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि जो हम लोग कह रहे हैं यूनीवर्सल तरीके से सारी चीजों को ले करके अगर हमारा शीश नवाना कबूल कर सकते हैं, सरकार मान सके। जो दे उसका भला, जो न दे उसका भी भला।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात बजट के समय रख लें। विभागवार चर्चा होगी उस समय।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

बजट में जब हमको कुछ देंगे ही नहीं तो उसे रखने से फायदा क्या। धन्यवाद।

श्रीमती नीलम करवरिया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देती हूँ साथ ही साथ मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्री खन्ना जी ने आम जनता को सुविधा और उसके विकास की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2021-22 का जो बजट प्रस्तुत किया है उसे यदि गरीबों और किसानों को विकास की दो कतारों से जोड़ने वाला बजट कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय अधिष्ठाता जी विपक्षी पार्टी के नेताओं का भी मन बजट की सराहना करने का जरूर हो रहा होगा, किन्तु सत्ता पक्ष का विरोध करने की मजबूरी उन्हें विपरीत दिशा में बोलने पर मजबूर कर रही है। वर्ष 2022 में विधान सभा के चुनाव होने हैं, किन्तु माननीय खन्ना जी ने चुनाव नहीं बल्कि प्रदेश के विकास को बढ़ाने वाला बजट प्रस्तुत किया है इसके लिये वे विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। विकास रथ के पथ पर उत्तर प्रदेश को जो तीव्र गति मिली है वह एक योगी के ही कर्मों का नतीजा है। माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रदेश के विकास, प्रदेश की जनता का विकास, बेरोजगारी समाप्त करने का संकल्प, महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके लिये सक्षम सुपोषण व सामर्थ्य योजना, असंगठित श्रमिकों के लिये मुख्य मंत्री दुघर्टना बीमा योजना, किसानों के लिये आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। हर मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय 2024 तक, हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल, सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करना आदि योजनाओं से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र भी आता है। वैसे हर किसान को टेल तक पानी मिल रहा है, लेकिन यदि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गुलरिया बाँध को अगर बाज सागर परियोजना से जोड़ दिया जायेगा तो किसानों को और भी राहत मिलेगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, किसी भी शहर, प्रदेश और देश की पहचान तथा विकास के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत अहम होता है। जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाकर सम्पूर्ण देश में आवागमन सुलभ किया जा रहा है उससे विकास के पहियों की रफ्तार बढ़ी है। मैं इस बजट में अपने क्षेत्र में गंगा नदी के पुल के ऊपर एक पक्के पुल के निर्माण का सुझाव देना चाहूँगी जिससे जो दो नेशनल हाई-वे आपस में जुड़ जायेंगे और मालवाहक वाहन या फिर प्राइवेट इस्तेमाल के वाहनों को कम से कम 50-60 कि0मी0 का चक्कर लगाने से बचाया जा सकता है और प्रतिवर्ष होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आ जायेगी, क्योंकि बरसात के मौसम में पैन्टून पुल टूट जाता है जिससे आवागमन बाधित हो जाता है। अगर यह पुल गंगा नदी में बन जायेगा तो आम जनमानस के साथ-साथ मेरी विधान सभा के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, इसके साथ साथ व्यापार की दृष्टि से भी इस पुल का निर्माण आवश्यक है। क्योंकि इसी के करीब एन0एच0-27 भी है जोकि प्रयागराज को

मध्य प्रदेश से भी पर जोड़ता है। एन0एच0-76 ई एवं एन0एच0-2 के मध्य गंगा नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। वैसे तो माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने तथा उत्तर प्रदेश के उप मुख्य मंत्री श्री केशव जी ने इस वर्ष पुल का निर्माण कराये जाने का आश्वासन मुझे दिया है, किन्तु मैं चाहती हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पुलों और सड़कों के, लिये जो बजट दिया है उस बजट में गंगा नदी का पुल बनवाने हेतु विशेष प्राविधान कराने का कष्ट करेंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 वित्त मंत्री जी को एक और सुझाव देना चाहती हूँ, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से संयुक्त परिवार समाप्त हो रहे हैं। इस कारण से संयुक्त जमीन जो खेती योग्य है या जिस पर मकान बने हुए हैं, के बंटवारे को लेकर परिवार के सदस्यों में आपस में झगड़े तथा दीवानी के मुकदमे अत्यधिक बढ़ रहे है। तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार के कोर्ट में दाखिल वाद के समय पर निस्तारित करने हेतु या तो उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देश दिया जाए या इसके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कराकर आपसी विवाद की सम्पत्ति को लेकर दर्ज हो रहे मुकदमों पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मा0 मुख्य मंत्री जी का कथन है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेन्स को आकार किया जा सकेगा तथा मुकदमों के बहाने तहसील तथा थानों में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। "निकलता है रोज सूरज यह बताने के लिए कि उजाले बांट देने से रोशनी कम नहीं होती है"। मैं मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी तथा मा0 वित्त मंत्री जी को और प्रदेश की नयी विकास की तरफ जाने वाले "सभी का साथ, सभी का विकास" बजट में प्राविधान का बजट प्रस्तुत करने हेतु हृदय से आभार देती हूँ। जय हिन्द, जय भारत, जय श्रीराम।

श्री पूरन प्रकाश-

बोलो गिरिराज महाराज की जय। बोलो श्री दाऊजी महाराज की जय। राधे-राधे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के बजट समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर दिया वैसे तो मुझे 20 वर्षों से सदन में बोलने का अवसर आपसे मिलता रहा है, लेकिन फिर भी मैं आज आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा 17वीं विधान सभा में यह पांचवां बजट जोकि लगभग 5 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का बजट पेश किया गया है तथा प्रदेश की 24 करोड़ जनता की अपेक्षाओं का भरपूर बजट है। अगर इस बजट की उपलब्धियों का क्रमवार वर्णन करें तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। प्रदेश के आखिरी छोर पर निवास कर रहे अन्त्योदय की प्रतीक्षा में जन-जन तक पहुंचाने वाला विकास का यह बजट है। बजट में बिना किसी भेदभाव के गरीब, किसान, कामगार, बेरोजगार, व्यापारी, श्रमिक, शिक्षक, बिजली, पेयजल, सड़क, रोड से लेकर प्रदेश की सेवा में लगे प्रहरी से लेकर हर तबके के लोगों का जीवन स्तर उठाने का समावेश बजट में है। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी एवं प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति के सर्वोच्च शिखर की ओर अग्रसित है। देश-दुनियां को वर्ष 2020

कोविड-19, कोरोना ने हिलाकर रख दिया था, परन्तु हमारी केन्द्र और प्रदेश की सरकार के कुशल नेतृत्व में कोरोना योद्धाओं ने देश-प्रदेश की 135 करोड़ जनता ने जो धैर्य का परिचय दिया, आज पूरा विश्व आश्चर्यचकित है कि कोरोना जैसी महामारी को भारत ने और उत्तर प्रदेश ने समाप्त करने की ओर अग्रणी भूमिका निभायी है। यद्यपि इस विपत्ति में सेवा में लगे योद्धाओं ने अपनी जान की चिन्ता न करके दूसरों के लिए समर्पण भावना से अपनी जानें गंवाई एवं जो अन्य कोरोना से भगवान को प्यारे हो गये, उनको भी मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस कार्य में आप सब लोग जो सदन में बैठे हैं चाहे इधर के हों या उधर के हों, मा0 विधायकगणों द्वारा भी अपनी विधायक निधि के साथ-साथ अपने एक वर्ष का वेतन देकर इस कोरोना जैसी महामारी में योगदान प्रदान किया। आप सभी इस बधाई के पात्र हैं। प्रदेश के चहुमुखी विकास में समय-समय पर योजनायें एवं कानून बनाकर जनहित में जो निर्णय लिये गये है, जैसे कि जम्मू-कश्मीर का भारत से पूर्ण एकीकरण, नागरिकता संशोधन अधिनियम सी0ए0ए0, समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, राम मन्दिर का निर्माण कराना, बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना, दुराचार से सुरक्षा का कानून बनाना।

किसानों की आमदनी दोगुना करना आदि ठोस कदम उठाए हैं। मुख्य मंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत मिशन मनरेगा योजना, हर एक को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना ग्रामीण अंचल और नगरों में सड़कों का जाल बिछाना, नव निर्माण कराना 20-20 साल तक सड़कों की मरम्मत नहीं होती थी उनको विशेष अभियान चलाकर उनकी मरम्मत कराना सड़कों का नव निर्माण कराना, निर्धन कन्याओं की शादी में 51-51 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान करना, किसानों के खाते में छह-छह हजार पहुँचाना इस सरकार की उपलब्धियाँ हैं। मान्यवर, आजादी के बाद पहली बार शहर, कस्बों, गांवों में अनवरत् बिजली सप्लाई देना, खेतों तक निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देना, कृषि क्षेत्र में किसानों का ख्याल रखना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन, यापन करने वाले नागरिकों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, गैस चूल्हे देना, महिलाओं को सम्मान देना, आवास देना रोजगार देना यह सब सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। बालू माफिया, भू-माफिया, मिट्टी माफिया, बदमाश, उचक्के, लफंगे प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। जो जेलों मे पड़े हैं वह जेलों से अपनी जमानत नहीं करा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप में कहें।

श्री पूरन प्रकाश-

उन्हें पता है कि अब कानून का राज है अगर नहीं सुधरेंगे तो चटका दिए जाएंगे। मान्यवर, अब मैं अपनी बात भी रखना चाहता हूँ। वैसे तो प्रदेश में हमारे ब्रज का भगवान की लीलाओं का विशेष पहचान है। आप सभी कभी जब विचलित महसूस करें तो मेरा दावा है कि अपने परिवार के साथ मथुरा, वृंदावन, गोकुल, दाऊजी गोवर्धन, बरसाना नन्दगांव, द्वारिकाधीन के दर्शन करके सभी दुख दर्द भगवान हरण कर लेंगे। मैं आप सबको आमंत्रण करता हूँ और साथ ही मथुरा-वृंदावन में चल रहे अर्द्धकुम्भ में पधारने का निवेदन करता हूँ।

आपके माध्यम से मैं यह अपील कर रहा हूँ कि अपने क्षेत्र दाऊजी बलदेव में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ महाराज का विशाल मंदिर है और भगवान बलदाऊ का शस्त्र भी हल है जोकि अन्नदाता किसानों का सबसे बड़ा हथियार भी हल ही है। हमारे क्षेत्र बलदेव में बलदाऊ महाराज का भव्य मंदिर है। इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस-वे गुजरता है इस एक्सप्रेस-वे पर चढ़ने-उतरने का कोई कट न होने के कारण 40 कि0मी0 दूर राया से होकर या आगरा से होकर बलदेव पहुँचना पड़ता है। अतः यहाँ एक्सप्रेस-वे पर एक कट बनवाने की मांग करता हूँ।

हमारे क्षेत्र में राया नगर पंचायत सबसे बड़ी पंचायत है इसकी आबादी 30 हजार से अधिक है लाखों छोटे-बड़े वाहनों से अलीगढ़, हाथरस, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, कासगंज और अन्य जनपदों को राया बाजार के बीच सड़क से गुजरते हैं। जिसके कारण हर समय चार-चार घंटे जाम लगा रहता है। अतः राया में बाईपास निर्माण की मांग करता हूँ साथ ही बलदेव में जो श्रद्धालु पर्यटक आते हैं उनको रात्रि विश्राम एवं रुकने के अभाव में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः बलदेव में एक रात्रि विश्राम ठहराव के लिए बड़े-बड़े हालों का निर्माण कराने का कष्ट करें। वैसे तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बृज तीर्थ विकास परिषद् जिसके मा0 मुख्य मंत्री जी अध्यक्ष है, के द्वारा ब्रज में जनपद मथुरा में काफी विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री पूरन प्रकाश-

हमारे क्षेत्र बलदेव व जनपद मथुरा में भारी तादात में किसान आलू का उत्पादन करते हैं तथा बड़ी अच्छी क्वालिटी का आलू पैदा होता है। इसको बेचने हेतु किसानों को बाहर जाना पड़ता है। बहुत अच्छा होगा कि अगर सरकार आलू से बनने वाले चिप्स या एल्कोहल, बीयर शराब की फैक्ट्री कारखाना स्थापित करवा दे जिससे किसानों को आलू की समुचित कीमत मिल सके तथा लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही साथ हमारे जनपद मथुरा में छाता में स्थित सरकारी चीनी मिल जो बन्द पड़ी है उसको भी चालू कराने की मांग करता हूँ। बांके बिहारी भगवान से मेरी प्रार्थना है कि इस सदन में चाहे इधर चाहे उधर सभी सदस्य बैठे हैं पीठ पर आप भी बैठे हैं आप सभी पुनः 2022 में चुनकर आवें और इससे भी बड़ा प्रदेश का बजट पास करें। शायद आप सभी मेरे ख्याल से सहमत होंगे। कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं पुनः इस सदन में न आऊँ चाहे संख्या इधर की हो उधर की हो ऐसे ही बनी रहे।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद। मा0 सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अब आप समाप्त करें।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, अभी वैसे तो कुछ मामले रह गये हैं, लेकिन आज आपका आदेश सर्वोपरि है। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि सत्रहवीं विधान सभा का हमारा यह पाँचवाँ

और आखिरी बजट है और इस बजट में पाँच साल से चाहे इधर के चाहे हम इधर के लोग जो अपनी बातें रखते हैं, निश्चित तौर पर वह प्रदेश की जनता तक पहुँचता है, क्षेत्र में पहुँचता है। आप सभी लोगों का इतना सहयोग मिला और मुझे अपने क्षेत्र की, अपने जनपद की बात रखने का मौका मिला। सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उसमें कोई भी बात छिपायी नहीं गयी है। मेरे ख्याल से यह सर्वोपरि और सर्वोच्च बजट है। पिछले 20 सालों में मैंने इतना भारी-भरकम बजट शायद ही देखा हो जिसमें हर तबके का ध्यान रखा गया हो। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

श्री मसूद अख्तर।

***श्री मसूद अख्तर-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जिस तरह से मा0 वित्त मंत्री जी ने बहुत भारी-भरकम बजट पेश करने का काम किया तो हमें लगा था कि पूरे उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिये इसमें योजनाएं दी होंगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर से सहारनपुर मण्डल और सहारनपुर मण्डल में भी सहारनपुर जनपद में कोई नयी योजना देने का काम नहीं किया गया है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में वुड कार्विंग का नाम लिया जाये तो वुड कार्विंग में जनपद सहारनपुर नम्बर एक पर आता है। सरकार ने "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट" का नारा दिया, लेकिन जनपद सहारनपुर में आज तक वुडेन क्लस्टर बनाने का कोई काम नहीं किया गया, इस क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किया गया, इससे बहुत सारे रोजगार सृजित हो सकते थे। सहारनपुर में वुडेन क्लस्टर बनाने की मांग बहुत दिनों से चल रही थी, वह करने का काम नहीं किया गया। मान्यवर, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान भाई पापुलर की खेती करते हैं और चूंकि सहारनपुर हरियाणा के बार्डर पर है तो वुड कार्विंग तथा वुड प्लाईबोर्ड की सारी फैक्ट्रियां हरियाणा में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा किसान जो पापुलर की खेती करता है उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिये बहुत दिनों से यह मांग थी कि जनपद सहारनपुर में प्लाईबोर्ड की फैक्ट्रियाँ लगें और यह हुआ भी और सरकार ने लाइसेंस देने का काम भी किया, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वह लाइसेंस निरस्त कर दिये गये और सहारनपुर में आज तक प्लाईबोर्ड की एक भी फैक्ट्री लगने का काम नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जनपद सहारनपुर में प्लाईबोर्ड फैक्ट्री के जो लाइसेंस दिये गये थे उनको दोबारा से बहाल किया जाये और वहाँ पर फैक्ट्री लगने का काम हो जिससे किसानों को उसका फायदा मिल सके। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार किसानों की बात करती है। हम लोग भी 04 साल से सुनते आ रहे हैं कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन वह मंत्र आज तक हमें नहीं पता लगा है कि वह कौन सा मंत्र है जिससे किसानों की आय दोगुना होगी। आज उनकी आय घट करके बहुत नीचे पहुँच

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी है। पूरे देश में 50 परसेंट गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन गन्ने का दाम एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया है उसके उलट डीजल, पेट्रोल और दूसरे उर्वरकों के रेट बेतहाशा बढ़ने की वजह से किसानों की आय घटने का काम हुआ है और यहाँ का किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो चुका है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में अभी उधर से बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल की गयी है। मैं जनपद सहारनपुर के मेरे क्षेत्र के ही दो उदाहरण देता हूँ। राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज, देवला में आज तक बाउण्ड्रीवॉल नहीं है। इसी तरह से राजकीय इण्टर कॉलेज, गागलहेड़ी में आज तक बाउण्ड्रीवॉल नहीं है और जो बात करते हैं शिक्षा की, खूब पढ़ें खूब आगे बढ़ें, यह संकल्प सरकार का है, लेकिन अभी तक मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ अभी भी बच्चों को नीचे टाट पर बैठकर पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, बिजली की बात करें तो हमारे जनपद सहारनपुर में या पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सी कालोनियाँ हैं जो दस-दस साल से विकसित हैं, लेकिन वहां पर आज भी बिजली उपलब्ध नहीं है। सरकार का यह दावा कि हर घर में रोशनी होगी, पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। वहां पर अधिकारियों द्वारा यह कह दिया जाता है कि यह कालोनियाँ नियमित नहीं हैं इसलिए इनमें बिजली नहीं पहुंचायी जा सकती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस तरह का बजट उन कालोनियों को दिया जाय जिससे सरकार का वह दावा घर-घर में रोशनी होगी, पूरा हो सके। आखिर में मैं एक दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य के मामले में सरकार ने बड़ी-बड़ी बातें करी है। हमारे जनपद सहारनपुर में मेडिकल कालेज है जिसको शुरू हुए पाँच साल हो गये हैं लेकिन आज भी वहाँ पर कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। वहाँ पर ट्रॉमा सेन्टर आज भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। मेरी मांग है कि मेडिकल कॉलेज में जो मूलभूत सुविधायें होनी चाहिए वह वहाँ पर जल्द से जल्द की जायें और पिछली सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने मा0 अखिलेश यादव जी ने यह घोषणा की थी कि मुजफ्फरनगर से मेडिकल कॉलेज तक फोरलेन देने का काम किया जायेगा, लेकिन अभी तक वहाँ पर फोरलेन बनने का काम नहीं किया गया है। आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि मुजफ्फरनगर से मेडिकल कॉलेज तक फोरलेन बनाया जाय जिससे बाहर से आने वाले लोगों को उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा हमारे जनपद सहारनपुर में पानी बहुत प्रदूषित है जिसके कारण गांवों में बीमारियाँ फैलती रहती हैं, लेकिन उसके उलट सरकार ने हमारे हैण्डपम्प भी बन्द कर दिए हैं। जल जीवन मिशन के तहत टंकियाँ बनाने का काम कहते तो हैं लेकिन जमीन उपलब्ध न होने के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो सका है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गरीबों को दुबारा हैण्डपम्प दिए जायें जिससे गरीब लोग जो पैसे न होने के कारण हैण्डपम्प नहीं लगवा सकते हैं उनको राहत मिल सके। आखिर में अपने क्षेत्र की दो-तीन समस्याओं को कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मान्यवर, गागलहेड़ी को नगर पंचायत का दर्जा देने की मैं आपसे अनुरोध

करता हूँ और मैं एक चीज के लिए सरकार की सराहना करता हूँ कि हमारे जनपद सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय देने का काम किया है इसी के साथ-साथ मैं एक मांग आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, चूँकि यह विश्वविद्यालय शहर से 10 किमी0 दूर है इसलिए शहर से वहां तक 10 किमी का फोरलेन बनाया जाय और उसको दिल्ली साकुम्बमरी हाई-वे से भी जोड़ा जाय ताकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर से आने वाले लोगों को समुचित लाभ मिल सके। इसके अलावा सहारनपुर मेडिकल कालेज तक फोरलेन बनाया जाय और जो विश्वविद्यालय सरकार ने दिया है वहां तक फोरलेन बनाने का काम भी किया जाय, नागादेव का पुल भी बनाया जाए, शहजमाजरा के सामने जो देहरादून पंचकुला मार्ग है उस पर फ्लाईओवर बनाने का काम किया जाय। इसी के साथ मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिन्द जय उत्तर प्रदेश।

***श्रीमती लीना तिवारी-**

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया है इस पेपरलेस बजट के समर्थन के लिए मैं अपनी पार्टी अपना दल की तरफ से मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है इसके लिए मैं तहे दिल से अभारी हूँ। अधिष्ठाता महोदय, यदि जन सेवा ही एक मात्र जुनून हो जाय तो कुछ भी मुश्किल नहीं। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट इतना आसान नहीं था जहां एक और पूरी दुनिंया वैश्विक महामारी से ठीक से उभरी भी नहीं है, सरकार के सामने तमाम चुनौतियाँ थीं ऐसे में सुव्यवस्थित और सर्वजन हिताय के तट पर बजट लाना सहज कार्य नहीं था। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत करके यह स्पष्ट कर दिया कि यदि वाकई आप सेवा भावना के साथ सामने आए तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। इस विषय पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व0 श्री अटल जी की एक पंक्ति याद आती है- छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हमारी सरकार ने श्रमिक, मजदूर, किसान, ग्रामीण, असहायों, महिलाओं, युवाओं और उद्यमियों के लिए जो दरियादिली दिखाई है वह वाकई काबिले तारीफ है मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देना चाहती हूँ। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने सभी विधायकों को टैब दिया इसमें यह नहीं देखा गया कि पक्ष और विपक्ष कौन है सभी को यह समान रूप से सुविधा मिली। सरकार ने डिजिटल इण्डिया का जो नारा दिया था उसे सदन में चरितार्थ करके दिखा दिया। कोई भी मिशन तभी सफल होता है जब उसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक हो, हमारी सरकार कहने पर नहीं करने पर विश्वास रखती है। इस बजट के द्वारा राज्य की श्रम विभाग में पंजीकृत लगभग 20 लाख श्रमिकों को प्रत्येक श्रमिको को एक-एक हजार भरण-पोषण सहायता के लिए दो किस्तों में दी गयी। इसके अतिरिक्त जो असहाय लोग थे उन्हें एक हजार रुपये भरण-पोषण सहायता दी गयी कुल 54 हजार लोगों को भरण-पोषण सहायता दी गयी। मैं देश के वैज्ञानिकों को आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत कम समय में ही कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर दी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज हमारे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 125 और निजी क्षेत्र में 104 लैब किग्रान्वित हैं। कोविड-19 की जांच क्षमता शून्य से बढ़कर अब 2 लाख प्रति दिन हो गयी है। कोरोनाकाल के समय अधिष्ठाता महोदय मैं बताना चाहूंगी कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मडियाहूँ में लगभग 26 हजार प्रवासी मजदूर लौटे जिसके रहने-खाने और रोजगार के लिए हर सम्भव प्रयास हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा किया गया। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने किसानों की समृद्धि और उनकी आय को बढ़ाने के क्षेत्र में कार्य करते हुए विभिन्न योजनायें लागू कीं जिससे आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना और मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना जोकि बहुत ही सराहनीय कार्य है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे गर्व है कि मैं एक महिला हूँ और मेरी सारी बहनें जो यहां पर बैठी हुई हैं वह भी गर्वित होंगी कि यह एक सम्मानित विधायक होने के साथ-साथ एक गृहणी भी हैं और यदि घर की गृहणी शिक्षित हो तो पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि प्रदेश सरकार द्वारा क्रियाशील कन्या सुमंगला योजना इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। मिशन शक्ति दृढ़ता से लागू किये जाने पर अवश्य ही नारी सुरक्षा के लिए सराहनीय कार्य होगा। हमारी सरकार ने युवाओं का पूरा ख्याल रखा है। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन द्वारा चार वर्षों में सात लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। आदरणीय मुख्य मंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। हमारी सरकार ने पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया है। जिससे निश्चित रूप से भविष्य में आगन्तुकों की संख्या में इजाफा होगा। उत्तर प्रदेश में संस्कृति और धर्मार्थ कार्य के लिए भी असाधारण कार्य किये हैं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जिस संस्कृत ने हमें जीना सिखाया जिसके संस्कार अपनाने मात्र से व्यक्ति नर से नारायण हो जाता है जिसके स्मरण मात्र से हमारे सारे संकट कट जाते हैं ऐसे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धाम तक पहुंचने के मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था के विषय में मैं कहना चाहूंगी-

"इन्साफ मांगने निकला था तुम्हारे जख्मों का
पर इस शहर में हर कोई तुम्हारा आशिक निकला,
अब जो आलम है हैवानों और कातिलों को मजहब से न जोड़ा जाये,
मुजरिम जो भी हो उसे किसी कीमत पर न छोड़ा जाये।"

न्याय प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले यह सरकार की जिम्मेदारी भी है। इसे ध्यान में रखते हुए जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया जाना एक अत्यन्त ही सराहनीय कार्य है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह मेरा सौभाग्य है और आप सभी का आशीर्वाद है कि मडियाहूँ विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए मैंने जो भी संकल्प लिये थे वह सब पूरे हो रहे हैं। मेरे चुनावी घोषणा-पत्र के अनुसार मड़ियाहूं के सभी कार्यों की स्वीकृति मिली है। मैं इस विषय पर एक चीज कहना चाहूंगी "प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू" आदरणीय

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी और आदरणीय संबंधित मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बस स्टैण्ड की बहुत जरूरत है इसलिये आप इस कार्य पर कृपा दृष्टि जरूर बनायें। अन्त में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" के मार्ग पर अग्रसर है और आगे भी रहेगी। महान क्रान्तिकारी पं0 चन्द्रशेखर आजाद जी के विषय में दो शब्द बोलकर मैं अपनी बात पूरी करना चाहती हूँ-

"शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भू का है,
जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है,
जिनके जीवन के दर्शन में हिम्मत को परिभाषा दी,
जिसने पिस्टल की गोली ने इन्कलाब को भाषा दी,
जिनकी यशगाथा भारत के घर-घर में नभचुम्बी है,
जिनकी बेहद अल्प आयु भी कई युगों से लम्बी है।"

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री बजरंग बहादुर सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट पर चर्चा पर भाग लेने के लिए मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इस सदन के अन्दर उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जी ने एक समावेशी और शानदार बजट प्रस्तुत किया है जिसके समर्थन में बोलने के लिए मैं सदन में खड़ा हुआ हूँ। इस बजट के माध्यम से हमारे वित्त मंत्री जी ने पूरे प्रदेश की जनता को यह संदेश देने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश का विकास है, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में इस प्रदेश का किसान है, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश का नौजवान है, उत्तर प्रदेश का गरीब और इस सब चीजों पर सरकार ने फोकस किया है और इसी नाते बजट का आकार भी बड़ा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को वर्ष 2017 में किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 2017 से पहले पूरे पांच साल से उत्तर प्रदेश की जनता कराह रही थी, उत्तर प्रदेश का नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा था, उत्तर प्रदेश का किसान मर्माहत था और इस नाते जब उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 का आम चुनाव आया तो इस उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ऐसा संदेश दिया जिससे राजनीतिक दलों को विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अधिष्ठाता महोदय, सिर्फ मेरे प्रयासों से नहीं उधर विपक्ष में बैठे हुए हमारे साथियों के कुकृत्यों के नाते भी उत्तर प्रदेश की जनता ने कड़ा संदेश दिया और जब उत्तर प्रदेश में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसका नेतृत्व एक ऐसे मनीषी, एक ऐसे तपस्वी, एक ऐसे कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बागडोर मिली तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते समय अपनी नियती, अपनी सुस्पष्ट विचारधारा का संदेश उत्तर प्रदेश में दे दिया और इसी नाते जो कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गयी थी। उस कानून व्यवस्था को संभालने में भी योगी सरकार को सफलता मिली। साथ ही साथ प्रदेश में जो अराजकता थी, प्रदेश में जो भ्रष्टाचार था उस पर भी लगाम लगाने में निश्चित रूप से योगी सरकार सफल रही। आज योगी सरकार के काम करने के नाते उत्तर प्रदेश की जनता का परसेप्सन इतना शानदार धीर-धीरे बन रहा है कि जनता इस बात को महसूस करती है चाहे वह बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो इन दोनों सरकारों से अलग आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में इस प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश, इस प्रदेश को एक विकसित प्रदेश, उत्तर प्रदेश को एक उत्कृष्ट प्रदेश बनाने की दिशा में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी निरन्तर काम करते रहे हैं। किसी प्रदेश का मानक उस प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उस प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए। उस प्रदेश में जल की सुविधा होनी चाहिए।

उस प्रदेश में किसानों को ऊपर उठाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। इन तमाम विषयों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी नीति से पूरे समर्पित भाव से लगभग चार वर्षों से काम कर रही है। आज चार वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश का जो परिदृश्य बदला है, उत्तर प्रदेश में कानून का जो माहौल बना है, विकास की लम्बी रेखा खींचने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जो किया है आज वह दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को उत्तर प्रदेश का विकास नहीं दिखता है। प्रतिपक्ष के साथियों का अपना शासनकाल याद आता है, जिसमें हर चीज पर विपक्ष के साथियों का कर्जा था और इसी नाते जो गुण्डा राज था, उसके नाते उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें प्रचंड बहुमत से सफाया करने का काम निश्चित रूप से किया। आज उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार हर पहलू पर काम कर रही है। हम उदाहरण के तौर पर कहना चाहते हैं कि वर्ष 2014 में इस देश की जनता ने इस देश की बागडोर नरेन्द्र मोदी जी के हाथों में दिया और नरेन्द्र मोदी जी ने गद्दी संभालने के बाद जब देश भर के गरीबों के बारे में सोचने का काम किया तो उन्होंने वर्ष 2011 की सेक सूची के आधार पर निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री आवास सभी गरीबों को आए, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 से और वर्ष 2015 से जो योजनाएं शुरू हुईं उन्हें वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई जामा नहीं पहनाया। उत्तर प्रदेश का गरीब, उत्तर प्रदेश का किसान पक्के मकान के लिये तरस रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब वर्ष 2017 में योगी सरकार आई तो दो साल के अन्दर वर्ष 2011 की सेक सूची को समाप्त करते हुए 2019 पूरा होते-होते उत्तर प्रदेश की सेक सूची को समाप्त कर दिया। जब गांव में हल्ला मचने लगा कि अभी भी बहुत सारे गरीबों के आवास नहीं बने हैं। तो हमारे कर्मठ मुख्य मंत्री जी ने तुरन्त जिलाधिकारी जी को निर्देश दिया कि सभी ब्लाकों में, सभी गाँव में खुली बैठक कराकर पुनः गरीबों की सूची बनायी जाये और

उस सूची के आधार पर पुनः गरीबों को आवास दिया जाये। 2011 को सेक सूची समाप्त करने के बाद अब 2020 में पुनः एक भारी-भरकम सूची बनी और उसके आधार पर अभी एक महीना पहले हमारे देश के मा0 प्रधानमंत्री जी के हाथों उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए 06 लाख मकान का पैसा निर्गत करने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार का यह काम है। लगातार उत्तर प्रदेश में विकास का माहौल बन रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास हो रहा है। आप जानते हैं कि अभी एक वैश्विक बीमारी में जिस ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी रात-दिन निरन्तर काम करते रहे उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश इस वैश्विक बीमारी से बच पाया है। उसी समय जब हमारे प्रदेश के नागरिक दूसरे प्रदेशों से निकाले जा रहे थे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने दरियादिली दिखाकर गाजियाबाद की धरती से हमारे प्रवासियों को लाने का काम किया, हमारे प्रयागराज के कोटा में बहुत सारे नौजवान उस समय वहाँ थे उनको लाने काम किया। आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में एक विकास का माहौल बना है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी एक तपस्वी मुख्य मंत्री हैं। हर क्षेत्र में मुख्य मंत्री जी ने निश्चित रूप से प्रयास किया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। लगातार मा0 मुख्य मंत्री जी ने हर क्षेत्र में प्रयास किया है। इतनी ईमानदारी से प्रयास किया है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी यहाँ पर बैठे हैं, किसी गलत काम को लेकर मा0 मुख्यमंत्री जी के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कभी अपना पराया नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी से पूरे समर्पित भाव से पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कराने की दिशा में निरन्तर प्रयास किया है और इसी नाते मैं आज इस बजट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए नौजवानों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके उसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का जो माहौल बनाया है आज निश्चित रूप से हम सबके सामने वह दिखायी दे रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यह बहुत बड़ा बजट है। मा0 वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमने अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराया है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक विधायक होने के नाते जो हमारा दायित्व है लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार से आग्रह करना चाहिए। मैं वित्त राज्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। एक रनियापुर चौराहे से शिमरेहनी मार्ग है जिस मार्ग पर रेलवे लाइन क्रास की है। दोनों मार्ग के पास इधर-उधर काफी मात्रा में किसान रहते हैं जिनके पास बड़ी-बड़ी कम्पाइन मशीनें हैं, लेकिन वहाँ रेलवे द्वारा अन्डरपास बना दिया गया है। उस अन्डरपास में हर समय पानी रहता है उस पर फ्लाईओवर निर्माण कराने के लिए डिप्टी सी0एम मा0 केशव मौर्य

जी को मैंने लिखा था उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है। मैं एक बार फिर मा0 वित्त राज्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अत्यन्त उपयोगी परियोजना को बजट में सम्मिलित करने का प्रयास करें। आज के अवसर पर इतना ही कहते हुये बजट के समर्थन में बोलते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उमाशंकर सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी, नेता बहुजन समाज पार्टी आदरणीय श्री लाल जी वर्मा जी द्वारा वित्त मंत्री के रखे गये बजट भाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि बाद वाले समय में जब अपनी समस्याओं की बात आती है तो बड़ी हड़बड़ी हो जाती है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। मैं केवल इतना प्रकाश डालूँगा क्योंकि बहुत देर से बजट के आकार की चर्चा हो रही है। हम मानते हैं कि बजट का आकार वर्ष 2016 के बाद वर्ष 2021 में बढ़ा है, लेकिन हम पूर्वांचल से आते हैं और हम पूरी बुकलेट के बजट भाषण का सार निकाल कर बता दे रहे हैं कि वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश सरकार का 3 लाख 46 हजार 935 करोड़ रुपये का बजट था और आज हम वर्ष 2021-22 के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश सरकार का 05 लाख 22 हजार 270 करोड़ रुपये का बजट है। हम केवल एक विषय पर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से ट्रांसपरेंसी और किस तरह से मैन्यूक्यूलेशन किया जा सकता है। मैंने पिछले सत्र में भी मा0 वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए इंगित किया कि मा0 वित्त मंत्री जी जब आप नियोजन मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड को विशेष पैकेज दिया जाता था, उसकी राशि देख लीजिए। चूंकि बहुत पुराना हो जायेगा इसलिए हम उसमें नहीं जा सकते हैं, लेकिन आज हम यह चाह रहे हैं कि मा0 मंत्री जी ने कहा था कि उसे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको यह बात याद है तो मैंने कहा कि हाँ मुझे याद है। लेकिन वर्ष 2016-17 में पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के लिए विशेष पैकेज था वह आज भी वर्ष 2021-22 के बजट में है। बजट का आकार 45-50 प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन जो पूर्वांचल विकास निधि के लिए 300 करोड़ रुपया का बजट था वह आज भी वही 300 करोड़ रुपया ही है। उसमें एक प्रतिशत का भी इजाफा नहीं हुआ है। हम इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि हम विकास के लिए कितना गम्भीर हैं। जब बजट रखा जाता है तो वह किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जाता है, उसको दो भागों में बाटा जाता है। एक तो मा0 उप मुख्यमंत्री पी0डब्ल्यू0डी, के अधीन होता है, जिसको उत्तर प्रदेश राज्यांश कहते हैं और कमिश्नर निवर्तन पर होता है जिसको पूर्वांचल के सभी सम्मानित विधायक एवं एम0एल0सी0 अपनी विधान सभा में क्षेत्र का चयन करते हैं और उनको प्रस्तावित करते हैं, लेकिन उसमें एक प्रतिशत की भी बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। जब मा0 वित्त मंत्री जी सभी मा0 सदस्यों का जवाब देंगे तो इसका जरूर संज्ञान लेंगे। चूंकि हमें बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि हम बलिया जनपद से आते हैं, हमें लगता है कि आखिर में बलिया का दुर्भाग्य क्या है। बलिया का दुर्भाग्य यह हो सकता है कि बलिया से ही नेता प्रतिपक्ष हैं,

बहुजन समाज पार्टी के उपनेता मैं हूँ, लेकिन इसके अलावा बलिया जनपद से दो-दो मंत्री हैं, हमारे तीन-तीन विधायक है, हमारे प्रभारी मंत्री अनिल जी भी बैठे हुए हैं। इस सदन में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से बलिया लिंक को जोड़ने की घोषणा होती है और जब बजट पढ़ रहा हूँ तो सारे बजट का प्रोविजन किया गया है, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए है, बुन्देलखण्ड के लिए है, गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए है, गोरखपुर लिंक के लिए है। लेकिन पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे से बलिया को जोड़ने के लिए बजट में एक भी रुपये का प्राविधान नहीं किया गया है। अब बताईये कि इसमें हमारी क्या गलती है। हम तो कहेंगे कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की जगह पर मा0 आनन्द शुक्ला जी बैठे हैं, कम-से-कम इस बात को रखना चाहिए कि हम क्या जवाब देंगे। लेकिन हम इस बजट में पूरी तरह से अछूते रह गये हैं। जो एक मेडिकल कॉलेज के वितरण का सिस्टम बना हुआ है। हमारे यहां गाजीपुर में हो गया है, गाजीपुर से बनारस की दूरी कितनी है लेकिन गाजीपुर में दे दिया गया है। गोरखपुर में एम्स भी है, सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है लेकिन फिर भी देवरिया में मेडिकल कॉलेज दे दिया गया है, बलिया में मेडिकल कॉलेज नहीं दिया गया है। अब इसमें बलिया का क्या दोष है ? लेकिन इस सदन को बलिया का इतिहास जानना चाहिए।

जब देश गुलाम था, उस समय जब सभी लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय पूरे भारत में सबसे पहले अगर आजादी किसी ने हासिल किया तो बलिया जनपद ने किया क्योंकि वह लड़कर लेना था, लेकिन आज अपने हिस्सा के लिए हर साल बजट सत्र में अपनी बात को झोली फैलाकर रखते हैं कि आखिर में हमारे बलिया का क्या दोष है। हमारे यहां बलिया से (कुछ सदस्यों के टोका-टाकी करने पर) जब बोलने का अवसर आएगा तब बोलियेगा, बीच में टीका-टिप्पणी हम नहीं करते हैं, श्री सुरेन्द्र भाई आते हैं उनके यहाँ एक उच्च स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय मिला है, उसकी बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। हमारे बलिया मुख्यालय से बनारस की दूरी डेढ़ सौ से पौने दो सौ कि0मी0 होगी, गोरखपुर की दूरी भी डेढ़ सौ से पौने दो सौ कि0मी0 है, अगर कोई गम्भीर बीमारी से ग्रस्त होता है तो उसे इन जगहों पर जाना होता है, तो बताइए इसमें बलिया का क्या कसूर है। मैंने तो इतना तक कह दिया कि बलिया जनपद को मिलना चाहिए। एक बार बात आई कि जमीन उपलब्ध नहीं है, मैंने जिलाधिकारी से भी बात की कि आप प्रस्ताव क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वह कहने लगे कि नहीं, जो जमीनें हैं उनका पैसा देना पड़ेगा। हमने कहा कि यदि कोई सरकारी जमीन है और एक विभाग से दूसरे विभाग को देना है तो यह कैबिनेट का मसला है, एक मिनट में हल हो जाता है, लेकिन कहीं-न-कहीं बलिया के प्रति भेद भाव है, जो नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि इस मामले में हमारे बलिया के सम्मानित विधायक लोग भी हमारा साथ देंगे।

मान्यवर, बजट में मा0 वित्त मंत्री ने कहा कि हम हर घर को ओवरहेड टैंक से जाडेंगे, मैं आपको दो उदाहरण दूंगा कि जैसे आज की डेट में मिट्टी का तेल गांवों में बन्द हो गया, सरकार भी कहती है कि हम 18 से 20 घण्टे तक बिजली दे रहे हैं, मान लेते हैं। मान्यवर, अगर वह बिजली जो 18 घण्टे दी जाती है, 6 घण्टा नहीं आती है, वह अगर शाम का टाइम है, रात्रि का वहम है, एक गरीब आदमी उस शाम के टाइम को जब बिजली नहीं

आती है तो कैसे दीपक जलाएगा। मुझे लगता है कि इसको जारी रखना चाहिए, उसी तरह से हर घर को नल से जोड़ने की व्यवस्था है, मुझे लगता है कि जब तक ओवरहेड टैंकों का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक सदस्य को दो-दो सी हैण्ड पम्प मा0 मुख्य मंत्री जी को देना चाहिए। यह केवल मेरे लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मुझे लगता है कि जब ऐसी बात आती है तो मा0 विधायकों से संबंधित चीजें आप भी रखते हैं, तो आपका भी इसमें समर्थन होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, कुछ चीजें हुई हैं जिनकी मैं तारीफ भी करूंगा, जैसे पिछले सत्र में मैंने उठाया था कृषि बीमा दुर्घटना, जिसमें मैंने कहा था कि बटाईदार को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, उसे आपने जोड़ लिया उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मैंने कहा था कि आज-कल 50 प्रतिशत लोग बटाई पर लेकर खेती करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब समाप्त करिये, सूची बहुत लम्बी है और आज ही सबको बोलना है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं बलिया की एक और समस्या बता देता हूं। हमारे पूरे बलिया जनपद में एक ही उद्योग के नाम पर चीनी मिल है, चूंकि वह बन्द हुई सपा सरकार में, तब भी मैं इस बात को सदन में रखा था और इधर ही बैठा था, दुर्भाग्य है कि इधर ही रहता हूं। तो उस बार भी बात उठाये तो उन्होंने कहा इसको ट्रिपल बी में लेकर जा रहे हैं, इधर भी मैंने मा0 गन्ना मंत्री जी से कहा तो वह कहे कि हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप प्रयास करते रहिए।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मुझे लगता है कि उस चीनी मिल को चलाने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। चूंकि मैं आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकता हूँ, इसलिए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 सदस्य बाबा गोरखनाथ जी।

श्री बाबा गोरखनाथ-

मान्यवर, मैं मा0 वित्त मंत्री जी सहित सभी मा0 विधायकों का स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ। यहाँ हंगामा बहुत होता है हंगामे के ऊपर चार लाइन में भी कहूँगा कि-

"भंवरा कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा,
हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा,
अभी तक डूब कर सुनते थे, सब किस्सा विकास का,
मैं विकास को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा।"

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मान्यवर, खासकर मैं जिस नगरी से आता हूँ, अयोध्या नगरी में कि-

"त्याग तो हर ख्वाहिश कुछ अलग करने के लिए,
राम ने बहुत कुछ खोया था, श्रीराम बनने के लिए।"

मैं ऐसी नगरी से आता हूँ। वहाँ पर माननीय मुख्य मंत्री जी की विशेष कृपा है, सूरजकुण्ड के लिए 140 करोड़ रुपया देने की व्यवस्था की है और हमारे अयोध्या के सौन्दर्यीकरण के लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपया दिया है और सरयू नहर की योजना लिए 610 करोड़ रूपया देने की योजना बनायी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के नाम से जो हवाई अड्डा बन रहा है, उसके लिए 101 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था की है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बजट का समर्थन करता हूँ और समर्थन करते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान, जो सबके लिए है, आकर्षित कराना चाहता हूँ। मान्यवर, सरकार बहुत अच्छी दिशा में और गति में चल रही है, पर जो निचले तबके के अधिकारी जो हमको, हमारे पत्रों का जवाब नहीं देते हैं, इस पर आपकी तरफ से एक विशेष निर्देश जाए कि हर विधायक के पत्र का जवाब 15 दिन के अन्दर दे दें। हम बैठक जिले में करते हैं, लेकिन इसी तर्ज पर जिले के विधानसभा क्षेत्रवार एक बैठक हो जिसका अध्यक्ष, विधायक हो। वह 45 दिन का ऐसा नियम बने जो कार्यवाही का हिस्सा हो और जब वह कार्यवाही का हिस्सा होगा तो निचले तबके की जो छोटी-मोटी कमियाँ हम लोग हाउस में कहते हैं, हम अपनी विधान सभा में ही उनका निपटारा कर लेंगे। हमारे यहाँ विशेष कृपा है सरकार की कि रायबरेली से लेकर अयोध्या तक फोर लेन बन रहा है। अधिष्ठाता जी, बहुत पहले के नियम हैं कि जो 6 एयर, 7 एसर 10 एयर भूमि पर मकान बने हैं, अगर हम उन्हें लिखाने जाते हैं तो उनकी कामर्शियल रेट से लिखा-पढ़ी होती है, परन्तु उसका जब हमको मुआवजा मिलता है तो वह कृषि रेट पर मिलता है। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि यह सन्देश पूरे प्रदेश से जुड़ा है। यह नियम हो जाए कि 10 एयर, 12 एयर जिस पर मकान बने हैं, उनको कामर्शियल रेट से पैसे दिए जायें। मान्यवर, एक नए तरीके का फ्राड़ चला है।

आज मैं सबको धन्यवाद देता हूँ पहले जिस तरीके से हत्या, लूट की घटनाएँ होती थीं, उसमें बहुत कमी आयी है, परन्तु जो नए-तरीके की एक बात आयी है, जो पूँजी अपनी कम्पनियाँ खोलते है और सपने दिखा कर अरबों रुपये ठग करके ले जाते हैं, इस पर मैंने बार-बार कहा है कि कानून बने। मान्यवर, इस पर एक मजबूत कानून बने, चूंकि जो भी 419, 420, 67, 68 के मुकदमे लिखे जाते हैं, जिनके पास अरबों रुपये हैं, वह अपने सोर्स के

माध्यम से, व्यवस्थाओं के माध्यम से छूट जाते हैं और जो जनता का पैसा होता है, वह वापस नहीं मिल पाता है। इन बिन्दुओं पर हमको ठीक से सोचने की जरूरत है और कड़े कानून बने बिजली की व्यवस्था पर सब ने माना कि चाहे पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, जिस तरीके से बिजली व्यवस्था सरकार दे रही है। मैं उसमें केवल इतना कहना चाहता हूँ, मेरी एक 42 दिन की यात्रा हुई थी, जिसे मैंने अपनी विधान सभा क्षेत्र में किया था। मैंने देखा कि हर व्यक्ति को अपने आपको समझना होगा और हर व्यक्ति, हर इन्सान जिस दिन समझ जायेगा, इस देश का जरूर भला हो जायेगा। मैंने बार-बार कहा, हम बल्ब लगाते हैं, वह बल्ब कम से कम 100 वॉट और 200 वॉट के होते हैं, आज जो नयी प्रणाली आयी है, नयी टेक्नॉलाजी आयी है, उसमें सीएफएल मात्र 5 वॉट और 7 वॉट के होते हैं। किसी घर में 4 और 5 बल्ब से ज्यादा नहीं जलते हैं। अगर जोड़ा जाए तो सात पचे पैंतीस वॉट केवल होता है। इसलिए जो हमारा बिजली का व्यय होगा, वह बड़ी संख्या में रुकेगा और जो 18 घण्टा और 20 घण्टा बिजली हम दे रहे हैं, निश्चित रूप से हम उसको 24 घण्टा दे पायेंगे। अतः बल्ब पर बैन लग जाए हमको चौथा साल है, उधर के लोगों को मैंने देखा, कभी हमको पत्थर दिल के अलावा कुछ नहीं समझे, उस पर भी मैं चार लाइन कहूँगा कि-

"रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा,
एक आयी लहर कुछ बचेगा नहीं,
तुमने पत्थर का दिल, हमको कह तो दिया,
पत्थरों पर लिखोगे, मिटेगा नहीं। आगे है-
योगी जी की बात पर भरोसा रखो,
मन कहीं भी रहेगा, डिगेगा नहीं।"

मान्यवर, आपने इस बजट सत्र पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपको और सभी मा0 सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी तरह बनती रहे और बजट को इसी तरीके से लाती रहे।

***श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत- बहुत आभार इस बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूंगा, बुंदेलखण्ड के जनपद बांदा से मैं चुनकर आया हूं। एक दौर था जब वहां की औरतें यह कहा करती थीं कि भौरा तेरा पानी गजब कर जाए, भौंरा तेरा पानी गजब कर जाए। गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए। ऐ भौंरा तेरा पानी गजब कर जाए और गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए, लेकिन यह जो आजादी के बाद की निरन्तरता थी इस कहावत की तो अगर इसको किसी ने बदला तो हमारे पूज्य योगी जी की सरकार ने बदला। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि बुन्देलखण्ड स्वर्ग बन रहा है पृथ्वी का, तो निःसंदेह जो यह कहावतें थी, अब यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतिहास के पन्नों में रह जाने वाली कहावतें रह जाएंगी। हर घर नल योजना में महानगरों के बाद पहली बार गांव में भी काम चालू है। मैं आमंत्रित करता हूँ, आप लोग देखने आइये। इसके अलावा जो पानी की समस्या थी जिस तरीके से पानी पीने का संकट था तो हर घर नल योजना ने समाप्त किया। उसी तरीके से नहरों के माध्यम से भी मा0 अधिष्ठाता महोदय खेत-खेत में पानी पहुंचाएं। मैं अभी सुन रहा था कि एक हमारे विद्वान सदस्य महोदय सम्मुख से बोल रहे थे पानी के सम्बन्ध में कि नहरों की सफाई का बजट कम कर दिया गया है, बात बिल्कुल सही है, जो नहरें पहले 25-25, 50-50 लाख में सफाई, होती थी, अब वह दो-चार लाख में हो जा रही है, बाकी का पैसा कहां जाता था यह भगवान जाने। आजादी के बाद से भी ब्रिटिश काल की उन नहरों में कभी किसी ने अधिष्ठाता महोदय जी यह चिंता नहीं की उनकी छोटी-छोटी समस्या रही।

आज सिंचाई विभाग ब्रिटिश पीरियड की उन सड़कों की नहरें जिनकी झाल टूटे, गुलाबे टूटे, नहर पटरियीं टूटी, और पुल टूटे, पुलिया टूटीं एक साथ एक अभियान चलाकर उनके अनुरक्षण और पुनरुद्धार का काम पहली बार बुंदेलखण्ड में आदरणीय योगी जी की सरकार कराने जा रही है। क्या बुन्देलखण्ड ने भी कभी सोचा होगा कि हमको एक्सप्रेस-वे मिलेगा ? लेकिन आपके भी एक्सप्रेस-वे को हम लोगों ने चलवाया है। तुम तो आधा-अधूरा छोड़कर भाग गए थे। हम लोगों ने बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे दिया। अधिष्ठाता महोदय, आप देखिएगा कि अब बुन्देलखण्ड वाले चित्रकूट से चलकर सीधे दिल्ली तक की यात्रा 5-6 घण्टे में तय करेंगे। आपको बताऊँ कि इसी तरीके से आज गाँव-गाँव में पी0डब्ल्यू0डी0 की रोडें हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्या मैं तो कहूँगा कि पूरे जनपद बांदा में 07 ऐसी रोडें हैं कि जिनमें आवागमन के भारी ट्रैफिक के कारण बड़ी कठिनाई होती थी लेकिन उनका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कर उन 07 मार्गों को राजमार्ग का दर्जा देने का काम पहली बार बांदा जनपद में मा0 योगी जी की सरकार ने किया। मैं धन्यवाद दूँगा अपने मा0 लोक निर्माण मंत्री और मा0 उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को जिन्होंने इस चीज की भी घोषणा की और घोषणा ही नहीं कि बल्कि उस पर अमली जामा भी पहनाया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से कनेक्टेड बुन्देलखण्ड के जितने भी गाँव 05 किलोमीटर की दूरी के अन्दर होंगे उनको हम एक्सप्रेस-वे से जोड़ेंगे। आज 12 सड़कें जिनको उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया और केवल घोषित ही नहीं किया बल्कि सभी मार्गों पर आज उन्होंने कार्य प्रारम्भ कराने का काम भी किया है।

महोदय, मैं कहूंगा कि बुन्देलखण्ड में जहाँ पानी का संकट था, इन 04 सालों में कृषि के क्षेत्र में भी एक व्यापक सुधार देखने को मिला। अकेले जनपद बांदा में इस वित्तीय वर्ष में 75 हजार एम0टी0 से भी ज्यादा धान की खरीद एम0एस0पी0 पर हुई है। अभी कृषि विश्वविद्यालय बांदा में तीन दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया जिसमें 07 राज्यों के किसान प्रतिनिधियों ने बाकायदे भाग लिया तो आज एक नई तकनीक के माध्यम से भी बुन्देलखण्ड का किसान खेती कर रहा है। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से उसको नई तकनीक पर आधारित खेती करने का अवसर मिल रहा है और आदरणीय योगी जी की सरकार जिस तरीके से किसानों के हितों में व्यापक सुधार के काम कर रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में किसानों की आमदनी में दोगुना की वृद्धि होगी। महोदय, मैं कहूँगा कि

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ बुन्देलखण्ड में एक डिफेन्स कॉरिडोर का प्रस्ताव है जिसमें झाँसी, जालौन, चित्रकूट और बांदा है। आने वाले समय में बुन्देलखण्ड में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसके लिए भी मैं अपने मा0 मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मैं केवल दो मिनट बोलूँगा। बुन्देलखण्ड में आप पहली बार देखेंगे कि आज पर्यटन के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। बुन्देलखण्ड एक धार्मिक स्थल रहा, जहाँ भगवान राम साढ़े 12 वर्ष से भी ज्यादा रहे हैं, लेकिन देश की आजादी के बाद किसी भी सरकार में पर्यटन की दृष्टि से कभी भी चित्रकूट और बुन्देलखण्ड के पर्यटन क्षेत्र पर कहीं कोई फोकस नहीं किया गया, लेकिन पहली बार हमारी सरकार ने इसी बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान चित्रकूट के विकास के लिए किया है। इसके लिए भी मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की अपनी कुछ मांगें हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह और अनुरोध करूँगा कि बांदा में एक गन्ना मिल स्थापित की जाए और वहाँ पर एक कताई मिल की जमीन पड़ी है। मैं आपके माध्यम से पहले भी आग्रह कर चुका हूँ और मैं फिर आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि उस जमीन का उपयोग वहाँ पर किसी अन्य उद्योग को स्थापित कराने में कर लिया जाए। प्लस बांदा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाँदा नगर पालिका की सड़कों के चौड़ीकरण और पुनरोद्धार की माँग करता हूँ। इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में गमछा गाँव पड़ता है जोकि नदी किनारे का गाँव है। वहाँ पर श्री राम जानकी पम्प कैनाल की स्थापना की भी मैं माँग करता हूँ। एक बार पुनः अपने इस बजट के समर्थन में आपने मुझको बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट के संशोधन प्रस्ताव जोकि मा0 नेता विरोधी दल और मा0 नेता बसपा के द्वारा रखा गया है मैं उस संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार का यह आखिरी बजट है। चार बजट इनके पास हो गये और उनके बजट के पैसे का कहीं पता नहीं चला कि किस योजना में इन्होंने खर्च किया। अबकी बार इन्होंने जो बजट पेश किया है ये जनता को धोखा देने वाला बजट है। आज किसान परेशान है। आज दिल्ली के बार्डर पर करीब ढाई-तीन महीना हो गया किसान विरोधी बिल जो केन्द्र सरकार ने पास किया है उसको वापस लेने के लिए धरना दिया जा रहा है लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया उसमें कम-से-कम सैकड़ों की संख्या में किसान शहीद हो गये उसके बाद भी उनकी बात को नहीं सुना गया है। ये केवल बात करने वाले लोग है ये विकास करने वाले लोग नहीं हैं। मैं तो 1985 से आ रहा हूँ देख रहा हूँ कि किस तरह से सत्तापक्ष के लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री ने बजट रखकर जनता को गुमराह करने का काम किया है, आज तक एक भी काम नहीं हुआ है। आज जो उद्घाटन भाजपा सरकार के लोग कर रहे हैं वह माननीय अखिलेश यादव की सरकार में जो विकास हुआ था उसी का ये उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। लखनऊ में जो मेट्रो ट्रेन अखिलेश यादव जी ने बनवायी थी उसके बाद उनका आगे का कोई काम शुरू नहीं हुआ। पूर्वान्चल का एक्सप्रेस-वे जो

लखनऊ से आजमगढ़ और गाजीपुर तक वह मा0 अखिलेश यादव के शासनकाल में ही स्वीकृत हुआ था और उसमें शिलान्यास भी हो गया था और किसानों की जमीन भी ले ली गयी थी। आज चार साल हो गये लेकिन आज भी पूर्वान्चल का एक्सप्रेस-वे तैयार नहीं हो सका। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि हमारे आजमगढ़ जिले में किसानों के लिए सठियांव चीनी मिल मा0 अखिलेश यादव जी ने बनवाने का काम किया था। आज उस गन्ना मिल के किसानों का करोड़ों-करोड़ों रुपये का बकाया आज भी पड़ा है। उत्तर प्रदेश में मेरी समझ से दो-तीन चीनी मिल हैं सबमें किसानों का गन्ने का बकाया पड़ा हुआ है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार पूरी तरह से हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। केवल यह हिन्दू और मुस्लिम की बात करके, धर्म की बात करके चुनाव के मैदान में आना चाहते हैं। विकास की बात तो करते हैं कि हमने विकास किया, मगर जब चुनाव होता है तो उसमें हिन्दू-मुस्लिम करके चुनाव लड़ने का काम करते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कहते हैं कि यह देश की बात है। देश की चिन्ता तो सबको है। मान्यवर, बिजली विभाग के सम्बन्ध में जो आज यह कह रहे हैं कि हम बिजली दे रहे हैं, उसमें कहना चाहूंगा कि सपा की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने कई पावर प्लान्ट अनपरा से लेकर, ऊँचाहार से लेकर कहाँ- कहाँ उन्होंने बनवाने का काम किया था। बिजलीघर बनवाने का काम सपा की सरकार में हुआ है। यह 5वाँ बजट है और एक भी पावर प्लान्ट नहीं बना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विकास की बात विधान सभा में करेंगे और जब चुनाव होगा तो दूसरी बात हो जाएगी। हिन्दू-मुस्लिम की और अलग-अलग बातें हो जाएंगी। आज छोटे-छोटे किसान हैं और छोटे-छोटे दुकानदार हैं। कोई एक बल्ब जलाता है और कोई दो जलाता है लेकिन बिजली विभाग के लोग वहां जाकर उन पर कई गुना जुर्माना लगाकर और रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें जेलों में बन्द करने का काम किया जा रहा है। उन गरीब लोगों के साथ कोई मुरव्वत नहीं हो रही है।

हमारे आजमगढ़ के सम्बन्ध में मैंने अभी नियम-56 में एक विषय कल उठाया था। यह सरकार व्यापारियों की बहुत हितैषी है, शुभचिंतक है और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रानी की सराय बाजार में बिना नोटिस दिये, न उनको बताया गया और लगभग 2 सौ मकान को सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर धराशायी कर दिया गया। न उसका मुआवजा दिया गया। अब उनका जो दुकान में सामान था, वह सारा सामान नष्ट हो गया। पुलिस की फोर्स लगाकर प्रशासन, पी0डब्लू0डी0 के लोग थे और जिस तरह से छापा मारा जाता है, उस तरह से छापा मारा गया। मैं स्वयं मौके पर जाकर खड़ा था और वहां देखने का काम किया था। क्या स्थिति हो गयी थी ? इसके बाद मुआवजे की बात को मैंने नियम-56 में कहा था। हमारे यहाँ जब सपा की सरकार बनी थी तो मैंने अपनी सरकार में मा0 अखिलेश यादव जी से कह कर आजमगढ़ में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय ले जाने का काम किया था। अभी उसकी जमीन एक्वायर्ड करने का काम हो रहा था तब तक सरकार बदल गयी और वह आजमगढ़ का पशु चिकित्सा महाविद्यालय गोरखपुर लोक में चला गया। मैंने जिला योजना की बैठक में मा0 केशव प्रसाद मौर्य जी, जो लोक निर्माण मंत्री भी हैं, वह वहां पर थे और उनके सामने मैंने इस बात

की चर्चा की थी। आजमगढ़ को कुछ नहीं दे सके और 5 करोड़ का काम कहते हैं कि आप लोग प्रस्ताव दे दीजिए, चाहे सत्ता पक्ष के हों और चाहे विपक्ष के हों। यह साबित कर दें कि विपक्ष के मा0 सदस्यों को एक भी सड़क का काम मिला हो और जो हमारे मा0 सदस्य सत्ता पक्ष के हैं, उनको 5 करोड़ का काम देने का काम किया है। इस तरह कभी नहीं हुआ था जो इन्होंने करने का काम किया है। अस्पतालों की यह स्थिति है कि हमारे पी0जी0आई0, मेडिकल कालेज को एक बार इस सरकार ने तोड़ने का काम किया था। डॉक्टर और नर्सों का ट्रांसफर कराने का काम किया था तो हम लोगों ने जनता को साथ लेकर वहां धरना-प्रदर्शन करके उस मेडिकल कालेज को बचाने का काम किया था। आज स्थिति यह है कि उसमें कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर सदर अस्पताल में रहते हैं, उसी तरह से डॉक्टर मेडिकल कॉलेजों में हैं। 6 महीने हो गये अस्पतालों में कुत्ते की सुई नहीं है। लोग बीमारी से मर रहे हैं, कुत्ता काटने से मर गये और सरकार कहती है कि दवा उपलब्ध है, हमने हर व्यवस्था कर दी है। जा करके देख लें कि सड़कों की क्या स्थिति हो गयी है ? सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि एक सड़क के बारे में नहीं मैंने 04-04 सड़कों के बारे में लिखकर दिया है, मैं सदन में पढ़ना नहीं चाहता। आजमगढ़ बाईपास से जो सड़क शहर को जोड़ती है और पश्चिम मनचोभा ममरखापुर जाती है, उस पर आपकी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की जो सड़क बन रही है, उससे जोड़ा गया है, वह सड़क बिल्कुल खराब हो गयी है। इस तरह से आपके आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग से जियनपुर कौठरा मनचोभा ककरहटा को जो सड़क जाती है वह भी बिल्कुल खराब है। हम कौन-कौन सी सड़कों के नाम लें गड्ढामुक्त कहते हैं और गड्ढ़ामुक्त हो भी नहीं पाता है। सिंचाई की बात करें तो आज नहरों से किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। कही धर्म की बात करेंगे, कहीं मन्दिर-मस्जिद की बात करके, हिन्दू-मुस्लिम करके ये क्या संदेश देना चाहते हैं ? यह देश और प्रदेश का विकास नहीं करना चाहते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***डा0 विमलेश पासवान-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया उसके लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी नागरिकों की तरफ से प्रथम मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा और इस सदन में जब भी हम जैसे युवा विधायक जो पहली बार चुन करके आये हैं, विधान सभा में कदम रखते हैं तो बहुत सारी अभिलाषायें, आकांक्षायें हमारे क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। जिसकी पूर्ति के लिए हम लोग ऐसे तमाम सपने संजो करके आते है कि हम अपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर सकते हैं और इस सदन की जो गरिमामय शोभा रही है जो महान विभूति इस सदन की गरिमा रही है और जिनके फुटप्रिंट, जिनके चरणों की छाप आज इस सदन में है जब उस पर हमारे चरण पड़ते हैं तो हमें एक अभूतपूर्व गौरव की अनुभूति होती है और हम स्मरण करेंगे अपने ऐसे सभी महान इस समवेत्

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के सदस्य रहे साथियों का जो श्री गोविन्द बल्लभ भाई पन्त जी से शुरू होता है, श्री चौधरी चरण सिंह जी, श्री बी0पी0 सिंह जी, श्री वीर बहादुर सिंह जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री मुलायम सिंह जी, श्री कल्याण सिंह जी और हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के परम्गुरू और ब्रम्हलीन महन्त और राष्ट्रीय सन्त पीठाधीश्वर महन्त अवैद्यनाथ जी जो इस समवेत् सदन के सदस्य रहे और जिन्होंने सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक समरसता की जो क्रांति पूरे देश में फैलायी और यही नहीं, उन्होंने एक ऐसा उदाहरण भारतीय राजनीति में पेश किया, इस सदन के सदस्य रहे मेरे श्रद्धेय पिताजी श्री ओम प्रकाश पासवान जी को एक सामान्य सीट से सदस्य चुनवा करके इतनी अच्छी और खूबसूरत मिसाल पेश की। आज उन सभी लोगों का हम स्मरण करते हैं और मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हूँ और माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। जो बजट सर्वांगीण विकास पर केन्द्रित है और समावेशी, समग्र विकास और विभिन्न व्यवस्थाओं के उत्थान से जुड़ा यह बजट है। इससे पूर्व का जो बजट हमारी सरकार में मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कार्यकाल में 2017-18 का पेश किया गया था, वह किसानों पर आधारित रहा और मुझे ताज्जुब होता है कि जब भी कोई कार्य या कोई भी बजट इससे पूर्व जो पेश हुये, हमारे विपक्ष के साथी सिर्फ उसकी आलोचना करते हैं।

अभी महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर नेता सदन ने जिस प्रकार से पूरे सदन का आवाह्न किया कि यह प्रदेश सिर्फ सत्तारूढ़ दल का नहीं है, बल्कि यहाँ का प्रत्येक साथी इस सरकार का अभिन्न अंग है और जितना हमारा अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है। तो आलोचना करना इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, पर सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना ही इनकी जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारियां हैं वह उसकी एक ऐसी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि जितनी भी योजनायें इससे पहले सरकार ने बनाई, सभी क्षेत्रों में उसका लाभ निरन्तर अविरल गति से सभी को मिल रहा है। जैसे ही यह सरकार बनी किसानों पर आधारित पहला बजट रहा लघु सीमान्त कृषकों का जो कर्ज माफ किया गया हमारी सरकार द्वारा, उसमें सभी कृषक शामिल होते हैं। वर्ष 2018-19 का जो बजट था उसके अन्तर्गत औद्योगिक विकास के तहत सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ कार्य हुये और गड्ढायुक्त सड़कों को जब हमारी सरकार ने गड्ढामुक्त करना शुरू किया तो सभी विधान सभा को उसमें चयनित हुयी।

अधिष्ठाता महोदय, उसी प्रकार से महिला सशक्तीकरण पर आधारित 2019-20 के बजट के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से महिलाओं को अधिकार दिया गया और जो यह बजट वर्तमान में 2021-22 का है यह शिक्षा और युवाओं के सशक्तीकरण के लिये और कौशल संवर्धन पर आधारित है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने नेता सदन को, जो साहस और संवेदना की इतनी अच्छी प्रतिमूर्ति हैं और जिनकी कार्यशैली है, जिनका नेतृत्व है, जिसका लाभ पूरे 23 करोड़ की आबादी वाले भारी जनसंख्या वाले प्रदेश को मिल रहा है। मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा अपने विधान सभा क्षेत्र में किये गये कार्यों का, जो समय से हमारी सरकार ने समय रहते पूरा किये। इससे पहले हमारे क्षेत्र में जब भी चुनाव आते थे तो यह चुनाव का मुद्दा बनते थे और

माननीय मुख्य मंत्री जी अपने कार्यकाल के पहले भ्रमण पर जब गोरखपुर जाते हैं तो उन्होंने सबसे पहले हमारे कुशवासी क्षेत्र के चन्दाघाट पुल का शिलान्यास किया उसके बाद जो हमारे क्षेत्र की लाइफलाइन एन0एच0-29 है, उसका शिलान्यास करके पूरे हमारे क्षेत्र की जनता की सेवा में तत्पर किया.....

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त कर दीजिए, समय बहुत कम है।

डॉ0 विमलेश पासवान-

और अभी हाल ही में उनकी संवेदनशीलता इससे लगाई जा सकती है कि उन्होंने अभी 2 फरवरी को बाढ़ बचाव के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग किया, जिसमें उन्होंने सभी तटबन्धों के बचाव के लिए हमारे विधान सभा क्षेत्र के ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल में बाढ़ से पहले शिलान्यास करके कार्य शुरू करा दिया।

श्री अधिष्ठाता-

पासवान जी समय बहुत कम है। अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप बैठ जाइये।

डॉ0 विमलेश पासवान-

मान्यवर, इससे पहले की सरकारें बाढ़ आ जाने के बाद बाढ़ बचाव का कार्य करती थीं और पैसे का कैसे बंदरबाँट किया जाता था।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिए।

डॉ0 विमलेश पासवान-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में रखे गये बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, 2014 में जब देश में माननीय मोदी जी की सरकार बनी और 2017 में प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तबसे देश हित, जनहित, समाज हित में लगातार विकास का क्रम चल रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का यह बजट लोक कल्याणकारी है, जनहित में है। मैं इस सदन में सदस्य रहा। प्रारम्भ से बता रहा हूँ। सदन शुरू होता था, लाल टोपी, नीली टोपी, पीली टोपी, सफेद टोपी, जिन्दाबाद-जिन्दाबाद-जिन्दाबाद, कोई कहता था जापानी बुखार, कोई कहता था गन्ना किसान और सदन की कार्यवाही पूरे-पूरे दिन लगातार इसी तरह भेंट चढ़ती रही। मान्यवर, इस सदन में सदन के किसी भी सदस्य ने गोरखपुर क्षेत्र के जापानी बुखार की चर्चा नहीं की। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में प्रदेश की यह एक जो बहुत बड़ी बीमारी है, प्रतिवर्ष गोरखपुर क्षेत्र में फैलती

थी, उस बीमारी पर नियन्त्रण करने का काम किया। अभी जब कोरोना आया और जब जानकारी मिली कि पूरे देश से मजदूरों का पलायन हो रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के कार्यकर्ताओ, पदाधिकारियों, विधायकों को निर्देश दिया कि सम्पूर्ण प्रदेश के अन्दर सारे जनप्रतिनिधि, मुझे भी स्मरण है एक्सप्रेस-वे से लेकर अवध चौराहे तक लगातार मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ चप्पल पहनाने से लेकर भोजन-पानी की चिन्ता कर रहा था।

अधिष्ठाता महोदय, कोई लाल, नीली पीली टोपी दिखाई नहीं दी। अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने गरीबों को भोजन पहुँचाने का काम किया। मोदी राशन किट पहुँचाने का काम किया, बस्तियों में सैनेटाइजर और मास्क वितरित करने के साथ-साथ इसके महत्व को भी बताने का काम किया गया। उस कोरोनाकाल में हमारे मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना। जब सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन था, पूरा देश थम चुका था, ऐसे समय पर मेडिकल सुविधाओं के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिन्ता की। सम्पूर्ण देश के अन्दर किसानों को मुफ्त राशन भी मुहैया कराया और कहीं पर भी कमी न होने पाये, हमारे जिला प्रशासन ने, हमारी महापालिका ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भण्डारे चलाये, स्वयंसेवी संस्थाओं ने भण्डारे चला रखे थे। एक अधिकारी मिले, कहने लगे यह अदब की नगरी लखनऊ है, पहले आप मैंने ऐसा कभी जीवन में नहीं देखा था प्रवासी लोगों की सेवा करते हुए। सम्पूर्ण प्रदेश में जब एक समय था कि घर-घर गैस का चूल्हा बंट रहा था। पूरे प्रदेश के अन्दर कितने करोड़ गैस के सिलेण्डर और चूल्हे गरीब के घर पहुंचाये गये। वह गरीब भी पहले यह समझता था कि यह चूल्हा बड़े आदमियों का है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्पूर्ण देश के वासियों को अमीर बना दिया और उनका यह भाव खत्म करने का काम किया। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया।

श्री अधिष्ठाता-

क्षेत्र के बारे में कह लीजिये और संक्षेप कर दीजिये।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूं कि मैं बजट के समर्थन में बोल रहा हूँ यह बजट लोक कल्याणकारी बजट है इसे पास किया जाय, क्योंकि सम्पूर्ण देश और प्रदेश में चौबीसों घण्टे बिजली गांव-गांव पहुंचाने का काम किया गया है, आज घरों में बिजली जल रही है, मोदी जी की योजना है, आवास बंट रहा है, मुख्य मंत्री आवास मिल रहा है, क्षेत्रों का विकास हो रहा है। अन्त में मैं अधिष्ठाता महोदय एक निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 13 छावनी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मैं लखनऊ के कैण्ट क्षेत्र का विधायक हूँ, कई ऐसी आबादी/बस्तियां हैं, जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपने घर में शौचालय बना लेता है तो उसे तोड़ दिया जाता है, वह अवैध बस्ती घोषित है। मान्यवर, सौ साल से रह रहे हैं और बस्ती अवैध है, शौचालय नहीं बना सकते,

सबमर्सिबल नहीं लगा सकते, पीने के पानी को वहां लोग तरस रहे हैं, वह बिजली नहीं लगा सकते है। मान्यवर, ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे निवेदन है, मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार इस विषय पर भारत सरकार से वार्ता और पत्राचार प्रारम्भ करे। हमारे विधान सभा कैंट क्षेत्र के निवासी जब अपना निवास प्रमाण-पत्र बनवाते हैं और पोर्टल कैंट थाना करके खोलते हैं तो नहीं खुलता, वह अपना पता भरकर हुसैनगंज, दूसरे थानों के पते पर अगर वह अपना निवास प्रमाणपत्र बनवाना चाहेंगे तो उन्हें मिलेगा।

मान्यवर, आप तो सम्पूर्ण सदन की चिन्ता करेंगे, मान्यवर, पूरे प्रदेश के विधायक हमारे लखनऊ में एक्सप्रेस-वे से होते हुए आते हैं और उस चौराहे पर 24 घण्टे जाम लगा रहता है। उस चौराहे के नीचे से जब तक अन्डरपास नहीं बनाया जाता है तब तक उस चौराहे का जाम लगातार बढ़ता जायेगा, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस अन्डरपास को बनवा दिया जाय। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में गंगाखेड़ा, केसरीखेड़ा, कनौसी माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके क्षेत्र के भी कई गांव हैं मुन्नूखेड़ा, चुन्नूखेड़ा, धनहरखेड़ा पहले ये मेरे विधान सभा क्षेत्र में आते थे अब आपके विधान सभा क्षेत्र में आते हैं। इन गांवों में आज भी न पीने के पानी की कोई व्यवस्था है और न ही वहाँ से जल निकासी की कोई व्यवस्था है, मान्यवर, वह हजारों एकड़ का इलाका पूरा का पूरा बरसात के दिनों में जलमग्न हो जाता है। मान्यवर, नाला हमारे उसमें प्रस्तावित भी है, आपके अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन उस नाले पर अतिक्रमण है। महोदय, हमारा निवेदन है कि अतिक्रमण हटाकर उसको नाला बनाया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम अपने कैंट विधान सभा के क्षेत्रवासियों के लिए माँग करते हैं कि मा0 मोदी जी और मा0 योगी जी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं कैण्ट वासियों को भी मिलें। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

श्री नरेश सैनी जी।

***श्री नरेश सैनी-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बजट में पढ़ रहे थे, तो सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वह स्वयं पढ़ा, तो ऐसा लगा कि जो वह रोज कहते हैं कि हम किसान की आय दोगुनी करने का काम करेंगे, उसमें मुझे कोई मंत्र ऐसा नहीं मिला कि जिससे किसान की आय दोगुनी होगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिष्ठाता महोदय, यदि पिछले समय की बात करें, तो इस सरकार ने पिछले चार साल में गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया और सरकार कहती है कि हम किसान की आय दोगुनी करने का काम करेंगे। जो सरकार बिजली के दाम लगातार बढ़ा रही है, हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है, वह सरकार कह रही है कि हम किसान की आय दोगुनी करने का काम करेंगे। दिन में सपने दिखाने वाली सरकार क्या इन सपनों को साकार करने का काम करेगी ? हर दिन उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, किसान के फसलों के दाम कम हो रहे हैं, तो किसान की आय दोगुनी करने का काम कैसे करेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है ? इस सरकार ने किसानों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं बनायी है, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके।

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं दूसरी बात यह भी कहूंगा कि जब भी कोई चुनाव की घोषणा होती है, तो भाजपा सरकार के बड़े-बड़े नेता मेरे क्षेत्र में जाने का काम करते हैं। "माँ शाकुम्भरी" देवी के दरबार में माथा टेकने का काम करते हैं, लेकिन बजट में "माँ शाकम्भरी" के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की है। पिछले बजट में भी "माँ शाकुम्भरी" का नाम आया था और इस बजट में भी "माँ शाकुम्भरी" का नाम आया है, लेकिन बजट में उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं तो यह कहूंगा कि जब "माँ शाकुम्भरी" के लिए बजट की कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो आने वाले समय में "माँ शाकुम्भरी" कहेगी कि इन झूठों का इलाज जरूर करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम "माँ शाकुम्भरी" के नाम पर बजट देने का काम करें। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरा क्षेत्र फल पट्टी का क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र का "चौसा" आम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। "चौसा" आम एक्सपोर्ट होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कम से कम "फल प्रसंस्करण" की फैकट्रियां लगाकर क्षेत्र की जनता को लाभ देने का काम करें। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में जो "शिवालिक" का एरिया आता है, उसमें मिलिट्री की फायरिंग रेंज है। उसमें बहुत गरीब वन गुर्जर बसे हुए हैं। उनको प्रशासन हर समय प्रताड़ित करने का काम करता है। जब भी फायरिंग होती है, तो उसमें कोई न कोई हादसा हो जाता है। पिछले वर्ष उसमें एक आदमी और एक बच्ची का देहान्त हो गया था, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि फायरिंग रेंज में आने वाले उन वन गुर्जरों को एक अलग स्थान पर बसाने का काम करें, जिससे वह दिनचर्या के साथ अपने काम को सही तरीके से कर सकें।

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पिछड़ा होने के साथ जिला मुख्यालय से कम से कम 50-60 किमी0 दूरी पर स्थित है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कम से कम एक महाविद्यालय देने का काम करें, जिससे वहाँ के बच्चे और नौ-जवान अच्छी शिक्षा लेने का काम कर सकें। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरा क्षेत्र शिवालिक की तलहटी से जुड़ा हुआ है। आपने जो नमामि गंगे योजना चलायी है कि हर घर में इस योजना के तहत वाटर सप्लाई होगी। लेकिन जब तक टंकी नहीं लगेगी, आपने विधायकों के नल काट दिये, वह कहाँ पानी पीने के लिए जायेंगे ? पानी पिये बिना आदमी एक घण्टा भी नहीं रह सकता। तो मैं आपसे निवेदन करना

चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में विधायकों को 200 नल दिये जाते थे, परन्तु हम लोगों को 100 नल दिये गये। मान्यवर, कम से कम मेरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जहाँ 600 फीट की गहराई में पानी है और वहाँ 3-4 लाख रुपये में एक नल लग पाता है। हमारे यहाँ बहुत गरीब लोग हैं तो कम से कम मेरे क्षेत्र के लिए 500 हैण्डपम्प देने का काम करे जिससे वहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके पानी पीने की व्यवस्था की जा सके। महोदय, साथ ही साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ पर खनन जोन है उस खनन जोन से जो राजस्व आता है उस राजस्व के कुछ हिस्से से उस क्षेत्र की टूटी हुई सड़कें बनवाने का काम करें। आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र में फैक्ट्रियों की कोई व्यवस्था करें। हमारे क्षेत्र में पापुलर अधिक होता है तो वहाँ पर प्लाई बोर्ड की फैक्टरी लगवाने का काम करें जिससे हमारे क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा। अन्त में आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जय हिन्द, जय भारत।

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री चौधरी उदयभान सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 22 फरवरी, 2021 को जो बजट प्रस्तुत हुआ उसका मैं पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे मित्रों ने सत्तापक्ष के जो सहयोगी हैं उन्होंने सरकार के किए हुए कामों की लगातार बार-बार, अनेक बार प्रशंसा की है। मैं अपने शब्दों और अपनी आवाज को अपने मित्रों के साथ जोड़ता हुआ समर्थन करता हूँ और परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि वह उत्तर प्रदेश और देश के मतदाताओं को यह सामर्थ्य दे, यह सोच दे कि भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता को विधायक बना करके इस सदन में भेजें। मित्रों ! मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि मैंने 1989 का वह दृश्य भी देखा है, जहाँ मेरी पार्टी ने स0पा0 के मुखिया आदरणीय श्रीमान मुलायम सिंह जी को अपना समर्थन दे करके इस प्रान्त का मुखिया बनाया था। यही नहीं, उससे पहले वह भी समय मैंने देखा है जब भारतीय जनता पार्टी ने (तत्कालीन जनसंघ) चौधरी चरण सिंह जी को अपना समर्थन दे करके इस प्रान्त का मुखिया बनाया था। मैंने वह समय भी देखा है कि जब बहन मायावती जी पर बेहद संकट था और उनका जीवन खतरे में हो गया था। मैं उन चश्मदीद गवाहों में से एक हूँ, उनको बचाने वालों में से एक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता ने बहिन जी का जीवन बचाया था। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आदर्श, भारतीय जनता पार्टी का विचार राष्ट्रदेव की आराधना करने का और देश की जनता को सुख और कल्याणकारी योजनायें देने का है। "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत।।" इस भावना से भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता गिन-गिन करके मतदाताओं की, प्रान्त की और देश की सेवा करता है। मुझे राजनीति करते-करते लम्बा समय हो गया है। मैं अपने स0पा0, ब0स0पा0 और काँग्रेस के मित्रों को सुन रहा था। मैं आदर करता हूँ स0पा0 के मुखिया का, जो विरोधी दल के नेता हैं, उनका बेहद आदर करता हूँ। ब0स0पा0 के जो मुखिया हैं और यहाँ जो दल के नेता हैं मैं उनका भी आदर करता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कुछ तो सच बोलो भाई। बिल्कुल सरासर झूठ। जहाँ

तक भ्रष्टाचार की बात है, कहना नहीं चाहता, मैं जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ एक लम्बा समय हो गया राजनीति करते करते। वाणी पर नियंत्रण करना मेरा धर्म है, मेरा नियंत्रण है जरा याद करें बसपा के मेरे मित्र कि हर वर्ष 15 दिसम्बर से ले करके 15 जनवरी के बीच जनता के बीच में, अधिकारियों के बीच में जो उगाही होती थी उसको आप ईमानदारी कहोगे क्या। खुलेआम बेईमानी। लेकिन चलता था आपके समय में, मैं उस पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। श्रीमान अधिष्ठाता महोदय, आप मुझे डाँटेंगे, यह कहेंगे कि समय पूरा हो गया इससे पहले मैं बजट का, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करते हुए जहाँ से जिस जनता ने मुझे विधायक बनाया है उसकी वकालत नहीं करूँगा तो मैं अपने आप को अधूरा समझूँगा। मान्यवर, मैं फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ। दुनियां का आदमी, दुनियां का पर्यटक जब हिन्दुस्तान में आता है तो अपना चेहरा ताजमहल की तरफ करके फतेहपुर सीकरी की तरफ मुड़ता है और जाता है लेकिन इतने लम्बे समय में 70 वर्षों में फतेहपुर सीकरी के विकास का जो बहुत बड़ा उद्योग बन सकता है पर्यटन का। दुनियां में सबसे बड़ा कृषि के बाद कोई उद्योग हो सकता है सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग वह पर्यटन है। अब एक जिला एक उद्योग जो मेरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय योगी की सरकार ने जो पूरा महत्व दिया उसके बाद यदि कहीं भी कोई दूसरा साधन बन सकता है, कोई दूसरा कारण बहबूदी का बन सकता है तो वह हिन्दुस्तान के लिये, खास तौर से आगरा के लिये, पर्यटन को जितना महत्व दिया जा सकता है उसके लिये मैं पुरजोर वकालत करता हूँ कि फतेहपुर सीकरी के पर्यटन के विकास के लिये यह मेरी वकालत है।

अधिष्ठाता महोदय, वहाँ ऐसी-ऐसी चीजें हैं। दुनियां का सबसे बड़ा युद्ध राणा सांगा और बाबर का युद्ध जो संसार जानता है कि सृष्टि में सबसे बड़ा युद्ध है। वह खानवा का मैदान फतेहपुर सीकरी में है। महाराजा सूरजमल जिसको सबसे बड़ा अजेय राजा कहा जाता है। पूरे हिन्दुस्तान में जहाँ से सूर्य निकलता था और कभी सूर्य छिपता नहीं था हर जगह पर अंग्रेजों का राज्य था, लेकिन उस समय भी एक राजा ऐसा था महाराजा सूरजमल भरतपुर का नरेश, जिसने कभी भी अंग्रेजों को राजस्व नहीं दिया। मैं उसी की तरह से गोकुला जाट की भी प्रशंसा करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा जिसने मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ किसानों का एक गुट बना करके किसानों का संगठन खड़ा करके लगान के विरुद्ध युद्ध लड़ा और पूरा जीवन भारतीय संस्कृति के लिये, भारतीय परम्पराओं के लिये और वैदिक धर्म के लिये लगा दिया, लेकिन विधर्मों की माँग स्वीकार नहीं की। यह गोकुला जाट का कर्म क्षेत्र फतेहपुर सीकरी रहा है। वहाँ मैं माँग करता हूँ, माँग शब्द मेरे लिये राज्य सहयोगी मंत्री होने के नाते ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं वकालत करता हूँ और वकालत करते-करते मैं चाहता भी हूँ और चाहूँगा भी कि वहाँ पर तेहरामूरी बाँध पर आगरा, जयपुर रोड है। आगरा, जयपुर रोड पर सबसे बड़ा तेहरामूरी बाँध है वहाँ पर 7 एकड़ जमीन उद्यान विभाग की बहुत फल फूल रही है वह स्थान गोकुला जाट का आश्रय था, वहाँ कभी उन्होंने कैम्प लगाया था, तो वह उद्यान केवल गोकुला जाट उद्यान के नाम से जाना जाय, पहचाना जाय यह मैं आपके माध्यम से वकालत करता हूँ, इस पर बहुत बड़ा विचार भी कर लिया जाय। मान्यवर, हमारे यहाँ ही अकबर बादशाह के

जमाने के नवरत्नों में से राजा टोडरमल की समाधि है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस व्यक्ति ने सम्पूर्ण विश्व में भू-विन्यास मानचित्र की जेवरी तैयार की हो, भू-विन्यास मानचित्र पूरे हिन्दुस्तान का तैयार करके अकबर बादशाह के हाथों में दिया हो, ऐसे नवरत्न की समाधि और उसकी यादगार भी फतेहपुर सीकरी में है। यह तो मैंने इतिहास की बात की है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगरा-मथुरा रोड पर मेरा क्षेत्र ब्रज से बिल्कुल लगा हुआ है, मथुरा और वृन्दावन से लगा हुआ है। हमारे यहां श्रृंग ऋषि का आश्रम सींगना के नाम से पहचाना जाता है। भगवान परशुराम का ननिहाल और रेणुका जी का जन्म स्थान रूनकता हमारे क्षेत्र में है। यमुना प्राकृतिक रूप से पश्चिम की ओर मुड़ी है, जिसको पश्चिमाई कहते हैं, वह हमारे यहां है। जहां द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने अक्षयपात्र दिया, वह जगह भी हमारे यहाँ है। जहां पर दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की वह दूरा गांव भी फतेहपुर सीकरी में है। मेरा कहने का भाव यह है कि चाहे ऐतिहासिक रूप में देख लें और चाहे आध्यात्मिक रूप में देख लें फतेहपुर सीकरी का पूरा कैरावली क्षेत्र अपने आप में बेहद महत्व रखता है। सूरदास जी की तपोभूमि आगरा के सींगना गांव में है। संसार में सबसे बड़े कवि तुलसीदास जी के बाद सूरदास जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, वह भी जगह हमारे यहां है। आगरा, जयपुर रोड, आगरा-मथुरा रोड पर दाहिने हाथ की ओर जब आप मथुरा से चलेंगे तो बायी ओर आपको मथुरा पार करते ही फतेहपुर सीकरी का वह क्षेत्र मिलेगा, जो आध्यात्मिक क्षेत्र का केन्द्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाकर आदमी वहां पूजा-अर्चना करके अपने आपको धन्य मान लेता है। जब आगरा-जयपुर रोड पर चलेंगे तो उसमें वीरों का इतिहास वह सड़क लिखती है। ऐसे ही चाहे अकोला ब्लाक हो, चाहे फतेहपुर सीकरी ब्लाक हो, चाहे अछनेरा ब्लाक हो, सबका अपना एक बेहद ऐतिहासिक महत्व है।

फतेहपुर सीकरी का विकास खण्ड पथरीला पहाड़ी है। वर्ष के माह मई-जून में पानी बोतलों में लीटर के मूल्य बिकता है। वहां किसी भी प्रकार का पानी का साधन नहीं है। मैं जब वहां से विधायक हुआ उससे पहले मैं दयालबाग विधान सभा क्षेत्र से था, जिसको कि आगरा ग्रामीण के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन तबसे लेकर आज तक इस पर बड़ा गहरा अध्ययन किया है। राजस्थान से एक उटंगन नदी आती है। उटंगन नदी आगे के लिए बढ़ती है अगर डॉवर और सिरौली गांव पर एक बहुत बड़ा बांध बना दिया जाए तो उन सारी समस्याओं का समाधान केवल वह बांध कर देगा। मैं आपसे केवल दो बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपके समय का आदर करूंगा। आपके दिये हुए समय का सम्मान करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता हूं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक हूँ, माँ के पेट से केवल यही सीखा है कि राष्ट्र देव और राष्ट्र की जनता की पूजा करना ही पूजा अर्चना है, कर्म ही सबसे बड़ा है, इसलिए मेरे सामने के जो मित्र बैठकर आलोचना करते हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह अपने गिरेबान में झांककर देखें कि कांग्रेस के लोगों ने इस देश पर जो आपत्ति लगायी है, इमरजेंसी लगायी, उसका क्या हाल रहा। जब मुलायम सिंह जी आये, वह प्रदेश के मुखिया बने, उन्होंने क्या किया, बसपा के ही नेता को जीवन से बेदखल करने की योजना बनायी थी। जब बहन जी आयीं तो गांव-गांव अन्याय, अनाचार, जाति, बिरादरी, मजहब के बीच में प्रदेश को बांट दिया गया। आपके टोकने से पहले अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं

इस बजट का और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का पूरी ताकत के साथ समर्थन करता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और फिर से कहता हूं कि यह पांचवां बजट नहीं है। यह आखिरी बजट नहीं है आपके सामने बैठे हुए यह सत्तापक्ष के विधायक फिर से आएंगे फिर से सत्ता में आएंगे फिर से मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे आप वैसे ही चिल्लाओगे ऐसे ही आपकी आधारहीन बातों का हम उत्तर देते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय आय-व्ययक 2021-22 पर विचार रखने के लिए जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभार भी प्रकट करता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त 17वीं विधान में 2021-22 का आय व्ययक प्रस्तुत हुआ है जिसका तुलनात्मक दृष्टि से सिंहावलोकन किया जाए तो इस निष्कर्ष पर पहुँचना स्वाभाविक है और सुगम है कि यह आय व्ययक राष्ट्रपरक है कृषिपरक है विकासपरक् है और ग्राम्यपरक् है इसमें कोई संशय नहीं है। पक्ष के लोग हार्दिक समर्थन तो करते ही हैं मैं भी उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। हमारे सामने जो प्रतिपक्ष के के लोग बैठे हैं वह प्रतिपक्ष की भूमिका के निर्वहन के कारण भले ही विरोध करें लेकिन उनकी अन्तरात्मा की आवाज इस आय व्ययक की प्रशंसा करने के लिए आतुर है और विवश है। आय-व्ययक 2021-22 का विश्लेषण किया जाय तो आय व्ययक का आकार सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही है जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को अति उत्तम प्रदेश बनाने में समर्थ है। साथ ही साथ इसका जो स्वरूप है, जो प्रकार है इस दृष्टि से आय-व्ययक गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का उत्थान, झोपड़ियों में रहने वाले इन्सान व महिलाओं के सम्मान के लिए समर्पित है। इसलिए मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ का मैं अभिनन्दन करता हूँ, बधाई देता हूँ जिनके निर्देशन में एक अभूतपूर्व अकाल्पनिक और दूरदर्शी आय व्ययक प्रस्तुत हुआ है। साथ ही साथ, उप मुख्य मंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य और मा0 दिनेश शर्मा जी जिनका इस आय व्ययक को प्रस्तुत करने में सहयोग रहा है, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। उनके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा जो आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया है इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह मुझे लग रहा है कि कम ही है। इसलिए मैं उनको कोटि-कोटि धन्यवाद और ढेर सारी बधाइयाँ भी समर्पित करता हूँ। यह कामना करता हूँ कि मा0 मुख्य मंत्री श्री आदित्यनाथ बार-बार इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बनकर इस प्रदेश को अति उत्तम प्रदेश बनाएंगे, उप मुख्य मंत्री मा0 केशव प्रसाद मौर्य और मा0 दिनेश शर्मा जी इस पावन कार्य में अमिट सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो अपनी प्रवीणता और कुशलता का परिचय देते हुए एक सर्वांगीण आय व्ययक प्रस्तुत किया है यह एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इन चारों प्रतिभाओं की कलाएं भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेंगी जब तक इस क्षितिज में सूर्य और चन्द्रमा रहेगा, गंगा जमुना की

धार रहेगी, ऐसी मेरी कामना और विश्वास है। अधिष्ठाता जी भारतवर्ष को कृषि प्रधान देश का अलंकरण प्राप्त है। इस मान सम्मान के लिए इस प्रदेश की 78 प्रतिशत जनता जो कृषि पर आधारित है, उनकी ही अहम भूमिका है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा, नक्षत्र प्रकाश पुंजित होते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ के कृषक के उत्पादन के द्वारा चाहे व्यापारी हों या अधिकारी हों या कर्मचारी हों सभी को जीवनदान मिलता है। मान्यवर, कृषि आधारित 78 प्रतिशत जनता यदि दुखी होगी तो भारत माँ की आँखों में आँसू होगा। यदि यह जनता अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकेगी तो उसके चेहरे पर खुशी ही नहीं होगी, बल्कि उसके परिवार से खुशियों की गंगा प्रवाहित होती हुयी सम्पूर्ण प्रदेश को प्रफुल्लित करेगी। इसलिये देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त से ही यह सपना संजोया गया कि कृषि उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। इसलिये सन् 1952 में राधा कृष्ण समिति का गठन किया गया, जिसकी संस्तुतियाँ और सुझाव आज भी रद्दी की टोकरी में पड़े हुये हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, उसके बाद वर्ष 2004 में इसी उद्देश्य से स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया, लेकिन उसकी भी संस्तुतियाँ व सुझाव वर्ष 2014 तक रद्दी की टोकरी में पड़े रहे। वर्ष 2014 में मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उन संस्तुतियों को पढ़ा और लागू करने का बीड़ा उठाया और यह प्रतिबद्धता की कि 2022 तक हम कृषकों की आय दोगुनी कर देंगे। इसलिये 05 सूत्रों का प्रादुर्भाव किया गया। नम्बर एक-कम लागत, नम्बर दो-अधिक उत्पादन, नम्बर तीन-लाभकारी मूल्य मिले, नम्बर चार अधिक से अधिक अनुदान दिया जाये, नम्बर पाँच-कृषि सहायक उद्योगों के लिये प्रेरणा दी जाये। इन सूत्रों को प्राथमिकता पर लागू करने का दायित्व मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सौंपा गया। मैं बताना चाहता हूँ कि सन् 1965 में एक कृषि मूल्य आयोग अर्थात् एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का गठन किया गया, जिसके तीन दायित्व थे। नम्बर एक- कृषि उत्पादों की लागत श्रम और लाभयुक्त लाभकारी मूल्य (एम0एस0पी0) घोषित करना, नम्बर दो- घोषित समर्थन मूल्य (एम0एस0पी0) कृषकों को प्रदत्त कराने की समुचित प्रभावी एवं त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करना, नम्बर तीन-कृषि उत्पादों तथा मिल उत्पादों के मूल्यों के मध्य सामंजस्य, समानता एवं संतुलन स्थापित करना। इस क्रम में आयोग ने समर्थन मूल्य (एम0एस0पी0) तो घोषित किया ही, अपितु इस बार गेहूं और धान को इतनी भारी मात्रा में क्रय किया गया जितना उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं क्रय हुआ है। इस मूल्य आयोग ने जहाँ कृषि उत्पादों का एम0एस0पी0 निर्धारित किया है वहीं मिल उत्पादों का एम0आर0पी0 भी निर्धारित करके संतुलन स्थापित करने का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दें।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

इसी क्रम में मा0 मोदी जी ने शांता कुमार आयोग की संस्तुतियों के आधार पर तीन अध्यादेश नम्बर एक-कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अध्यादेश, 2020, नम्बर दो-कृषि (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर इकरार

अध्यादेश, 2020 नम्बर तीन-आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रस्तुत किये हैं। यह लोक सभा में 17 सितम्बर, 2020 को तथा राज्य सभा में 20 सितम्बर, 2020 को पारित हुये, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 26 सितम्बर, 2020 को हस्ताक्षर किये। इस प्रकार अधिनियम के रूप में आज यह प्रचलित है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आपने सभी बातें इम्पार्टेट कही हैं। अब आप समाप्त कर दें। आप संख्या देखिये, अभी बहुत लोग बोलने के लिये बैठे हैं।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, कतिपय नेताओं को यह भ्रम है कि कृषि मण्डियाँ समाप्त हो जायेंगी और कम से कम समर्थन मूल्य लागू नहीं रहेगा, लेकिन मा0 मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि न ही एम0एस0पी0 समाप्त होगी और न ही मण्डियाँ समाप्त होंगी। मान्यवर, दूसरा जो अधिनियम है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिये। अधिनियम का उल्लेख मत कीजिये।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, उसमें यह व्यवस्था की गयी है कि कृषक अपनी खेती का नहीं, बल्कि उपज का इकरार व्यापारियों से अथवा कंपनियों से कर सकता है और कृषक को इकरार समाप्त करने का भी अधिकार रहेगा, लेकिन उन कंपनियों और व्यापारियों को यह इकरार समाप्त करने का अधिकार नहीं होगा, उनको इकरार किये हुये मूल्य का भुगतान करना ही पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो चुका है। आप बैठ जाइये।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं अपने क्षेत्र की थोड़ी सी बात कह दूँ। हमारा विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

शाहजहाँपुर, बरेली, पीलीभीत तथा लखीमपुर खीरी के केन्द्रीय स्थल बीसलपुर की जनपद स्थापित करने की आवश्यकता है क्योंकि बीसलपुर परिक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्गों से घिरा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूँ, आप बैठ जाइये।

(सदस्य श्री अगयश रामसरन वर्मा जी का माइक बंद कर दिया गया)

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये बजट पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, इस बजट के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं की गयी है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा एक से लेकर आठ तक जो व्यवस्था दी गयी है वह बहुत ही कम है। अभी हमारे सत्ता पक्ष के कई मा0 सदस्यों ने इस बात का जिक्र भी किया है कि हम लोग बहुत सारे प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर अध्यापक नहीं रहते हैं प्रधानाध्यापक नहीं रहते हैं और बच्चे भी नहीं रहते हैं। इसका रीजन यह है कि बजट के प्राविधान में प्राइमरी स्कूलों को जब तक बेंच से पूरी तरह सुसज्जित एवं पाठ्यक्रम अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की तरह नहीं किया जायेगा तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। मान्यवर, शुरू में जब मैं विधायक बना और सदस्य बनकर इस आदरणीय सदन में आया तो उस समय भी मैंने इस बात को रखा था। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मिला था और उनसे कहा था कि प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों को अगर आप सुदृढ़ बना देंगे तो उससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की 90 प्रतिशत सामान्य आबादी, 95 प्रतिशत पिछड़ी आबादी और 99 प्रतिशत अनुसूचित आबादी को तुरन्त उसका लाभ मिलने लगेगा और उनके बच्चों का भी भविष्य आगे बढ़ने लगेगा। हमें बताया गया था कि मा0 मुख्य मंत्री जी तो इच्छुक हैं लेकिन बजट की मुश्किलों के कारण यह नहीं हो सका। बजट के बारे में भी मैंने चर्चा की है, अपना सुझाव रखा है कि शराब पीकर जो आदमी अपने बच्चों को नंगा देखा करता है, शराब पीकर पड़ा रहता है, मजदूर है, किसान है, नौजवान है जो कि शराब की लत में पड़ा हुआ है निश्चित रूप से अगर शराब के दामों में वृद्धि कर दी जाय जिससे 20 से 30 हजार करोड़ रुपये का बजट आता है जिससे एक साल के अन्दर पूरे प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में बदला जा सकता है। जिसका कहीं से भी कोई विरोध नहीं होगा। शराब की कीमत बढ़ा करके उन शराबियों के बच्चों का भविष्य बना देना यह हमारे बजट में होना चाहिए था। शराब के दाम बढ़ाने में कहीं से कोई भी आपत्ति नहीं होगी और न ही उसका विरोध होगा।

मान्यवर, आगे मैं बताना चाहता हूँ उच्च शिक्षा में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों, डेन्टल मेडिकल कॉलेजों में कहीं भी कोई भी प्राविधान आरक्षण का नहीं है जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया था। जबकि मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि तमाम विधेयक लाये जा रहे हैं, तमाम कानून बनाये जा रहे हैं इसी तरह यह भी एक महत्वपूर्ण कानून है कि जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें भी हमारे सामान्य वर्ग के जिनको 10 प्रतिशत का आरक्षण मिला है और 27 प्रतिशत का आरक्षण पिछड़ों को मिला है, 22.5 प्रतिशत का आरक्षण अनुसूचित जाति को मिला है अगर यह कानून बन जाता है तो उन्हें भी मेडिकल कॉलेज में एडमीशन का मौका

मिल जायेगा जिससे उन बच्चों को भी पढ़ने का अवसर प्रदान हो जायेगा। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। आगे मैं कहना चाहता हूँ कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हमारे बच्चे एक साल से स्कूल नहीं जा पाये हैं जिसके कारण उनकी पूरे साल की पढ़ाई प्रभावित हुई है, उनका भविष्य बिगड़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है बच्चे का दिमाग इधर-उधर भटक जाता है लेकिन स्कूलों को अगर देखा जाय तो पूरे साल स्कूलों का कोई भी खर्च नहीं हुआ है न पानी का, न बिजली का और न अन्य खर्चे बल्कि वहां के अध्यापकों का वेतन भी 50 प्रतिशत काट लिया गया है लेकिन जितने भी अभिभावक हैं उनसे स्कूल वालों ने पूरी की पूरी फीस वसूल ली है। पूरी ताकत के साथ वसूली जा रही है कि अगर आप नहीं देंगे तो आपके बच्चे का नाम काट दिया जायेगा। यह व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए कि उन प्राइवेट स्कूलों में जहां बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पूरी ताकत के साथ यह निर्देश दें कि आप लोग जब तक कोरोना काल में आनलाइन पढ़ाई हुई है किसी भी अभिभावक को चूंकि वह आर्थिक रूप से तंग हो चुका है। काफी परेशान हो चुका है, उसको राहत दिया जाये, उसकी फीस आधी की जाये जब वे अध्यापक की सैलरी आधी कर सकते हैं तो बच्चों की फीस भी आधी कर सकते हैं, मान्यवर, इसकी मैं मांग करता हूँ।

पिछड़ी जाति के जो बच्चे जिनकी छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से वह परीक्षाओं में नहीं बैठ पाये और उनका करियर बर्बाद हो गया यही छात्रावास अम्बेडकर छात्रावास है। मैं भी दलित परिवार से आता हूँ, बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की कृपा से इस सदन का सदस्य बना हूँ। मान्यवर मैं गया था वहां कई बच्चे अपनी पीड़ा रखे कि हम लोगों का नाम काट दिया गया हमको परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया क्योंकि हमारी छात्रवृत्ति नहीं आ पाई। माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन भी किया था लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि बजट की व्यवस्था उतनी नहीं है इसलिए हम लोग नहीं कुछ कर पायेंगे। बच्चों का करियर बर्बाद हो गया। मैं आपके माध्यम से इस सदन से मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को भी जोड़ा जाये ताकि किसी बच्चे का आगे भविष्य में चाहे वह पिछड़ी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे सामान्य जाति का हो, छात्रवृत्ति की वजह से उसका करियर बर्बाद न हो। वह अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखे।

आयुष्मान गोल्डन कार्ड के बारे में, मैं बात कर रहा था कि स्वास्थ्य सम्बन्धित जो आयुष्मान गोल्डन कार्ड सरकार ने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है 5 लाख तक तो उसमें अपने स्वास्थ्य की सुविधा ले सकते हैं लेकिन मान्यवर मैं बता रहा हूं कि जितने गोल्डन कार्ड है उस पर कहीं भी 5 लाख तक किसी भी गम्भीर बीमारी के लोगों को नहीं मिल पाता है। बहुत सारे गम्भीर बीमारी के लोग जिनको माननीय मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से हमने खुद 5-5 लाख रुपया 4-4 लाख रुपये माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि वे एक हफ्ते 15 दिन के अन्दर पैसा भेजने का काम करते हैं लेकिन उसमें भी एक कठिनाई है कि मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इस्टीमेट बनता है उसमें 50 प्रतिशत ही पैसा रिलीज़ करते हैं मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जो गरीब है मैं यह मांग करता हूँ माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जो भी गम्भीर रोगी है जो बीमार है जो किडनी से तमाम ऐसे रोगों से पीड़ित

हैं जिसमें 10 लाख तक के बजट आते हैं जिसमें 8 लाख 6 लाख तक के बजट आते हैं और जिसमें एक मुश्त पैसा अस्पतालों में जमा करना पड़ता है तभी उनका इलाज सम्भव हो पाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय उस परिस्थिति में गरीब आदमी को 3 लाख भेज देते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन 3 लाख की वजह से उसकी जान चली जाती है, वह पैसे वापस आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पर जरूर विचार किया जाय क्योंकि अगर उनको स्वस्थ रखना है, ठीक करना है उनकी मदद करनी है तो पूरी तरह से उनके इलाज की व्यवस्था करके हम उनकी मदद करें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली के क्षेत्र में मैं बताना चाहता हूं कि बिजली क्षेत्र में हमारी विधानसभा क्षेत्र पूरा कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और मजदूरों से बाहुल्य क्षेत्र है जहां की बिजली के खम्भें अभी पर्याप्त मात्रा में नियमित नहीं लग पाये। मैंने कई बार पत्र भी भेजें हैं जिसमें बांस-बल्लियों के सहारे बहुत दूर-दूर तक बिजली खींच कर ले जा रहे है, जिससे दुर्घटनाओं की सम्भावनाएं बनी रहती हैं और दुर्घटनाएं हो भी रही हैं। मैं माननीय बिजली मंत्री से भी मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जिस तरह से कहते है कि हम बिजली के क्षेत्र में सुधारात्मक कार्य कर रहे है तो निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा सरकार सभी काम कर रही है। अभी बहुत सारे सदस्यों ने बताया कि 70 साल में भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक काम किया लेकिन यही लोक भवन, मेट्रो रेलवे और स्टेडियम यह सब किसकी देन है इन लोगों ने सरकार बनते हो उद्घाटन करने का मौका पा लिया। मान्यवर यह भी इनका संयोग और सौभाग्य है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने यह सब बनाकर गिफ्ट में दे दिया कि लीजिये अपने नाम से उद्घाटन कर लीजिये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दिव्यांगजनों के विषय में एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। सरकार ने दिव्यांगजनों की पेंशन 500 रुपये की है लेकिन आज जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है उस आधार पर दिव्यांगजनों का भरण-पोषण 500 रुपये में होना संभव नहीं है। मेरा अनुरोध है कि दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाये। मान्यवर, 80 प्रतिशत दिव्यांगता पर मोटराइज्ड साईकिल देने का प्राविधान है लेकिन मेरा कहना है कि 80 परसेण्ट दिव्यांगता बहुत अधिक होती है और इस पोजीशन में बहुत सारे दिव्यांग मोटराइज्ड साइकिल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि सरकार इसमें संशोधन करके दिव्यांगता का प्रतिशत 60 परसेण्ट कर दें तो निश्चित रूप से बहुत सारे दिव्यांग इसका लाभ लेने लगेंगे और अपना कारोबार भी करने लगेंगे। मान्यवर, वर्तमान बजट में श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति का अनावरण करने का जो प्राविधान किया गया है उसका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2006 में हमारे नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने वाराणसी में अपने प्रयास से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति स्थापित कराई है। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास बहुत पहले से पूरे विश्व में जाना जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जाईये। आपके बोलने का समय समाप्त हो चुका है।

‡ **श्री हर्षवर्धन बाजपेयी**-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं इस अच्छे बजट पर सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं सर्वप्रथम आर्थिक आंकड़ों पर थोड़ी रोशनी डालते हुए अन्य मुद्दों पर बात करूँगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें सरकार को बधाई देनी चाहिये क्योंकि प्रदेश का जो ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है वह 21,73,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है। यह फाइनेन्सियल ईयर 2020 से 13 प्रतिशत ज्यादा है और यह फाइनेन्सियल ईयर 2021 की तुलना में 8.3 प्रतिशत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्र का जी0डी0पी0 कम हो रहा है और यदि आंकड़ों को देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर जी0डी0पी0 7.5 प्रतिशत घटेगा तो उत्तर प्रदेश का जी0डी0पी0 8 परसेण्ट से ज्यादा रहना यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में शायद ही कहीं पर ऐसी उपलब्धि होगी। इसके अलावा यदि हम लोग व्यय को देखें तो यह एक ऐतिहासिक बजट है। कई लोगों ने इसके बारे में बोला है इसलिये मैं एक लाइन में इस आंकड़े को दर्शाना चाहूंगा कि हमारा यह जो 5,50,000 करोड़ रुपये का बजट है वह फाइनेन्सियल ईयर 2020 से 20 परसेण्ट ज्यादा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है।

मान्यवर, परम्परागत तरीके से ज्यादातर आंकड़ों की तुलना पिछले वित्तीय वर्ष से की जाती है तो मुझे भी इसकी तुलना फाइनेन्सियल ईयर 2021 से करनी चाहिये लेकिन मैं ज्यादातर तुलना फाइनेन्सियल ईयर 2020 से करूँगा क्योंकि फाइनेन्सियल ईयर 2021 कोरोना की वजह से इतनी बुरी तरह से प्रभावित था कि सरकार के राजस्व और व्यय दोनों तरह के आंकड़े इतने प्रभावित हो गये कि उसके बारे में एक अच्छी तुलना हो नहीं पायेगी। यदि हम लोग ओवर ऑल बजट की पिक्चर देखें तो तीन प्रकार के जो बैलेन्सेज होते हैं उसमें रेवेन्यू बैलेन्स देखा जाये तो यह एक परसेण्ट सरप्लस में है, फिजिकल बैलेंस देखा जाये तो फिजिकल रेवेन्यू सरप्लस में एक प्रतिशत है। फिजिकल डेफिसिट में 4.17 परसेंट है और प्राइमरी डेफिसिट हमारा मात्र दो परसेंट है। इससे यह चीज समझ में आती है कि सरकार के इस साल के जो करेंट टैक्सेज है उससे जो सारा कर्जा लिया गया है उसे हम पूरा कर सकते हैं। हमें नये साल में कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। हमें जो भी कर्जा लेना है वह हम पिछले साल का पेमेंट करेंगे। यह एक अच्छी चीज है कि सरकार नये कर्जे, नये खर्चों के लिये नहीं ले रही है। यह इससे पता चलता है कि हमारा जो पूरा फिजिकल डेफिसिट है वह चार परसेंट हैं, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट जिसमें पिछले साल का अगर हम लोग ब्याज हटा दें तो वह मात्र दो परसेंट बनता है। इसका मतलब दो परसेंट का जो फर्क आ रहा है। फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में इससे सरकार पिछले साल का कर्ज पूरा कर रही है न कि इस साल नया कर्ज ले रही है। अगर हम लोग खर्चे की तरफ देखें तो सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है जो शायद किसी भी फाइनेंसियल ईयर में मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की किसी भी सरकार ने किया होगा।

---

‡ वक्ता ने भाषण की पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कैपिटल एक्सपेंडीचर में एफ0वाई0-20 के कम्पेरीजन में 35 परसेंट की बढ़त की है। बजट एस्टीमेट से 20 से लेकर इस फाइनेंसियल ईयर में कैपिटल एक्सपेंडीचर में 35 परसेंट की बढ़ोत्तरी है, जिसमें कैपिटल आऊट-ले जिससे सड़कें बनेंगी, जिससे हमारे कारखाने लगेंगे, जिससे हमारे ब्रिजेस बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे इन सब चीजों में 38 परसेंट मतलब की 35 परसेंट कैपिटल आऊट-ले है और उसमें 38 परसेंट प्रोडेक्टिव आऊट-ले हमारा बढ़ा है। यानी 35 परसेंट के रेट से भी 3 परसेंट ज्यादा। मैं अभी थोड़ा सा इसमें डिटेल पर आऊँगा कि इतना बड़ा खर्चा जो सरकार कर रही है वह कहां पर कर रही है ? लेकिन यह काबिले तारीफ है इसलिए क्योंकि हमारा देश कोरोना से ग्रस्त रहा है और ऐसे में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गयी है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैं अपने साथियों को बता दूं कि तीन मुख्य हथकंडे होते हैं जो किसी भी राष्ट्र के पास होते है, जिसमें से प्रदेश के पास मात्र दो हथकंडे होते है। केंद्र में क्योंकि वह आर0बी0आई0 से पैसा छपवा सकती है और इसलिए उनके पास मॉनिट्री पॉलिसी भी होती है और सरकार ने इसको इस्तेमाल भी किया है। हमारी आर0बी0आई0 ने बिजनेसेज को बहुत सपोर्ट भी किया है। मेरा खुद का जो बिजनेस है उसमें आर0बी0आई0 ने जो लूज मॉनिट्री पॉलिसी रखी है उससे बड़ा लाभ मिला है, लेकिन जो प्रदेश सरकार होती है उसके पास अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केवल और केवल फिजिकल पॉलिसी होती है और ऐसे में हमारी प्रदेश सरकार में डिमांड साइड इकोनॉमिक्स जो सबसे कारगर तरीका होता है बुरे समय में सरकार को देश को मजबूत करने का, प्रदेश को मजबूत करने का उसको इस्तेमाल करते हुए डिमांड साइड इनीशियल इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल करते हुए भारी मात्रा में डिमांड को क्रिएट करने के लिए पैसा इंजेक्ट करने का काम किया है।

निर्मला सीतारमण जी की जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है, जिसमें उन्होंने पी0एल0आई0 स्कीम के तहत प्रोडेक्टिविटी लिंक इंसेन्टिव स्कीम के तहत उन्होंने पूरे देश में अलग-अलग सेक्टर्स को चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग हो, चाहे वह अन्य कंस्ट्रक्शन की फोल्ड हो, चाहे रोड मेकिंग हो, चाहे मोबाईल मेन्युफेक्चरिंग हो, इन सबका जिक्र योगी जी ने भी किया था कि पहली बार एल0ई0डी0 स्क्रीन चाईना के बाद भारत में बनने जा रही है। यह सारी चीजें जो हो रही है वह सप्लाई साईड इकोनॉमिक्स को डिमांड साईड इकोनॉमिक्स से हमारी प्रदेश सरकार ने जो सपोर्ट दिया है इससे इकोनॉमी को डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा था कि किसी सरकार ने आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च नहीं किया है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ कि पानी सप्लाई एण्ड सैनीटेशन पर, मैं बताना चाहता हूं कि आपने आंकड़े पांच परसेंट, दस परसेंट, 15 परसेंट का अनुमान लगाया होगा, लेकिन वॉटर सप्लाई में 136 परसेंट का इजाफा हमारे बजट में है। आंकड़े के तौर पर एफ0वाई0-20 में तीन हजार करोड़ का बजट दिया गया था और इस बजट में 17 हजार 4 सौ करोड़ दिया गया है। तीन हजार करोड़ से 17 हजार करोड़, जिसमें से 15 हजार करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र में जल-जीवन मिशन को अकेले दिया गया है और 2000 करोड़ रुपये जो है 17000 करोड़ का वह शहरी पेयजल योजना के लिए दिया गया है। इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देखा जाये तो 26 प्रतिशत का इजाफा है एफ0वाई0 20 से 27 हजार करोड़

से 44 हजार करोड़ जिसमें से 8 हजार करोड़ की राशि तो हमारे प्रयागराज को गंगा एक्सप्रेस-वे के रूप में मेरठ से और दिल्ली से जोड़ने के लिए दी जा रही है। 7700 करोड़ यह बहुत बड़ी एमाउंट होती है। इसके अलावा हजार करोड़ पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को दिया गया है और 15 सौ करोड़ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को दिया गया है। हमारे गोरखनाथ बाबा भी बैठे हुये हैं जिनके शहर को भी एयरपोर्ट सिटी के लिए 241 करोड़, यह सारी चीजें दी गयी हैं। मेरठ को एक नई स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी, इसके अलावा मुझे लगता है कि एक आंकड़ा जो हम सबको याद रखना चाहिए चाहे वह अपोजीशन के साथी हो चाहे वह सत्तापक्ष के हो एक बहुत बड़ी लेगेसी रहेगी इस पहली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की हम लोग मानकर चलते थे कि हर कमिश्नरी में एक मेडिकल कालेज होता है लेकिन इतनी भारी मात्रा में मेडिकल कालेज बनवा दिये गये हैं। मेरे पास लिस्ट है कुछ बन रहे हैं, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षिप्त करिये।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, यह बन रहे है और 13 जिलों के लिए पैसा दिया जा रहा है। यह सारी चीजों को अगर देखा जाये तो मुझे लगता है कि इस सरकार की सबसे बड़ी लेगेसी यह होगी कि हर जिले में एक मेडिकल कालेज होने जा रहा है। यह बहुत बड़ी एचीवमेंट है। इस इतिहास को हम सबको याद रखना चाहिए। मैं एक बात और कहूंगा कि हमारी सरकार में जो कमिटेड एक्सपेंडीचर था उसकी अगर हम ग्रोथ देखेंगे एफ0वाई0 20 से एफ0वाई0 22 में तो जो कमिटेड खर्चा होता है वह तीन हेड का होता है तनख्वाह, पेंशन और इन्टरेस्ट जो तनख्वाह है, उसमे 19 प्रतिशत का इजाफा है पेंशन में 18 प्रतिशत का इजाफा है लेकिन ब्याज में मात्र 12 प्रतिशत का इजाफा है। 34 हजार करोड़ से 43 हजार करोड़। इसका मतलब कि हमारी सरकार ने जो रेवन्यू एक्सपेंडीचर भी किया है वह नौकरी देने में किया है न कि ब्याज का पैसा देने में किया है। यह बहुत बड़ी एचीवमेंट है। अब मैं एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि और लोगों को भी बोलना है कि हमारी सरकार ने एक बहुत बहादुर फैसला किया है कि हमारा जो फिसिकल डेफिसिट था बहुत कन्ट्रोल में हम ले आये थे उसको 03 प्रतिशत पर ले आये थे लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से राष्ट्र स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों ने जो जिम्मेदार सरकारें थी उन्होंने यह समझा कि अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो हमें इकोनामी में पैसा इंजेक्ट करना पड़ेगा हमें जाब्स क्रियेट करनी पड़ेगी। इसलिए हमारी सरकार जिम्मेदारी से अबकी बार फिसिकल डेफिसिट को 04 प्रतिशत की दर पर ले गयी है लेकिन इसके बावजूद मैं सरकार का डेड पेमेंट प्लान अगली पांच साल का देख रहा हूँ। फाइनेंसियल ईयर 24 में हमारी सरकार का जो कुल कर्जा होगा वह 28 परसेंट ऑफ जी0डी0पी0 होगा जो आज की तारीख में 30 परसेंट है। इसलिए कुल मिलाकर यह एक बहुत अच्छा बजट है। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम

देता हूँ कि सभी विधायकों के लिए यह सीख है चाहे वह अपोजीशन के हों, चाहे सत्तापक्ष के हों, क्योंकि यह आखिरी बजट है हम लोगों को एक दूसरे को कुछ कहकर जाना चाहिए। अगर अच्छा विधायक बनना है तो मुझे लगता है कि सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी नजर न आये और मुझे लगता है कि हर विधायक यह मानेगा कि यह बहुत अच्छी सलाह है, ''जुबां से जरा सा याद कर लेना अपने वादे, अगर तुम्हें जुबां का कहा याद आ जाये।'' बहुत-बहुत शुक्रिया।

***श्री रामरतन कुशवाहा-**

माननीय अधिष्ठाता जी, पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि तीन दिन लगातार पूरे टाइम बैठने के बाद आज नम्बर लग गया है। निश्चित रूप से सम्मानित वित्त मंत्री जी के द्वारा जो वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ और यह बजट सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धान्त के आधार पर बनाया गया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण विकास इस बजट के माध्यम से इस वर्ष 2021-22 में होगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी ओर से मा0 सदस्यगण से एक अनुरोध कर चाहूँगा कि कार्यवाही में विगत 04 वर्षों मे आप सभी को बोलने का बहुत मौका मिला होगा, लेकिन मैं आज पहली बार इस सदन में बोल रहा हूँ। जब प्रथम बार विधायक बनकर आया था तो प्रबोधन के समय विपक्ष के नेता श्री राम गोविन्द जी, श्री श्याम सुन्दर शर्मा जी और अन्य नेतागणों ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें सिखाई थीं, लेकिन उस तरफ बैठने का क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि उनको सिर्फ बुराई ही करनी है। चाहे जितनी अच्छी योजना हो, चाहे सरकार कितना भी बढ़िया काम कर रही हो, लेकिन हम चूंकि "न" की लॉबी में बैठे है तो हम केवल बुराई और विरोध ही करेंगे। मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि जब सरकार अच्छे काम करती है, सरकार विकास के काम करती है तो आप सभी को सहयोग की भावना के साथ सरकार का सहयोग करना चाहिए। मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सभी के माध्यम से जो हम नये लोग सीखते हैं, हम लोगों की बुद्धि पर किसी तरह का कुण्ठित प्रभाव न पड़े, इसके लिए आप सभी को वही सिखाना चाहिए कि जो हम बोलते है वह करें भी।

मैं आज के दिन, चूंकि बजट के सम्बन्ध में हमारे सभी लोगों ने बहुत सी बातें कहीं है लेकिन मैं उस संदर्भ में न जाकर मैं आपके माध्यम से अपनी विधान सभा क्षेत्र के कुछ कार्यों के लिए जरूर यह कहना चाहूँगा कि मैं अपनी विधान सभा के सभी मतदाता बंधुओं का जनसेवक हूँ और उस नाते उनकी समस्याओं को सदन में रखते हुए आपसे उसे पूर्ण कराने की मांग करते हुए कहना चाहूँगा कि हमारी विधान सभा क्षेत्र में तालबेहट विकास खण्ड है जिसमें राजकीय इण्टर कॉलेज की आवश्यकता है। तालबेहट से 20 कि0मी0 दूर पूराकलां है जो पिछले लोक सभा के चुनाव पर हमारे उप मुख्य मंत्री श्री दिनेश शर्मा जी के माध्यम से खुली बैठक में घोषित किया गया था। मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से उस इण्टर कॉलेज का निर्माण कराया जाए। इसी तरह से तालबेहट से पूराकलां की सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपनी बात रखूँगा। चूंकि हमारे पास शहर में जो आवागमन के साधन हैं, शहजाद नदी और बयाना नाले पर दो पुल ब्रिटिश समय से बने हुए हैं। उन पुलों का पुनर्निर्माण होना बहुत आवश्यक है और दोनों पुलों को इस बजट के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति देते हुए काम कराने की व्यवस्था की जाए। ठीक इसी तरह इन नालों और नदियों के किनारों एवं मुहानों को सौन्दर्यीकरण में लेते हुए स्वच्छता अभियान के तहत नगर क्षेत्र में जितनी दूरी तक नाले और नदी है उसके मुहाने को पक्का बंधवाते हुए धार्मिक स्थलों पर घाटों का निर्माण कर नगर के सौन्दर्यीकरण में सहयोग किया जा सकता है। मैं आपसे नगर विकास मंत्रालय की योजनाओं में इसको शामिल करके विकास कराने के लिए अनुरोध करूंगा। इसके साथ ही शहर के मध्य, जैसा अभी हमारे सुरेश तिवारी जी कह रहे थे कि छावनी क्षेत्र होने के कारण विकास नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह ललितपुर छावनी क्षेत्र नहीं है, लेकिन फौज विभाग के नाम शहर के बीचो-बीच में कई एकड़ों में जमीन कागजातों में दर्ज चल रही है। उस जमीन को परिवर्तित करने के लिए कई बार प्रस्ताव बना, लेकिन उस प्रस्ताव पर चूंकि पहले सरकारों की क्या मंशा रहती थी, मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं अपनी सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी सरकार ललितपुर के मध्य में जो फौज की जमीन है उसको स्थानांतरित करते हुए तालबेहट छावनी क्षेत्र में देने की कृपा करें। वहां पर जमीन बहुत खाली है और हमारा जिला प्रशासन इसकी योजना को बनाये हुए हैं। निश्चित रूप से हमारी विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय का विकास इस फौज विभाग की जमीन के कारण अवरुद्ध हो रहा है। मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि इस फौज विभाग के सम्बन्ध में इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव जरूर जाए।

मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ललितपुर जनपद पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यदि सरकार उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित करके ललितपुर का विकास करे तो निश्चित रूप से जो पिछड़ा- पिछड़ा कहा जाता है कि पिछड़े सुदूर क्षेत्र में है ललितपुर, यहां से दूरी 400 किमी है, अंतिम छोर से हम आते हैं और उस क्षेत्र के विकास में महती भूमिका होगी यदि पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र का विकास किया जाये। चांदपुर, जहाजपुर, देवगढ़, जुअन, नाराहट, मानसरोवर झील, करकरावल, झुमरनाथ का मंदिर और इसी तरह के अन्य कई क्षेत्र ऐसे है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पर्यटकों का आना जाना अभी कम होता है, अगर इस ओर ध्यान दे देंगे तो निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार की वहां व्यवस्था हो जायेगी। एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मुख्य मंत्री जी ने हवाई अड्डा बनने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। पहले से वहां हवाई पट्टी है और साठ-सत्तर एकड़ में वह पट्टी बनी हुई है, जिसका उपयोग काफी समय से नहीं हुआ है। निरंतर सर्वे किया जा रहा है, चूंकि वैधानिक दृष्टि से उसमें भी फौज विभाग की कुछ ज़मीन है, फौज विभाग की जमीन का उस भूमि में समायोजन हो जाये तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी हमारे यहां हवाई अड्डे की व्यवस्था हो जायेगी। इसके लिए इस विधान सभा के सत्र में मैं मा0 वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उसके लिए भी बजट का प्रावधान करें। आपने जो समय दिया उसके लिए मैं पूरे सदन का धन्यवाद दूंगा और अपनी विधान सभा

के निवासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपनी बात रखने का मौका आज आप सबके बीच मिला उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद्। जय हिंद जय भारत जय श्री राम।

***श्री संग्राम यादव-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वित्त मंत्री द्वारा रखे गये बजट पर मा0 नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए समय दिया। मान्यवर, जब वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश की विधान सभा में अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो पूरे उत्तर प्रदेश का जो गरीब, नौजवान, किसान, बेकार और कोविड-19 के कारण जो बदहाल व्यवस्था थी, सारे लोगों की नजर थी कि वित्त मंत्री जी अपने बजट में उन्हें राहत देने का काम करेंगे लेकिन बहुत घनघोर निराशा हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 श्री अखिलेश यादव जी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का बजट जो एक विदाई बजट है, यह जनता को रूला दिया। वाकई जनता में घनघोर निराशा फैल गयी, जनता को कोई उम्मीद नहीं रह गयी। हमारे सत्तापक्ष के साथी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। आप यहीं से निकल कर जाये तो शानदार लोक भवन आपको आकर्षित करेगा और जब आप इससे कुछ दूरी पर जाये तो क्या आप इतिहास के पन्नों को झूठला देंगे, लखनऊ के अंदर इतनी शानदार मेट्रो रिकार्ड समय में बनकर तैयार होकर जनता की सेवा में समर्पित हो गयी। जब आप गोमतीनगर विस्तार की ओर जाएंगे, ऐसे पुलिस मुख्यालय बना कि पूरे देश और दुनिया के लिए अनुकरणीय हो गया। उससे आगे जब शहीद पथ पर जाएंगे तो इकाना का अंतरर्राष्ट्रीय स्टेडियम इस बात की गवाही देता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा मुख्य मंत्री बने जो विजनरी मुख्य मंत्री हो। आप कैसे इतिहास के पन्नों को झूठला देंगे कि कैसे पुलिस की गाड़ियों को धक्का मारा जाता था, हमारी सरकार में तत्कालीन मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने पुलिस के लिए 100 नंबर का रिस्पान्स सिस्टम दिया, उससे बेहतर पुलिस सिस्टम नाम बदल कर 100 से 112 करके, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मान्यवर, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर शानदार एक्सप्रेस-वे मा0 अखिलेश यादव जी ने बनाया, शानदार लोक भवन बनाया, मेट्रो बनाया, उसे संचालित किया, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने का काम किया। मान्यवर, कोविड-19 के समय 108 को कैसे भूलेंगे, चकगंजरिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर अस्पताल बना है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप मा0 मुख्य मंत्री जी से बात करके एक बहुत बड़ी समस्या है, कैंसर की बीमारी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल बना है, आप उसको चला देते तो उत्तर प्रदेश की जनता पर महती कृपा हो जाती।

(इस समय 07 बजकर 07 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मंयकेश्वर शरण सिंह पीठासीन हुए)

आपने शिक्षा के बारे में कहा। मान्यवर, शिक्षा के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को न जाने कौन बताता है और कौन क्या राय देता है, हम उस पर नहीं जाते। कल माननीय मुख्य मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी विधान परिषद् में बोल रहे थे कि आजमगढ़ के अन्दर चाहे वह मा0 मुलायम सिंह यादव हों, चाहे वह मा0 अखिलेश यादव हो, उन्होंने कोई भी विकास का काम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ कि विधान परिषद् में कही हुई बातें, विधान सभा में कही हुई बातें, सदन की प्रापर्टी हो जाती है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आजमगढ़ के अन्दर राजकीय मेडिकल कालेज बनाने का काम मा0 अखिलेश यादव जी ने किया। उन्होंने सठियाँव में चीनी मिल रिकार्ड समय में 16 महीने में बना करके आजमगढ़ के अन्दर गन्ना किसानों को समर्पित करने का काम किया। सठियांव के अन्दर चीनी मिल बनाने का काम आजमगढ़ के अन्दर अखिलेश यादव जी ने किया। मान्यवर, इतना ही नहीं, आजमगढ़ को मण्डल मुख्यालय बना करके, आजमगढ़ को मुख्यालय बना करके मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने आजमगढ़ की महत्ता को स्थापित करने का काम किया। मान्यवर, इतना ही नहीं, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ के अन्दर जो कलेक्ट्री बनी है, वैसी कलेक्ट्री उत्तर प्रदेश के अन्दर कहीं नहीं दिखती है। आजमगढ़ के अन्दर एक ऐसा कलेक्ट्री भवन बनाया गया है कि जो भी जिलाधिकारी आता है, वह जब अपनी नजरों से देखता है, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आइये और देखिए। संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे मण्डल के हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह आयें और देखें कि उस तरह की कलेक्ट्री अगर उत्तर प्रदेश के अन्दर बन जायें तो अपने आप उत्तर प्रदेश का विकास दिखायी देने लगता है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, 02 मिनट और दे दें। इतना ही नहीं, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय का कैम्पस आजमगढ़ के अन्दर बनाने का काम हुआ और जिस हवाई पट्टी पर आपके प्रधानमंत्री जी उतरे थे, उस हवाई पट्टी को बनाने का काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। इतना ही नहीं, मान्यवर, हम तो आपसे कहना चाहते है, 200 बेड का हास्पिटल, राजकीय महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक कालेज मैंने गाँव के अन्दर बनवाया है, अपने विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र में, जहाँ पर पूरे आजमगढ़ के पूर्वांचल का विकास, वहीं पर मान्यवर, जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे है, जिसका चौधरी साहब की मूर्ति के सामने शिलान्यास हुआ था। आपका केवल यही काम हो गया कि शिलान्यास का शिलान्यास करो, उद्घाटन का उद्घाटन करो और बताओ कि हमने भी लोक भवन बना दिया, हमने मैट्रो बना दिया, हमने इकाना स्टेडियम बना दिया, अरे, कितना असत्य प्रलाप करेंगे आप ? आपके बजट में, आपके भारतीय जनता पार्टी के लोक संकल्प-पत्र में था कि हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनायेंगे। मैं छात्र नेता रहा हूँ, यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जी बैठे है, क्या आप एक भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में बना पाये ? कब तक आप गिनाओगे कि यह राम की धरती है, कब तक आप कहोगे कि शिव की धरती है, कृष्ण की धरती है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 संग्राम जी कृपया समाप्त करें।

डॉ0 संग्राम यादव-

राम और कृष्ण की यह धरती आपसे कहना चाहती है कि आप एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाओ, आप टेक्निकल विश्वविद्यालय बनाओ ताकि उत्तर प्रदेश का लड़का हुनरमन्द हो करके, अपने पैरों पर खड़ा हो करके दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करे। आप कब तक कहोगे कि यह कृष्ण की धरती है, कब तक आप कहोगे कि यह राम की धरती है। अरे, राम तो घट-घट में व्यापी हैं, राम को कौन नहीं मानता है। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले को सभी ने स्वीकार किया। लेकिन आपका जो बजट आया है, उसमें न तो किसान के लिए चिन्ता है, न तो गरीब के लिए चिन्ता है, आपका बजट खोखला है, आपके बजट से प्रदेश की जनता में घनघोर निराशा है। प्रदेश के गन्ना किसानों का जो बकाया है, उस बकाये को देने का काम आप नहीं कर पाये। चार साल हो गया है, लेकिन गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। आपने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जायेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टे खाद और बीज के दाम बढ़ गए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 संग्राम यादव जी, अब आप बैठिए अब आपका नहीं लिखा जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

श्री राजेश गौतम जी, आप बोलिए।

***श्री राजेश गौतम-**

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रखे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अधिष्ठाता जी, हम लोग अपने आपको सौभाग्यशाली मानते है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी और देश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी, जिन्होंने निरन्तर काम करके, जिनकी प्रशंसा इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व में की गयी। हम लोग अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि देश में प्रधानमंत्री और प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री ने एक अभिभावक के रूप में काम करके कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को रोकने का काम किया। आप बजट की बात करते है, हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा कि पेपर लेस बजट कि पेपर लेस बजट, ट्रुथ लेस बजट, इमोशन लेस बजट और हम कहते है कि हमारी सरकार आधुनिक सोच लेकर के चल रही है। आज हमारा युवा सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी कार्यवाही करता है, वह एक्टिव रहता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारे जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहे है। पेपर लेस बजट इस प्रतीक रूप में देखा जाएगा कि हमारी सोच, हमारी सरकार आधुनिक सोच लेकर के चल रही है। जैसे कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गांव पंचायत में ई-गवर्नेस की व्यवस्था की गई है। बजट को विपक्ष आंकड़ों का खेल बताकर के गुमराह करती है, लेकिन यदि उसमें जनकल्याण कार्य विकासवादी सोच और दूरदृष्टि दिखाई दे तो उसका चेहरा भावनात्मक और संवेदनाओं से भरा नजर आता है। बजट का महत्व उसके आकार से नहीं, बल्कि इस आधार पर आंका जाना चाहिए कि आम लोगों के प्रति वह कितनी संवेदनशील है। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं जिस विधान सभा से आता हूँ सुल्तानपुर जिले में कादीपुर विधान सभा है और बगल में अम्बेडकरनगर जिला है, उसके पीछे जौनपुर जहां से हमारे सम्मानित ललई भाई साहब जी की विधान सभा सटी हुई है। आपकी जब सरकार थी तो आप ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे और बगल में अम्बेडकरनगर जब हम लोग जाया करते थे, तो हम लोग भी सोचते थे कि जब सरकार बनी है तो कुछ सोचेंगे, अभी कि जैसे हमारे मित्र बोल रहे थे वह आजमगढ़ और लखनऊ से बाहर निकल ही नहीं रहे थे जो कि एक प्रदेश 24 करोड़ की जनता का प्रदेश है। जनता सोचती थी कि भाई अम्बेडकरनगर में जौनपुर में एक खास विधान सभा में आप ऊर्जा मंत्री रहे तो बिजली टिमटिमाती थी, तो वह भी सोचते थे कि हम लोगों के यहां कैसे आएगी तो मैं चंद लाइनें पढ़ना चाहूंगा। जब गरीब जनता सोचती थी, जब आपको चुनकर के भेजती थी, सत्ता में आप आते थे तो गरीब जनता सोचती थी कि हमारे बारे में भी सोचेंगे।

हमको मोहब्बत होगी उनकी भी और उनको भी हमसे मोहब्बत होगी।
एक से दोनों की हालत होगी जरूरी तो नहीं,
मुस्कुराने से भी बयाने गमें दिल होता है,
दर्द को रोने की आदत हो जरूरी तो नहीं।

उस दर्द को हमारी सरकार ने जाना है, उस दर्द को हमारी सरकार ने महसूस किया है। हम पंडित दीन दयाल उपाध्याय और डा0 साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं। एक नारा हुआ करता था, बाबा साहब की सोच थी शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, लोगों ने उसका उल्टा नारा कर दिया। संघर्ष किस बात का इन्हीं का नारा था तिलक तराजू इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। एक संघर्ष गांव में चलने लगा, संगठित किस बात का, वोट के नाम पर आपने संगठित किया। शिक्षा का कहीं अता-पता ही नहीं था। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने यशस्वी मुख्य मंत्री जी को कि कायाकल्प के माध्यम से जो गरीब, दलित, शोषित वंचित के बच्चे पढ़ने जाया करते थे एक ड्रेस जिसको देखकर के लगता था कि कहाँ के बच्चे आ गए हैं। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं वहीं बच्चे जूता, मोजा और स्वेटर पहनकर जाते है, उनको भी यह महसूस होता है कि हम भी अच्छी व्यवस्था में जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष बजट पर सवाल तो उठाएंगे ही, उठाना जायज भी है। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार ने कुछ काम ऐसे नहीं किए जिससे यह बौखला गए है। हमने लोक सेवा आयोग को किसी जांच विशेष का आयोग नहीं बनने दिया। हमारी सरकार ने अपराध अपराधी को संरक्षण नहीं दिया। हमारी किसी योजना को हमने कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का घुन नहीं लगने दिया और हम आपकी हिम्मत की दात देते है कि जब की सरकार थी, मुज्जफरनगर में दंगे हो रहे थे लोग सड़कों पर

थे। वहीं से बगल में सैफई में 3 सौ करोड़ के ठुमके लगाए जा रहे थे यह आपके सरकार की देन थी। कम्पटीशन करना है तो ईमानदारी का कम्पटीशन करिए। कम्पटीशन करना है तो अनुशासन का करिए। हमारी सरकार और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी पर उंगली उठाने वालों पर मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा।

भटकते रह गए वह बाहर, वह अंदर तक नहीं पहुंचे।
उछलते है वह दरिया, जो समंदर तक नहीं पहुंचे।
मेरे घर से चिढ़ थी जिन्हें पागल है वह सबके सब,
मेरा कद नापने आए, मेरे सर तक नहीं पहुंचे।

मैं वर्ष 2021-22 के इस बजट को पूर्ण रूप से समर्थन देता हूं। अधिष्ठाता महोदय, मेरी अपनी विधान सभा में दो कस्बे ऐसे है, सूरापुर बाजार बीस हजार की आबादी वाला बाजार है और करौंदी कला जो ब्लॉक है वह भो 20 हजार की आबादी वाला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर इसको नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जाए तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर हमारा विधान सभा क्षेत्र आगे और भी उन्नति करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्रीमती प्रतिभा शुक्ला-**

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। साथ ही अपने वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया और इसी के साथ ही साथ में यह कहना चाहूँगी कि जब कोरोना वायरस का समय चल रहा था तो पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा संकट छाया हुआ था और उस समय सभी लोग बहुत ही परेशान थे। केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व ही परेशान था। उस समय की यह दशा थी कि हम यह कहना चाहेंगे कि-

निर्वाक है हिमालय, गंगा डरी हुई थी
बलपुंज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई थी।

उस समय ऐसा वातावरण था लेकिन हम कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्य मंत्री जी ने एक सही निर्णय लिया और हम सभी लोगों को संकट से बचाया। आम जनता को संकट से बचाया। उस समय हमारे सदस्यों की तीन सदस्यीय समूह की बैठक होती रहती थी और वह हर समय कोरोना में पीड़ित लोगों की मदद के लिए हमेशा लगी रहती थी और 20 लाख लोगों को सहायता राशि दी गई। अभी हमारी सरकार ने टीकाकरण के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही साथ हम यह कहेंगे कि शहरी क्षेत्रों में 10 लाख 35 हजार लोगों को तुरन्त ही उन्होंने पेंशन देने का काम किया। साथ ही साथ एडवांस में वृद्धा पेंशन दे दी गई और जगह-जगह अन्न और खाना हमारे कार्यकर्ताओं ने जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने बाहर निकलकर सभी लोगों को अन्न का वितरण किया और साथ ही साथ कपड़े भी दिए। हम तो यह भी कहेंगे कि चप्पलों को भी दिया कि कही भी किसी को दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन अभी हमारे विपक्षी लोग कह रहे थे कि किसी ने कोई कार्य ही नहीं किया। जब कोरोना वायरस था तो उस समय सभी लोगों ने कार्य किया। हो सकता है कि आपने भी किया हो, जिसके साथ जो जुड़ा है तो सभी लोगों ने काम किया क्योंकि जब पूरे देश में संकट की घड़ी आती है तो सबको निकलकर काम करना पड़ता है।

किसानों के लिए राहत देने का काम हमारी सरकार कर रही है। किसी भी तरह से जो भी लोग अभी धरने पर बैठे है, हम तो यह कहेंगे कि वे किसान ही नहीं हैं। वे कुछ लोग ऐसे है जो उनको प्रोत्साहन दे रहे है और दलाल टाइप के लोग है। हम यह गन्दा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको प्रोत्साहन देकर भड़काने का काम कर रहे है। लेकिन हमारी सरकार जो है वह किसानों के लिए इतना अच्छा काम कर रही है कि उसने किसानों की फसल के लिए फसल बीमा योजना को चलाया। साथ ही साथ मृदा परीक्षण कराया और किसान सम्मान निधि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी मुख्य मंत्री जी ने प्रोत्साहित किया तो किसानों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपने विधान सभा क्षेत्र में जाती रहती हूँ वहाँ कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है और ये जो किसानों के तीन बिल आए है, उनसे कोई भी नाराज नहीं है। हम लोग अपने क्षेत्र में बराबर निरन्तर जाते रहते हैं। हमने देखा है कि जो आम किसान है, छोटा किसान है, वह बिल्कुल खुश है। उसको अपनी फसल की सुरक्षा के साथ-साथ मण्डियों में बेचने के लिए पूर्णतया से कही कोई दिक्कत नहीं है। चाहे रबी की फसल, चाहे खरीफ की फसल हो कहीं किसी को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। वे बिल्कुल सन्तुष्ट है और हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि जो बड़े किसान हैं, जगलर्स है उनका जरूर घाटा हो गया। इसके साथ ही साथ चूंकि मैं महिला हूँ तो मैं महिलाओं के लिए जरूर कहूंगी कि हमारे मुख्य मंत्री जी इस भावना को लेकर चलते है कि-

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास-जगत नग पगतल में
पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।

उन्होंने नारी शक्ति मिशन चलाकर अब नारी को पुरुष के समान खड़ा कर दिया है। अब उसको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा भी यह मानना है कि आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। वह न पुरुष होता है, न स्त्री होती है। लेकिन फिर भी उन्होंने शक्ति मिशन चलाकर नारी को शक्तिशाली बनाया है, इस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। शक्ति मिशन में जगह-जगह काम कर रहे है। इसमें उन्होंने पोषण के माध्यम से काम किया है कि हमारा कुपोषण न हो, नारी शिक्षित हो और साथ ही साथ महिला डेस्क चलाकर उन्होंने जो मुकदमे लगते हैं, उस पर भी पूरी तरह से सुरक्षा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके साथ ही साथ हम यह कहेंगे कि आज सामूहिक विवाह योजना चली है। पहले बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं होते थे लेकिन दहेज प्रथा जैसे दानव को समाप्त करने का काम हमारे मुख्य मंत्री

जी ने किया है क्योंकि जब सामूहिक विवाह होता है तो दहेज दानव के कारण पहले हमारी बेटियाँ जला दी जाती थी लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे हमारे गरीब लोग भी अपनी बेटियों का विवाह आसानी से कर लेते हैं और साथ ही साथ प्रशंसा का अनुभव भी करते है। अब तो बहुत से लोग हमसे भी कहते है कि विधायक जी हमारी बेटी का विवाह सामूहिक विवाह योजना में शामिल करवा दीजिए। पहले इसको हीन दृष्टि से देखा जाता था लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही साथ मा0 अधिष्ठाता महोदय हम अपनी विधान सभा के विषय में जरूर कहना चाहेंगे। हमारी विधान सभा क्षेत्र कानपुर देहात अकबरपुर रनिया के अन्तर्गत बहुत ज्यादा नहर पर पट्टी बनी हुई है लेकिन दो पुलों की सख्त आवश्यकता है एक मैथा ब्लॉक में पुल है जो कि अभी क्षतिग्रस्त हो गया है। बहुलदेवी जो एक मान्यता प्राप्त देवी है, ऐतिहासिक देवी हैं उनके यहाँ कदम पुलिया बनाने की हमें सख्त आवश्यकता है। इसी के साथ ही साथ हमारा रनिया औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें ड्रेनेज की बहुत समस्या है। वहाँ पर जल भराव हो रहा है इसके समाधान की सख्त आवश्यकता है। मा0 अधिष्ठाता एक बिन्दु और रह गया है हमारे यहाँ आर0ओ0बी0 बन रहा है उसमें क्षेत्र की जनता ने यह माँग की है कि वहाँ अण्डर पास भी बनना चाहिए। मैं माननीय केशव मौर्या जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी मैंने उनके पास प्रस्ताव भेजा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे वित्त मंत्री जी के वर्ष 2021-22 के बजट भाषण पर नेता प्रतिपक्ष की बातों से खुद को सम्बद्ध करते हुए इस बजट के संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ हम लोग आते है और तमाम आवाम यह समझकर, सोचकर अपना भरोसा अपना विश्वास, अपना यकीन हम सब को सौंपती है कि जाओ प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी तरक्की के तमाम रास्ते खोजो हमारे बच्चों का कैसे विकास हो उनसे सम्बन्धित मुद्दों पर बहस करें, उस पर चिंता करें। हमारा बच्चे शिक्षित कैसे हो, हमारे व्यापारी तरक्की कैसे करें और हमारा गाँव, गरीब तथा किसान कैसे आगे बढ़े इन बातों पर चिंतन और मंथन करने का काम करो यही सोचकर तमाम आवाम हम सबको यहाँ भेजने का काम करती है। मान्यवर, हम लोगों के तमाम साथी हैं, जो विकास की बात नहीं करते हैं वो कहेंगे। इन्होंने अच्छा किया और हमें कहेंगे इन्होंने खराब किया। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूँ कि चार साल इस सरकार को लगभग पूरे हो रहे हैं लेकिन एक योजना बता दे कोई भी जनहित और कल्याणकारी योजना जो अभी शुरू हुई हो। कभी मोदी जी का गुणगान, कभी दूसरों का गुणगान, जाने कौन-सी योजना आ गई अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि "हर घर नल, हर घर जल," मा0 अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2016 से 42 पानी की टंकियाँ बनकर बाराबंकी खड़ी है लेकिन एक भी घर में आज तक पानी पहुँचा हो तो जो भी सजा आप देना चाहेंगे सम्मानित विधायक मैं लेने को तैयार हूँ। बाराबंकी यहाँ से दूर नहीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम

आवाम की तरक्की के तमाम रास्ते यहाँ से खुले हैं, हमारे तमाम पूर्वज नेता यहाँ रहे हैं और जिन्होंने वास्तव में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। तमाम आवाम की तरक्की के तमाम रास्ते खुले हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ ये हमारी निंदा करें और हम इनकी निंदा करे इससे क्या होगा ? आप देख रहे हैं कि विधायिका के बाहर क्या हाल हो रहे है ? हमारा क्या सम्मान बचा है। कोई हमको चोर बताता है कोई उधर चोर बताता है आखिर यह सब क्या है, अब यही बचा है। तमाम आवाम के बीच से हम लोग जीतकर आते हैं। तमाम पुराने विधायकों के साथ बैठकर सीखना चाहे तो सीखे चाहे वह हमारी तरफ के लोग हो या उधर के हो। हमारा आज क्या सम्मान बचा है ? हम लोग क्या कर रहे हैं ? हम लोग केवल गुणगान कर रहे हैं, मैं तमाम आवाम के बीच में कहना चाहता हूँ और हमारे सम्मानित विधायक भी यहाँ पर है अगर हम देखें मा0 अधिष्ठाता महोदय तो देश में केवल धर्म और जाति के नाम पर तमाम विरोधियों को परेशान करने के नाम पर हर प्रकार से प्रताड़ित करने का काम यह सरकार कर रही है। मान्यवर, अगर हम देखें तो विधि आयोग में पूरे हिन्दुस्तान में 816 मामले राजद्रोह के दर्ज हुए थे, विधि आयोग की रिपोर्ट का 10 साल का आँकड़ा हम दे रहे हैं। मान्यवर, उसमें जहाँ 5 भाजपा शासित प्रदेश है मैं उनका आँकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाजपा या तो वहाँ पर अभी है या इससे पहले वहाँ पर थी। मान्यवर, तमिलनाडु में 139, यू0पी0 में 115, झारखण्ड में 62, कर्नाटक में 50 और बिहार में 168 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए।

मान्यवर, ऐसा क्यों हैं ? क्योंकि हम अपने विरोधियों पर जाने कितने-कितने गंभीर मुकदमें लगाने का काम कर रहे है। क्या यही हमारा राजधर्म है ? क्या यही हमारी सोच होनी चाहिए ? कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, यह क्या है ? इसी प्रकार से कई सौ साल पहले हिन्दुस्तान में अंग्रेज आए। तब यहां मुगलों का शासन था। तमाम हिन्दू राजाओं को अंग्रेजों ने बहलाया, बरगलाया और कहा कि "ऐ हिन्दू राजाओं मेरी मदद करो, मैं आपको यहां का राजा बना दूंगा, और मुगलों को यहां से भगाने का काम करूँगा"। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वही काम भारतीय जनता पार्टी ने हिन्दू-मुस्लिम के नाम से सत्ता हासिल करने का काम किया है। मान्यवर, यह देश हिन्दू-मुस्लिम से चलने वाला नहीं है। हम तमाम लोगों के बीच देखना चाहते हैं कि कितने अस्पताल बने हैं। चकगंजरिया फार्म बाराबंकी शिफ्ट हुआ और आज तक नहीं चला। क्या उसमें समाजवादी लोग ही इलाज कराने जाएंगे ? माननीय अखिलेश यादव जी की जो सोच थी, यह पूरा चकगंजरिया हमारी बाराबंकी में शिफ्ट हुआ।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

मान्यवर, थोड़ा सा संरक्षण चाहूँगा। हम कहें कि सड़कों की हालत देखिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि देखा जाये तो बहुत बढ़िया बजट होता है। तमाम लोग तारीफ करते हैं। दिसम्बर, वर्ष 2015 से बना अस्पताल बाराबंकी में पी0एच0सी0 यदि जायें, जो बबरी गांव के पास है, आज तक आप शुरू नहीं कर पाएं है। यही स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हैं ? अस्पताल बना

खड़ा है, आप मैनपावर नहीं दे रहे है। यदि मैं कहूँ कि इस सरकार ने तो भगवान को भी पक्ष और विपक्ष में बाँटने का काम किया है। एक योजना पर्यटन विभाग की चली है, "मुख्यमंत्री संवर्द्धन योजना"। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बाराबंकी में सभी विधायकों ने सरकार को प्रस्ताव दिया था। अभी 3 दिन पहले शहर से जानकारी हुई और अखबारों में प्रकाशित भी हुआ कि 4 भाजपा के जो विधायक हैं, उनके धार्मिक स्थलों पर 49 लाख रुपया देने का काम इस सरकार ने किया और समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, उनको पैसे देने का काम नहीं किया है। आप तो भगवान को भी पक्ष और विपक्ष में बाँटना चाहते हैं। यह कौन-सी बात हुई ?

(किसी सदस्य के टोका-टाकी करने पर व्यवधान)

हमारी सरकार में यहां जितने पुराने हमारे मा0 सदस्य बैठे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप हमारी तरफ देखिए, दूसरों की बात न सुनिए। आपका समय खत्म हो जायेगा।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

मान्यवर, क्षमा चाहूँगा। जितने भी हमारे सदस्य हैं, मा0 अखिलेश यादव जी ने सबका सम्मान किया था और सभी के लिए बराबर काम करने का काम किया था।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद सुरेश जी।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

मान्यवर, अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा। मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहां चिल्लाने- चीखने से आपकी आत्मा तो तृप्त हो सकती है लेकिन आपकी पीढ़ियाँ आपसे सवाल करेंगी, कि "ऐ बाबा, ऐ बप्पा, यह एक सरकार आयी थी और देश बेच रहे थे तो आपने उनकी मदद की थी या उनका विरोध करने का काम किया था। "आप सब नजर नहीं मिला पाएंगे, यह मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। मा0 अखिलेश यादव जी की बराबरी करने का कोई मतलब नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, धन्यवाद। मा0 वेद प्रकाश गुप्ता जी।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

मान्यवर, किसान सम्मान निधि, आपने 2 करोड़ 40 लाख परिवारों को देने की बात की परंतु बाकी लोग कहाँ है, उनको नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, वेद प्रकाश गुप्ता जी।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

हुजूर, मैं अपने क्षेत्र की केवल एक बात कहना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

बस हो गया, अब आप बैठ जाइये। माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी।

(सदस्य का अपनी सीट से निरंतर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका लिखा नहीं जा रहा है।

***श्री वेद प्रकाश गुप्ता-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-22 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रदेश का पहला पेपर लैस बजट साढ़े 5 लाख करोड़ का पेश किया गया। इसके साक्षी हम सभी बने, यह हमारे लिए गौरव का क्षण है। माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह प्रदेश सरकार निरंतर जन कल्याण के लिए समर्पित हो कर कार्य कर रही है। गरीबों, वंचितों, महिलाओं, युवाओं, किसानों सभी वर्गों के लिए विशेष प्रकार की योजनाओं को लागू करते हुए विकास की ओर आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा पर कार्य कर रही है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह बजट उत्तर प्रदेश को अब तक की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला पहला बजट है। यह बजट उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाकर स्वावलंबन से सशक्तीकरण पर ले जाने वाला बजट है। यह बजट सभी वर्गों को खासकर युवाओं को स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत, महिलाओं को सम्मान, किसान भाइयों की आय को दोगुना करने वाला है। साथ ही प्रदेश की धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, धरोहरों को सहेजने और प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने की दिशा में आगे ले जाने वाला यह पहला बजट है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का संकल्प किसान भाइयों की आय को दोगुना करना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हमारी सरकार ने किसान भाइयों को उन्नत तकनीक, प्रशिक्षण एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नहरों की टेल तक पानी पहुंचा है। हमारे बहुत सारे साथी सिंचाई की बात कर रहे थे आज तक टेल में कभी पानी नहीं पहुंचा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहरों पर पुलियों के मरम्मत/ पुनर्निर्माण व नवनिर्माण के कार्यों का शिलान्यास अभी जल्दी ही किया है, जिन पर आजादी के बाद आज तक कोई भी कार्य नहीं किया गया था, जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डा0 महेन्द्र सिंह, जल शक्ति विभाग, मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गन्ना किसानों का भुगतान, आत्म निर्भर कृषक संबंधित विकास योजना, मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, रियायती दरों पर फसली ऋण जैसी कई योजनाओं से किसान भाइयों का कल्याण हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत 02 करोड़ 40 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाकर हमारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री वेद प्रकाश गुप्ता-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अयोध्या से सेवक हूं और आपसे अनुरोध है कि अयोध्या के बारे में सब लोग बोले चाहे पक्ष-विपक्ष, मुझको कुछ अवसर दे दीजिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मुझे कहने में गर्व की अनुभूति हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर करने और 23 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में कोरोना महामारी का डटकर सामना किया, जिसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की है और डब्ल्यू0एच0ओ0 ने भी की है। आरोग्य मेला मरीजों के लिए संजीवनी बन रहा है। जिला चिकित्सालयों का उच्चीकरण किया गया है। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में टी0पी0 मोड पर मेडिकल कालेजों की स्थापना करायी जा रही है। जिससे प्रदेश के किसी भी मरीज को इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी यह हमारे लिए गौरव का विषय है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोग व्यापारियों की बात करते है, मैं व्यापारी समाज से हूं, व्यापारी वर्ग ऐसा विशेष वर्ग है जिसकी सहभागिता के बिना किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उस व्यापारी वर्ग के लिए एक राष्ट्र, एक कर जी0एस0टी0 की व्यवस्था, पेंशन की व्यवस्था शुरू करने का कल्याणकारी कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पटरी दुकानदारों को एक-एक हजार रुपये की सहायता दी गयी। व्यापारी दुर्घटना बीमा को 05 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विद्युत व्यवस्था की स्थिति दयनीय थी, बिजली कब और कितने समय के लिए आयेगी, इसका कोई पैरामीटर नहीं था, माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में लॉइन लास को कम किया गया है और प्रदेश की शहरी क्षेत्रों को 24 घण्टे, ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे बिजली देने का ऐतिहासिक कार्य किया गया।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वेद प्रकाश गुप्ता-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अयोध्या के बारे में कहना चाह रहा हूँ। मुझे अयोध्या के बारे में बोलने का अवसर दीजिये। आपके संरक्षण की आवश्यकता है। आपसे 2 मिनट लूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

उस पर आपको पहले बोलना चाहिए था।

***श्री रत्नाकर मिश्र-**

बोलिये, माता विंध्यवासिनी की, जय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय योगी जी के द्वारा जो माननीय खन्ना जी बजट लाये वह बहुत अच्छा है। क्योंकि जनहितकारी है, जन-जन के लिए, अभी तक तमाम सरकारें आयी, मां विंध्यवासिनी के तमाम लोग भक्त थे लेकिन किसी ने भी आज तक वहां ध्यान नहीं दिया। चाहे अयोध्या हो, चाहे देवीपाटन, चाहे नैमिषारण्य, चाहे चित्रकूट हो कहीं भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हर जगह माननीय योगी जी ने बजट दिया, काशी में भी बजट दिया। जल के लिए देखा जाय तो जैसे बुन्देलखण्ड में था वैसे ही हमारा विंध्य क्षेत्र भी था वहां नल के द्वारा पानी दिया जा रहा है और खेती में जो दोगुना आमदनी कही जा रही था, चन्दौली जिले के विधायक जी होंगी। आप जानते है कि वहाँ काला धान करीब 300 एकड़ में पैदा किया जा रहा है जो कि 60 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। यह यहाँ पहली बार हुआ और जिसे भूटान, आस्ट्रेलिया और कतर में जाना चालू हुआ। इस प्रकार से तमाम योजनाओं को अगर देखा जाय। रोड को देखा जाय, बिजली को देखा जाय जो कि नहीं आती थी, वह आज हर गांव में आ रही है। आज मंदिर हमारा देखा जाय तो विन्ध्य कॉरीडोर के नाम से काफी हद तक दूसरा स्वरूप सामने आ गया है लोग अगर वीडियो देखते होंगे तो उससे ही पता चलना चालू हो जाता है। तमाम हमारे सामने के मित्र लोग हिन्दू, मुस्लिम के नाम पर बोल रहे थे और अपने माननीय विपक्ष के नेता राम गोविन्द जी भी कहे कि 14 बरस वनवास के बाद आप लोग आ रहे है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 14 बरस के बाद जब प्रभु श्री राम आये थे तो सभी लोग जानते है कि सब जगह उन्हीं का राज्य था, किसी दूसरे का राज्य था ही नहीं। राम और रावण में क्या अंतर था उनके बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि रावण मनुष्य को पशु बना देता था। मारीच को जो सोने का मृग बनाया गया था तो वह पशु ही था और प्रभु श्रीराम में क्या अंतर था वह प्रभु श्रीराम ही थे जो बंदर, भालू, आदिवासी, वनवासी को देवता की श्रेणी में ला देते थे। हनुमान जी क्या थे, एक बंदर ही थे, आज वह घर-घर पूजनीय हो गये है यह प्रभु श्रीराम का ही प्रताप था।

श्री धर्मराज सिंह यादव "उर्फ सुरेश यादव"-

माननीय सदस्य हनुमान जी को बंदर न कहें, मैं भी हिन्दू हूँ और हनुमान जी हमारे भी पूजनीय है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य आप कृपया बैठिये। कृपया टोका-टाकी न करें।

श्री रत्नाकर मिश्र-

आप बैठिये, जब आप बोल रहे थे तो हमने आपको नहीं टोका था। आप लोग हिन्दू मुसलमान के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग राम के भक्त हैं। क्योंकि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रभु श्रीराम ही घर-घर में हनुमान जी को पूजनीय बना दिये। यह राम और रावण में अंतर था, उसी तरह इधर रामभक्त लोग हैं जो कि सबको मनुष्य बनाते है और आप लोग पशु बनाने का काम करते हैं। कृष्ण के समय में दो वंश चल रहा था एक कृष्ण भक्त थे और दूसरे कंस भक्त थे। आप लोग तो हिन्दू, मुसलमान के नाम पर बॉटने का काम करते हैं। हम लोग हैं प्रभु राम के नाम पर सबका साथ, सबका विकास और आदिवासी, वनवासी, बृजवासी सबका काम करते हैं। हम लोग किसी की जाति बिरादरी देखकर काम नहीं करते। जाति बिरादरी के नाम पर आप लोग वोट लेते है। कृष्ण के समय भी दो वंश चल रहा था आधे लोग कृष्ण को मानने वाले थे और जो कंस को मानने वाले लोग हैं वह आज उधर बैठे है, जो कि कृष्ण के और श्री राम जी के नाम पर चिढ़ते हैं। अब मैं अपनी विधान सभा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे विधान सभा में एक रामकोट जोता मार्ग पर पुल देने की मांग हम करते हैं जिससे कि लाखों लोगों को आवागमन में फायदा रहेगा, गंगा सेतु है और मिर्जापुर नगर में एक नये फोर लेन पुल की भी मांग करते है इसी के साथ हम इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हैं धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय।

***श्री ओमकार सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, इस सदन में बड़ा भारी भरकम बजट पेश किया गया, लेकिन मेरे विचार से यह जनता के किसी काम का बजट नहीं है। यह जनता के साथ धोखा है, छलावा है और जनता को भ्रमित करने वाला बजट है। सरकार में किसान बरबाद हो रहा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलायें सुरक्षित नहीं है। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरा यहाँ नाधा में डिग्री कॉलेज और इन्टरकॉलेज है, लेकिन वहाँ चार साल से एक-एक मास्टर है। अस्पतालों में कुत्ते के काटने का इंजेक्शन 6 महीने से नहीं है। मेडिकल कॉलेज में पूरा स्टाफ नहीं है और मेरी विधान सभा क्षेत्र में, सहसवान में 10 से 6 घण्टे सप्लाई आती है। मैं चाहता हूँ कि नाधा, जरीफनगर, दहगवां, सहसवान, खितौरा, उधैती, इस्लामनगर व रुदायन की क्षमता वृद्धि कर दी जाये और इनकी जर्जर लाइनों को बदल दिया जाये जिससे किसान और वहाँ की जनता को राहत मिल सके। एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि-

"हम तो सब झेल के आ पहुँचे किनारे के करीब,
तुम खबरदार कि दरिया भी है, गर्दाब भी।"

श्री अधिष्ठाता-

माननीय ओमकार सिंह जी को बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 अरुण कुमार-

धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय, आपने हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रस्तुत बजट में बोलने के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हिन्दुस्तान की किसी भी विधान सभा का यह पहला पेपर लेस बजट है और प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ रुपये से अधिक का बजट पहली बार प्रदेश में प्रस्तुत किया गया है। यह देश की 5 ट्रिलियन डालर इकोनामी की ओर देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। गाँव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के उत्थान के लिए यह बजट है। अधिष्ठाता महोदय, यह बजट कोविड-19 की महामारी के बाद का पहला बजट है, जिसमें आमदनी कम रही, फिर भी यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन एवं वित्त मंत्री, माननीय श्री सुरेश खन्ना की सूझबूझ एवं वित्तीय अनुशासन बनाये रखने की वजह से जनकल्याणकारी कार्यों, वेतन तथा पेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मार्च, 2020 में जब कोविड शुरू हुआ तब हमारे प्रदेश में कोविड टेस्ट की एक भी लैब नहीं थी, एक भी जाँच की सुविधा नहीं थी, जबकि आज 129 लैब है और 2 लाख टेस्ट रोज होने की हमारे पास इंतजाम है। हर जिले में लेविल-2 अस्पताल स्थापित किया गया तथा मण्डल मुख्यालय पर लेविल-3 का अस्पताल स्थापित किया गया। कुल डेढ़ लाख बेड की कोविड इलाज के लिए व्यवस्था की गई। यह कुशल व्यवस्था की वजह रही कि हमारे यहाँ इतनी अधिक पापुलेशन, डेंस पापुलेशन होने के बाद भी मुत्यु दर बहुत कम रही और लगभग 8 हजार के करीब ही मृत्यु हुई। वैसे तो एक भी मृत्यु बड़े अफसोस की होती है, लेकिन हमारे यहाँ और जगहों से बहुत कम रहीं, जबकि और देशों में और प्रदेशों में हमसे कहीं ज्यादा डेथ हुई। हमारे यहाँ रिकवरी रेट 98 परसेण्ट से ज्यादा रहा और डेथ रेट 1.5 परसेण्ट के करीब रहा और मोदी का यह कहना कि जान है, तो जहान है। जो हमारे यहाँ योगी जी ने व्यवस्था रखी, उसी की वजह से यह रहा है कि जान है, तो जहान है। लेकिन उसके बाद में जान भी, जहान भी। कोविड वैक्सीनेशन के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और कोविड वैक्सीनेशन बहुत तेजी से शुरू हो गया। लोग इसकी ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही कोविड वैक्सीनेशन और बढ़ेगा और कोविड हमारे प्रदेश से और देश से जल्दी समाप्त होगा। इसके साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना, मुख्य मंत्री आरोग्य योजना, आरोग्य मेले आदि आयोजित किए जा रहे है, जिससे जनता को स्वास्थ्य में बहुत फायदा हो रहा है। सबसे बड़ा एक काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हुआ है, वह है डायग्नोसिस बुनियादी ढाँचा। पीएचसी पर 1073 करोड़ रुपये जिसके लिए दिए गए है और मुझे उम्मीद है कि रूरल एरियाज में भी और अरबन एरियाज में भी डायग्नोसिस फैसिलिटीज और ज्यादा बढ़ेगी, ताकि बेहतर इलाज हो। 2017 में हमारे प्रदेश में 15 मेडिकल कालेज थे, जबकि आज 30 अन्य मेडिकल कालेजों में निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ में ओपीडी सर्विस शुरू हो गयी है, वहाँ पर एडमिशन शुरू हो गए है, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे प्रदेश में 15 के बजाय 45 मेडिकल कॉलेज होंगे।

माननीय अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ को ज्यादा अपग्रेड किया गया है ताकि हमारे प्रदेश के अन्दर जितने भी मेडिकल स्टूडेन्ट्स है, उनको बेटर गवर्नेस मिले, उनके ऊपर बेटर कन्ट्रोल हो, एग्जाम्स हो, एकरूपता हो और बच्चे मेहनत करके खूब तरक्की करे। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि बरेली के आस-पास सरकारी मेडिकल

कॉलेज, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत और उत्तराखण्ड के हल्द्वानी में है लेकिन बरेली में कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। मैं चाहता हूं कि बरेली में एक एम्स स्तर का इन्स्टीट्यूट जल्दी ही खोला जाय। हमारे बरेली में एक 300 बेड का नया अस्पताल बना है, जिसके एक हिस्से में कोविड-2 अस्पताल इस समय चल रहा है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर सुपर स्पेस्लिटी हॉस्पिटल बनाया जाय। सरकार के पास सुपर स्पेस्लिस्ट्स बहुत कम हैं, मेडिकल कॉलेजेज तक में सुपर स्पेस्लिस्ट्स ढूंढने पड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तीन सौ बेड के अस्पताल में पी0पी0पी0 मॉडल पर सुपर स्पेस्लिस्ट मिल जायेंगे इसलिए सुपर स्पेस्लिटी हॉस्पिटल शुरू किया जाय। इसके साथ ही साथ बरेली में एक बड़ी इण्डस्ट्री की भी मैं मांग करता हूँ। स्वच्छता के लिए मैं यही कहूंगा कि आज हमारा पूरा प्रदेश ओ0डी0एफ0 डिक्लियर है। हर घर में पाइप वाटर सप्लाई शुद्ध पेयजल के लिए सरकार वचनबद्ध है। शहरों के अन्दर और देहाती एरिया में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ ही साथ अमृत योजना में तरल अवशेष प्रबन्धन, सीवरेज प्रबन्धन के लिए जो 22 सौ करोड़ रुपए दिये गये है इससे शहरों के अन्दर काफी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट होगा। स्मार्ट सिटी के अन्दर दो हजार करोड़ रुपए दिये गये हैं। महिलाओं के लिए हमारी सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है, आधी आबादी का पूरा ख्याल जो हमारी सरकार रख रही है वह एक मिसाल है। मिशन शक्ति में सुरक्षा और स्वावलम्बन को बढ़ावा दिया गया है, महिलाओं का कुपोषण दूर करने के लिए योजनाएं चलायी जा रही हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

डॉ0 अरुण कुमार-

कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत परिवार के अन्दर बेटियों का सम्मान बढ़ाने के लिए 15 हजार रुपए 6 फेजेज में दिये जा रहे हैं ताकि बेटी के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूंगा कि हमारी सरकार ने जो जनहित के काम किये हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है और यह बजट हमारे प्रदेश को और ज्यादा तरक्की के रास्ते पर ले जायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय।

***श्री केसर सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बजट 2021-22 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। यह बजट लोकहित, किसान हित और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए है। सबसे पहले तो मैं अपने मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए अपनी दृढ़ता का जो संकल्प लेकर प्रदेश का विकास किया उससे हम लोग अपनी विधान सभाओं में जो वादा करके आये थे वह पूरे हुए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अलावा माननीय योगी जी ने देश में जो अपना स्थान बनाया, हम देखते हैं कि देश की दूसरी विधान सभाओं में जब चुनाव होते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी की बाहर से डिमांड होती है और वह जाते है और जब वह चुनाव की मीटिंग करके आते हैं तो बाद में अखबार और टी0वी0 चैनल्स के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि योगी जी के आने से बिहार की सरकार बन गई। इस तरह से जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग खुशी से गदगद हो जाते है। हमारे विपक्ष के साथी इसे हमारा आखिरी बजट बता रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह आखिरी बजट नहीं है, वर्ष 2022 का बजट भी हम लोग ही प्रस्तुत करेंगे। जो सपने आप संजो रहे हैं, सपने देखने से काम नहीं चलता बल्कि काम करने से मंजिलें हासिल होती है

(इस समय 07 बजकर 53 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अभी हमारे विपक्ष के साथियों ने मा0 अखिलेश जी के बहुत सारे कामों के बारे में व्याख्यान किया। बिल्डिंग्स या भवन बनाने से काम नहीं चलता, धरातल पर काम करना पड़ता है। अभी गन्ने और गन्ने के भुगतान के बारे में आप लोग बात कर रहे थे। वर्ष 2017 से पहले गन्ने के भुगतान की जो दुर्दशा थी, वह आप सब जानते हैं। वर्ष 2017 से पहले क्रय केन्द्रों पर किसानों का 3-3, 4-4 क्विंटल गन्ना प्रत्येक ट्राली पर कम तौला जाता था, उन लोगों के क्रय केन्द्रों/गेट पर गन्ने तुलते थे, जिनका एक भी बीघा गन्ना कहीं खड़ा नहीं होता था, लेकिन सप्लाई टिकट उनके 1000, 1500 लगते थे। जब उनके पास एक भी बीघा गन्ना नहीं होता था, तो आखिर वे किसका गन्ना खरीदते थे ? वह औने-पौने दामों में हमारे किसानों का गन्ना खरीदते थे और जहाँ-तहाँ उनके गन्ना खरीदने के इंस्टाल बने हुए थे। हमारा जो किसान एक-एक, डेढ़-डेढ़ दिन से लाइन में लगा रहता था, वह इतने असरदार लोग हुआ करते थे कि ट्राले पर गन्ना भरकर ले जाकर बीच में गाड़ी लगा देते थे, जिसमें किसानों के ट्रैक्टर भी डैमेज हो जाया करते थे। आज आपकी जो पर्ची आती है वह लगभग एक हफ्ते पहले पता लग जाती है कि हमारी सप्लाई टिकट फला तिथि में आ रही है। किसान आराम से अपना गन्ना छिलकर सफाई कर लेता है और समय से गन्ना तुलवा देता है। इस तरह से हमारे किसानों का जो शोषण होता था, वह अब नहीं हो रहा है। एक तरह से आप कह सकते हो कि हमने गन्ने का रेट बढ़ाया नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं कितनी सुधरी है, इस पर खुद एहसास करने की बात है कि आप के समय में गन्ना माफिया किस तरह से काम करते थे।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, ऐसे ही प्राइमरी स्कूल के बारे में आप बात कर रहे थे। वर्ष 2017 से पहले प्राइमरी और जूनियर में माँ-बहनें अपने बच्चों को स्कूल में बैठने के लिए यूरिया का कट्टा बनाकर देती थी और एक हाथ में टाट के थैले में बच्चा किताबें लेकर जाता था। स्कूल में बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी। वे बच्चे स्कूल में जाया करते थे, जिनको खाने की किल्लत रहती थी, वे बच्चे मिड-डे-मिल का खाना खाने के लिए स्कूल भेजे जाते थे। ऐसे ही प्राइमरी और जूनियर स्कूल में पढ़ाई की अव्यवस्था बन गयी थी, लेकिन वर्ष 2017 में मा0 योगी जी की सरकार आने के बाद आज विद्यालयों के अंदर पंखे लगे हुए है, टाइल्स लगी हुई है, अच्छे-अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं। अध्यापकों का विद्यालय जाना अब सुनिश्चित हो गया है,

यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। प्राइमरी स्कूल के जो टीचर महीने या 15 दिन में हाजिरी लगाने जाते थे, आज 95-98 प्रतिशत अध्यापक विद्यालय आ रहे है। वह बात अलग है कि कोरोना काल की वजह से विद्यालय में इस समय पढ़ाई का माहौल नहीं है, लेकिन कल से विद्यालय खुल गये हैं और पढ़ाई का एक वातावरण बनाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस तरह से समय- समय पर प्रशिक्षण देने के बाद आज प्राइमरी और जूनियर स्कूल के अध्यापकों में पढ़ाई का एक वातावरण बन गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप संक्षेप करिये।

श्री केसर सिंह-

महोदय, अभी एक माह पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अपने-अपने ब्लाकों में आवास बांटे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप समाप्त करिये।

श्री केसर सिंह-

महोदय, मेरे दो विकास खण्ड है। उनमें लगभग 650 आवास गरीबों को बांटे गये हैं। ऐसे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में 7 करोड़ रुपये का यूनानी अस्पताल बनकर कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से जो रोड 20-25 साल से नहीं बने, रोड का नामो-निशान तक खत्म हो गया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप संक्षेप करिये।

श्री केसर सिंह-

महोदय, वह रोड वर्ष 2017 में हमारी सरकार आने के बाद, चाहें वह गन्ना विभाग का रोड हो, आर0ई0एस0 का रोड हो या पी0डब्ल्यू0डी0 का रोड हो। बहुत से रोडों का तो ये भी नहीं पता कि ये किस विभाग के रोड है, वह सारे के सारे रोड छः माह के अंदर पेंट रोड कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्री केसर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में रोडवेज की एक समस्या है। हमारे यहाँ एक पुराना रोडवेज है, लेकिन वहाँ पर बसें नहीं रुकती हैं। अगर उस रोडवेज का जीर्णोद्धार करा दिया जाये, तो उसे चालू किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हुआ। अब बैठ जाईये।

श्री केसर सिंह-

ऐसे ही मेरी विधान सभा में एक कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने की माँग रखता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आप समय समाप्त कह रहे है तो मैं आपके आदेश का पालन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत।

***श्री आजाद अरिमर्दन-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुजन समाज पार्टी विधान मण्डल दल के नेता माननीय श्री लाल जी वर्मा से अपने को सम्बद्ध करते हुए संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ। अध्यक्ष जी, यह बजट पूर्णतया काल्पनिक है। व्यवहार में यह बजट जनहित में नहीं है। यह बजट किसान, नौजवान, एस0सी0/एस0टी0, ओ0बी0सी0, अल्पसंख्यक और गरीब सर्वण विरोधी बजट है। इस बजट में आय के स्रोतों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि ज्यादा से ज्यादा अनुत्पादक कार्यों में व्यय दिखाया गया है। यह सरकार नारा देती है कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन 25,000 करोड़ रुपये का बजट मात्र प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी में ही खर्च कर दिया गया और अन्य जनपदों की अवहेलना की गयी। मान्यवर, सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का वायदा किया था लेकिन अगर देखा जाए तो तहसीलों, थानों, ब्लाकों पर खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना रिश्वत लिये कोई काम नहीं हो रहा है। पूरी जनता त्रस्त है। जहाँ तक अपराध के संदर्भ में बात कही गयी थी तो मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार, छिनैती, डकैती आदि की घटनायें आये दिन हो रही है और यह पुलिस और जनता के बीच टकराव का कारण हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी हमारे विधान सभा क्षेत्र देवगांव ग्राम निहोरगंज बाजार में वीरेन्द्र यादव जी की दुकान थी जिस पर गुण्डों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और जब शिकायत किये तो वहाँ के पुलिस प्रशासन और खुद पुलिस अधीक्षक ने वहाँ पर जबरदस्ती कब्जा करवाया जिससे वहाँ पर लाठी चार्ज कराया गया। दर्जनों महिलायें घायल हुईं और उसे गम्भीर धाराओं में जेल भेज दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके मुकदमें वापस करते हुए जो दुकान का वास्तविक मालिक है उसे कब्जा दिलाया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में मेरी विधान सभा क्षेत्र के वैरीडीह में दिन-दहाड़े दलित युवक विजय की हत्या कर दी जाती है, जिसके विरोध में उसकी कुछ मांग होती है परन्तु उस पर भी लाठीचार्ज कर दिया जाता है और गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार जब से आयी है बिजली की समस्या हमारी विधान सभा क्षेत्र में विकराल है। फर्जी बिजली बिल की समस्या आये दिन देखने को मिलती है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्युत दर को दोगुनी कर दी गयी है। कोरोना महामारी में जो हमारे शिक्षण-संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान जो बंद पड़े थे उनकी लाखों रुपये की बिजली बिल आयी है। मैं माँग करता हूँ कि उनके बिजली बिल को माफ करने को व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब संक्षेप करिये।

श्री आजाद अरिमर्दन-

प्रदेश के सभी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं। एस0सी0/एस0टी0, ओ0बी0सी0 के आरक्षण के अनुपात में मैं माँग करता हूँ कि विशेष अभियान चलाकर भर्ती करके उनके बैकलॉग को पूरा किया जाए। आउट सोर्सिंग के माध्यम से जो भर्ती की जा रही है उनको स्थायी रोजगार दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, दशमोत्तर छात्रवृत्ति में जहाँ हमारे नवयुवकों को जीरो बैलेन्स पर प्रवेश दिया जाता है, इस सरकार ने उसे बंद कर दिया है, उसे पुनः चालू किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा में खुरसू एवं रामपुर बढ़ौना के बेसो नदी पर पुल का निर्माण किया जाए। ग्राम सिरसेड़ी में बेसो नदी पर पुल का निर्माण कराया जाए। ब्लाक तरवा ग्राम खुसनापुर एवं नई बस्ती में गांगी नदी पर पुलिया का निर्माण कराया जाए। साथ ही ग्राम- बहादुरपुर चकनोनारी, डीहबाबा के स्थान के पास पुलिया का चौड़ीकरण किया जाए। ग्राम महगूपुर में मिर्जापुर, देवगाँव में रामलगन के घर के पास नहर पर पुलिया का चौड़ीकरण किया जाए और जो पुलिया क्षतिग्रस्त है उनका निर्माण किया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में तमाम सड़कें अधूरी पड़ी हैं विशेष रूप से ग्राम दौना के प्राथमिक विद्यालय से इस्माइलपुर बरहती होते हुए गुलरियायादव बस्ती होते हुए हाई-वे तक सड़क का निर्माण किया जाए। ब्लाक लालगंज के ग्राम कटौली में मो0 मुअज्जम के घर से मो0 तनवीर के घर तक सड़क का निर्माण किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ब्लाक ढ़ेकवा में ग्राम रोहुआ के हाई-वे से ग्राम वेला हाई-वे तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। लालगंज बाजार में महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बन कर पड़ा हुआ है लेकिन संसाधनों के अभाव में उसको चालू नहीं किया गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उसे चालू किया जाए। हमारी विधान सभा लालगंज में कोई उद्योग नहीं है इसलिए वहाँ पर कोई उद्योग स्थापित किया जाए जिससे कोरोना काल में जो तमाम बेरोजगार अपने घरों में पड़े हुए हैं उनको रोजगार का अवसर मिल सके। लालगंज बाजार में ग्राम चेवारपूरब में गांगी नदी के पुल से ग्राम गोवर्धनपुर तक की सड़क का निर्माण किया जाए। लालगंज में बुढ़ऊबाबा से केराकत तक नई सड़क का निर्माण किया जाए। अंत में यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, दशमोत्तर छात्रवृति और रोजगार के लिए जो बजट एलाट किया गया है वह ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। इसी के साथ अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के 2021-22 के बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बाद जिस तरीके से 5 लाख 50 हजार करोड़ के लगभग बजट प्रस्तुत करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पूर्व एक संकल्प-पत्र प्रस्तुत करने का काम किया था। हमारी सरकार ने 2017 में घोषणा-पत्र की जगह संकल्प-पत्र देने का काम किया और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के संरक्षण में गरीब, किसान, महिला, दलित, संचित, शोषित, अल्पसंख्यक, युवा और श्रमिकों के कल्याण का यह बजट दिया है। यह बजट सभी पहलुओं को छूने वाला बजट है और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट है। इसके लिये मैं माननीय योगी जी को माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पूज्य योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश के चौमुखी विकास का बजट यह प्रदेश के विकास की ऊँचाइयों को छूने वाला बजट है और इसके साथ-साथ हमारे देश के बहुसंख्यक समुदाय की जो एक पाँच सौ वर्ष की जन आकांक्षा थी हमारे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो कार्य किया है उसके लिये भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि "**तुम अपने पास रखो अपने सूर्यो का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है**।" यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। हमारी सरकार ने किसान की आय दोगुनी करने का संकल्प लेकर इस बजट को देने का काम किया है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः।

सर्वे सन्तु निरामयाः।

की मंगलकामना के साथ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी और पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी ने अपने जीवन को दाँव पर लगाकर कोविड-19 काल में देश के और प्रदेश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सहायता पहुँचाने का काम किया। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

मान्यवर, कोरोना काल में भाजपा को छोड़कर अन्य राजनैतिक दल घरों में बैठकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालने का काम कर रहे थे उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री रात दिन दौरा करके कोविड-19 के दौरान अपनी जनता के जीवन की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुरक्षा के उपाय देने में लगे हुए थे। हमने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर कल्पना के साथ बजट देने का काम किया है। एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश जिसमें अपराधी को कोई जगह न हो। जो अपराधी हमारे विरोधी दलों के संरक्षण में संरक्षण पाते थे कोई भी दल का हो, चाहे किसी का हो, अपराधी को कोई जगह नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। मैं नियम- 51 ले रहा हूँ।

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

हमने भूमाफिया, खनन माफिया सबके ऊपर प्रभावी कार्यवाही करके उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिये हेल्प डेस्क बनाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हमने किसानों के कल्याण के लिये आत्मनिर्भर कृषक समुचित विकास योजना, मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना योजना और रियायती दर पर फसली ऋण देने का काम करके हमने किसानों की आय को दोगुनी करने का काम किया है। आज हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला योजना, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना मिशन शक्ति से थानों में महिला हेल्प डेस्क और प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में बिजनेस सखी के माध्यम से महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में एक कठोर कदम उठाया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

राजीव जी बैठें।

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

हमने गाँव-गाँव में स्टेडियम बनाकर आई0टी0आई0 और जी0आई0टी0 खोलने का काम किया है। गरीबों को शहरी में 16 लाख और गाँवों में गरीबों को 6 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। हमारी सरकार कोविड-19 की रोकथाम के लिये टीकाकरण का भी काम कर रही है। हमने पेयजल घर-घर देने का काम किया है। हमने आयुष्मान भारत योजना और मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना लागू की है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। समाप्त करें।

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

मान्यवर, हमारा आपसे एक निवेदन है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र दातागंज में एक चीनी मिल, एक स्टेडियम, एक अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजना, एक इंटर कालेज और हजरतपुर में एक पशु चिकित्सालय बनवाने का काम करें। अंत में, मैं इस बजट के पक्ष में बोलते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

[8:10] नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा कल भी चलेगी और परसों भी चलेगी। अब हम नियम-51 की सूचनायें लेते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मा0 सदस्य उपस्थित नहीं है, उनके स्थान पर मेरी सूचना वक्तव्य के लिए ले ली जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

पहली सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के एडेड महाविद्यालय में गरीब मेधावी छात्राओं की पढ़ाई में आ रही बाधाओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज की बदायूँ सिंचाई परियोजना में मानकों के विपरीत नहर का निर्माण कराए जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव, की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में तैनात प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री अनिल सिंह, की जनपद उन्नाव के विधानसभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत मौरावाँ मोहनलालगंज उन्नाव मार्ग की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी पर सेतु का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री विनोद कटियार की जनपद कानपुर के नगर पालिका पुखरायां में सीवर व्यवस्था का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में तथा सातवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह, की जनपद अमेठी के अन्तर्गत आवास हेतु पात्र व्यक्तियों का चयन न किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पहली सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत खनन में व्याप्त अनियमितताओं की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में दूसरी सूचना श्री नितिन अग्रवाल की जनपद हरदोई में राजकीय कृषि महाविद्यालय में शैक्षिक- सत्र प्रारंभ कराए जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज में नगर पंचायत सेवरही में धन उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में, तथा चौथी सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की जनपद देवरिया के भाटपाररानी में फायर स्टेशन की स्थापना कराने के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तथ हेतु स्वीकृत हई। पहली सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा नजीबाबाद में हाईटेंशन लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में गन्ना कृषकों का शोषण किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, प्रदेश के सेवानिवृत्त पशु चिकित्साधिकारियों को कैडर रिव्यू एवं वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी

सूचना अन्तर्गत श्री देवेन्द्र निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारनपुर के अन्तर्गत गांगनौली शुगर मिल द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री श्रीकान्त कटियार की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड फतेहपुर चौरासी में बिजली घर बनवाए जाने के सम्बन्ध में छठी सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में कतिपय मार्ग एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में सातवीं सूचना श्री कमल सिंह मलिक, की जपनद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कतिपय अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा, की परली एवं पराली जलाए जाने के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री विनय शंकर तिवारी की जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के अन्तर्गत उरुवा ताल की जल निकासी अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की श्री राजदेव सिंह निवासी जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा लिये गए ऋण माफ किए जाने संबंध में है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संस्थाओं में शैक्षिक तथा अशैक्षिक स्टॉफ को लाभ दिलाए जाने के संबंध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती निर्मला शंखवार की में, जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद में नाला एवं सड़क का निर्माण कराए जाने के संबंध में है, तेरहवीं सूचना श्री आनन्द शुक्ला की जनपद चित्रकूट स्थित रानीपुर वन्य जीव विहार को चित्रकूट वन प्रभाग के नियंत्रणाधीन कराए जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद सोनभद्र स्थित ब्लॉक कोन अन्तर्गत निर्माणाधीन सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत सड़क का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री मसूद अख्तर, की जनपद सहारनपुर के ब्लॉक पुवारका के राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज की चहारदीवारी का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री रवि कुमार सोनकर की जनपद बस्ती में कुआनों नदी पर पुल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाहरवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की वाराणसी के ग्राम चौबेपुर में रैन बसेरा की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री संजय गर्ग,की 60 वर्ष से ऊपर की आयुवर्ग के जी0एस0टी0 पंजीकृत व्यापारियों हेतु पेंशन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की जनपद कानपुर नगर में राइफल के स्थान पर शूटिंग रेंज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी, की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेईसवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धरौरा में मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र यादव की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत गाजीपुर-चोचकपुर मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल की उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों की विधवा पत्नियों को लाभ दिलाए जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की मया

टाण्डा राजमार्ग पर बाईपास बनाए जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत पिच मार्ग का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में तथा अट्ठाइसवीं सूचना श्री मोहम्मद फहीम इरफान की जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईः-

श्री हरीशंकर माहौर, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री सीताराम वर्मा, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री सुरेन्द्र मैथानी, बृजभूषण राजपूत, उर्फ गुड्डू भईया, श्री प्रमोद उटवाल, श्री कैलाश नाथ शुक्ल, श्री पूरन प्रकाश, श्री राम चन्द्र यादव, श्री प्रेम नरायण पाण्डेय, श्री सुभाष पासी, श्री अबरार अहमद, श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, श्री बवान सिंह, श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ़ सुरेश यादव, श्री दिग्विजय नारायण उर्फ़ जय चौबे श्री विनोद सरोज, श्री प्रेम सागर पटेल, श्रीमती जय देवी, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री जटाशंकर त्रिपाठी, श्री विजेन्द्र सिंह, श्री लकी यादव, श्री संजीव कुमार, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, श्री शीतल पाण्डेय, श्री राम अचल राजभर, श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री आशीष सिंह पटेल आशू, डॉ0 नीरज बोरा, श्री बम्बा लाल, डॉ0 अनीता लोधी राजपूत, श्री देवमणि द्विवेदी, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्रीमती लीना तिवारी।

जनपद श्रीवस्ती के गिलौला बाइपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम फेरन पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय)-

मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत पूरनपुर-गोला-बहराईच सिद्धार्थनगर-पडरौना मार्ग) पर.....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत कि0मी0 282.00 से कि0मी0 285.00 के मध्य गिलौला कस्बा स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त भाग पर पूर्व में मार्ग की चौड़ाई मात्र 6-7 मीटर थी। उक्त मार्ग को भारत सरकार द्वारा ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत जॉब सं0-एनएच-370-यू0पी0-2015-16-526, दिनांक 30-03-2016 में स्वीकृत होने के पश्चात उक्त भाग को दो लेन विद् पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण करते हुए 12 मी0 चौड़ा कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त भाग का पी0सी0यू0 12561 तथा चौड़ाई दो लेन पेव्ड शोल्डर (12.00 मी0)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है एवं उक्त भाग में यातायात सुगमता पूर्वक चल रहा है तथा किसी प्रकार की जाम की समस्या नहीं है।

प्रश्नगत मार्ग की भविष्य की आवश्यकताओं एवं यातायात की सुरक्षा के दृष्टिगत गिलौला कस्बे में बाईपास का कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की कार्य योजना वर्ष 2022-23 में स्वीकृत हेतु प्रस्तावित है।]

श्री रामफेरन पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं आग्रह करता हूँ, बड़ी कृपा हुई है। हमारी रोड बन गयी है। बाईपास का जो ईश्यू है, एक स्टीमेट पड़ा हुआ है। कम पैसे में बाईपास बनकर काम चल जाएगा। उसको अगर बनवा दिया जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी, जो जाम लगता है, उससे निजात मिल जाएगा।

श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, हम इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने तो और ज्यादा महत्व दे दिया।

श्री रामफेरन पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत भौरेश्वर धाम मन्दिर को जोड़ने वाले रास्ते का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण का वक्त

लोक निर्माण राज्य मंत्री, (श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय)-

मान्यवर, लखनऊ जनपद में धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गों के निर्माण.....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तण्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत कुर्री सुदौली मार्ग पर स्थित भौरेश्वर महादेव मंदिर, पहुँच मार्ग के चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य लम्बाई 0.800 कि0मी0 एवं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लागत रु0 196.16 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

शेष लम्बाई में मार्ग की मरम्मत का आगणन कार्यालय मुख्य अभियन्ता (म0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-3053सी0जेड0काम/802सी0जेड0-लखनऊ/2020, दिनांक 19-11-2020 द्वारा गठित कर प्रेषित किया गया है जिसकी कुल लम्बाई 1.050 कि0मी0 तथा लागत रु0 242.85 लाख है। उक्त कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

श्री अध्यक्ष-

आपको कुछ कहना है।

श्री अनिल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि भौरेश्वर धाम एक प्रसिद्ध धाम है, जो आदिकाल से वहां पर बना हुआ है, वह रोड बहुत ही पतली है। उस रोड का चौड़ीकरण कर दिया जाए। आपकी कृपा से सारी हो गयी है बस एक बची है। वहां पर लाखों श्रद्धालु शिवरात्रि के दिन जाते हैं। 4-5 कि0मी0 की सड़क है, उसका चौड़ीकरण करा दिया जाए। मैं मा0 मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं।

श्री अनिल सिंह-

सारी कर दी है एक बची है वह हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं इस पर आश्वासन चाहता हूँ।

श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

जो 800 मीटर है इसकी लागत 196.16 लाख है इसकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

श्री अनिल सिंह-

आपको अधिकारी लोग भ्रमित कर रहे हैं। यह वह चीज ही नहीं है। जो इसमें दे दिया है।

श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

इसमें लिखा है कि मार्ग की मरम्मत का आगणन कार्यालय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के पत्रांक दिनांक इतने द्वारा गठित कर प्रेषित किया गया है जिसकी लम्बाई 1.05 कि0मी0 है। जिसकी लागत 2 करोड़ 42 लाख 85 हजार है उक्त कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

श्री अनिल सिंह-

मंत्री जी यह वह रोड ही नहीं है। इसमें मंत्री जी कह देंगे तो बन जाएगी।

श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

माननीय सदस्य का कहना है कि यह दूसरी रोड है तो वह लिखकर दे दे उसको भी दिखवा लिया जाएगा। हमारे जवाब में यही है।

श्री अनिल सिंह-

दूसरी रोड नहीं यही रोड है वह 8 कि0मी0 की है। यह एक कि0मी0 की। अध्यक्ष जी इस पर आश्वासन मिल जाए।

श्री अध्यक्ष-

इसमें जो उल्लेख है। महादेव मंदिर पहुँच मार्ग यह दो जिलों के बीच में है। सौंदर्यीकरण का कार्य 0.80 कि0मी0 लागत इतने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसका मतलब 196 लाख की स्वीकृति हो गई। कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है। शेष में लोक निर्माण विभाग द्वारा आगणन बनाया गया है।

श्री अनिल सिंह-

इसमें केवल चौड़ीकरण करना है। सात मीटर पर हम लोग जो बनवा चुके हैं वह उसकी बात कर रहे है। मेरा आग्रह है कि यह बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसको दिखवा लीजिए।

जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत चौकी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा नियम- 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक उन्नाव के पत्र सं090/2020 दिनांक 1 मार्च, 2021....

श्री लाल जी वर्मा-

इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

की वस्तुपरक आख्या प्राप्त हुई, जिसमें निम्न तथ्यों से सूचित किया गया है :-

[जनपद उन्नाव में थाना फतेहपुर चौरासी की चौकी राजेपुर अस्थायी तौर पर ग्राम समाज की 02 बिसवा जमीन पर संचालित है जो पंचायत भवन के बगल में है। पुलिस चौकी में 01 कमरा, 01 बरामदा व शौचालय, स्नान गृह जनता के सहयोग से निर्मित है। इस चौकी क्षेत्र में 18 नम्बरी गांव व 32 उनके मजरे हैं चौकी क्षेत्र की कुल आबादी लगभग 51 हजार है तथा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

थाने से चौकी की दूरी 18 किमी है। थाना फतेहपुर चौरासी के अन्तर्गत राजेपुर चौकी को मिलाकर कुल 03 पुलिस चौकी है। चौकी के नाम पर भूमि आवंटित नहीं है। भूमि आवंटन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, उन्नाव से अनुरोध किया गया है। भूमि आवंटन होने के उपरान्त रिर्पोटिंग पुलिस चौकी राजेपुर का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

पुलिस अधीक्षक, उन्नाव की उक्त आख्या दिनांक 01 मार्च, 2021 से स्पष्ट है कि उक्त पुलिस चौकी अस्थायी तौर पर संचालित है। अतएव पुलिस मुख्यालय के माध्यम से पूर्ण व औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को प्राप्त होने पर प्रस्ताव का संगत मानकों व भूमि उपलब्धता की सूचना आदि के परीक्षण उपरान्त तथा बजट व्यवस्था आदि का दृष्टिगत रखते हुए ससमय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

***श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-**

इसमें थोड़ा समयबद्ध कर दें। समय से रिपोर्ट आ जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सिद्धान्ततः हमारी सहमति है। पुलिस चौकी बनना मैं समझता हूँ कि ला एण्ड आर्डर की दृष्टि से और आवश्यकता को देखते हुए उपयुक्त मालूम होता है। लेकिन अभी भूमि की व्यवस्था नहीं हुई भूमि की व्यवस्था में आपको सहयोग करना चाहिए। अगर भूमि हो जाती तो हम अभी कह देते। भूमि की व्यवस्था करवा दें मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

संसदीय कार्य मंत्री जी आप जवाब देखिए दो बिस्वा जमीन के ऊपर वह बना ही है। इसका मतलब हो गया करीब 2820 स्क्वायर फीट।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसमें लिखा है कि भूमि के आवंटन होने के उपरान्त।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

आवंटन तो जिलाधिकारी को करना है वह उसी जमीन का आवंटन कर देंगे। यह उसी जमीन पर बनी है। एक कमरा एक बरामदा एक शौचालय उसी पर बना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लैण्ड अगर है तो मेरी समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम डी0एम0 से प्रस्ताव मंगवाए लेते है।

श्री रवि सोनकर-

मान्यवर, मेरा नाम रवि सोनकर है मेरा नियम-51 में छूट गया है। मेरा नाम छूट गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बांदा राजकीय जिला अस्पताल में नवीन भवन संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

इसमें केवल वक्तव्य है।

(केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 100 शैय्यायुक्त जिला चिकित्सालय, बांदा को उच्चीकृत कर 300 शैय्यायुक्त मण्डलीय चिकित्सालय भवन का निर्माण [भू-गृह (बेसमेंट), भूतल, प्रथम तल] द्वितीय तल, तृतीय तल व चतुर्थ तल) कुल छः तलों का प्रस्तावित है, जिसमें भू-गृह (बेसमेंट), भूतल व प्रथम तल तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बांदा ने वर्ष 2017 में हस्तगत कर लिया परन्तु प्रथम तल पर अभी टाइल्स, नल फिटिंग का कार्य चल रहा है। शेष तल द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ तल अभी भी निर्माणाधीन है।

जिला चिकित्सालय, बांदा को 100 शैय्या से 300 शैय्या में उच्चीकृत किये जाने के लिये चिकित्सक, पैरामेडिकल व अन्य आवश्यक मानव संसाधन के पदों को सृजित किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने का अनुरोध वित्त विभाग से किया गया था। उक्त पद सृजन प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा कतिपय पृच्छायें की गयी है, जिसका समाधान किया जा रहा है। प्रश्नगत मण्डलीय चिकित्सालय को क्रियाशील/उच्चीकृत करने हेतु शासनादेश दिनांक 02-02-2019 के द्वारा रुपये 5,44,65,614/- मात्र की निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के फलस्वरूप उपकरण/मशीनों का क्रय कर लिया गया है।

वर्तमान में प्रथम तल में कोविड समर्पित एल-2 चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है। कोविड- 19 महामारी की समाप्ति के उपरान्त 100 शैय्या से 300 शैय्या में उच्चीकृत किये जाने के लिये मानव संसाधन के आवश्यक पदों के सृजन की कार्यवाही के पश्चात् 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय में उपलब्ध मानव संसाधन (चिकित्सक-13, नर्सिंग स्टाफ-12 पैरामेडिकल स्टाफ-25 व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-25) कुल 75 पदों से मण्डलीय चिकित्सालय संचालित किया जायेगा।]

जनपद चित्रकूट के मानिकपुर के अन्तर्गत मऊ पेयजल योजना के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द शुक्ल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

इसमें भी केवल वक्तव्य है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

मान्यवर, मेरा नियम-51 में छूट गया है। मेरा नाम छूट गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 08 बज कर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 02 मार्च, 2021

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 108 विधान सभा (190)-11-08-2022-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।